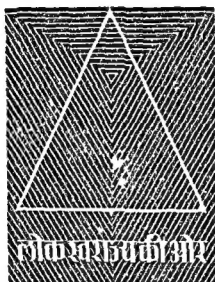




# लोक स्वराज्य की ओर

• सर्वेक्षण • मूल्यांकन • भावी योजनाएँ



प्रकाशक

राजस्थान पंचायत राजे संघ

जयपुर

- प्रकाशक

प्रधान मंत्री

राजस्थान पचायत राज सघ

पार स्त्रीम रोड जयपुर

- प्रकाशन तिथि

२५ अगस्त, १९६६

- भविल भारतीय पचायत राज परिषद् द्वारा  
दिनांक २५ २६ अगस्त को जयपुर म  
घायोजित होत्रोय सरोवरी के अवसर पर  
प्रकाशित

- मूल्य

दत्त रुपये

- मुद्रा

नवल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर

माहभूमि प्रेस जयपुर



- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- राजस्थान के राज्यपाल
- पंजाब के राज्यपाल

## राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिजी को यह ज्ञानकर प्रसन्नता हुई कि प्रखित भारतीय पंचायत परिषद्, नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान पंचायत राज सघ, जयपुर द्वारा क्षेत्रीय गोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस अवसर पर राष्ट्रपतिजी अपनी शुभ कामनायें भेजते हैं।

ह० रा० राममुख्यम  
भवर सचिव

## उपराष्ट्रपति

यह सुखी की बात है कि आप प्रखित भारतीय पंचायत परिषद् नई दिल्ली के तत्वावधान में भागामी २५-२६ अगस्त १९६६ को राजस्थान पंचायत राज सघ जयपुर द्वारा एक क्षेत्रीय गोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर गोष्ठी के विचारणीय विषयों से सम्बंधित स्मारिका भी प्रकाशित होगी।

मैं आपका सम्मेलन तथा स्मारिका की सफलता के लिए हार्दिक शुभ कामनायें भेजता हूँ।

आपका  
जाकिरहुसन

## प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्रीजी आपकी धन्यवाद देती हूँ और पचायती राज के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करने के लिए जयपुर में आप जिस क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, उसकी सफलता के लिए अपनी शुभ कामनाएँ भजती हूँ।

ह० एच० बाई० शारदाप्रसाद  
(प्रधानमंत्रीजी के उप सूचना सलाहकार)

## राजस्थान के राज्यपाल

यह है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं कुछ अधिक नहीं लिख सकता। आशा करता हूँ कि गोष्ठी सम्पन्न होगी और राजस्थान में जा पचायती राज के विषय में सारे देश में अग्रगण्य रहा है। हम धाम को आगे बढ़ाने की नयी दिशाएँ खुलेंगी। निश्चय ही आपको अपने अध्यक्ष श्री जयप्रकाशनारायण से बहुत उपयोगी परामर्श मिलेंगे।

भवदीय  
सम्पूर्णान्व

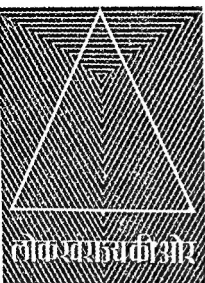
## पंजाब के राज्यपाल

यह बड़े हृदय का विषय है कि भारतीय पचायत राज परिषद् देश में पचायत राज के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करने के लिए एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। भारत में पचायत राज व्यवस्था पुरातनकाल से चली आई है। मर्यादा विदेशी शासनकाल में इनको निजी बना दिया गया था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पचायतों को सौजन्य की मुद्रा आधारित रूप में स्थापित कर दृढ़ सुनियोजित गणतन्त्र का रूप प्रदान किया गया।

पचायतों ने राष्ट्र विकास कार्यक्रमों में प्रगतिशील योग दिया है। वर्तमान समय की मांग है कि देश से मुनाफाखोरी, अनुचित मजदूर और मिलावट आदि अशुभ कार्यों को समाप्त करने की दिशा में पचायतों दलबन्दी से ऊपर उठकर सरकार का हाथ बटाएँ।

इस क्षेत्रीय संगोष्ठी की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनाएँ आपके साथ हैं।

धन्यवाद  
राज्यपाल, पंजाब



## उलटा पिरामिड सीधा पिरामिड

हमारा सोचतंत्र बहुत सकुचित भाषार पर टिका हुआ है। यह एक ऐसे उलट पिरामिड की तरह है जो सिर के बल खड़ा है। अत्यन्त हमारा काय है बिच को ठीक करना और पिरामिड को फिर सही भाषार पर खड़ा करना। केवल यह तथ्य कि हर बालिग भारतीय को वोट दान का हक है, शासन पद्धति के पिरामिड को व्यापक भाषार नहीं देता।

× × × ×

समाज के राजनीतिक ढांचे का ही सादृश्य उलटे पिरामिड से नहीं है, भाषिक ढांचे की भी तस्वीर वसी ही बेतुकी है।

× × × ×

इसलिए ऐसा हर व्यक्ति, जो इस सवाल पर जरा भी गम्भीरता से सोचने को तयार है, स्वीकार करेगा कि सिर के बल खड़े राजनीतिक पिरामिड को उलट कर तब तक सीधा नहीं किया जा सकता, जब तक भाषिक पिरामिड को भी इसी प्रकार सही हालत में न किया जाय। दूसरे शब्दा में, बिना भाषिक विकेंद्रिकरण के राजनीतिक विकेंद्रिकरण कारगर नहीं हो सकता।

—जयप्रकाशनारायण



## लोक स्वराज्य की ओर

### अनुक्रम

खंड	विषय
१	प चायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२	प चायती राज का अभिप्राय और दर्शन
३	प चायती राज की संरचना की पृष्ठभूमि
४	प्राप्त-समा
५	प चायती राज की वित्त व्यवस्था
६	प चायती राज और राजकीय नियंत्रण
७	प चायती राज में नियोजित कार्यक्रम
८	विविधा

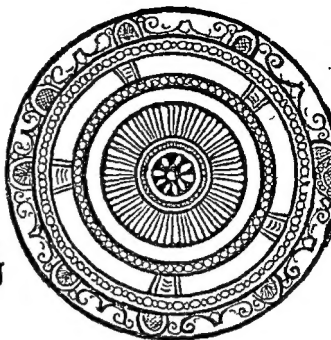
---





खंड-१

## पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि



१ सोमसत्तापरक व्यापिक, राजनीतिक  
सत्स्यामा के उद्भव, विवास और  
ह्रास की प्रक्रियाएँ

—डॉ. मुन्शीसिंह मेहता

१-८



# लोकसत्तापरक आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव, विकास और हास की प्रक्रियाएं

— श्री पृथ्वीसिंह मेहता

पूर्णतः स्वयासित लोकसत्तापरक आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व और उनकी परम्परा चायद विद्वद् म सबसे प्राचीन स्वस्थ और परिपुष्ट रूप म भारत मे ही कार्य करती रही प्रतीत होती है, अतः लोकसत्तात्मक आनुवांशिक संस्थाओं को उद्भव और विकास एवं हास की प्रक्रियाओं को टटोलन के लिए भारत मे उसने आरम्भिक काल से लेकर अब तक बदलते हुए रूपा का एक विश्लेषण यहा प्रस्तुत करना कदाचित् अप्रासङ्गिक न होगा ।

भारतीय कृष्टि का वास्तविक आरम्भ भारत मे जनमूलक संघटन वाले ग्रामों के विभिन्न समूहों के आकार इस देग की विभिन्न प्राकृतिक प्रादेशिक इकाईया मे अपना-यास ग्रहण करने के बाद उन्हे पूर्णतः अपने २ जन का स्थाई निवास अपना जनपद स्वीकार कर लेने के बाद एकजनपद भावना से प्रेरित राष्ट्रीय कृष्टि का विकास करने की प्रक्रिया से होता है । यह प्रक्रिया उत्तर वदिक काल में सम्पन्न हुई । ग्राम लोग तब तक अपने आरम्भिक जनमूलक स्वरूप को धाम भुला चुके थे और एक प्रादेशिक भावना परक कृष्टि का विकास करने लगे थे ।

विन्तु उस कृष्टि के मूल बीज क्योंकि ग्रामों के जनमूलक विश्व जनता के सामाजिक राजनीतिक संघटन म थे, अतः उसने स्वरूप को समझ लेना पहले आवश्यक है ।

ग्रामों का समग्र आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से भारत में आकर बसने से पहले ही अपनी आखेटक व्यवस्था को साथ पशु पालक और इषक व्यवस्था तक पहुँच चुका था । आखेटक जीवन की स्मृति उसमें बची थी, सो बहुत ही घुबली । सामाजिक सम्बन्धों की दृष्टि से वह समाज सम्मिश्रण (Promiscuity) की दशाओं की पूरी तरह पार कर पारिवारिक रचना की स्थिति तक पहुँच चुका था ।—यह स्थिति समाज की विह्वलता का आरम्भ हो चुकना बताती है उससे पहले समाज मातृमूलक था, जन-समाज में स्त्री

पुरुष सम्बन्ध अभी स्थिर नहीं होते और एक घाबरेटक या पशुपालक समूहों के स्त्री पुरुष आपस में सब भाई-बहिन समझे जान से स्त्री पुरुष सम्बन्धों के लिए उन्हें दूसरे समूहों से मंत्री या बाधक सम्बन्ध स्थापित करने पड़ते। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के लिए ऐसे मित्र जनों के बिना इस काम के लिए निश्चित संकेत म्यला पर होने वाले उत्सवों मला आदि में ग्रामवार एकत्रित होने और इस प्रकार एक समूह की स्त्रियों या सारी सत्ता उस समूह के पुण्या के भानज या दोहित्र होते और अपने मातृगणों के नाम से ही समाज में पहिचान जाते थे। यन्त्रिक भाषों का समाज दूरी तरह वित्तमूलक पारिवारिक इकाईयों में विभक्त हो चुका था तो भी स्त्री की स्थिति अभी उससे बेरो या दास्य होने की उपेक्षा बराबरी की सहकारिणी की सहचरी की थी। समाज में और सम्पत्ति में उत्तम अधिकार पुरुष के सम्बन्ध और बराबरी का ही माना जाता था। इसके लिए उम्र किसी न किसी पुरुष का प्राथम्यता होना अनिवार्य नहीं था। वह चाहती तब तक किसी पुरुष की प्राथम्यता या आधिकारिक रूप से परमुखापेक्षणी हुए बिना समाज में सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र जीवन बिता सकती थी।

## वैदिक समूह का संघटन

ग्रामों के ये आरम्भिक समूह जसा कि ऊपर कहा जा चुका है उन कहलाते जो परिवार के समूह पर बन, किसी बड़े पूर्वज या विद्यमान पुरुष के नाम पर प्रसिद्ध होते जाते। उन फिर कई जाँतों या टुकड़ियों में बंट जाते जो ग्राम कहलाती। ग्राम शब्द का मूल अर्थ उत्पत्ति या समुदाय या और ग्राम जहाँ बस गए वह जमीन भी पीछे ग्राम कहलाने लगी। ग्राम का एक चुना हुआ या बगानुगत नेता ग्रामणी था। जनों के सम्पत्ति प्रायः मुँहों आदि के धक्कड़ों पर जब होते तो उनकी सेना ग्रामवार अपना जलपदार जमा होती जिससे पीछे मुँह ही संग्राम कहा जाने लगा।

ग्राम की तरह समूहों में भी नेता होता जो राजा कहलाता। वह जन या विश का राजा या भूमि का स्वामी नहीं। राज्य जनसूत्रक होने से जनराज्य कहलाना अपना उममें जन से बाहर के दूसरे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था, जब तक वह अपने मूल जन (प्रमिजन) का प्रत्याग्रहान कर अपने निवास क्षेत्र के जन की सजायता ग्रहण न करे ? विभिन्न जनों को मिलाकर ग्रामों की सामूची धावादी संरचना अपना मूल आकार लेती जाती।

## वैदिक राज्य संस्था

राजनीतिक संघटन राष्ट्र कहलाता जिसका अपना एक देश होता। और राजा उस राष्ट्र का मुखिया। राजा का करण बिना करती और यदि वह पिछले राजा का बैठा हो तो उसे पसंद कर राजा बनाने की स्वीकृति देती। वरान होने पर अस्थिर होता उसमें राजा जिस के साथ कभी झग न करने की प्रतिज्ञा करता उस राज की पाती सौंपी जाती और विरोध पहिनाया जाता एक पुराहित ऋषि कहकर वह राज्य तुम्हें दृष्टि के लिए लोग के लिए, समृद्धि के लिए पुष्टि के लिए सौंपा गया तुम इसके यत्ना यमन और प्रमुख धारण करता हो, उसके धर्मिकों की भावित्वा अपना घोषणा करता, जिसे निभाने के लिए उसे प्रजा के बलि या भाग देने का धर्मधार दिया जाता।

सत्ता प्रकार से करण राजा की प्राप्ति कर के लिए होता पर यदि वह सत्ता में नियंत्रण अपना

असिधेक के समय की हुई प्रतिष्ठा को पूरा न करे तो जिस उमे पदच्युत और निर्वासित भी कर देनी । निर्वासित राजा का कभी कभी ये फिर वरण भी कर देती ।

राजा समित को सहायता ने राज्य करता, जो ममूची जिस की सत्ता थी । राज्य की बाग और समिति के हो हाथ में रहनी । समिति के सदस्य कौन कौन होने और कौन चुने जाने प इसका ठीक पता नहीं है, पर शायदो, सूत रथकार और-कर्मार अर्थात् प्रत्येक गांव के ग्रामीण और शिल्पी उमम अवश्य सम्मिलित होते थे । ये ग्राम समिति के आधार थे । समिति का एक पति या ईशान होना । राजा भी समिति में जाता । राजा का वरण निर्वासन पुनर्वरण समिति द्वारा ही होता । राज्य का मन्त्र अर्थात् नीति निर्धारित करता भी समिति का ही काम था । उसका बठरा म बाद-वि द पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त शान्ति से होत बगल साध बुद्धिबो और बकतुत्व फला से सदस्यो को अपने एक में कवन का दान करने ।

समिति के प्रतिरिक्त सभा नाम की एक सत्ता भी राज्य में होती जो समिति में छात्रा जाता । राज्य के मुख्य 'ग्रामालय का काम बड़ी करती । प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती जिसमें न केवल बुद्ध प्रत्युत जवान लोग भी भाग लेते । प्रावश्यक कार्यों के बाद ग्रामी की भाषायो म विनो की बातें भी होती और तब वे सभाएं गोष्ठी का नाम देती । गाँवा की चर्चा गाँवियों म सबसे अधिक होती इसीम उनका नाम गोष्ठी पडा ।

समिति के सदस्य 'राजानी राजकृत अर्थात् राजा बनाव वाले राजा कहलाते थे । किन्तो किमो राज्य में राजा न होता और वे ही मिलकर राज्य करते । वस राज्य को मब कहा जाता क्यकि उनम एक मुख्य क ब्रजाम सब का राज्य होता । उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण अनुप्राप्ति में है । महाभारत युद्ध में ठीक पहले मथुरा प्रदेश म यादवो की दो लीयें—धृष्टक और दुषिण—रहती थी । धृष्टको का राजा कन मयध के राजा जरासभ का दामादा था । जरासभ न मध्यप्रदेश पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था कस ने उनके सहारे के आरोह अपनी प्रजा को पीडित किया । धृष्टको ने तब अपने परोसी दुषिण यादवो से सहायता मांगी, और दुषिणो के नेता बासुदेव दुषिण न कन की मार डाला । तब जरासभ का काया धृष्टको और दुषिणों पर उमडा । वे लोग जरासभ का सामना न कर सके थार मथुरा छोड़ दारका चले गये । वहाँ धृष्टक वणिग-सभ स्थापित हुआ जिसके दो मय मुख्य एक धृष्टक पुन जाते । उमसेन एक मय मुख्य था और बासुदेव दुषिण दूसरा ।

## उत्तर वैदिक काल

किन्तु जसा कि कहा आ चुका है मास भारता राष्ट्रीय कवि का स्वल्प मयिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में स्थिर हुआ और सभी भारतीयकवि का अविच्छेद अवस्था शुरू हुआ ।

ग्रामी की राज्यसत्तामें इस युग तक भीतर भीतर बडा परिवर्तन हो जाता है । जनों के बतने के स्थान जनपद कहाने और राज्य अब जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जान मंगता है । जनपदों के नाम जनों के नामों से हो पडे थे, जैसे जैसे कुछ पञ्चास, वेदि वल, धम धरेसन धवन्ति धीपय, मेद धिदि, मानव, बैक्य, गंधार आदि । किन्तु नाम बहो रहते हुए भी भीतर से उनही राज्यसत्ता म धुरे-धुरे परिवर्तन हो गया । जनराज्य के बजाय अब वे जनपदराज्य बन गये । यन्पि धम भी जन-जन

नामों के जनपदों में वही मूल जनो के बस्य मुख्यतः बसे हुए थे, तो भी लोगों ने धब सजातता की परवा करना छोड़ दिया। जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय और उसमें भक्ति रखे वह सजात हो या न हो धब उनकी प्रजा बन सकता था। जन्मद में भक्त का बिचार उत्तर-वर्द्धिक काल के अन्त में पहले-पहल सुनाई देता है। धार्मिक ग्रन्थों में उसी भक्ति शब्द का प्रयोग और पीछे होता है।

एनरेय ब्राह्मण में एक सप्तम (८१४) से यह पता मिलता है कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की राज्यसंस्थाएँ स्थापित हो गई थी। उस सप्तम का सार यह है कि पूर्व के अर्धार्थ मगध आदि जनपदों के राजा अपने अपने को सम्राट कहने वहाँ सम्प्रजाय जनन की प्रवृत्ति थी। मध्यदेश के राजा राजा कहलाते, वहाँ साधारण राज्य थे। पश्चिम में मुराष्ट्र और विदर्भ तक अधिकतर सम्राज्य थे। यह सब महारथ की सूचना है। हम देखेंगे कि लगभग ८०० ई० पू० से यह जो प्रवृत्ति प्रकट हुई सो प्राचीन काल के अन्त-समय ५४० ई० तक अर्थात् लगानार डेढ़ हजार बरस तक बनी रही।

जन और बौद्ध धर्मों का उदय उन्हीं सभ राज्यों के वातावरण में हुआ और उनके धर्मण सभ धर्मों का डोबा भी उन्हीं के हासन विधान में समुन पर बनाया गया।

दार्शनिक इन्द्र में एकेश्वरवाद की कल्पना एकराजिक समाज के राजनीतिक ढाँचे के आधार पर हो उठना है। सभ राज्यों में किसी एक स्थायी नियामक राजा की आवश्यकता नहीं थी। अतः विश्व के भी किनो एक स्वयम्भू नियता की अनिवार्यताका प्रश्न नहीं उठ सकता था। भारतीय दर्शनशास्त्र में साक्ष्य जन और बौद्ध-दर्शनों की स्वतन्त्र चिन्तना धृति इस प्रकार इन सभ राज्यों की ही देन थी।

## महाजनपद युग

जनपदों के बाद में बहुत से छोटे जनपदों के अपनी धार्मिक राजनीतिक समस्याओं के हल के लिए स्वेच्छा से मिलजुलने या एक जन द्वारा प्रबल होकर प्राप्त प्राप्त के ऐसे बना की जीत कर अपने साथ मिमा लेने से बह बह जन पदों की रचनो हुई।

हुद से प्राय एक सतादी पहले ऐसे सोलह महाजन पदों की छाठ जोड़ियों की गिनती प्रतिष्ठ हुई—

## धार्मिक सघटन और राज्यसंस्था

जनपद राज्य में राज्य भूमि पर निर्भर हो गया था तो भी भूमि राज्य की नहीं कृषको की सम्पत्ति थी। राजा धर्मों की उपज पद धार्मिक भाग या वस्ति में सकता अगम और परती भूमि का निपटारा कर सकता और अस्वामिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था। इस राजमोग का वह निजी धर्मों के लिए भी उपयोग कर सकता। राजकीय भाग को धार्मिकमोज (गांव के धृष्टिया) या राजकीय महामाण्य बसूलते। भूमि धर्मसिद्ध सम्पत्ति थी। उसका दाय विभाग दान् और विक्रय हो सकता था। पर गांव का कोई व्यक्ति गांव के बाहर के किसी व्यक्ति का अधीन दे या धिक् सकता था कि नहीं सा स्पष्ट नहीं है।

धर्मोपनिषद् बड़ी थी इषय हो मुस्वामी थे। धाम उन्हीं के समूह थे। प्रत्येक धाम में धर्म

कुल धनार्थ समुक्त परिवार रहते । ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है । इषि ऊँचा पेड़ा गिना जाता था । भुतको धर्षन् भ्राडे के धमिको से भी खेतो कराई जाती थी । एक व्यक्ति को जमीन पर २५ सो तक सलवाहो के मजदूरी करने का उल्लेख है । उन भुतवा का का जीवन काफी कठिनाई का था । उन्हें नहने की जगह और घनाज धपवा मुदा क रूप में मृति मिलती । इषि में अम विभाग भी हो चला था । उदाहरण के लिए बहुत लोग का पेसा हल वाहन का हो था ।

ग्राम के लोग सामूहिक रूप से सिबाई और धाय सामूहिक कार्यों का प्रबन्ध करते । ग्रामभोजन रोज-सभा में ग्राम का प्रतिनिधि तथा ग्राम के सामूहिक जीवन का नेता होता, पर वह मनमाना नहीं कह सकता था । ग्राम के सभी लोग मिलकर सामूहिक कार्यों पर विचार और निश्चय करते । ग्राम समार्य सभा भवन और पायगावाएँ बनवाती, गणेश लगवाती, सड़का की मरम्मत करवाती तालाब खुदवाती और उनके बाँध बंधवाती । उनके निश्चय के अनुसार ग्राम के युवक बारी बारी युक्त मजदूर करते । ग्रामों की उन सभाओं और उनके कार्यों में स्त्रियाँ भी सुलभ कर भाग लेती ।

शिल्प व्यवसाय की पण्डित उन्नति और अमविभाग हुआ गया था । प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे लोग का अपना सघटन था जिसे श्रेणि कहते । श्रेणि शब्द पहले-पहल उत्तर बर्दिक वाङ्मय में मिलता और फिर प्राचीन काल के अन्त तक बराबर इसी-धारा में शिल्पियों के सघटित समूह के—मध्य में बसा जाता है । महाजनपद युग के वाङ्मय में 'वड्डवि कम्मार चम्पकार चित्रकार प्राति भठारह श्रेणियाँ' प्रचलित हुआ करता है । एक-एक श्रेणी में हजार तक शिल्पी होते । प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख या ज्येष्ठ चुना जाता । प्रत्येक शिल्प का संचालन और नियंत्रण श्रेणि के हाथ में रहता । कच्चे मान की खरीद तथा की बिक्री उपज और अमकाल का निर्धारण मिलावट की रोकना शिल्प सीखने वाले श्रमिकों को श्रेणि के नियम, श्रमिकों और भुक्तों की भुक्ति नियत करना आदि सब श्रेणि के हाथ में रहता । ये श्रेणियाँ जाती न थी । अमविभाग के बढन और व्यवसाय के स्थान विनोदों में क्रान्ति होने से यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बड़ा बाप के धन में जाय, तो भी सगा बैसा न होता । श्रेणि के लोग के अपने बड़ा के अतिरिक्त दूसरे नवयुवकों के श्रमिक बनने के बहुत दृष्टान्त इस युग के वाङ्मय में हैं ।

शिल्प और व्यापार के बढने से अनेक नगरियाँ खड़ी हो गई थी । नगरियों में व्यापारियों के सघ बन गए थे जो निगम कहलाते । उनके मुखिया श्रेणी कहलाते जो ग्राम जीवन मर के लिए चुन जाते ।

निगम और श्रेणियाँ अपने सदस्यों की धार्मिक चर्या का संचालन तो करती ही, वे श्रोतों के साथ-साथ राज्यसंस्था की सबसे निचली इकाईयाँ भी थी । वे अपने सदस्यों के लिए स्वयं नियम बनाती, उन नियमों को चलाती और व्यापारिक का भी काम करती । ग्रामों की संस्था तो बर्दिक काल से चली आती थी । बर्दिक काल के ग्राम 'जन' की टुकड़ियाँ थे, धन के भीतरा परिचर्चन द्वारा कृषका के समूह धन गये । श्रेणी और निगम-संस्था भी ग्राम संस्था के समूह पर ही बनी ।

यों महाजनपद युग में भारत की प्रत्येक बस्ती की प्रजा अपने धन के अनुसार विभिन्न समूहों में बँटी हुई थी । प्रत्येक छोटा समूह अपनी भीतरी सामन्य में पूरी तरह स्वतन्त्र था । ये समूह—ग्राम श्रेणी और निगम—प्राचीन की सबसे छोटी स्वतन्त्र इकाईयाँ थी ।



प्रत्येक नगर में जनक श्रम गिणा होती। नगरों का विकास इसी युग में हुआ था इसलिए उनका प्रबंध और शासन इस युग का नई समस्या थी। इस युग में नगर संस्था का नाम भी नियम ही था—प्रगले युग में जा कर उसका एक और नाम पूज खाज लिया गया।

वदिक काल की राजसंस्था में वैद्रीय शासन में ग्रामगणियों का जो पक्ष था वह इस युग में ग्रामाणियों के साथ-साथ श्रेणीमुख्या और निगम श्रमियों का भी था। प्रत्येक महत्व के कार्य में इस युग में राजा नगमजानपदा की सलाह सता जा बाद में पौरजानपदा कहलान चगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदमजानपदा या पौरजानपदा वदिक काल की समिति का नया रूप था—यह वैद्रीय शासन में राजा का हाथ बगाने वाली संस्था थी।

## पूर्व नन्द युग की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएँ

उत्तर वदिक और महाजनपद युग में श्रेणी नियम आदि जो संस्थाएँ खनी हुई थी उनके लिये इस युग के बाह्य में जातिवाचक संज्ञाएँ थी—निकाय समूह या वर्ग। निकाय का अर्थ था श्रमवाचक समूह। अव्यवस्थित जमघट के अर्थ में निचय कहा जाता था। निकाय और निचय दोनों समान मूल हैं। श्रेणी और निगम दोनों आर्थिक निकाय थे, उनमें विभिन्न कुलों के परंपराएँ बुरा या जावका वाले लोग हाज थे। नगरों के साथ इस युग में पूज कहलाने लगे और उनकी यह परिभाषा थी कि विभिन्न कुलों तथा विभिन्न वस्तियाँ काल साथ पूज होती हैं (मत्स्याध्यायी ४.३.११२ पर काशिका वृत्ति)। अर्थात् पूज प्राणिक संघ के वे जिनमें जनक श्रेणियाँ और निगमों के प्रतिनिधि होते थे।

गौतम धर्मसूत्र ११.२१) से पता चलता है कि कौटिली अर्थात् कारीगरों के प्रतिरिक्त बचन बलिष्ठा पशुपालकों और ब्रह्मिण (छाया उधार देने वालों) की भी श्रेणियाँ थी। एक जगह रहने वाले ब्राह्मणों की श्रेणियाँ बनना सरल था पर बिलर शर रहने वाले कुँवका की भी श्रेणियाँ हाना उल्टा सामूहिक जीवन का सूचक था।

विद्युत युग के समान ग्राम श्रम नियम पूज आदि निकाय अपना भीतरी शासन व्यवस्थालाने अपने भीतर के विचार नियमों के लिए 'यायालय का काम' करना, पर सबसे बढ़कर वे आपस में मिल कर जो समझ या सौदवर्ग अर्थात् ठहराव करें वह समयवर्ग यदि देव के पूज घम और व्यवहार जानून के विषय न हो तो उसे चरिताप करना राजा का कर्तव्य होता। कोई वर्ग अपने वर्ग के समय की तोड़ तो दण्ड पाता था। समय (समय) का अर्थ था मिश्रकर विचार-हृषा ठहराव। या इन निधायों के ठहराव जानून थे। उन सभी में निश्चय विधियाँ ने प्रस्ताव रखने (कर्म बचन=कार्य का कहना) उस पर प्रकट या गुप्त रूप से मत मन और बहुमत से निश्चय करने की पद्धति थी। ग्राम, श्रेणी नियम पूज आदि निकाय जो समयवर्ग अर्थात् भाग्यो निश्चय द्वारा जानून बनाते वह भी ठीक पद्धति से विचार करने बनाया जाता वह यों हि चल जान खाना रिवाज नहीं था।

राजरोप विनिश्चयस्थानों ('यायालय') में विनिश्चायन ('यायायोग') के साथ उदाहरिका (जुरी) बैठती थी, और उसमें प्रत्येक वर्ग के अपने ही वर्ग के अर्थात् प्रत्येक समियुक्त के अपने निकाय के लोगों के बटने का नियम था।

यों इन निकायों का जहा पूरे स्व शासन के अधिकार थे वहाँ जनपद के केन्द्रिय शासन की भी  
 यहाँ बुनियाद थी । यहिक काल की समिति की तरह इस युग में भी परिषद् या पौरत्रानपद नाम का  
 निकाय समूचे जनपद के शासन को चलावे के लिए था । उसमें ग्रामस्थियों के प्रतिनिक्त श्रीणिमुख्य और  
 निगम श्रीष्टी पादि होते तथा राजा को उसके परामर्श के अनुसार चलना पड़ता । रामायण में राम की  
 युवराज बनान के लिए बुलाई गई राजा दशरथ की भत्ता का जो विषय है उसमें श्रीणिमुख्यों और निगम  
 श्रीष्टियों का विशिष्ट स्थान है ।

## सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँच-नीच का विषय यह था—“जातियो दो हैं, हीन जाति और उत्कृष्ट जाति । हीन  
 जाति को भी १ चण्डाल जाति बेला जाति नृपाद जाति ‘पुक्कस जाति । उत्कृष्ट जाति कौनसी ?  
 क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति ” । शिल्प दो हैं हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे नवचार  
 शिल्प कुम्हार का शिल्प हरकाने का शिल्प चमार का शिल्प नाई का शिल्प और जो उन जनपदों  
 में “ भवशात परिभूत हो । उत्कृष्ट शिल्प, जैसे मुद्रागणना सेल भण्डा उन जनपदों में  
 बर्ग दा है हीन बर्ग जैसे कोठा बनाने का काम । सूखे, फूँ बटोरने का काम । उत्कृष्ट काम जैसे श्री  
 बाणिज्य गोरक्षा’ (विनय पिटक) ।

इससे स्पष्ट है कि कृषक, कनिषा, व्यापारी, हरकारा, सराफ, नाई आदि विभिन्न जनपदों की  
 दशा के अनुसार ऊँचे नीचे काम और शिल्प थे, जाते नहीं । चण्डाल, बेला निपाद आदि वस्तुन धनार्थ  
 जातियों प्रथमतः नहीं थी । पर क्षत्रिय और ब्राह्मण कल्पित जातियाँ थीं । क्षत्रियों में अपने कुलों की  
 उच्चता का भाव इतना परिपक्व हो चुका था कि वे अपने की जाति बहनें लग थे और ब्राह्मण भी अपने  
 की जाति गिनना चाहते थे, यद्यपि उनके जाति होने की बात निवादयस्त थी—बहुत से ब्राह्मण स्पष्ट  
 कहते थे कि ब्राह्मण पत का जन्म व कोई सम्भव नहीं वत और श्रौत से है (मत्स्यनिपात अष्टमस्क ३५  
 वस्तुनृपा तथा ६५०) । जो भी हो, क्षत्रिय और ब्राह्मण भार्य कृषक शिल्पियों और बाणिज्यों से निम्न जाति  
 के न थे ।

## मौर्य राज्यसंस्था तथा कौटिल्य के राष्ट्रीय आदर्श

मौर्यों का समूचा साम्राज्यक्षेत्र या विजित् चार या पाँच सप्ताह में बड़ा था । जिन्हें चक्र भी  
 कहा जाता है चक्र पौ-मध्यम, प्राची दक्षिणापथ पश्चिमदेश पार उदारापथ । एक-एक चक्र के अन्तर्गत  
 अनेक जनपद थे । जन दो के भीतर शासन की छोटी इकाईयाँ गाह्वार जिले और कौटुवियम (यद्वा से  
 नामित प्रदेश) थे । पुरान बसे हुए जनपदों द्वारा प बट व, कौटुवियम प्रायः अठवीं(अगली)प्रदेशों में थे ।

राज्य का अनुशासन राजा सुस्थापित कानूनों (धर्म) के अनुसार ही चलता था । कौटिल्य ने  
 अपने धर्म-शास्त्र के धर्मस्थीय में लिखा है कि

--विवादों (मुद्दमों) के विषय के चार आधार होते हैं--धर्म, व्यवहार, अरिज और राज  
 शासन । इनमें से शिक्षा पहले का आधार होता है । धर्म धर्मानु पुरान स्थापित सदाचार-सम्बन्धी प्राय-

द्वितीय नियम। से व्यवहार अर्थात् पुराने स्थापित दीवानी फौजदारी कानून का महत्व अधिक था। चरित्र इन दोनों को हटा कर इनका स्थान न सनता था। चरित्र का अर्थ किया गया है पुराने के समूह अर्थात् समूहों का वाय उनका बनाया हुआ विधान। अगले युग के अभिलेखा में चरित्र शब्द स्पष्ट रूप से समूहों या निवासों के बनाये विधानों के अर्थ में वर्तित गया है।

चरित्र बनाने वाले राजा के छोटे बड़े समूह या निकट थे—ग्राम, ग्राम, नगम और जनपद। अर्थशास्त्र में अर्थ (२७) यह कहा गया है कि राजा अपने मुख्य दरबार में देश ग्राम जाति और कुलों के सभाओं (समूहों, निवासों) के धर्म व्यवहार और चरित्र सन्धान को निबन्ध पुस्तक में दर्ज करावे। यह निबन्ध पुस्तक राजकीय रजिस्टर था जिसमें सब जनपदों, ग्रामों आदि के बनाये चरित्र दर्ज किये जाते थे।

अर्थशास्त्र में राज्यसंस्था का जो चित्र हम पाते हैं उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्य साम्राज्य भारत के विभिन्न जनपदों और उनके अन्तर्गत ग्रामों और ग्रामों के स्तम्भों पर लगी रचना थी जो उनकी राजा के स्वशासन सहयोग से चलती थी। उन जनपदों में उस स्वाधीन भावना होने से उन्हें कठिनाई से एक विजित में लाया जाता पर एक बार सम्मिलित हो जाने के बाद उनके प्रभुत्व की नीति बर्ती जाती।

## सातवाहन युग का आर्थिक राजनीतिक संस्थाएँ

महाजनपद बाद मौर्य युगों में हम भारतीय समाज का जो आर्थिक राजनीतिक जीवन देखने पाते हैं उस युग में उसी का विशिष्ट रूप पाते हैं।

कृषि की मर्म कृषक की सम्पत्ति थी। मनु न कहता है राजा भूमि का अधिपति है (२३६)। पर उसके अर्थ सम्पत्तियों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वहाँ अधिपति का अर्थ अर्थशास्त्र या शासन ही है।

मानवस्य सम्भूतसंस्थान की विवेचना साम के लिए समवाय में काम करने वाले बाणजों के उत्प्रेषण से आरम्भ करता है पर अन्त में कहता है कि कृषकों और कर्मियों की भी यही विधि है। इसका यह अर्थ हुआ कि सामुदायिक शक्ति और मजदूरों के समूह मौर्य युगों की तरह इस युग में भी थे।

आज हमारे देश में जारीगर प्रायः सब महाजन्यों के नज्द्वार हैं। वे प्रगाढ़ कर्ज लेकर सर्वे भुक्तानों की ही सत्ते रहते हैं। यह देश जिस सभ्य युगल युग से चल रहा है। पश्चिम-यूरोपी व्यापारी अब यहाँ पाये सब हमारे राज्यों में उन विदेशियों की भी भारतीय जारीगरो का इस प्रकार विदीहन करने दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय कुलाहों पर जिन शक्तियों की याद हम आज तक करते हैं वे इसी देश के कारण सम्भव हुए। इस देश के मुकाबले में अब हम देखते हैं कि सातवाहन युग के कुलाहों और लेखियों की अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का साथ-साथ राजाओं के लिए यहाँ का काम भी बरती थीं सब स्वर्ण मरके का कर हुआ दिखाई देता है।

महामारत में मौर्यीय अर्थशास्त्र की तरह अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रों की सेवा का उत्प्रेषण है।

परराष्ट्र-मीडन अर्थात् शत्रु को सताने के उपायो में थ्रेण्णिमुय्योपजाप अर्थात् थ्रेण्णियों के मुखिया का फोड़ना भी बताया है। गंधर्वों से हारने के बाद दुर्योधन कहता है कि मैं थ्रेण्णिमुय्या को कैसे मुह दिवाऊँगा।

थ्रेण्णिया और जनपदों के धर्मों तथा ग्रामों और जनपदों के समयों वा सविदों का पहले की तरह महत्व चला आता था। 'मनु' कहता है— 'धर्मवेत्ता (धर्मस्य) जाति जानपद धर्मों, थ्रेण्णि धर्मों और कुल धर्मों को देख कर अपने धर्म का प्रतिपादन करे (८ ४६)।

व्यवहारदर्शन — 'यवहारो को देखने अर्थात् 'याय के अनुशासन-के लिए 'यागवल्क्य (२ ३०) के अनुसार सबसे नीचे कुला के 'यायालय य फिर थ्रेण्णियों के पूगा (ग्रामो नगरों) के और सब से ऊपर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। पूगा ग्रामों नगर सम्राज्ञा का इसक प्रतिरिक्त एक और बड़ा काम था लेखा का निबन्धापन (रजिस्टरी)। उपवन्ता ग्राम गिरनार के अभिलेख के मत में कहता है— यह सब निगम समा में सुनाया गया और फलस्वरूप म चरित्र के अनुसार निबद्ध किया गया। फलक याने फलमारी, फलस्वरूप=लेखा दफ्तर। या राजकीय दानों की रजिस्टरी भी नगर-सम्राज्ञा के पैला दफ्तर। मे उनके चरित्र अर्थात् सम्राज्ञों में पारित किये नियमों के अनुसार होती थी।

इन राजविप्लवों के बीच अनेक गणराज्य भी फिर उठे थे। अलखमन्दर अफगानिस्तान-पञ्जाब के छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों को दबाता व्यासा तक चला आया था। सेलेव्कस् के उसी प्रकार अनेकों राज विप्लव और बाहरी आक्रमण इस युग में भारत पर हुए फिर भी इन संस्थाओं के आन्तरिक ढाँचा बचाने में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सका।

## मध्य युग

गुप्त साम्राज्य का ह्रास ५१० ई० के लगभग हूणों के मध्यएशिया के हमलों के बाद आरम्भ हो गया। उनके आक्रमणों से भारतीय प्रजा की रक्षा शुभ संभव न कर सके तब यशोधर्मा नामक सम्भवत एक राजस्थानी सरदार ने, जो जनता का नेता था किसी राजवंश का सम्बन्ध नहीं उठकर हूणों को वेग से निकाला। ५४० ई० के लगभग उसके देहान्त के बाद भारतीय इतिहास के प्राचीन युग का अन्त होकर मध्यकाल का आरम्भ होता है।

## जनता के राजनीतिक चैतन्य का ह्रास

मध्यकाल के राजनीतिक इतिहास के दस खाने में बढत हम नी कहानो है। ५५० से ६२० ई० तक ह्रास घोडा है उसके बाद एकाएक अधिक।

इस ह्रास के एक पहलु पर उक्त इतिहास ही प्रकाश डालता है। जिसमें हिन्दुओं के अंध विश्वास और धर्मापत्ता ने विदेशियों के हाथों उन्हें पराजित कर लिया।

एक तरफ धर्म-धर्म में अंध विश्वास का बढना प्रकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चैतन्य का क्षीण होना। सिंध के जाटा ने जो भनोवृत्ति दिखाई वह गामन का अर्थात् बहुत बड़ जान और

द्वितीय नियम से व्यवहार प्रार्थना पुरान स्थापित दीवानी फौजदारी कानून का महत्व अधिक था । चरित्र इन दोनों को हटा कर इनका स्थान ले सकता था । चरित्र का धर्म किया गया है पुराना के सग्रह प्रार्थना समूहों का वाप उनका बनाया हुआ विधान । प्रगले युग क प्रसिद्धि में चरित्र सद स्पष्ट रूप से समूहों या निकायों के बनाये विधानों के धर्म में वर्त्ति गया है ।

चरित्र बनाने वाले प्रजा के छोड़कर समूह या निकाय थे — ग्राम, ग्रामिण, नगम और जनपद । प्रार्थनासूत्र पचास (२७) यह कहा गया है कि राजा अपने मुख्य दरबार में देश ग्राम जाति और कुलों के सभाया (समूहों निकायों) के धर्म व्यवहार और चरित्र-संस्थान को निबंध पुस्तक में दर्ज करावे । यह निबंध पुस्तक राजकीय रजिस्टर था जिसमें सब जनपदों, ग्रामा आदि क बनाय चरित्र दर्ज किये जाते थे ।

प्रार्थनासूत्र में राज्यसंस्था का जो चित्र हम पाते हैं उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्य साम्राज्य भारत के विभिन्न जनपदों और उनके अलग-अलग ग्रामों, ग्रामिणों, नगरों के स्तम्भों पर खड़ी रखता था जो उनकी प्रजा के स्वच्छाप्रदत्त सहयोग से चलती थी । उन जनपदों में उच्च स्वाधीन भावना होने से वही कठिनाई से एक विजित में लाया जाता, पर एक बार सम्मिलित हो जाने के बाद उनके प्रशसन की नीति बर्ती जाती ।

## सातवाहन युग की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएँ

महाजनपद नद और मौर्य युगों में हम भारतीय समाज का जो आर्थिक राजनीतिक जीवन देखते पाते हैं इस युग में उसी का विवक्षित रूप पाते हैं ।

कृषि की भूमि कृषकों की सम्पत्ति थी । मनु में कहा है, राजा भूमि का अधिपति है (८ ३६) । पर उसके धन सम्पदों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वहाँ अधिपति का धन अध्वन या धानक ही है ।

याज्ञवल्क्य सम्भूतसमुत्पन्न की विवेचना लाभ के लिए संधाय से काम करने वाले बाणेशों के उल्लेख से प्रारम्भ करता है पर अन्त में कहता है कि कृषकों और शर्मियों की भी यही विधि है । इसका यह ध्येय हुआ कि सामुदायिक खेती और मजदूरी के सम्बन्ध मौर्य युगों की तरह इन युग में भी थे ।

प्रायः हमारे देश में कारीगर प्रायः सधन महाजनों के वर्जदार हैं । वे अनाक कर्ज लेकर उन्हें धुँवने की ही छतों रहते हैं । यह दशा कस से कम शुंगल युग से चल रही है । पश्चिम-यूरोपी व्यापारों के यहाँ प्रायः सब हमारे राज्यों ने उन्हें विदेशियों की भी भारतीय कारीगरों का इस प्रकार विनोद करने दिया है । ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारतीय जुलाहों पर जिन जुल्मों की याद हम आज तक करते हैं वे इसी दशा के कारण सम्भव हैं । इस दशा के युवावले में जब हम देखते हैं कि सातवाहन युग के जुलाहों और शैलियों की ग्रामिण प्रणाली का धन के साथ-साथ राजाओं के लिए बलों का काम भी करती या तब स्वयं नरक का द्वार हुआ दिखाई देता है ।

महाभारत में कौटिलीय व्यवस्था की तरह ग्रामिण प्रार्थना ग्रामिणों की सेना का उल्लेख है ।

परराष्ट्र-मीडन अर्थात् शत्रु को सताने के उपायों में श्रेष्ठिपुत्रोपजाप अर्थात् श्रेष्ठियों के मुक्तिप्राप्ति को फोड़ना भी बताया है। गन्धर्वों से हारन के बाद दुर्माधन कहता है कि मध्यश्रेष्ठियों को कैसे मुह दिया जा।

श्रेष्ठियों और जनपदों के 'धर्मों' तथा ग्रामों और जनपदों के 'समयों' वा सविदों का पहल की तरह महत्त्व बना धाना था। 'मनु' कहता है— 'धर्मवेत्ता (धर्मस्थ) जाति, जानपद, धर्मों, अर्थात् धर्मों और कुल धर्मों को देख कर अपने धर्म का प्रतिपादन करे (८-४६)।

व्यवहारदर्शन — 'व्यवहारों को देखन' अर्थात् 'याम के अनुशासन'—के लिए 'यामवस्तु' (२-३०) के अनुसार सबसे नीचे कुला के 'यायास्तय' से फिर श्रेष्ठियों के पुत्रा (ग्रामा नगरो) के और सब में ऊपर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। पुत्रा अर्थात् नगर सभाओं का इसके प्रतिरिक्त एक और बड़ा नाम था सेखों का निवन्धापन (रजिस्ट्री)। उपरान्त अपने गिरनार के अमिलेख के अंत में कहता है— "यह सब निगम सभा में सुनाया गया और फलस्वरूप में चरित्र के अनुसार निवृत्त किया गया।" 'फलक' यान धनमारी, फलस्वरूप=सेखा दपतर। या राजकीय दानों की रजिस्ट्री भी नगर-सभाओं के सेखा दपतर में उनके चरित्र अर्थात् सभाओं में पारित किये नियमों के अनुसार होती थी।

इन राजविप्लवों के बाद अनेक गणराज्य भी फिर उठे थे। अलबत्ता दर अफगानिस्तान पंजाब के छोटे छोटे राज्या और गणराज्यों को दबाना अयासा तक बना आया था। सेलजुक्स के उसी प्रकार अनेकों राज विप्लव और बाहरी आक्रमण इस युग में भारत पर हुए फिर भी इन सत्ताओं के आन्तरिक षाय सबहुन में अनेका कोई हस्तगत नहीं हो सका।

## मध्य युग

गुप्त साम्राज्य का ह्रास ५१० ई० में लगभग हुआ। मध्यएशिया के हूणों के बाद आरम्भ हो गया। उनके आक्रमणों से भारतीय प्रजा की रक्षा गुप्त लोग न कर सके तब यशोधर्मा नामक सम्भवत एक राजस्थानी सरदार ने जो जनता का नेता था किसी राजवंश का अचयी नहीं उठकर हुगो का देश से निवृत्ता। ५४० ई० के लगभग उसके देहांत के बाद भारतीय इतिहास के प्राचीन युग का अंत होकर मध्यकाल का आरम्भ होता है।

## जनता के राजनीतिक चैतन्य का ह्रास

मध्यकाल के राजनीतिक इतिहास के इस भाके में बढ़ते ह्रम की कहानी है। ५५० से ६२० ई० तक ह्रास घोटा है, उसके बाद एकाएक अधिक।

इस ह्रास के एक पहलु पर उक्त इतिहास ही प्रकाश डालता है। जिसमें हिन्दुओं के षाय विद्वान और धर्माधरा न विवेचिषा के हाथा उम्हे पराजित कर दिया।

एक तरफ धर्म-धर्म में अंध विश्वास का बढ़ना प्रकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चेतन का क्षीण होना। सिध के जाटा न जो मनोवृत्ति दिसलाई यह धामन का षाय वृत्त बढ़ जाने और

गासको और शासिता के बीच बर्ग विद्वेष उत्पन्न हो जान से ही हो सकती थी। वह दंगा भारत के दूसरे प्रांता में तब तक न थी। तो भा जनता की शासन के प्रति उफाना क्रमशः बढ़ रही थी। उस दशा में जनता के पुराने निवादा—याम थोड़ी निमग्न, जन्मद सघ आदि-का क्या हुआ? मध्यकाल में हम एक भी गणराज्य का पता नहीं पाते। जैसा कि जायसवाच न लिखा था— ३२० ई० सहि दू इतिहास पिघल कर उजल चरित मात्र रह जाते हैं—राष्ट्रीय या सामूहिक जीवन की डोर में न पिरोये हुए अनेक प्रकेले रत्न। हम बड़े धर्मात्मा और बड़े पापी मिलते हैं—पर व साधारण सतह से इतने ऊँचे हैं कि घस हाथ बनकर उनकी प्रसथा या पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जन समूह स्वतंत्रता की साँस लेना छोड़ देता है।

प्राचीनकाल में स्थानीय शासन जनता के निश्चयो के हाथ में था तथा राज्य और साम्राज्य उसी नींव पर खड़े होते थे। मध्यकाल में निवादा की दशा में क्रम-परिवर्तन बसे हुआ इसकी खोज बाकी है। तमिलनाडु में धामा की सभाएं राजराज और राजेंद्र चान के युग तक भी सुसंरक्षित रही। पर जनता का सामूहिक जीवन जब क्षाण होने लगता है और वह प्रयाय सहने की तयार हो जाती है सभी राजा द्वारा नियुक्त स्थानीय शासक जागीरदार उत्पन्न हो उठते हैं। कश्मीर का इस काल का इतिहास पूरा मिलता है और उससे हम जानते हैं कि हमनी शासकी से डामर अर्थात् जागीरदार सिर उठाने लगते हैं और धीरे धीरे राज्य की मक्का गिन उनसे हाथों बँटकर धिन भिन्न हो जाती है। ऐतिहासिक कल्हण उठे तस्कर (चोर) और दस्यु (डाकू) बहकर यात्रा करता है। राजा सम्राट् देव (१२३६-५२) को डामरों के उपद्रवों के कारण दण्ड छोड़ जाना पड़ता है। दूसरी राजतरंगिणी के समय जानराजने उस अवसर का अछुत करत हुए लिखा। (श्लोक १००) —

तस्मिन् दडधे दूर यात डामरैरेव ।

अत्राप्यपि विनामागुर गप रक्षनपायिन ॥

—उस दण्डधर के दूर बसे जान पर खून पान जाने डामर सियार प्रतापा की घातों में पूरी पूरी खा गये। प्राता का सब कुछ सहने की तयार होना इस दुरवस्था की जड़ में था।

नीची गतान्ते के अंत में कश्मीर के राजा गकर बमान शुद्ध के अवसर पर रुडभारान्ति अर्थात् प्रजा के लिए भार डीन की बगार चनाइ। वह भी उसी दंगा की सूचक है। जनता की इस उफाना की दशा में एक और बात जो इस काल में खली वह थी रायों में भाइत में बना का उपपाप। उसे हम कम से कम नीची गतान्ते के प्रारम्भ में अभिलेखा में पाते हैं। वगण तक के राज्यों में तुर्क भात न मनिन धाने थे जिहे यहां के लोग में दूरा हो कहा है। तुर्क न बाद में भारतीय राज्या का आवासी में कप लात लिया इस पर दूसरे प्रमाण बताता है।

१३ वीं शताब्दी में तुर्क विनात विमान प्रजा के ऊपर जागीरदार बन कर बठे गये।

बीच बीच में धनक भवन सम्प्रदाय न भक्ति मार्ग में और विद्वान विचारता न गान्धीय विवेचनाप्रा द्वारा लोगो की जगाकर जनता की इन प्रवृत्तियों में बचान का प्रयत्न किया। तमिल देश में बहुत से वल्लभ और गव भवन हुए जो नमन भालवार और नायमार कहलाते थे।

## पन्द्रहवीं शताब्दी का पुनरुत्थान

तुर्कों की सत्ता भारत से १६ वीं शताब्दी का अन्त होते होते देश से सुप्त हो गई। उसके स्थान पर विभिन्न जनपदों में जो नये प्रादेशिक राज्य उठे व सब प्रायः या तो हिन्दुओं के थे या हिन्दी मुसलमानों के और उन सभी न प्रायः मुसलमान स्थापित करने के लिए अग्न अपने प्रयत्न में वहाँ की पुरानी शासन संस्थाओं को फिर जिलाने का प्रयत्न किया। मेवाड़ में महाराणा हम्पीर सगर्बिह साबा, मोकल और कुम्भा के समय अपने उजड़े इलाका को फिर से बसाने के लिए किसानों को भूमि सबाधी बहुत से सत्त्व जो तुर्क शासन के समय लनसे जिन गये थे वापस दन और स्वायत्त संस्थाओं, पंचायतों आदि को पुनः जीवित करने के जो यत्न किए गए थे व इतने आधुनिक प्रतीत होते थे कि १६२३-२५ में मेवाड़ का माण और बंदाबस्त अधिकारी उन पुराने पट्टे, परवानों को देखकर दंग रह गया था।

कश्मीर में इसी प्रकार इस समय जनुल भावदीन के किये सुधारों के कारण पूरा रामराज्य स्थापित हो गया था।

बाबर के मृत्यु में तुर्कों की जो तीसरी घारा भारत में आई पठान आत तक उससे लड़ने रहे। पठान पुनरुत्थान का करम उत्कृष्ट शरशाह के प्रशासन में प्रकट हुआ। उसके रामराज्य की कहानी सुविदित है। उत्तर भारत की प्रजा ने मिहिरभोज के जमाने के बाद बसा मुसलमान न दिया था। शेरशाह का सबसे महत्व का काम जमींदारों का उखाड़ कर पुराना राज्यसंस्था को फिर खड़ा करने का प्रयत्न था। उसने गाँवों का पंचायतों का फिर जमाया और उन्हें परिगणक या परगना नामक माल गुजारी-बसूली की पुरानी इकाइयों में सघटित किया। सघहवीं शताब्दी में शिवाजी ने नये पुनरुत्थान का प्रारम्भ करते हुए शरशाह की नीति का अनुसरण किया। पर शिवाजी के मराठा ने उनीबसनी सगी में जब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली तब भी पठानों ने अपने को स्वतन्त्र रखा इससे प्रकट है कि पन्द्रहवीं शताब्दी का पठान पुनरुत्थान और गहरा था।

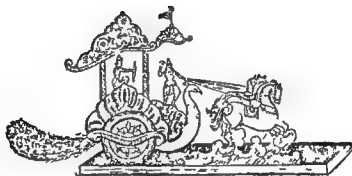
किन्तु जमींदारों द्वारा प्रथा अर्थात् शासित और शासन के बीच एक तीसरे बिचवा या टैकेदार वर्ग की प्रथा को हटाने का शरशाह की नीति को उसके बाद उसके बगल और अकबर भी जारी न रख सके। वह काम १७ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकबर महाराष्ट्र में शिवाजी ने फिर जारी करना चाहा किन्तु मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जीवन भरग के सघर्ष में पड़कर उसके अनुयायी उस पर बाद में दख न रह सके। मुगलों के विरुद्ध अपने प्रजासत्ता की उभाड़न के लिए उ है फिर से लोगों की जमीनरा की प्रलोभन देना पड़ा। इससे शिवाजी के लिए बराए पर पानी फिर गया और १७ वीं सदी में योद्धा की तरह यहाँ भा दू केन्द्र सघिन राज्य संस्था खड़ी न हो सकी। १८ वीं सदी में अकबर यहाँ के मे दोले-दोले राज्य प्र प्रेजों की मुद्रित राष्ट्रीय शक्ति के सामने न टिक सका।

## मिहावलोकन

वदिक में गुप्तकाल तक भारतीय राज्यसंस्था का विकास किये दृष्टा सा हमन देता है। उमने बाग उमके ह्रास की भी भनन पाई है। वदिक काल में भारतीय समाज का मवर्ग जनपुलक या साम्राज्य



मूर्तक था। उनसे मिलता-जुलता सघटन आर्य नृवश की दूसरी गालाघा का भी था। उत्तर वृत्तिक वाङ्मय में धौलि शाल पहले पहल आता है। फिर महाजनपद युग में भारतीय राज्यसंस्था का विविष्ट रूप प्रस्फुटित हो जाता है और उसी रूप का विकास मुक्त युग तक होता चलता है। उसमें मुख्य संभरण हैं १) प्रत्येक जनपद और नगर में जनता का घघा के अनुसार सघटित होना तथा २) प्रत्येक ग्राम, घघे के निकाय अथवा धौलि, नगर और जनपद का स्थानीय स्वशासन और उस पर निर्भर राज्य।



खण्ड-२

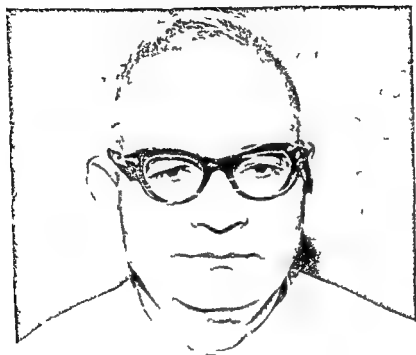
# पंचायती राज का अभिप्राय और दर्शन



१ पंचायती राज का दशन	श्री बलवन्तराय मेहता	१-४
२ पंचायती राज क्या है	श्री एस० एन० मजूमदार	५-८
३ Panchayti Raj—Philosophy & Objectives	Shri S K Dey	१०-११
४ पंचायती राज के स्वरूप की कल्पना	डा० इकबालनारायण	१२-१५
५ Concept of Panchayti Raj—Some Broader Aspects	Shri Jaiprakash Narain	१८-२१
६ पंचायती राज	डा० बृलक्ष्म	२२-२३
७ पंचायती राज और उत्तमा समाज दशन—श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा		२७-३०
८ विवेकीकरण—आर्थिक, राजनतिक एवं जनतांत्रिक समाजवाद— श्री सोमप्रकाश धारा		३३-३५







सोवतात्रिक विवेचोवरण क अग्रदूत  
स्व० श्री प्रल०तराय महता

# पंचायती राज का दर्शन

श्री बलवन्तगय मेहता

पंचायती राज के सम्बन्ध में महारमा गांधी के जो विचार थे उनको प्रकट करते हुए उन्होंने एक बार लिखा था —

भारत में सात लाख गांव हैं। हर गांव में नागरिकों की इच्छानुसार यानी सब के मत से सगठन कार्ययोजना होगी। उसके बाद सात लाख मत होंगे। दूसरे चारों में प्रत्येक गांव का एक मत होगा। गांव के साथ जिला प्रशासन की चुनौती, जिलों के शासन प्रान्तों के शासन की चुनौती और ये ही बाद में ग्राम्यता की चुनौती जो कामपालिका का ग्राम्यता होगा।

इससे पता चलता है कि गांधीजी क्या सोच रहे थे। वे सोचते थे कि गांव के लोग जिला प्रशासन की चुनौती और जिला प्रशासन राज्य सरकार का आधार होगा। उन्होंने भ्रमन किया है—

मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं सविधान सभा की कार्यवाही को नहीं समझ पाया हूँ। ग्राम पंचायतों का जिक्र या निर्देश या विवेकीकरण भावी विधान में नहीं है निश्चित रूप से यह भूल है। यदि हमारी आजादी में जनता की भावना पूरती है तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। पंचायतों की जितनी अधिक शक्ति दी जाएगी, जनता के लिए अपनी अधिक प्रचंडी बात होगी।

उन्होंने भागे कहा—

शक्ति का केन्द्र नहीं दिखता है या कलकत्ता या बम्बई में—यानी बड़ शहरों में। मैं चाहूंगा कि उस सात लाख गांवों में बांट दिया जाए।

फिर इच्छा से सहयोग होगा—नाजो तरीका से नहीं। स्वेच्छित सहयोग से सच्ची आजादी पैदा होगी। एक नई व्यवस्था बनेगी जो सोवियत रूस की व्यवस्था से बहुत प्रचंडी होगी।

गांधीजी ने एक बार लिखा—

'ग्राम स्वराज्य का मेरा रूप है कि वह पूर्ण गलन्य हो—अपनी जल्दता के लिए वह पड़ोसी गांव पर निर्भर न रहे लेकिन जहां निर्भरता आवश्यक हो जाए वहां गांव एक दूसरे पर निर्भर भी रहें। इसलिए गांव का पहला काम होगा कि वह अपना अपना स्वयं पदा करे—कपड़ के लिए रुई पैदा करे। पशुओं के चारागाह हो—बच्चों के खेलने-कूदने के लिए मदान हो। अथवा जमीन बचे तो बिक्री वाली पसल पैदा करें लेकिन गाजा, तम्बाकू व मफीम नहीं। गांव में एक नाटकघर, स्कूल व परिषद हाल हो।

जनघर अपना हो जहाँ मे सज को गुद जल मिल । बसिब कोम के अतिम दर्जे तक शिखा अनिवाय हो । सभी काम सहकारी आधार पर हो । छूपा छून के आधार पर बोई जातिया न हो ।

ग्राम रक्षा के लिए अनिवाय सेवा हो । उहे बारी-बारी से उना जाए । गाव का शासन पाच पचा की पचायत करे जिसे हर साल गाव के बालिग लोग चुनै ।

## आधारभूत विचार

ये आधारभूत विचार हैं जो समय समय पर राष्ट्रपिता ने प्रगट किए थे । हम इन विचारों के साथ ही चलना चाहिए । हम द्यो कि हम जिस पचायती राज की बनाना जा रहे हैं वह किस प्रकार का होगा । पचायती राज का विचार कोई नया विचार नहीं है । गुरु मे ही ग्रामी म गणतन्त्र चल आ रहे हैं देश मे भल हो किसी गण का राज रहा हो । इतिहास हम बताता है कि इस पुराना देश मे सदा पचायतें हमारे जीवन का आधार रहे हैं । इनके अतिरिक्त गांधी ने जो स्वतन्त्रता का आन्दोलन लड़ा था उसका आधार शहर नहीं थे । गाव थे शहरी लोग नहीं बकि गाव के लोग । इतना ही नहीं, गोनमन परिषद मे उल्लेखित पचन स्वराज्य की व्याख्या करते हुए कहा कि वह ग्राम गणतन्त्रा पर आधारित होगा । प्रातीय स्वतन्त्रता के दिना मे और बाद मे भी कुछ प्राता ने पचायतों के लिए कानून पाम किए जो इस मनीनरी का विकास करना चाहते थे । उनके दिमाग मे बुनियादी विचार यही था कि गावा की स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप मे काम करना चाहिए । वह हमारे सविधान बनाने बाल मारे छाये की ग्राम पचायता पर आधारित नहीं कर पाए, फिर भी अले ही बाद मे सोचा हो उन्हाने उस विचार की निर्णिक सिद्धान्तो मे जोड़ दिया । हमारा लोकतन्त्र गावों की इकाईया पर आधारित होगा इस विचार के सविधान का विकास काफी हद तक हुआ है ।

ग्राज कहा जाता है कि पचायतें भविष्य का निमाण करेंगे लेकिन क्या ये पचायतें पचायन समितिया, जिला परिषदें जिन्हें मिला कर हम पचायती राज कहते हैं भविष्य के निर्माता की भाति काम कर सफती हैं ? इसने बजाय देश का भविष्य उनके हाथो मे भौप लिया गया है जिन्हें जनता कम जानती है । यदि हमारे भविष्य के आधार-स्तम्भ गाव, ब्लाक व जिला पचायतें बन पातीं तो उन लोगों के लिए स्वराज्य का कुछ अर्थ हो पाता । उनकी आवश्यकताएँ व महत्वाकांक्षाएँ मारे नाचे में कुछ भ्रम रहती ।

## जनता की योजनाएँ नीचे से बनें

पिछले १२ या १५ साल मे योजनाएँ जिहे नीचे से बन के आना था ऊपर से बनाई गई है । इसलिए जनता ने लिए योजनाया की नीचे से ही बनाना चाहिए । गाव वाले बताए कि व क्या जीवन बिताना चाहते हैं उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं ? उनकी क्या महत्वाकांक्षाएँ हैं ? ग्राम स्तर से ऊपर स्वायत्त शासन की इकाईया के बारे मे भी यही बात है । इस प्रकार यदि नाचे से योजना बनेगी तो अधिकतर लोगो की नाम होगा । लेकिन अब तक नीचे स्वायत्त शासन की इकाईया नहीं बनती हैं तब तक ऐसी योजना नहीं बन सकती है । यदि एक स्वामित्व पचायन है तो वह अपने गाव की आवश्यकता

के बारे में बता सकता है, और यह भी बता सकती है कि वे कब पूरी होंगी। उसने लिए कसा योजना का आवश्यकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत प्रक्रिया में भाग लेता हमारे देश का भविष्य बनायेगी। उस समय में पंचायत सरकार को केवल ग्राम या एजेंट मान नहीं रह सकती है जिसका काम केवल ऊपर के अधिकारियों का हुनम बनना हो। पंचायतें गांधीजी के आदेशों के अनुसार ग्राम-गणतन्त्र बनें। उनका संगठन स्वायत्त शासन का इकाई का हो। इसका एक मुख्य कारण यह है कि यदि गांधी की सत्ता नहीं सीपी जाती है तो जनता यह अनुभव नहीं कर सकती है कि यह उनका लोकतन्त्र है उनका स्वराज्य है।

## जनता का विश्वास आवश्यक

देश की स्वतन्त्रता में जनता का विश्वास होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके अन्तर यह विश्वास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वह लोकतन्त्र या स्वराज्य में भाग नहीं लेता है। हमने उन्हें भागीदार बनाने की नहीं सोची है। अब उस दिना में हमने बड़ना गुरु कर दिया है, लेकिन यदि लोग में यह विश्वास पैदा नहीं होता है कि वे लोकतान्त्रिक ढांचे के अंग हैं—ता हमारे प्रयत्न सफल नहीं होंगे। इस लिए हम उनके अन्दर यह भावना भरनी है। यदि उनके अन्दर यह भावना नहीं होगी तो ग्राम जनसंघ संस्मृति बन सकता है कि लोकतन्त्र या देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। हम इस निर्माण कार्य में इसलिए भी उन्हें भागीदार बनाना चाहिए कि यदि वे भागीदार नहीं बनते हैं तो फिर स्वराज्य का गांधी कांसे के लिए क्या भय रह जाता है। जब तक लोकतन्त्र ऊपर पार्लियामेंट या विधान सभाओं में रहता है और गांधी में नहीं आता है—गांधी के लोग को यह विश्वास नहीं हो सकता कि यह उनका प्रजातन्त्र है या उनके साम के लिए है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक होगा कि हम उनके अन्दर स्वायत्तता की भावना, भागीदार की भावना, हिता की एकलपता की भावना, पैदा करें। इसलिए आवश्यक है कि पंचायती राज के स्वरूप का अर्थ है—ग्राम, स्थान व जिला स्तर पर स्वायत्त शासन को इकाईयां।

लोकतन्त्र की काममें रचना होगी—उसकी रक्षा करनी होगी। स्वतन्त्रता प्राप्त करना और लोकतान्त्रिक ढांचा बना देना ही काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता के अन्दर लोकतन्त्र का वास्तविक ज्ञान पैदा करना, जीवन की लोकतान्त्रिक प्रणाली में विश्वास करना है। हम उन्हें तयार करें ताकि वह लोकतान्त्रिक ढांचे की काममें रखने के लिए समर्थ कर सकें। यह तभी हो सकता है जब उन्हें लोकतान्त्रिक ढांचे का अर्थ बताया जाए। अर्थात् जहाँ हुआ वे अपनी काम में करने रहेंगे और लोकतान्त्रिक मर्यादों को कोई संशय पैदा हो जाए। पहलू जमान में कुछ भी हुआ उ होन परवाह नहीं का। बादशाहों ने हमें हो गई बाहर के लोगों में श्रद्धा कर लिया या भीतर का कोई बादशाह बन बठा लोग सामोरी से सब देखते रहें। अब इस भावना की श्रद्धा नष्ट करना है और आत्मिकता की भावना पैदा करनी है। इन उद्देश्य के लिए भी ग्राम की स्वायत्त शासन की इकाई बनानी पड़ती। जिला व लोक स्तर पर भी स्वायत्त शासन की इकाई होगी।

कुछ लोग अजीब ढंग से बात करते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक परीक्षण है जो कामयाब भी हो सकता है व असफल भी हो सकता है। यह परीक्षण नहीं है। जनता स्वामी है। वह प्रभुसत्तासम्पन्न है जिससे हम सत्ता हासिल करते हैं। जो गांधी नहीं कर सकता उस गांधी करेंगे और जो 'लोक' नहीं कर सकते उसे मिलें करेंगे और जो जिसे नहीं कर सकते उसे राज्य करेंगे और जो राज्य नहीं कर सकते उसे द्रव्य करेगा। जो भाज का तरीका है वह इससे उल्टा है तो भाज के तरीके को पसंदना पड़ेगा। इनका



प्राचीन भारत में गांव पंचायत मुख्य रूप से 'याय पालिका' का नाम करती थी। इस गांव के बड़े-बूढ़े और बुद्धिमान लोग होते थे। विनोबा जो ने पंचायत का चित्रण इन 'गांदा' में किया है—पंच बोले परमेश्वर। सम्भवतया प्राचीन काल में भी पंचायत का यही रूप था। परम्परा से ही भारत में जब नया व्यक्ति या हिता में सफल होता तो पंच फसल को मायता दी जाता रहा पंच नियम दन की और इस तरह 'याय करान की क्षमता परम्परा में ही समाई हुई है। पंचायत के लिए एक मुविधा यह भी थी कि वह गांव के सब आदमियां और मामला से भली भांति परिचित हानी थी।

## प्राचीन पंचायत से बुनियादी तौर से भिन्न

आज की पंचायत प्राचीन पंचायत से बुनियादी तौर से भिन्न है। प्राचीन भारत की स्थानीय मत्स्याएँ जान-बूझ कर विकेंद्रित आधार पर नहीं बनाई गई थीं। न ही जनम सत्ता निहित थी। किन्तु आज की समन्वित 'गासन प्रणाली' में पंचायत एक तत्त्व है। राष्ट्रीय सत्ता के सधीय ढांचे में यह भी एक प्रशासनिक इकाई है। अब यह जरूरी नहीं कि पंचायत में गांव के बड़े-बूढ़े और बुद्धिमान शामिल हों। यह ठीक है कि 'याय पंचायतें पंचायतों राज का ही एक अंग हैं, किन्तु उनका कामकाज सीमित है। अपने वर्तमान रूप में पंचायत 'गासन की एक पूर्ण इकाई है जिसके हाथ में अपने इलाके में रहने वाले लोगों के कल्याण सम्बंधी सभी काम आते हैं। पुरानी ग्रामिणों को बड़ा बड़ा और जिला बड़ा से इसके काम कहीं ज्यादा हैं। इनका उद्देश्य तो जनता के ऐसे समान हित वाले बग तयार करना है जो उत्साही हों प्रगतिशील हों उत्पादक हों सामाजिक हों और समुदाय के पूर्ण विकास के लिए काम करें।

## सत्ता का मोह

क्या हम इसमें सफलता मिलेगी? आम तौर पर तो जब एक सिद्धान्त से सभी लोग सहमत हो तब सफलता मिल जाती है यह कहा जा सकता है कि हम सब भी ससद से लेकर पंचायत तक लोकतन्त्रीय पद्धति अपनाने का हामी हैं। परन्तु कुछ लोग दिलों में कुछ बातें रखे हुए हैं। यद्यपि सभी राज्यों में आवश्यक कानून पास किए जा चुके हैं किन्तु उन्हें लागू करने में सभी राज्य एक-सा उत्साह नहीं दिखा रहे। सत्ता के विकेंद्रीकरण में एक रूपता दिखाई नहीं देती। सभी का हमारी जनता की समझदारी में, उसकी योग्यता में, जिम्मेदारी उठाने की उसकी भावना में एक सा विश्वास नहीं है। सत्ता से एक मोह पैदा हो जाता है और उससे छुटकारा पाना संभव ही एक कठिन काम होता है। तीन या चार राज्यों के प्रतिरिक्त अन्य राज्यों में अधिक ऊँचे पदों पर बैठे सत्तापारी व्यक्ति पंचायती राज के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। यह सब स्वाभाविक ही है परन्तु यदि लोगों को सत्ता सोपनी ही है तो इसका मोह छोड़ना ही पड़ेगा।

यह तथ्य सभी प्राप्त किया जा सकता है कि जब प्रशासन की बुनियादी इकाई छोटी हो। तब यदि सत्ता का सदुपयोग किया जाए तो वांछित परिणाम स्पष्ट हो सकते हैं। सभी समुदाय अपने प्रयासों का मोठा फल चख सकेंगे। सभी सामूहिक जागरूकता पैदा होगी। एक छोटे से इलाके में रहने वाले लोगों में जो स्वाभाविक प्रतिष्ठा पैदा हो जाती है उसने फलस्वरूप यह और अधिक वास्तविक बन जाएगा।

## ग्राम समस्याएँ सजीव सस्याएँ बनें

किन्तु इसे साधक तभी बनाया जा सकता है जब समुदाय अपने कामों की योजना भी बनाए। तभी आयोजन और कार्य-व्ययन में धनिय सख्य स्थापित हो सकेगा। केवल उसी दशा में लोग आयोजन और कार्य-व्ययन का काम थोड़ा स निवाचित लोग के हाथों में सौंप कर निश्चित नहीं हो जाए नें बल्कि स्वयं भी काम करेंगे। पचायती राज की सफलता के लिए आवश्यक है कि ये सस्याएँ सजीव सस्याएँ बनें और इनकी सुदृढ नींव समूचे समुदाय पर आधारित हो। अभी तक गावा में लागू का इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया गया कि अपने कल्याण कायकमा की योजना के स्वयं बनाए, और इसीलिए इन परियोजनाओं के प्रति उन्हें कोई सभाव नहीं होता।

जिते में विकास खण्ड प्रशासन की नई इकाइया हैं। पचायता से मिन कर विकास खण्ड बनता है। व ऐसे समान हित के काम करते हैं जिनके लिए समुक्ति प्रयास की आवश्यकता होती है। परन्तु यह बात सत्य प्रच्छी तरह नहीं समझी जाती कि खण्ड में पचायतों वाले समुदायों को बिरोपता होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि हमने सामुदायिक विकास की भावना का नहीं समझा है और लोकतन्त्र के लिए जन-सहयोग के महत्व को भी पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी मनोवृत्ति के कारण विकास खण्ड कई जगह जिला प्रशासन के एजेंट बन कर रह गए हैं।

जब तक यह स्थिति बना रहती तक तक गाव वालों को अपना ग्राम सभा की पचायत के कामों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई लाभ नहीं होगा। गांधीजी के विचार में प्रशासन एक ही के है स खींचे गए वत्तों की भांति या न कि पिरामिड की भांति। इसी तरह समुदाय के विकास के लिए बनाई गई योजनाएँ भी एक ही केन्द्र से खींचे गए वत्तों की भांति होनी चाहिए जो पचायत योजना से गुरु होकर बराबर चलती हुई राष्ट्रीय योजना तक पहुँचे।

एक कारण बहुत "यापक रूप में पक्षी हुई है कि सत्ता चलाने में गाव वाला का सहयोग जल्दबाजी में लिया जा रहा है। यह विचार उन दिनों के प्रचलित विचार से भिन्न होता है। जब यह कहा जाता था कि हम माय्य होने से पहले ही आजादी मिल गई है। कुछ लोग तो गाववालों के लिए फसले करना अपना पत्रक कलम्य समझ बैठते हैं। बाकी लोगों की राय यह है कि अनपढ़ गाववाले आयोजन कर ही नहीं सकते। परन्तु लोकतन्त्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि तमने सलाह की जाय, उससे परामर्श किया जाए, शासन में उसका भी हिस्सा हो। इन भूलभूत अधिकारों के अंतर्गत उसे अपना अस्तित्व प्रकट करना ही चाहिए। किसी व्यक्ति के अनपढ़ होने का यह मतलब नहीं कि वह बुद्धिमान भी नहीं। हर ग्रामीण यह समझना है कि उसका और समुदाय के लिए अला बुझा क्या है। उन्हें अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए उनके दिमाग पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। कई देशों के अनुभव प्राप्त एक अधिकारी व्यक्ति का भारत के बारे में कहना है कि गाववालों की सभा बुद्धि का अण्डार हाथी है। इसके अन्निहित मूल्य के लिए और लाभ कर जनता में साम-सहामता की भावना पैदा करने के लिए इसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

## गुटबन्दी से निराश न हों

प्रायोगिकों का कहना है कि पचायती राज का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि गुटबन्दी में अग्रद बढ गए हैं। परन्तु मानवीय सम्बन्धों में गुटबन्दी को दूर नहीं किया जा सकता। जल्द तो इस बात

की है कि सामाजिक हितों के गुट या ग्रुप बनाए जाए जैसे युवका के, महिलाओं के संगीत व नाच के संरक्षकों के आदि आदि। समाज में सामाजिक विभिन्नता से तो बचा नहीं जा सकता। वांछित भिन्नता धीमे धीमे और कठिनाई से आती है। इस बीच यदि गुटबंदी बढ़ जाए तो हम उससे निराश नहीं होना चाहिये। जब लोग देखेंगे कि गुटबंदी के शासन से सब लोगो का भला नहीं होता, तो वे उन देर तक सहन नहीं करेंगे।

इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि लोगों को अधिवाधिक अधिकार सौंपे जाए और इस बात को। अनुचित रूप से चिंता न की जाए इसके परिणाम क्या निकलेंगे। पंचायती राज ने यही किया है। हम तो केवल इसका आधार और अधि-व्यापन बनाना चाहते हैं ताकि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित न रहे। हर सुविन्न व्यक्ति का यही कथन है कि हमारे लोग वृद्ध बुद्धिमान हैं। यही बात जरूरी होती है। गलती किससे नहीं होती? किन्तु लोकतन्त्र की छोटी-सी इकाई में (जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है) इन गलतियों के परिणामों को नजर धुंधला नहीं किया जा सकता है। इस तरह सत्ता के केन्द्रित होने से स्वामाजिक रूप से बचा जा सकेगा।

## पर्याप्त धन की व्यवस्था आवश्यक

किन्तु केवल सत्ता और उत्तरदायित्व से ही काम नहीं चलता। प्रारम्भिक सोपानों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि ऐसे सामंजस्य कार्यक्रम का संच पूरा हो सक जितना लाभ सारी जनता अनुभव करेगी। कुछ समय बाद स्वतंत्रता साधन विकसित हो जाएंगे। यह माना करना कि शुरू में ही लोग भारी बोझ उठाने को तैयार हो जाएंगे मानव प्रवृत्ति के भी विरुद्ध है और उनकी वर्तमान आर्थिक दशा के भी। इसलिए यह जरूरी है कि गावा का आर्थिक विकास भी राज नीतिक विकास के साथ साथ हो बल्कि उसमें भी तेजी में हो।

यदि सामुदायिक विकास का उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति करना है, तब पंचायती राज लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। परन्तु लोगों को समाज शिक्षा देना पंचायती राज से प्रत्यक्ष सम्बद्ध किया जाना चाहिये। दुर्भाग्यवश समाज शिक्षा की अपेक्षा की जा रही है। यह एक पीछे से आने वाला कदम है। शिक्षा और प्रशिक्षण किसी भी क्षेत्र में मूलभूत वस्तु होती है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि क्या सामुदायिक विकास प्रान्दोवन अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा तो इसका कारण धन की कमी कभी नहीं होगी बल्कि यह होगा प्रशिक्षण की कमी।

क्या पंचायती राज की स्थापना से समुदाय के विकास का काम सिद्ध गया है? कई प्रश्नों का यही कहना है। इस बात से खतर की वृद्धि आती है। प्रशासन और उसके संचालन मिलाए हो तेज धरावा की तरह होना है। जिसे में सांस्कृतिक स्वास्थ्य विभाग निर्माण विभाग शिक्षा विभाग आदि के लिए भारी सहायता में कमचारियों को व्यवस्था करना एक बड़ा अच्छा काम लगता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिये सामुदायिक विवास पर, और कुल प्रगति के साधन के रूप में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पंचायती राज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि यह प्रवृत्ति रोकੀ जाय। यदि समुदाय का विकास नहीं होता और उसे प्रगति के रास्ते पर नहीं बनाया जाता है तो पंचायती राज डगमगाने लगता है।

## कार्यकर्त्ताओं की भूमिका

सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की भूमिका बड़ी कठिन है। इसमें उन्हें पोसाहित व निरुत्साहित कर के लोगों का भागदखल करना होता है। उनका रोबदाब से नहीं, बल्कि मित्र व गुरु की तरह भागदखल करना होता है। प्रशासन में सभी व्यक्ति योग्य भागदखल नहीं होते। इसलिए पुरानी भूमिका को भटपट छोड़ कर बिलकुल नई भूमिका अदा करने के लिए जिस मानसिक सन्तुलन की आवश्यकता होती है उस प्राप्त करना आसान नहीं। सफलता प्राप्ति के माग में सब से बड़ी बाधाओं में से यह एक है। यह तो स्पष्ट है कि अयोग्य व्यक्तियों को हटा देना चाहिये। फिर इस क्षेत्र में अब तक उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण भी नहीं हुआ। विभागीय प्रतिद्वन्द्विता को भी हटाना होगा। हम समूचे समुदाय का एक साथ विकास करना है, उसके जीवन के किसी एक साम पहलू का नहीं। इस सम्बन्ध में केंद्रीय व राज्य सरकारों की भूमिका भी दोनों का ही अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये।

पंचायती राज का अब प्रतिष्ठापित हो गया है। कुछ सुविधा परिवर्तनों का बचन है कि यह समय में पूरा भी नहीं आया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सरकार में केंद्रीकरण की जा प्रवृत्ति देखी जा रही थी, उसे रोकना आवश्यक था। इसमें अतिरिक्त, एक प्रश्न यह भी है कि पंचायती राज के अन्तर्गत व्यापक आधार पर सौंपे जाने वाली सत्ता और जिम्मेदारियाँ के बिना सच्चा नृत्व कस सामने आएगा और बराबर आता रहेगा ? सामयिक आलोचना की निगाह इस ओर गई हो नहीं।



# PANCHAYATI RAJ

—S K Dey

## PHILOSOPHY AND OBJECTIVES

Panchayati Raj is a culmination of the recognition given by our Constitution to the role of Panchayats. One of its Directive Principles enjoins that the "State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self governments". The devolution of powers is an implementation of a Directive

Panchayati Raj aims at making democracy real by bringing the millions into the functioning of democracy. It is a system of grassroots democracy which seeks to link the individual family in the remotest village with the Central Government.

The basic unit of self government is the family. The family has been guaranteed certain fundamental rights which cannot be interfered with by the State. But there are certain spheres of activity which can only be executed by several families collectively. These activities will obviously have to be left to an organisation called the village panchayat. It is essential to build up the Panchayat as a dynamic organisation which can look after all the facets of life of the village community. It has to draw its strength and sanction from the village people as a whole simultaneously working in close co-operation with self governing bodies at higher levels in an organic set up.

The Panchayat must constitute a strong base for a three tier structure of self governing institutions located at block and district levels. Responsibilities and activities which fall beyond its scope will be surrendered by the panchayat to the next higher body which is called the panchayat Samiti. While the Samiti will look after these activities it will also try to use the panchayat as its agent for some of its numerous tasks.

The Panchayat Samiti will be linked to the next higher body at the district level known as Zila Parishad. The latter will guide the former in technical and administrative matters and engage in activities which only a district organisation

can discharge effectively. This process of assuming responsibilities with the requisite authority within its own sphere and surrendering those which involve interunit co-operation are the main features of the Panchayat Raj system. In other words, as one steps down them these three tiers the coordination and policy making functions decrease correspondingly to the executive responsibilities which increase till at the village level, the panchayat becomes mostly an executive body.

It will be seen that by this pattern Panchayat Raj will bring about a complete link up of the millions in this country from the Gram Sabha to the Lok Sabha. It seeks to bring to the individual family the highest guidance available from the Parliament downwards. People will be free to handle matters within specified spheres without interference from others. This freedom to think, plan and work will draw out the latent initiative and ability in every individual for the growth and welfare of the family and the community. Panchayat Raj is thus a way of life and involves a new approach to Government.

The Balwant Rai Mehta Committee had recommended democratic decentralisation by the association of peoples representatives through the three tier system. The new Panchayat Raj legislation has been enacted in Andhra, Rajasthan, Madras, Assam, Mysore and Punjab. Andhra and Rajasthan were the first to implement their legislation and they have completed one year of operation under this system. Assam, Madras, Mysore and Punjab have also started setting up such institutions. In Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh legislation is shortly expected to be introduced while Gujarat and Maharashtra have set up high level committees to recommend the type of institutions which will suit local conditions.

The growing concept of Panchayat Raj will bring in its wake a number of problems, the most important of which will be rural industrialisation. The needs of the millions of families, artisans, traders and small industrialists will have to be complied with. As a result a rapidly growing cooperative sector is envisaged, specially in agriculture, small industries, trade and spheres of social services. This sector helps build up Sahakari Samaj in the economic field as a complementary counterpart of the three tier democratic system of Panchayat Raj.

# पंचायती राज के स्वरूप की कल्पना

—डा० इकबाल नारायण  
रीडर, राजनीति शास्त्र विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय

पंचायती राज का दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। इसके आदर्शों की कल्पना के आधार पर और व्यवहार से जो वास्तविकताएँ सामन आई हैं उनसे आधार पर। आदर्श और यथाय के अध्ययन का एक परिणाम यह हो सकता है कि पंचायवादी, पंचायत राज के स्वरूप में परिवर्तन के लिए दबाव डालें। फिर पंचायती राज से जिन आदर्शों की पूर्ति की भाँगा की गई है उनमें फेर बदल करने की बात करें। जिस स्थिति की कल्पना यहाँ की गई है वह अभी सुदूर भविष्य का गम है।

आदर्श में पंचायती राज की कल्पना भी अभी स्वरूप से रही है। इस स्वरूप को उभारने में ग्राम्य और यथाय—दोनों प्रकार की विचारधाराओं को महत्वपूर्ण भूमिका देना पड़ेगी है। इन दोनों विचारधाराओं का लाभ इनके एकांगी रहने में नहीं है बल्कि उनसे आपसी सहयोग और सामंजस्य की भावना पर है। इससे पंचायती राज के स्वरूप में निखार आने के साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वालों की भी बार बार यह चेतावनी मिलती रहेगी कि आदर्श से वे कितने पाछे हैं। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय आवश्यक है।

## आदर्शवादी और यथार्थ विचार

आदर्शवादी विचारधाराओं में भी बहुत भिन्नता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दृष्टिकोण उल्लेखनीय हैं।

एक विचारधारा सर्वोप्य मान्गिा की है जिसे अधिक स्पष्ट भाषा में श्री जयप्रकाश नारायण का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। इस विचारधारा का उन्ग्य गांधीवादी विचार से हुआ है और विनोबा इसके पक्षपाती हैं। श्री जयप्रकाश नारायण ने इस दृष्टिकोण को क्रम बढ़ता प्रदान की है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं पहले बात यह है कि यह विचारधारा ससदीय लोकतन्त्र की समर्थक नहीं है। श्री जयप्रकाश नारायण ने अनुसार ससदीय लोकतन्त्र भारत की परिस्थितियाँ कि अनुकूल नहीं है इससे अलावा इस विचारधारा के तहत भारतीय नीति से पुनरुद्धार की बात कही जाती है।

तीसरी बात यह है कि वर्तमान संसदीय लोकतन्त्र का स्थान पर इस विचारधारा के समकक्ष सामुदायिक लोकतन्त्र की बात करते हैं और उसे संसदीय लोकतन्त्र से धोखे मानते हैं। पंचायत को वे इसका आधार मानते हैं और केवल इसी के प्रत्यक्ष निर्वाचन में विश्वास करते हैं। इसके अलावा पंचायत का व ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। सामुदायिक लोकतन्त्र जिसकी वे कल्पना करते हैं निम्नलिखित होना चाहिए और उसमें सब सम्मति का तत्त्व मुख्य रूप से रहना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण की यह कल्पना अनेक सवास बड़े कर देती है जो पंचायती राज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं।

पंचायती राज और उच्च स्तरीय चुनाव में और राजकीय तथा राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के बीच तानमेल की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पंचायती राज योजना में ग्राम सभा का क्या स्थान होना चाहिए? क्या पंचायत को पंचायती राज के ढांचे की मूल भूत इकाई मानकर चला जा सकता है? क्या पंचायती राज का गठन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है? इन प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार आवश्यक है।

## पंचायत शासनारम्भक कल्पना

एक विचारधारा स्वायत्त शासन व्यवस्था की है जो पंचायती राज की कल्पना प्राथमिक स्वायत्त शासन के रूप में करती है। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का मत यह है कि ग्राम स्तर पर सभी प्रकार की प्राशासनिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्रामवासियों को होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ग्रामवासियों में स्वयं किसी भी काम में पहल करने की शक्ति होनी चाहिए। प्रशासन में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने की 'यूनितम उच्चस्तरीय सरकारी हस्तक्षेप' के अंतर्गत छूट होनी चाहिए। इस विचारधारा के कुछ समर्थकों का यह भी कहना है कि पंचायतों का राजस्व प्राप्ति में सीधे देना चाहिए और धीरे धीरे कानून और व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी उन पर डाला जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण सादिक अला कमेटी के अधिकारों पर सरकारी सदस्या न व्यक्त किया है।

## नौकरशाही और पंचायत राज

इनके विपरीत एक विचारधारा नौकरशाही की भी है। इस दृष्टिकोण से अधिकारी बत अव्यक्त प्रभावित हैं और पंचायती राज सम्बन्धी नियमों उपनियमों में यह विचारधारा यथेष्ट प्रभावित होती रहती है। इस विचारधारा के पीछे अतिरिक्त ग्रामवासियों के प्रति अधिकारों की यह भावना काम करती है, कि वे अपने आप अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए इस दृष्टिकोण में पंचायती राज संस्थाओं की प्राशासनिक व्यवस्था संपन्न पर बहुत कम जोर दिया गया है। इन विचारधारा के समर्थकों में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो यह कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को केवल सरकार की एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए। दूसरे वे जो पंचायती राज संस्थाओं का सतवत्ता पूर्वक कुछ अधिकार प्रदान करने के समर्थक हैं।



## निकासवादी भिद्धान्त

एक विनासवादी सिद्धांत है। इस सम्बन्ध में बलवत्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट में कुछ विचार द्योतित किए गए हैं। इनका मानना यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता में आत्म विश्वास उत्पन्न करने और उत्साह तथा स्वच्छा में जनता को ग्राम विकास के कार्यों में नियोजित करने में असमर्थ रहा है। इस काम को, सम्भवतः सामुदायिक प्रशिक्षण और खासतौर से ग्राम विकास की योजनाएं जनता की जुनी हुई संस्थाओं को सौंप कर पूरा किया जा सकता है। यह एक दृष्टिकोण है जिसके तहत बलवत्तराय मेहता समिति की रिपोर्ट में पचायत राज की कल्पना ग्राम विकास के सक्षम में की गई है। इस दृष्टिकोण का यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता कि उद्देश्य और कार्यक्रम दोनों ही दृष्टियों से पचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार मात्र है। और पचायती राज संस्थाओं को विकास की मशीन के पुर्जों के रूप में काम करना है, उसको प्राप्त होने वाली शक्ति के रूप में नहीं। पचायती राज की परिकल्पना के सम्बन्ध में सक्षम में विभिन्न आदर्शवादी दृष्टिकोण यही हैं।

## यथार्थवादी दृष्टिकोण

अब हम पचायती राज के स्वरूप पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण से पचायती राज के स्वरूप पर विचार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम शक्ति जानकारी और आकड़ों का अभाव है। क्योंकि पचायती राज के विकसित होने हुए स्वरूप पर बहुत कम अनुसंधान कार्य हुआ है। दूसरी समस्या पचायती राज संस्थाओं की अल्पकालिक अवस्था का है। तात्कालिक बात यह है कि पचायत राज संस्थाओं के संस्था जनक स्वरूप में बहुत भिन्नता है।

कुछ मिला कर पचायती राज की काम पद्धति के अनुसार विकसित स्वरूप के बारे में कल्पना करना भी संतर्लभ होगा। इन सीमाओं के बावजूद पचायती राज संस्थाओं के स्वरूप की कल्पना उनकी काम प्रणाली में आधार पर की जा सकती है।

## तीन प्रकार के स्वरूप

पचायती राज के तीन प्रकार के स्वरूप विकसित हुए हैं—राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी। राजनीतिक स्वरूप वह है जो ग्रामतौर पर हमारे जिम्मेदार नेताओं के भाषणों वक्तव्यों और लेखों में माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता है। उनकी कल्पना यह है कि ग्रामीण प्रशासन की दक्षिणा स्वयं ग्रामवासियों द्वारा हो। इस कल्पना का पचायती राज निश्चित रूप से ग्रामीण स्वायत्त शासन का स्वरूप लेगा। पचायती राज का सामाजिक स्वरूप यह है कि ग्राम जनता उससे यह आशा करती है कि इस व्यवस्था से उनकी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। खास तौर से वह प्रशासन और राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए दिशा से भी अधिक उत्सुक है। इसलिए पचायती राज का सामुदायिक विभाग योजना से भी जो सम्बन्ध है इस बात की उन्हें बहुत कम जानकारी है। जब पचायती राज को केवल विकास की मशीन बनाया जाना है तो इससे ग्रामीण जनता अधिक प्रोत्साहित नहीं होगी। पचायती राज का कानूनी स्वरूप सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण से बनता है। इसमें

सीन विनियोजित हैं। यह पंचायती राज संस्थाओं के विकास के काम करने के पक्ष पर ही अधिक जोर देता है। यह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती एजेंसी के रूप में मान्यता देता है और उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उनका दुरुपयोग न हो, इसलिए सतर्कता बरतने की बात करता है। इस दृष्टिकोण में पंचायती राज संस्थाओं की सत्ता की अपेक्षा उनके सेवा कार्य पर अधिक जोर दिया गया है। उनके कर्तव्यों पर अधिकारों की अपेक्षा अधिक बल है। उन्हें अधिक उत्तरदायित्व सौंपने के स्थान पर सीपे गए उत्तरदायित्वों के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहने की दिशा में विशेष जोर दिया गया है।

इस प्रकार एक गम्भीर समस्या यह है कि पंचायती राज भी कार्य प्रणाली से उभरते हुए उनके इन व्यापक स्वरूपों की विभिन्न कल्पनाओं के बीच उत्पन्न खाई को कस पाया जाय। इसके लिए कुछ श्रम तथ्यों पर विचार आवश्यक है।

## पंचायती राज की भूमिका

पंचायती राज संस्थाएँ वास्तव में जब तक लगभग सरकारी एजेंसी की भूमिका ही निभा रही हैं इसलिए ग्रामीण स्तर पर वे विचार प्रक्रिया का केन्द्र नहीं बानपाई हैं और ग्रामीणों में पहल करने की शक्ति जाग्रत नहीं कर सकी हैं। केन्द्रीयमूल राष्ट्रीय नियोजन की प्रणाली में काफी हद तक ऐसा होना अनिवाद्य भी है। यदि विकेंद्रित लोकतन्त्र का कोई अर्थ है और यदि पंचायती राज को भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भाँति असफल नहीं हो जाना है तो नियोजन की शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं को अनवरत स्वाकृत करने और योजना निर्धारित करने की दिशा में कुछ स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता का महसूस करना होगा।

पंचायती राज संस्थाओं का सत्तात्मक स्वरूप उनका विरासतमय स्वरूप से अधिक विवक्षित हुआ है। इस बात की मायता दनी होगी कि विकेंद्रित लोकतन्त्र के रूप में पंचायत राज संस्थाओं को सत्तात्मक स्वरूप देना होगा।

पंचायत राज से ग्रामाण गृहबन्दी ज्यादा बड़ी है और सब सम्मत चुनावों की प्रवृत्ति कम है। सत्ता के आधार पर चलने वाली गृहबन्दी के कारण पंचायतें भी अनेक मुठों में बँट गईं। इसका नतीजा यह हुआ है कि पंचायतों को मिलने वाला सामान भी पक्षपात का तत्व आगया है। इससे योजना के लक्ष्य की पूर्ति में भी प्रभाव पड़ा है। यह प्रवृत्ति लोकतन्त्र के भी प्रतिकूल है। इससे गाँव की सामाजिक एकता दर भी प्रभाव पड़ता है।

## पंचायती राज और नियोजन प्रक्रिया

यह नहीं कहा जा सकता कि पंचायती राज संस्थाएँ वास्तव में नीचे के स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और इससे उनके स्वरूप की कल्पना करने में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। क्या हमारे केन्द्रीयमूल नियोजन की प्रणाली में निचले स्तर पर नियोजन की व्यवस्था के साथ तालमेल बैठ सकता है तथा भारत जस विकासशील देश में निचले स्तर पर नियोजन की क्या सोचाएँ होनी चाहिए? किस स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को योजना के क्रमान्वयन में नियोजित किया जाय? उनके नियोजन का कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिया जाय?

एक प्रश्न यह भी है कि क्या पचायत राज संस्थाओं को केवल योजना में सहयोग देने का भूमिका ही प्रदान करनी है या उन्हें खोखले भी वास्तविक इकाई बनाना है और इस दिशा में शिमा को क्या भूमिका अदा करनी है।

एक समस्या सरकारी और घर-घर मरवारों व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध की भी है। इससे पचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह सही है कि यह केवल सनातनतात्मक तालमेल की समस्या है जो कुछ समय बाद उपलब्ध हो जायगा। फिर भी यह विचार करना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय कि दोनों पक्षा ने जो सन्तुल्य स्थापित करने की दिशा में क्या प्रयास किए जाय ? प्रत्येक इकाई की क्षमता की दृष्टि से भी पचायती राज का अध्ययन करना उचित होगा। 'राज स्थान के सद्म में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं।

## ग्राम सभा विकसित नहीं

ग्राम सभा अभी तक स्वरूप नहीं ले सकी है। इससे जनक महत्वपूर्ण प्रश्न पड़ा होता है। क्या पचायत की मजबूत बनाने से ग्राम सभा मजबूत होगी या मजबूत ग्राम सभा बनाकर सुदृढ़ पचायत की स्थापना की जा सकती है ? क्या ग्राम सभाएं बहुत दुर्बल हैं क्योंकि इन्हें वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं। एक प्रश्न यह है कि पचायत राज के वर्तमान विचारमार्मक ढांचे में ग्राम सभा का स्तर और भूमिका क्या है ? गाँव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्राम सभा के स्वरूप और वास्तविक आन्तरिक स्वरूप की सहज ही कल्पना की जा सकती है। पचायती राज की विमुखी प्रणाली में ग्राम सभा का क्या स्थान हो और ग्राम ब्लाक तथा जिले में से कौनसी इकाई को अपना मजबूत बनाया जाय ?

## पचायतें और केन्द्रीय नियोजन

एक समस्या यह है कि पचायत राज और राज्यस्तरीय या केन्द्रीय स्तरीय संघीय लोकतन्त्र में समन्वय कैसे स्थापित किया जाय। यह समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया जाय या अपने आप प्राकृतिक रूप से तालमेल बैठन दिया जाय। क्या राजनीति दलों को पचायत चुनावों से अलग रखा जाय ? विधायकों की पचायत राज के सम्बन्ध में क्या भूमिका हो।

इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पचायत राज से एक सत्या जनक गति धीरे-धीरे उत्पन्न हुई है जिसके कारण पचायती राज संस्थाओं को स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप देने के लिए नीचे से ऊपर की ओर दबाव पड़ रहा है। पचायती राज के विकसित होने का स्वरूप की कल्पना करने समय इस तथ्य को भी नजरअन्दा नहीं किया जा सकता।

## स्वरूप उद्देश्य नहीं साधन

ऐसी स्थिति में पचायत राज संस्थाओं को क्या स्वरूप दिया जाय यह एक समस्या है। क्या देश भर में एका ही स्वरूप लागू कर दिया जाय या विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रयोग चलने दिए जाय जिससे जो प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हों उसे बाद में प्रयोग कर लिया जाय। इस दृष्टि से पचायत

राज के लिए बनाए गए नियमों, उपनियमों और पचायत राज के उद्देश्यों के बीच तालमेल होना चाहिए । पचायती राज का स्वरूप निर्धारित करना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है । खतरा यह है कि पचायत राज का स्वरूप क्या हो इसी बात को मूल लक्ष्य न समझ लिया जाय । इस दिशा में सतर्कता जरूरी है । पचायत राज के उद्देश्यों पर अनग्न विचार न करके, पचायत राज संस्था का स्वरूप निर्धारित करते समय उद्देश्यों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए ।



# CONCEPT OF PANCHAYATI RAJ

## SOME BROADER ASPECTS

*By Shri Jayaprakash Narayan*

I should like to deal with broader aspects of the concept of Panchayati Raj. We have looked at from the limited point of view whether they are units of self governments or agencies of state Governments. We say both, but primarily self government. I think it would be taking a very limited view or if we understood Panchayati Raj only in that sense. I have spoken about this problem and written about it. In my booklet 'Swarajya for the People' I have dealt with it briefly. There has been further development in my thinking since then. Some day I hope I will be able to write them. However there are three ideas to put before you in connection with the concept of Panchayati Raj. It is really one single idea but with different parts which when put together, make it a whole. I think that the concept that has been accepted is the concept of Panchayati Raj as a new kind of society and social order. We can find indication of this society in Gandhi ji's writings and western authors who have written on community. By and large there are two concepts of social organisation today. One is the concept prevalent in the western societies. Western societies are what has been called Mass Societies though there is no society which is hundred percent mass society. If you take European part of the world you also have rural and urban communities, professional communities, communities of artists, doctors etc. There are local communities also in which we use the word. Even in the U S A, which is an example of mass society per excellence. There are communities as a result of pressures of 'pace' problems of detail, like parking etc. People are going out to work 25 to 50 to 100 miles away. I think this is in response to cultural needs of the people of big cities that have grown, which derives them in search of countryside which has smaller habitations. They are thus, deliberately establishing more of shared life. There is thus no society which is 100 percent mass society. There are populations extensive or less extensive, which can be described as mass societies because of their predominantly mass character.

## THE MASS V/S THE COMMUNITY

In Communist ideology the word community has a comprehensive meaning. It is a society made of communities that is village soviets, soviets in factories, etc. To what extent it would be possible to develop communist societies and the societies based on communities together is very difficult to say. The path followed by the communist societies both economically and politically, shows that there will be more of organic principle in them than that in the mass society. Let us take the example a heap of sand near a sea shore. You have inorganic mass separate from each other. It is 100 percent mass society. In human society it is not possible to have such a society since there is family. Because human society will not exist without the basic unit—the family. The problems of children have to be taken up by parents as their problems. If you have a perfect mass society it will be like a heap of sand. On the other hand, the community is like a body made of living selves. They are all inter-related. However, there is no mass society in which there is no inter-relation that is matter of degree.

## THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF A COMMUNITY

What are the characteristics of a community? The first thing a community should have is a sense of identification with it by the members. In the village, there is self-identification but in a city there is no identification of the same degree. The village has an identity.

Community should have also wholeness about it and a body of people living their life together, working performing marriages, playing together, living together dining together. When we say that community has a sense wholeness we mean that most activities of human life are carried on together. In a highly industrialised society it may not be possible that the whole working population finds employment in that community alone. The concept of wholeness, therefore, does not apply for example on the community of artists, doctors, etc. It is a partial community because there the sense of belonging or participation exists only for a particular activity. In a community you have this sense spread over all the important activities of life.

The third characteristic community is a sense of mutuality and belonging. There is a sense of belonging to each other. In the mass society, it almost disappears. In a community that sense is highly developed and covers a very wide field of human life. This

sense of mutuality results in sharing in cooperation, sharing joys and sorrows of life, cooperating with each other. This leads to development of a sense of responsibility in members of the community. You don't feel in Delhi that degree of sense of responsibility as you feel in a village. Here the concern is felt only in an impersonal way. This is not an individual commitment but it is a social and mass commitment. The whole society feels an obligation towards the invalid, the handicapped, children persons of old age, etc. Community is an organic society in which one is inter-related with another in the manner I have stated.

## COMMUNITY-THE BASIS OF PANCHAYATI RAJ

If the underlying concept of social organisation which I have mentioned is not there, Panchayati Raj will be merely an instrument for the people to take in some political decision at their level and no more. They can think only in terms of powers and responsibilities given to them. They will not be bodies having wider vision. I personally think that it has not been accepted or discussed at Udaipur. We should go beyond the partial concept of Panchayati Raj because this concept cannot fully discharge its obligations if it was not associated with a society which is modelled in this fashion. If this is the underlying social content behind Panchayati Raj, the question would be how do we extend the concept of the community to whole of the society—society made up of communities as I have described. It will have to be geographical also. There has to be an optimum or a minimum population; there is no sense in thinking that community will remain as villages are to-day. Just as we conceive three tiers of political self-government bodies, we should also conceive community—of communities at block level. A block may have a population of 65 thousand out of 40 thousand may be voters, therefore, political responsibility is discharged individually. The communitarian concept is that a block area is made of 30 villages each with a population of 2 to 4 thousands. These 30 villages are 30 communities from a larger community. Panchayat Samiti is a community of these communities and member represents communities. At the block level if the communitarian concept is maintained, Panchayat Samiti represents 30 primary communities. It is a secondary community and likewise upwards. It will be utopian to think that there will be a 100 percent a communitarian society. It can be possible, of course, through the institution of Panchayati Raj to convert local communities into secondary communities etc. It will also be possible to create new Urban communities which will be communitarian to a very large extent. May be even in a large community you do not have engineers, teachers, etc. and they come

from somewhere else outside Switzerland is a good example of communitarian society to a very large extent. Israel is another example where you have cooperative villages. I do not know if you have read about communities at work in France. It is very interesting development though it does not seem to be making much progress. It is being swamped by the mass society. In the book called "All Things Common" a French lady has explained the functioning of the community. Take a 'shoe makers cooperative society' or weavers cooperative society. They are not communities but for economic purposes, some persons have come together while the rest of life is lived independently. In the communities at work, they have taken the several steps beyond the persons life. It is not only a cooperative society, for production sale or distribution but also for living the rest of life on a community basis. Decision for each individual member is taken jointly. This principle could be applicable to a few urban communities as well.

Communitarian society in a technical age will be an agro industrial society. It has got to be so if it has to follow a pattern of life as a whole and mutually inter dependent development carrying out agriculture and industries on a regional basis—the region being larger or smaller depending on many factors like raw material, power, etc.







## पंचायतो-राज

—डा० कुलचन्द

यह बहुत स्पष्ट है कि भारत में अद्विध काल से पंचायतों का अस्तित्व रहा है। विन्तु प्राज से पहले किसी भी स्थानीय शासन का अंग नहीं रही। प्राचीन काल में पंचायतें अदालती मामलों निपटायी करती थीं आपसों और आन्तरिक विवादों के मामले सुनभाती थीं और राज्य की ओर से कर वसूली का काम करती थीं। पंचायत एक ग्रामीण सगठन के रूप में गांव के सामाजिक जीवन का केंद्र बन गई थी और यह लगभग राजकीय प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर काम करती थी। सरकार उस समय तब कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी जब तक उसे भू राजस्व ठीक ढंग से मिलता रहे। इसलिए सरकारस मन्त्रालयों के पंचायतों का ऐसे लघु संस्थानों की सहायता है जिन्हें वे सभा वस्तुएं उपलब्ध थी जो वे अपने भीतर चाहते थे और उस स्थिति में भी उनका अस्तित्व बना हुआ था जहां किसी व्यवस्था का अस्तित्व बना रहना कठिन होता है।

### प्राचीन और अर्वाचीन स्वरूप

यह समझना भूल होगी कि प्राचीन काल में पंचायत गांव के स्थानीय शासन का अंग थी। वर्तमान लोकतांत्रिक शासन में स्वायत्त शासन संस्थाओं का स्वरूप इतना नया है कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास में राजकीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकतांत्रिक स्वायत्तशासन संस्थाओं की खोज करना भ्रम भरी विचार होगी। हमारे गांवों का जीवन ऐसी राजकीय शक्ति द्वारा संचालित था जो उसमें कम-से-कम हस्तक्षेप के सिद्धांत में विद्वान् करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्रीय शासन के अन्तर्गत पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

देहाणों से धावादी का गहरो की ओर निष्क्रमण, मजार, साधनों का विकास, व्यक्तिवाद की भावना की प्रबलता आदि कुछ ऐसे कारण थे जो इस समस्या (पंचायत) के पतन में सहायक हुए। १६ वीं शताब्दी के अंत तक जब भेटवाके आलखम एनफिसटम और मुनरो ने उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी भारत के जीवन के बारे में अपना ग्रन्थ लिखा, प्राचीन ग्राम परिषदें व्यवहार रूप में अस्तित्व में होती थीं।

## स्थानीय समितियों का निर्माण

बाद में अंग्रेजों के शासन काल में देहाणी क्षत्रियों में स्थानीय समस्याओं का नए नामन के अंग के रूप में निम्नांकित किया गया। ये समस्याएँ वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप पैदा हुई थीं। क्योंकि केंद्रीय सरकार का कार्य भार बहुत बढ़ गया था। सन् १८७१ में एक स्थानीय विधि-अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के तहत स्थानीय समितियों को प्रशासनिक कार्य सौंपे गए जिनमें सड़कों, प्रस्पतालों स्कूलों बाजारों आदि की देखरेख तथा सफाई और रोग निरोध के प्रयत्न शामिल थे। बाद में सन् १८८२ में स्थानीय समस्याओं का एक जाल बिछाने का सुझाव दिया। ऐसी समस्याएँ जो ग्रहणी और देहाणी दोनों क्षेत्रों में काम करें और जनता की स्वशासन का अनुभव प्रदान कर सकें।

## संविधान की व्यवस्था

इन स्थानीय समस्याओं ने हमारे देश की जनता की स्थानीय स्वशासन के बारे में जिस हद तक अतिशय किया यह एक दूसरा विषय है, किन्तु यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की धारा ४० के तहत अपने देश में जो पंचायती राज लागू किया है वह पूरा एक नई पद्धति है। यह पद्धति हमारे देश की प्राचीन पंचायतों और ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित समितियों की पद्धति-दोनों से मिलती है। इन बातों को हम जितना अधिक समझेंगे उतना ही यह हमारे पंचायती राज की समस्याओं के सही ढंग से समाधान के लिए उपयुक्त होगा। संविधान की ४० वीं धारा में ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए काम उठाएँ और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वयंसेवक शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बना सकें। संविधान में पंचायतों को पुनर्जीवित या पुनर्गठित करने की व्यवस्था नहीं है, जसा कि आमतौर पर किया जा सकता था, यदि संविधान समाप्त हो गया। पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करने की हवा नहीं है। संविधान समाप्त की गया ब्रिटिश पद्धति पर पंचायतों के विनाश की भी नहीं थी।

## संपन्नता का आधार

ग्राम पंचायतों को संगठित करके उन्हें आवश्यक सत्ता और अधिकार देना हमारे संविधान निर्माताओं ने आवश्यक समझा, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि सर्वोच्च लोकतंत्र के आधार पर सभी सरकारें इस तरह की समस्याओं के निर्माण को टालना नहीं जा सकती। ऐसी लोकतांत्रिक सरकार, जो केंद्रीयस्तर पर भी लोकतांत्रिक हो उस समय तक सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक उसे लोकतांत्रिक आधार पर गठित स्वायत्त शासन संस्थाओं का समर्थन प्राप्त न हो।

यद्यपि सविधान निर्माताओं ने ग्रामीण स्वायत्त शासन के लिए गांव को आधारभूत इकाई माना है, देहाती स्वायत्त शासन की सबसे छोटी इकाई के आधार का निर्धारण आदि सम्बन्धी प्रश्न उद्घोषित राज्य सरकार पर छोड़ दिए।

## विभिन्न प्रदेशों के अधिनियम

क्षेत्रीय क़रीब देश के सभी राज्या में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम १९४७ में यह व्यवस्था है कि गांव के सभी जातिगत निवासी मिल कर गांव सभा बनायेंगे और एक कार्यमिति का चुनाव करेंगे जो ग्राम पंचायत कहलायेगी। उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम १९४८ और आन्ध्र प्रदेश देहाती पंचायत अधिनियम सन् १९४८ में भी यही व्यवस्था है। बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम १९३३ (सन् १९४६ में संशोधित) मद्रास ग्राम पंचायत अधिनियम १९५०, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम १९५२ और मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम १९४६ में ग्राम सभा का उल्लेख नहीं है। इन अधिनियमों में जातिगत मतान्तर द्वारा पंचों के निर्वाचन की व्यवस्था है। निर्धारित सख्या में निर्वाचित पंच मिलकर पंचायत का गठन करते हैं। विभिन्न प्रदेशों द्वारा बनाए गए कानूनों में निम्नलिखित मूलभूत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं—

१ पंचायत संस्थाओं की स्थापना हम से प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। गांवों में सिद्धांततः निर्धारित न्यूनतम आबादी पर पंचायतें बनी हैं। निकटतम छोटे छोटे गांवों को जहाँ आबादी निर्धारित न्यूनतम संख्या से भी कम है आपस में मिलाकर पंचायत बना दी गई है। यदि किसी गांव की आबादी बहुत बड़ी हो तो उसके लिए अनेक राज्या में दो या दो से अधिक पंचायतें बनाने का प्रावधान किया गया है। खास तौर से बिहार में इस सिद्धान्त के पीछे यही मूल धारणा है कि पंचायत का गठन हजार या दो हजार की आबादी पर होना चाहिए।

२ पंचायत का गठन पूरा तो लोकतांत्रिक आधार पर होना चाहिए। किसी किसी राज्य में सरपंच का चुनाव पंचायत द्वारा के सभी जातिगत व्यक्ति करते हैं और किसी किसी राज्य में पंच स्वयं अपने में से सरपंच का चुनाव करते हैं। पंचों का चुनाव गांव की विभिन्न बांछों में विभक्त करके किया जाता है। महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व भी सरकार ने वाछनीय माना है। पंचायत में किसी भी सदस्य का मनोनयन सरकार द्वारा नहीं होता।

३ पंचायतों के कार्य दो भागों में विभाजित होने चाहिए। ग्रामिणों और ऐच्छिक। ग्रामिणों नामों में सफाई और रोग-निरोधक कार्य शामिल किए जाने चाहिए और ऐच्छिक-भागों में ग्राम विकास कार्य शामिल किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ ग्रामीणों की राहें पक्की करना, कृषि विकास सहकारी खेती, वाहनानुगो और पुस्तकालयों की व्यवस्था, खेल-कूद तथा ग्रामोद्योगों की व्यवस्था लघु उद्योगों का विकास ग्रामिण तथा ग्राम विकास जो पंचायत आवश्यक धन और प्रासादिक कुशलता उपलब्ध होने पर हाथ में लेना चाहे।

जनपद सभा या जिला बोर्ड का पंचायतों को अपने क्षेत्रीय सत्ता के रूप में प्रयोग करने का अधिकार रहना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

## अदालती अधिकार

सभी राज्यों में पाय करन के लिए सभी पचायतों को कुछ अदालती अधिकार भी दिए गए हैं। अनुभव से इस कदम के पीछे निहित विवशता से भरा हुआ है। पाय पचायतों हमारे प्राचीन इतिहास की परम्पराओं का अनुकूल है। व्यवहारिक दृष्टि से भी पचायतों को एक सोचित क्षेत्र में अदालती अधिकार पदान करना लाभप्रद सिद्ध हुआ है। सभी राज्यों को पाय पचायत में परवी करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसमें गांववासियों पर मुश्किलें बाजी के खर्च का जो भार पड़ता था उससे बच गए हैं। इसके अलावा छोट छोट मामलों के लिए जिनके की अदालत में जाने से की परवाही होती थी उससे भी उन्हें राहत मिल गई है। इसके अलावा स्थानीय व्यक्तियों को ग्राम स्तर से मुश्किलों के तथ्यों से परिचित होते हैं और ठीक वक्तव्य के मामले में समाप्त हो गए हैं।

## कुछ नई बातें

इस तरह की ग्राम पचायतों सम्बन्धित कानून में लाभ बतें नवीन हैं—(१) पचा और सरपंचों के चुनाव की पद्धति कुछ बेचीदा है। हमारे देश की देहाती जनता चुनाव लड़ने के लिए सारी की प्रचारिकताओं से पूर्णतः अनभिज्ञ है। हमारे सम्पूर्ण इतिहास में चुनाव केवल बड़ी सत्ताओं के गठन के लिए ही उपयुक्त माना गया है। चुनाव गांव में छोटी-छोटी पचायतों के विभाजन के लिए अत्यधिक अनुपयुक्त समझा गया है। (२) दूसरी नई बात यह है कि पचायतों की प्रशासनिक काम भी सौंपे गए हैं। अभी तक इन प्रशासनिक और नागरिक कार्यों के सफल संचालन के लिए बहुत कम उदाहरण देखने का मिले हैं।

## प्राचीन धारणाएँ और चुनाव

समस्त विश्व भर के देहाती म—विशु सास स्तर से हमारे देश के देहाती म उन लोगों का सम्मान होता है जो चरित्रवान हैं। लोगों की सलाह मशविरा देकर उनकी मदद करते हैं और गाँवों में मय में काम में मदद देते हैं। जब पचायत का ऐसे काम का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है तो जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा होता है। लेकिन ऐसे लोग सदैव चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते। क्योंकि चुनाव से ग्राम स्तर पर जातिवाद और गृहबाजों का बढ़ावा मिलता है। जैसा कि भारत में हुआ भी है। इसलिए पचायतों में चुनाव की लोकतांत्रिक पद्धति अपनाते का परिणाम यह हुआ है कि अनेक बहिष्कारिता उत्पन्न होने के साथ ही समन्वय और उच्च चरित्र की धारणाओं का आघात लगा है जो "वाल मटवाके" के अनुसार हमारे लघु गणतन्त्र में युगों से विद्यमान थी।

## नेताओं का दायित्व

हमारे नेताओं को चाहिए कि वे इन प्रश्नों पर विचार करते और स्थिति की परिवर्तना करने पचायतों की चुनाव पद्धति में सुधार करते। हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः सिद्धान्तवादी रहा और हमने अपने इतिहास का समुचित अध्ययन करके निश्चित परिणामों की कल्पना करने का अवसर छोड़ दिया। हमने अपनी वास्तविक स्थिति और सुपरिचित तथ्यों का ध्यान में नहीं रखा। यह समझ से परे

की बात है कि पंचायतों को इस हद तक अनिवार्य और ऐच्छिक प्रशासनिक व नागरिक काम क्या सौंप गए हैं, जबकि उनके पास उन्हें सुचारु रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उनकी क्षमता भी नगण्य है।

सोमिट घनश्याम का अधिवाश भाग सचिवों आदि की नियुक्ति पर खय करता पड़ता है। पंचायत कानून के तहत इतनी अधिक बैठकें घुलानी पड़ती हैं कि बैठक में निपटाने के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि पंचायत की बैठक में पंच की रुचि बहुत कम रह जाती है और केवल ऐसे एक दो व्यक्ति जो सत्ता का दुरुपयोग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, पंचायत की बैठक में आते रहते हैं। इसलिए पंचायतों का वातावरण सरकारी प्रभुत्व में पूर्ण और कृत्रिम हो गया है। इसका परिणाम ग्रामों के विपरीत हुआ है।

## द्विमुखी पद्धति

इसके प्रतिरिक्त त्रिमुखी पंचायत प्रशासन के स्थान पर यदि द्वि-मुखी पद्धति अपनाई जाती तो अधिक बेहतर होता। कुछ गांवों को मिलाकर पंचायत बनायी जाती और उसके ऊपर जिला परिषद होती। पंचायत का निर्माण कुछ गांवों को मिलाकर १० या २० हजार की आबादी पर किया जाना चाहिए था। ऐसी पंचायत के साधन भी अधिक होने और जातिवाद और गूट बाजी भा चुनाव के समय अधिक नहीं पनप पाती। वर्तमान विकास खण्ड का क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत बड़ा होता है कि उसमें किसी प्रकार की एक सूत्रता को कल्पना कीजिये तथा ग्रामिक और तकनीकी विकास को इकाई मानकर उस किया जाय इस दृष्टि से वह बहुत छोटा है। इस दृष्टि से जिला उपयुक्त इकाई है। इसलिए जिला स्तर पर निर्मित परिषद को प्रशासनिक व भय विकास के कार्य सुविधा पूर्वक सौंपे जा सकते हैं और उसके सक्रिय संचालन की शक्ति भी जा सकती है, जो खण्ड स्तर पर सम्भव नहीं है।



# पचायती राज और उसका समाज दर्शन

—श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा

भारत में पचायती राज का स्थापना भारतीय लोकतन्त्र की प्रौढ़ता का लक्षण है। आज तक पचायती राज पर दो दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। एक के अनुसार उसमें पचायतें शासन की प्रामाणिक शक्ति हैं और दूसरे के अनुसार वे स्वशासन की स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं। पचायती राज पर १९६४ में उदयपुर में हुई एक गाँवों में त्रिसप्त केन्द्रीय और सभा सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे यह दूसरा विचार मान लिया गया है। हमारे सविधान में भी पचायती को स्वशासन का इनाइया माना गया है। सविधान के ४० वें परिच्छेद में कहा गया है कि "राज्य ग्राम पचायती का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासन की इकाइयाँ के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।" अतः पचायती राज केवल शासकीय एक प्रणाली मात्र नहीं है बल्कि एक नवीन समाज व्यवस्था या जसा गांधीजी ने कहा था—मज्जा प्रज्ञान का कार्य करने का एक वैधानिक और रचनात्मक आन्दोलन भी है। यह प्राचीन भारत में प्रचलित पचायत राज व्यवस्था से भी पृथक् बीज है जिस मनु की भाषा में गुरुत्व व्यवस्था और ग्राम-व्यवस्था कहा जाता था। किन्तु वे गुरुत्व या ग्राम भी सामान्य प्रशासन की एक सुविधाजनक प्रणाली मात्र थे। आज की भाँति उनका पीछे समाज व्यवस्था का कोई विशिष्ट रूप देने, जो आज उस बात के मुकाबिले हमारे लिए अत्यन्त अनिष्ट हो गया है, या समाज रचना की कोई वैधानिक दृष्टि नहीं थी। वर्तमान पचायतीराज की इसी कारण वास्तविक अर्थों में लोकतान्त्रिक विदेशीकरण भी कहा गया है। यह एकदम नवीन विचारधारा है जिन पर गांधीजी का स्पष्ट प्रभाव है और जो नितांत नवीन समाज शास्त्रीय प्रयोग भी है। अतः हम पचायती राज का मूल में निहित सामाजिक दर्शन की खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

'मनुष्य सामाजिक प्राणी है' यह कथन वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यपूर्ण नहीं है। जीवन के 'जीवन सघन' में योग्यता का हाँ मिलान करने वाले सिद्धान्त की तरह इस सिद्धान्त में भी बड़ी गहवरी मचाई है और यह मादक ही मानना चाहिये कि परस्पर विरोध होने हुए भी पश्चिम में ये दोनों परिधि एक में मिल गई हैं। समाज वास्तव में समुदायों से विनिर बनता है और समुदाय दो व्यक्तियों के पारस्परिक चेतन सम्बन्धों का फल है। किन्तु ये सम्यक् अवलोकित या अवलोकित नहीं होते वे मध्यवर्ति

होत है। और हम वास्तव में व्यवहार में सदा ही समाज से अपने समुदाय का ही धर्म लेते हैं। समुदाय में बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता और समाज से मनुष्य का सम्बन्ध समुदाय के सदस्य और उनके ही मारफत होता है। समाज प्रत्यक्ष और अस्पष्ट होता है किन्तु समुदाय प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट होता है समाज मनुष्य की एकता नहीं होता समुदाय होता है। क्योंकि समाज में पारस्परिकता और प्रतिमयता नहीं होती किन्तु समुदाय का तो वह स्वभाव ही है। समाज में स्वार्थों की एक रूपता तथा अभिन्नता का भावना या जिसे समाजशास्त्र में हम भावना कहा गया है, नहीं होती पर समुदाय में होती है। समाज में समग्रता नहीं होती और जब होती है तब उसको प्रतीति नहीं हो सकती किन्तु समुदाय तो समग्रता और उसकी प्रतीति पर ही टिकता है। मनुष्य में तो चेतने की भाँति एकाकी रहने वाला जगती जानवर है और न चीटी की तरह झुंड प्राणी ही है। वह अकेले में भी डरता है और उसे दूसरे से भी डर लगता है। समुदाय में उसकी ये दोनों स्थितियाँ समायोजित होती हैं किन्तु समाज में ऐसा सम्भव नहीं। समाज धनानिका ने मनुष्य में जिस नस्ल की चाह का जिक्र किया है वह समुदाय और उसकी इकाइयाँ में ही पदा होती है। समुदाय ही मनुष्य की सामाजिकता का परिच्छाया है। समाज को एक पिंड समूह कहा गया है किन्तु समुदाय तो सम्बन्धों की एक निश्चित और सायक व्यवस्था है। समाज में व्यक्ति छोटा जाता है किन्तु समुदाय में तो वह पनपता है। आज की नागरिक सम्प्रदाय में भी बड़े बड़े नगरों में जिय गये मध्यमकों से पना चलना है कि कलकत्ता, बूयाक आदि जैसे नगरों में भी मनुष्य में छोट छोट समुदायों पर ही। यद्यपि वे परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण ध्रुव और पृथ्वी किन्तु फिर भी एक मात्र सहारा है। जीवन को खड़ा किया है। वास्तव में कोई भी समाज पिंड समाज नहीं हो सकता अतः कहना चाहिये कि मनुष्य सामुदायिक प्राणी है। समुदाय मनुष्य का स्वभाव है और समाज प्राप्ति है। पश्चिम में मनुष्य को समाजवादी बनाने का जो आन्दोलन चला वह असल में सामुदायिक 'यक्तियों' के हास होने के बाद ही चला जिसका कारण तब कथित औद्योगिक क्रान्ति थी। सामुदायिक 'यक्ति' को भारतीय भाषा में पुरुष कहा गया है। जब पुरुष पुरुष बन रहे हैं तब व्यक्ति बन जाता है तब व्यक्तिवादी पनपता है। 'यक्ति' पर उसके आश्रय हावी रहने हैं किन्तु पुरुष अपने स्व से चालित होता है। वेदा में इसी कारण पुरुष को पुरुष में साना जाना वह घर परिभाषित किया गया है। 'यक्तिवादी' मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है और पुरुषवाद उसकी साम्प्रदायिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है। यही पुरुषवाद सामुदायिकता है। क्योंकि 'यक्ति' का अस्तित्व तभी कायम रह सकता है जब वह दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व भी स्वीकार करता है। यही कारण है कि मनुष्य केवल उत्ती काय में रुचि लेता है जो उसके तथा उसके हम या हमारा के हित में हो। उसकी पकड़ में ही और उसके लिए स्वयं हो। ऐसा समुदाय ही जाना है। यह कोई मयोग मात्र ही नहीं है कि पूजोवादी प्रजातन्त्र और समाजवादी समाजवाद दोनों में ही व्यक्ति स्वतन्त्र की आधार माना गया है किन्तु दोनों ही जगह वास्तविक व्यक्ति गायब हो गया है और रह गया केवल तथानुचित समाज की प्रतिस्पर्धा तानाशाही और गुलामी का पर्याय बन गया है। समाजशास्त्र में पुनः जिस हृष्ट छिम्पोजियन डेब्रेथमेट नाम दिया है वही सामुदायिक विकास है। इसकी प्रकृति न जानने के कारण ही ज्यो ज्यो समाजवादी नारा बढ़ता गया है त्यो त्या 'यक्तिवादी' प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती गई हैं और सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई है। किन्तु असल में लघु सामुदायवादी समाज ही मनुष्य के लिए स्वाभाविक समाज-व्यवस्था है। यहाँ भारत में श्री जयप्रकाश नारायण जैसे समाज धनानिका ने इन समुदायवादी समाजों को युरोप में प्रथम पादचार्य देना में इसे हाऊजर जैसे विद्वान ने 'जुबानी नमाश' और श्वेत् रङ्गीट जने मानवशास्त्रों ने लोकसमाज नाम दिया है।

साक्षीओ इसे नवींदय समाज या 'समाज' कहा करने थे। यही तब कि ठेठ चौकी सदी में प्रख्यात अरब विद्वान इब्न खल्दून ने कहा था कि स्वाभाविक और सही समाज व्यवस्था तो 'तसन्नियत' पर निर्मित होती है जिसका अर्थ था भाईचारा या बंधुभावना। नाम चाह जो भी दें किन्तु तात्त्विक बात यह है कि सामाजिक समूहों का निर्माण मानव की सोमाप्रा के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है और तब समूह सञ्चाल्य हो हो पाते हैं। यही मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता है। समाजज्ञाने और पूज्योपासी लोग ही व्यवस्थापन में अभी तक इस तथ्य को उभेगा जो गई है और नतीजा यह है कि कुछ मनान और अशांति पैदा करने में लोग ही समान रूप में जिम्मेदार रहे हैं।

किर समाज में सत्ता का प्रश्न है। मनुष्य जिसमें अब रहता है उस पर अन्तः सत्ता भी चाहता है। सत्ता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी रहती है। वही यशस्वी का यही आधार या समाज में सत्ता के लिए जिम्मेदारी के अभाव में अक्षय होता है किन्तु सञ्चाल्य में मनुष्य की जिम्मेदारी ही उससे अधिकारी का अधिकार होती है। हमारा काम यह देखना है कि इन रूप में व्यवधान पैदा न होने पावे। सत्ता जब तक दूर रहती है तब तक वह केवल अक्षय ही रहती है जिम्मेदारी नही बन पाती यह उम्मा स्वभाव है। जिम्मेदारी स्वतः स्मृत होती है उसे सत्ता के लिए सामानुपासन आवश्यक माना गया है उसे ही समुदाय के लिए भी होता है। याने अनुपासन ता अन्तरिक हो होना चाहिये आन्तरिक लोकाह्ला में। सामानुपासन जिम्मेदार बनाता है ता बाहरी अनुपासन (बाहरी या अन्तः) उद्भवा और तनाव पैदा करता है। युगपी का कारण होता है। जिम्मेदारी में आन्तरिकता है किन्तु बाहरी अनुपासन तो व्यक्ति के अविश्वास पर ही टिका होता है। समाज का काम व्यक्ति की जिम्मेदार बनाना है अनुपासित नहीं। यह तब ही हो सकता है जब समाज व्यक्ति की पकड़ में हो और व्यक्ति समाज के निष्ठा। ऐसा पुन समुदाय में ही हो सकता है व्यक्ति प्रीष्टा और सुरक्षा चाहता है और वह भी समुदाय में हो सकता है जो कि व्यक्ति के लिए परिवर्तित होता है। प्रीष्टा के लिए और सुरक्षा के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है व्यक्ति का सामाजिकरण (समुदायीकरण) कहना अधिक ठीक होगा। समुदाय में ही होता है यह बात अब सामाजिक मनोविज्ञान विद्वेषणात्मक मनोविज्ञान दोनों में आय हो गई है। हमारा काम मनुष्य की बदलता नहीं है (वह हम स्वयं मनुष्य होने के जाने कर नहीं सकन) हमारा काम उस अवसर देना है और अवसर भी समुदाय में ही मिल सकता है।

इस सम्म में यह सवाल भी उठा होता है कि समाज व राज्य क्या पर्यायवाची है? अर्थवादियों ने राज (राज्य ?) — अर्थ बनाई और उनका राज्य राजा का पर्यायवाची बन गया। इसी परम्परा के कारण अर्थ में अर्थ विद्वानों ने जो मनुष्यों का कहना पड़ा कि राजा ही काल का कारण होता है। (राजों का काल कारण महाभारत) समाजवादियों ने राज्य सत्ता बनाई किन्तु समाज के नाम पर। उनके अर्थों में सत्ता के सामाजिक कारण का अर्थ राज्य द्वारा उस पर कब्जा कर लेना ही होता है (यद्यपि अब वे इस धारणा में सुधार कर रहे हैं किन्तु कम्युनिस्टों का तो अब भी सही विद्वान है)। उन्होंने समाज और राज्य का एक मान लिया। किन्तु वे एक नहीं हैं और न मात्र न ही उन्हें एक माना है। अस्तित्व में राज्य तो एक समुदाय है और वह दूसरे समुदायों का स्थान नहीं ले सकता। आज पश्चिमा देशों में राज्य ने जब से परिवार आदि समुदायों का काम अपने हाथ में लेना प्रारम्भ किया है (क्योंकि कम्युनिस्टों द्वारा राज्य का ऐसा करना ही पड़ता है) तब से



वहा राज्य ही पपा है और बाकी व समुदाय नष्ट प्राय हो गये है और अब यह बात छिरी नहीं है कि व लोग इस अवस्था में परलान है। असल में राज्य का काम अन्न कामा में से एक काम है। यह स्वभाविक विवासक्रम है और हमारा काम इसमें व्यवधान पदा करना नहीं करना उन प्रगति देना है। मानस न भी यहाँ कल्पना की थी किन्तु अन्तर्विरोधों को खोजने की उसकी पिपासा न स्वयं उसे ऐसी अन्तर्विरोधों में फसा दिया कि राज्य के भुर्भान के बजाय समाज ही राज्य में विभोजन हो गया है। गांधी न न केवल मानस के उद्धार का मार्ग खोल दिया है वरन् विवास क्रम को भी गति प्रदान की है। संसार में समस्त राजनसि और सामाजिक चित्तों का यह अर्थ है कि एक ऐसा समाज-व्यवस्था कायम होगा जब राज्य काव का अर्थ ही नहीं रहेगा। इस अर्थ की तरफ बढ़ने की दिशा में ही गांधी जी न धोरो की इस उक्ति को ही अपना राजनसि अर्थ बनाया कि 'सर्वोन्नत राज्य 'यूनतम शासन' करता है। धोरो का यह कथन महत्वपूर्ण है किन्तु धोरो इसके अनर्थ समाज का निर्माण नहीं कर सके थे गांधी कर सके हैं। अपनी इस अर्थ समाज व्यवस्था की ही गांधी रामराज्य या सर्वोन्नत कहा करते थे। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम को उन्होंने इसी के आधार पर खड़ा किया था।

अपनी कल्पना के उस अर्थ समाज का चित्र उपस्थित करने हुए गांधी जी न कहा था यह उस जाति विहान और वर्ग विहीन समाज का चित्र है जिसमें न कोई ऊँचा है न कोई नीचा है। सार काम एक ही है और सारे कामों का मजदूरी भा एव' सो है। जिन लोगों के पास अधिक है वे अपने लाभ का उपयोग छु'क लिए नहीं करें, परन्तु उस पवित्र धराहूर मानकर एक सेवा की सेवा में उसका उपयोग करते हैं जिनके पास कम है।—प्रत्येक व्यक्ति अपने पास के वस्तुओं के लिए जिम्मेदार होता है और नार प्रति समाज के निर्वाह जिम्मेदार होने के। उसमें अधिकार और कर्तव्यों का नियमन परस्परालम्बन के सिद्धान्त से तथा परस्पर आदान प्रदान से होता है। ऐसी समाज में हमके अगम्य 'यत्नित्य' तथा सम्पूर्ण समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं होता और न तो राष्ट्रवाद के संकुचित स्वार्थी या आत्मक बान का खतरा रहता न अन्तरराष्ट्रियता या केनिंग अर्थ वन बान का खतरा रहता है। वे ऐसे समाज की स्थापना के लिये हैं स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने सन् १९२५ में ही अपने स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि 'सच्चा स्वराज्य थोड़ा सागो द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं बल्कि जब सत्ता का उपयोग होना हो तब सब लोगों के द्वारा उनका प्रतिहार करने की क्षमता प्राप्त करने' हासिल किया जा सकता है। हमारे अर्थ में स्वराज्य जनता में इस बात का पान पदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर अधिकार करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है। इस समाज में सत्ता एक साधन होती है जिसका उपयोग समाज की सेवा के लिए किया जाता है। किन्तु गांधी जी मानस की तरह कल्पनावामी नहीं थे। वे जानते थे कि इस समाज की स्थापना के लिए उन्हें उस तरह के संगठन भी खड़े करने पड़ेंगे और ऐसे समाज की राज्य प्रणाली भी भिन्न होगी अतः इस सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने साफ-साफ कहा था कि 'ऐसा समाज अनगिनत गांधी का होगा। उसका फलव एक के ऊपर एक के ढग पर नहीं, बल्कि सहारा की तरह एक के बाद एक की शक्ति में होगा। जिन्दगी मोनार की शक्ति में लड़ी होगी जहाँ ऊपर की तग चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर सदा होना पड़ता है वहाँ तो सप्रेम की लहरा की तरह जिदगा एक के बाद एक घेरे की शक्ति में होगी और व्यक्ति उसका मध्य बिन्दु होगा।' यह एक ऐसा अरातनीय सामुदायिक-समाज का चित्र है जहाँ समाज असंख्य लघु समुदायों के केन्द्रासारी वृत्तों पर खड़ा है। वहाँ बुनियादी लघु समुदायों के वहार मध्यवर्ती समुदायों का घेरा है, वे भी पुनः कुछ बड़े समुदायों से घिरे हैं और यह फलव अतः म फलते फलते विश्व समुदाय बन जाना

है। इन पचावा को सबसे मौलिक विषयता यह है कि अत्यन्त बाहरी घेरे की शक्ति ( Force ) क्या कम होनी जाती है। यही राज्य 'लोन' तो नहीं हो सकता ( क्योंकि गांधी जी के ही शब्दों में वह तो यल्लिड के बिन्दु की तरह आदश हो है ) किन्तु राज्य लगभग अदृश्य हो जाता है। राज्य रेत में उस जमीर की भाँति हो जाता है जो महत्वपूर्ण तो है किन्तु जिसका उपयोग कभी कभी होता है। राज्य रेत में उस जमीर की तो कभी उसका पता भी नहीं होता। राज्य की शक्ति ऐसी बढ़ती रहेगी। प्रख्यात विद्वान् की सी० ई० एम० जोट न अपनी पुस्तक 'माडन पोलिटिक्स थियरी' में एक जगह कहा है कि 'यदि सामाजिक काम में मानव की श्रद्धा को पुनर्जीवित करना है तो राज्य का घाटकर छोटे छोटे धना में बाँट देना चाहिए। और उन को विकेंद्रित कर देना चाहिए। प्रसिद्ध समाजवादी लेखन की जी० डी० एच० कोल न भी अपनी पुस्तक 'केवियन सोशलिज्म' में भी यही कहा है। यह कल्याणकारी राज्य में बाँट देना चाहिए। सोही है जहाँ कल्याण का अधिकार राज्य के बजाय लोक हो जाता है। मानव न कल्याण जब राज्य की जिम्मेवारी हो जाती है तो उसका लोकतांत्रिक स्वरूप तत्काल नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जहाँ तक कल्याण का प्रश्न है पश्चिम में आज साम्यवादी और पूँजीवादी राज्यों में कोई तात्त्विक भेद नहीं रह गया है। दोनों ही जगह नागरिक लगभग नुन्य बन गया है। श्री हल्कु फाइडमन ने अपनी पुस्तक 'ला इन ए वेरिजग सोसायटी' में कहा है कि कल्याणकारी राज्य पर 'रक्षक सामाजिक' सवाभा का प्रदाना एक औद्योगिक प्रवर्धक एक धार्मिक नियन्त्रक और एक मध्यस्थ होता है। 'तब बान स्पष्ट है कि नागरिक के लिए क्या बच जाता है।

कभी कभी पचायती राज का स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वायत्त प्रशासन जस नाम भी भिदे जाते हैं। किन्तु ये सब भी मध्य युगीन प्रत्यय हैं जब राज्य अपनी सुविधा की दृष्टि से नीचे की ओर झुके सरप्रायो का निर्माण कर लेता था जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में और शासन के काम में मदद कर सकें। राज्य उ हँ दिखे गये कोई भी अधिकार जब चाहे तब वापस ले सकता था क्योंकि वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में रहती थी। हमारा स्थान है कि हमारे पचायती राज की मसा ऐसी नहीं है। यहाँ तो पचायती के कुछ ऐसे दुर्निवादी अधिकार क्षान हैं जिनका अतिप्रचण राज्य नहीं कर सकेगा यहाँ जीवन की मौलिक आवश्यकताओं पर पचायती सत्ताओं का कब्जा रहेगा क्योंकि स्वतन्त्रता की यही एक मात्र गारंटी है। और जो काम वे स्वयं नहीं कर सकेंगे उ हँ कम बाहरी घेरे वाली सत्ताएँ करेंगी। कहा जा सकता है कि इनमें तो केन्द्रीय सरकार कमजोर रहेगी किन्तु बात एकदम उलटी है चूँकि केन्द्रीय सरकार के पास बहुत कम काम होगा और वह महत्वपूर्ण होगा जैसे तार व संचार सेवाएँ, बड़े बड़े उद्योग और सुरक्षा तथा विदेशी व्यापार आदि इसलिए सरकार का 'यान डू' पर रहेगा और वह अपने काम की समझता से कर सकेगी। हाँ उसमें नोकरशाही अदृश्य हो समाप्त हो जावेगी किन्तु नोकरशाही तो प्रजातन्त्र का सबसे खतरनाक दुश्मन है और उस तो किसी भी हालत में समाप्त करना ही चाहिए। नोकरशाही भी मध्ययुगीन राज्य-प्रवस्था का स्वभाव है और असल में उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति है। श्री पार किसन ने जब नोकरशाही की राज्य की नब्ब बताया था तो व उस वक्त तक लोकशाही से परिक्रित नहीं था न उ हँ यही मालूम था कि राज्य बहुत समाज व्यवस्था का एक अंग मान है।

इसलिए पचायती राज केवल प्रशासन का एक सुविधाजनक अंग ही नहीं बरन् एक नई समान व्यवस्था की रचना की ठीस योजना है। आज विज्ञान की प्रगति ने उम और सरल बना दिया है। अब स्वतन्त्रता समानता और बहुल्य के आदर्श की मानव जीवन का 'मावहारिक' अंग बनान का अवसर आ

गया है। प्रसन्न में आज तक हमने मानव पर उसके बातवार्ता से प्रयोग करने के विचार किया है इसे बान मनहाइम ने स्वल्प वृत्त मानव नाम दिया है किन्तु मनुष्य तो प्रसन्न में एक ठोस वास्तविकता है और हमें उसे ऐसा ही मान कर चलना होगा। हम ऐसा समाज चाहिए जो मानव को एक मानव होने की वरदान से मुक्त कर सके। ऐसा समाज केवल बड़ी हो सकता है जो मानव की पकड़ में हो और उसके लिए स्पष्ट हो। जिसके साथ वह स्पष्ट प्रिया प्रतिक्रिया कर सके। श्री आर्थर फिन् प्रसन्न विद्वान् ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि फिल्टर ऑफ सासल वॉ' में एक धार्मिकतापूर्ण गुण एण्ड मटल हेल्थ ए रिपोर्ट टु द इन्टर नेशनल वॉर स आफ मेटल हेल्थ को उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि 'मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही सामाजिक इकाई वह छोटा सामाजिक समूह है। उ होने यहाँ समूह का प्रयोग सामुदाय के लिए किया है—स०) जिसमें परस्पर अविरোধी और एक दूसरे की निष्ठा से जानने वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं और जिनके अन्तर्गत सभी सदस्य प्यार विदवाह, आपसी व्यवहार और समझ पर आधारित होते हैं। ऐसे ही समूह में रह कर व्यक्ति को इस बात की सबसे अधिक अनुमति होती है कि वह समाज का एक सदस्य है। स्पष्ट है ऐसा सामुदायिक समाज हो सकता है और यह समाज अनिवार्य लोकतांत्रिक होता है क्योंकि सामुदायिकता मनुष्य का आंतरिक गुण है और उसका आरोपण नहीं होता। इस समाज में मनुष्य को समाजवादी बनाना नहीं पड़ता वह तो समुदायों का प्राणी होने के नाते सामाजिक के अनायास और कुछ हा ही नहीं सकता।

इस दृष्टि से भारत में विनोबा जी द्वारा चलाया जान वाला ग्रामदान और प्रबल प्रसन्न या जिलादान आन्दोलन का अतीव महत्व है। क्योंकि यह आन्दोलन ऐसे समुदायों की स्थापना के लिए जन अभिन्न जगत् का प्रबलतम प्रयास है। इसके अलावा ऐसे समाज की रचना और किसी तरीके से ही नहीं सकती। समुदायों की स्थापना बानूना या अन्य अनेक तरीके से बड़ी होती और ही भी तो वह समाज संभव नहीं होता। उसमें मनुष्य रेत के बरतों की भाँति दर से तो होते हैं किन्तु उस संस्था में गुण नहीं होता। सामुदायिक समाज गुणमय समाज है। मनुष्य का विकास अपने समुदाय में ही होता है यह धर्म मनोविज्ञान का सब सिद्धि तथ्य है। श्री प्रो० साइमान ग्रोस ने अपनी सुन्दर पुस्तक 'दि नवस्ट अमेरिका' में जोरदार शब्दों में लिखा है कि प्रजातन्त्र का अर्थ है इस बात पर निर्भर करता है कि वह नागरिक को स्वयं के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रिया करने का कितना अवसर देता है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है—'कैसे किंवदन्ति में की एक्सिपेट द आर नाट डेमोक्रेटि'। यहाँ हम पचायती राज को ऐसे गुण प्रदान सामुदायिक समाज की स्थापना का एक अनुकूल और वैधानिक अवसर मानकर चलना चाहिए और इस निम्नता में ग्रामदान आन्दोलन को पचायती राज में सम्मिलित समझना चाहिए। मालूम नहीं ग्रामदान के कार्यक्रमों का प्रभाव ऐसा ही अनुभव करत है या नहीं किन्तु ग्रामदान का समाजगर्भ भी यही है। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास और ग्रामदान के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता अनुभव की है। किन्तु उसमें यह एक त्रुटि रह गई कि उसमें हमारे वर्तमान गावों की वास्तविक समुदाय मान लिया गया है किन्तु वही प्रयोग में आया समुदाय नहीं रह गये हैं। उन्हें समुदाय बनाना सहज है यह बात सही है और उन्हें समुदाय बनाना होगा। ग्रामदान आन्दोलन यहाँ काम कर रहा है। इसलिए पचायती राज और ग्रामदान आन्दोलन एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें बने ही मानकर चलना चाहिए।

**विकेन्द्रीकरण :**

**आर्थिक, राजनीतिक**

**एवं जनतान्त्रिक**

**समाजवाद**

—श्री सीमप्रकाश शीदा

**रा**जनीति और अर्थनीति का आरम्भ से बहुत गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो समाज प्रगति करता है। वह स्थिर और स्वस्थ होता है। यदि राजनीति और अर्थनीति एक दूसरे से टकराती हों तो फिर समाज अन्धार्ध, अस्थिर और अशांत बन जाता है। कुछ राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन के वर्तमान प्रतिबन्धों और दृष्टि ही आज तक के सामाजिक उदय पतन का मौलिक कारण रहा है। उनका यह भी मत है कि आर्थिक व्यवस्था ही किसी समाज का आधार होता है जिस पर उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा धार्मिक सिद्धांत और संगठन के ढांचे खड़े होते हैं, यदि हम इसकी दूर न भी जाएं तो भी इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह तो सब एक ही धारा में बह रहा है कि राजनीति और अर्थनीति का सबसे पारस्परिक अनुबन्धन और मोड़ाने प्रदान का ही होना चाहिये। मानव समाज की प्रगति का रहस्य इसी में है, दोनों में से कौन साध्य और कौन साधन इसका निष्पाद करता मुखर है। एक माने में दोनों एक दूसरे के साध्य और एक दूसरे के साधन हैं दोनों का वैयक्तिक विदु मानव है, जिसकी प्रगति जिसकी सहाई और सुख सतोष दोनों का लक्ष्य है। परन्तु जब मानव साध्य न रहे कर साधन बना दिया जाए, किसी सिद्धान्त और संगठन के प्रयोग का एक साधन, तो ऐसा समाज अगति और पतन की ओर जाता है।

**सीमित जनतन्त्र**

जनतन्त्र में मानव ही प्रभुसत्ता का स्रोत है। परन्तु आज जनतन्त्र की सीमा यही तक बढ़ी हुई है। समाज की बुद्धिमान और श्रीमान प्रभुसत्ता के इस स्रोत से अन्ध धुंधले हैं। इस स्रोत से प्रभुसत्ता के प्रभाव की

वह रूप और दिशा नहीं देना चाहते हैं, जो सारे समाज को तृप्त करे। आज का जनतन्त्र चाहे वह ससंदेह हो या श्रमयोग्य उसकी राजनीति तथा श्रमनीति प्रभुसत्ता को एक छोट से स्रोत तक ही सीमित किये हैं जिसका परिणाम यह है कि समाज पर चंद बुद्धिमान चंद श्रीमान, जिनमें सब स प्रभावशाली धनवान होते हैं, छाये हुये हैं। ऐसा समाज चंद राजनीतिक और आर्थिक वर्गों का समाज होता है। दुनिया में चाहे वह रूस की दुनिया हो, या अमेरिका की मानव भी अस्थिर और अशान्त है और समाज भी। आज तक छोटे-बड़े बुद्धा का मौलिक कारण यही रहा है। परन्तु गांधीजी न समाज के परिवर्तन का एक क्रांतिकारी रास्ता सुझाया वह मानव को प्रभुसत्ता का स्रोत तो मानते ही थे, किन्तु इसलिए नहीं कि चंद श्रीमान और चन्द बुद्धिमान हमसे अपनी प्यास बुझा सकें बल्कि इसे माने कि मानव अपने निकटतम समाज जिसका कि वह स्वयं एक अंग है यानी प्राथमिक समुदाय को अपनी प्रभुसत्ता प्रदान करे। मानव एक सामाजिक प्राणी है परन्तु आज के समाज में आर्थिक और राजनीतिक वर्गों का प्रभावहीन बल्कि अधीन बना हुआ है वह अपने प्राथमिक सामुदाय से भी अछूटा हुआ है।

## स्वराज्य का आधार स्वशासित प्राथमिक समुदाय

मानव की इसी अधीनता के गढ़ से उठाने के लिये गांधी जी ने स्वराज्य की कल्पना की थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि—असुर्य गांवों में वह व्यवस्था लगातार बनने वाले ऐसी वृत्तों की होगी जिसका कोई अंत ही न हो। ऐसी व्यवस्था में जीवन का अंतिम उद्देश्य पिरामिड के शिखर के सामने सङ्कुचित नहीं होगा बल्कि समुद्र में बनने वाले वृत्त के समान होगा जिसका केन्द्र बिन्दु व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति गांव के लिए त्याग करेगा, गांव जनपद के लिये त्याग करेगा जनपद राज्य के लिये राज्य राष्ट्र के लिए त्याग करेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया व्यक्तिरूपी केन्द्र बिन्दु से आरम्भ हो कर हमेशा त्याग और सहयोग की भावना से निमित्त होकर सामूहिक वृत्त के रूप में जीवन का पूर्ण वृत्त बनेगा।”

अपने मूल्य के सिर्फ बारह दिन पूरा गांधी जी न अपने एक आपण के प्रसंग में भारत के लिये सच्चे लोकतन्त्र की चर्चा करते हुए कहा था कि भारत के लिये सच्चे लोकतन्त्र की इकाई गांव होगा। अगर एक गांव को पंचायत राजस्थापित करने को इच्छुक हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सच्चा लोकतन्त्र तो केन्द्र में बड़े घेरे प्रतिनिधित्व से नहीं चलाया जा सकता। इसे प्रत्येक ग्राम की जनता द्वारा नीचे से चलाया होगा जिसका अग्रिमार्ग यह है कि प्राथमिक समुदाय न केवल प्रभुसत्ता का स्रोत है बल्कि प्राथमिक समुदाय ही समाज का आधार है। यह समुदाय जितना स्वस्थ और शक्तिशाली होगा। मानव समाज भी उतना ही स्वस्थ और शक्तिशाली होगा और शक्तिशाली भी। ऐसा स्वराज मुट्ठी भर केन्द्रों पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि इसमें शक्ति सभी केन्द्रों में विकेंद्रित होगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के दस वर्ष बाद जब सामुदायिक विकास योजना सफल सिद्ध होनी लगे तो राजनीतिक विवेकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। यही अनुभव पंचायती राज की मूलधारा है और विस्तरीय प्रणाली सांगू की गई परन्तु छ वर्षों बीत जाने के बाद भी सब प्रदेशों में विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना नहीं हो पाई। यहाँ इस बात को साफ कर देना की आवश्यकता जरूर है कि आज के पंचायती राज में प्राथमिक समुदाय स्वशासन की इकाई नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक अधिकार

देना तो दूर की बात है। ध्यान के पचायती राज म ग्राम समा और पचायत सबसे कमजोर सस्था है। कहीं-कहीं तो विकेन्द्रीकरण केवल श्रिले तक ही सीमित है। गांधी जी का स्वल्पम तो पचायत अपने स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक स्वशासन की इजाजत थी। गांधी जी का सारा विचार एक तक संगत धारा में चला हुआ है। मौलिक तब यह है कि राजनीतिक और व्यवस्थित दोनों का एक दूसरे के अनुकूल होना अनिवार्य है। यह बात कतई तौर पर अस्मभव है कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम पर राजनीतिक विकेन्द्रीकरण हो सक या वह एक दूसरे के साथ साथ रह सक। पचायती राज मस्थापना को शासन प्रबंध का अंग बना कर आर्थिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इतना तो किया जा सकता है कि वह स्वशासन की इजाजत नहीं होगी वह तो मशीनरी के निर्जीव कलपुर्जा होंगे।

## चतमान स्थिति का एक विश्लेषण

पचायती राज का उद्घाटन इसलिये हुआ था कि विकास के कार्यों में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। पचायती राज सस्थाओं को जनतान्त्रिक रूप देकर जनता में इस बात का गौरव पैदा करना कि वह नीचे स्तर पर जो अपनी सस्थाओं का निर्वाचन कर सकती हैं और उन निकटतम सस्थाओं द्वारा शासन के कार्यों में भागीदार हो सकते हैं। किंतु यह गौरव तो मिथ्या है। इन छत वर्षों में पचायती राज के अनुभवों ने इस गौरव को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। जनता में वह विश्वास, वह आशा, वह आकांक्षा उत्पन्न नहीं हो सकी जो उदात्तपुरुष भागीदारी और सहकारिता को उभार सक, इसलिए तो विकास की गति न केवल धीमी ही रही है बल्कि सीमित भी। नगरीकरण की एक भयानक प्रक्रिया पड़ी, और गांव सज्जने लगे, गांव के युवक रोजगार की तलाश में सहरो की ओर हजरत करने लगे हैं। जिन देहातों में गांधी जी स्वराज का द्रवना माने थे वही देहात निर्जन होकर छिन भिन हो रहे हैं। यदि इससे भी देग का आर्थिक विकास हो पाता जनसाधारण की कम से कम पारम्यिक आवश्यकता पूरी होन लगती, रोजगार के क्षेत्र विस्तृत होन लगते शिक्षा, स्वास्थ्य की सुलभ लियत बनने लगती, तो इतना सन्तोष तो होता कि ग्रामीण जीवन के सख्तहरो पर एक नय और स्वस्थ जीवन का विकास हो रहा है। केन्द्रिय भाषिकता का प्रभुत्व भी सिद्ध होता, परन्तु हुआ इसके विपरीत। विकास की गति धीमी रही, राष्ट्रीय सामदनी तो बढ़ी पर इसका ज्यादा भाग बन्द कर्त्र तथा सिमट कर रह गया। ग्रामीर और ग्रामीरों का दरम्यान प्याइ और भी ज्यादा विस्तृत और गहरी हो गई है। यद्यपि ग्रामि कता के विसो भी क्षम म कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रामि की स्थिति बिगड़ी है जमींदारी व्यवस्था के बावजूद मालवियन के प्रबंध म कोई प्रगतिशील परिवर्तन नहीं हुआ, देहात छिन भिन हा गये। ग्रामीरों के धनराशि का योजनाओं के द्वारा लच हुई मानो देग की प्यामी घरनों के समा सी है। इस स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा कारण यही सिद्ध होगा कि योजनायें गलत माध्यम पर बनाई गई, और वह इसलिये कि योजनाओं के निर्माणों के दृष्टिकोण ही गलत थे। जिस वान को यह प्राथमिकता देते हैं वह केन्द्रीय औद्योगिककरण है। वाना सब बातें इस लक्ष्य के माधोन कर दी गई हैं। ग्रामि के विकास पर लघु उद्योग और दस्तकारी इन पर भी ग्रामीरों क्षम की धनराशि खच हुई, इसलिये कि यह केन्द्रित भाषिकता के विकास में सहायक हो।

**राजनैतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण : अनिवार्य सम्पन्न**  
राजनीति में विकेन्द्रीकरण का प्रचार और आर्थिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण पर जोर

# हिन्दी वाङ्मय की अभिवृद्धि के लिए हिन्दी समिति के

## उच्चस्तरीय प्रकाशन

विज्ञान एवं नकनौक, सामाजिक शास्त्र, राजनीति, इतिहास, कला, साहित्य विषयों पर १३२ मौलिक तथा अनूदित ग्रन्थ प्रकाशित ।

## कुछ नये प्रकाशन

१—योग दश	डा० सम्पूर्णानन्द	६-००
२—व्याख्य उद्भाषा का इतिहास	श्री जगपति चतुर्वेदी	५-००
३—भारतीय संहिता	श्री अग्निदेव विद्यालकार	४-५०
४—पश्चिमी आलोचना शास्त्र	डा० लक्ष्मीसागर बाणर्ष्य	८-५०
५—शैक्षिक सर्विसिंग	श्री रमणचन्द्र बिजय	८-५०
६—समवाद और सधारमक शासन	डा० ब्रजमोहन शर्मा	८-५०
७—स्टाच और उसका व्यवसाय	डा० सतप्रसाद टण्डन	७-५०
८—पदाप शास्त्र	श्री आनन्द झा	८-००
९—उद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धान्त और प्रयोग	प्रो० कृष्णजी	६-००
१०—भारतीय ऋतु विज्ञान	आचार्य भास्करानन्द सोहानी	४-५०
११—प्राचीन भारत में जनतन्त्र	डा० देवीदत्त गुप्त	५-५०
१२—समय की सूट	श्री राजेन्द्र पाण्डे	३-५०
१३—राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त	डा० ब्रजमोहन शर्मा	७-००
१४—राज की दार्शनिक विचारधारा	श्री के० सी० जोगी	६-००

उचित मूल्य आवकक समीक्षण  
पूर्ण विवरण और पुस्तकों की सहीद के लिए  
लिखिये —

सचिव, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ

सङ्क-३

# पंचायती राज की सरचना की पृष्ठभूमि



- १ राष्ट्रपिता के सपने का ग्राम राज—गांधीजी १-५
- २ भारतीय सविधान के सदन में पंचायती राज की गरिमा—श्री जयप्रकाशनारायण ६-८
- ३ नवीन भारत में पंचायतों की भूमिका—श्री लक्ष्मणराय डबर ६-२२
- ४ पंचायती राज के लिए जनधनराय मेहता कमेटी की प्रारम्भिक सिफारिशें २१-३०
- ५ सोवियत विदेशीकरण की प्रमत्त योति—श्री जवाहरलाल नेहरू ३३-३७
- ६ युगोस्लाविया में सत्ता की विभेदित व्यवस्था—श्री भगवत्सिंह महता ३८-४३





# राष्ट्रपिता के सपनों का ग्रामराज

—गांधीजी



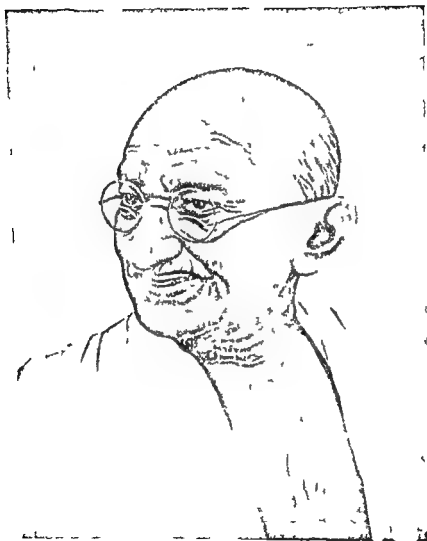
**ग्राम-स्वराज्य** की मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा पूरा प्रजासत्तव होगा जो अपनी ग्रहण जल्लरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी जल्लरतों के लिए-जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा—वह परस्पर सहयोग से काम लेगा, इस तरह हर एक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जल्लरतों का समाज बनाए और कपड़ों के लिए कपास खुद पैदा कर ले उससे पास इतनी सुरक्षित जमीन होना चाहिये जिसमें और घर सब, और गांव के बच्चों व बच्चों के लिए मन बहलाव के साधन और खेलकूद के मदान बगैरा का बन्दोबस्त हो सके। इनके बाद भी जमीन सबे तो उसमें वह ऐसे उपयोगी फलनें बीयेगा जिन्हें बेब बर वह आर्थिक लाभ उठा सके, या वह गाबा, तम्बाकू अफीम बगैरा की खेती से बचेगा।

## गांव की स्थानीय समस्याएँ

हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटकदाता, पाठसाळा और समामबन रहता। पानी के लिए उसका अपना इन्तिजाम होगा—बाटर बकस होंगे-जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी निज्जा करेगा। कुआ और ठालाओं पर गांव का पूरा नियंत्रण रख कर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी स्थानीय के प्राप्तिरी दरजे तक दिग्मा सबने लिए लाजिमी होंगे। जहाँ तक हो सकेगा, गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। आस-पास और कमागत अस्त्युत्पत्ता में जसे भद भाज हमारे सम्राज में पाये जाते हैं, वसे इस ग्राम-समाज में निजकुल नहीं रहेंगे।

## गांव की रचा के लिए ग्राम मैनिंक

गांव की रसा के लिए ग्राम-सन्निक्ता का एक ऐसा दन रहेगा, जिस लाजिमी तीर पर बाये-बारी से गांव के बोली-पहरे का काम करता होगा। इसके लिए गांव में ऐसे लोग का रजिस्टर रखा जायगा।



पचापतीराज के स्वप्न द्रष्टा  
महात्मा गान्धी

# राष्ट्रपिता के सपनों का ग्रामराज

—गांधीजी



**ग्राम-स्वराज्य** की मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा पूरा प्रजातन्त्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए—जिनमें दूसरा का सहयोग अनिवार्य होगा—वह परस्पर सहयोग से काम लेगा, इस तरह हर एक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरतों का तयाम समाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होना चाहिये जिसमें खीर बर सके, और गांव के बड़ों के बच्चे के लिए मन बहलाव के साधन और खेलकूद के मदान बगीचा का बल्लोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बचे तो उसमें वह ऐसी उपयोगी कसमें बोयेगा जिन्हें बेब बर वह आर्थिक लाभ उठा सके, जो गांव गांव, तम्बाकू अफीम बगीचा की खेती से बचेगा।

## गांव की स्थानीय समस्याएँ

हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटकशाळा, पाठशाला और सभासदन रहता। पानी के लिए उसका अपना इन्तिजाम होगा—बाटर बक्क हूँगे—जिससे गांव के सभी लोगों को गुड पानी मिला करेगा। नुमो और ताताओं पर गांव का पूरा नियन्त्रण रख कर वह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए साजिशमी होगी। जहाँ तक हो सकेगा गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात-पात और क्रमागत असमृद्धता के जस भेद भाव हमारे समाज में पाये जाते हैं, वसे इस ग्राम-स्वराज्य में बिलकुल नहीं रहेंगे।

## गांव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिक

गांव की रक्षा के लिए ग्राम-सैनिक का एक ऐसा दल रहेगा जिस साजिशमी तौर पर बाती-बाती से गांव के चौकी-पहरे का काम करना होगा। इसके लिए गांव में ऐसे लोग का रजिस्टर रखा जायगा।

## ग्राम पंचायत

गांव का शासन चलाने के लिए हर साल गांव के पांच प्रादमियों की एक पंचायत चुनी जायगी इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। तू कि इस ग्राम-स्वराज्य में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई रिवाज नहीं रहगा इस लिए यह पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारासभा, 'यायगभा' और कार्यकारिणी सभा का सारा काम समुक्त रूप से करेगी।

## गांव का प्रजातंत्र

आज भी अगर कोई गांव चाहे तो अपने यहां इस तरह का प्रजातंत्र कायम कर सकता है। उसके इस काम में मौजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तदाजी नहीं करेगी। क्योंकि उनका गांव से जो भी कारण सम्बंध है वह सिर्फ मालगुजारी वसूल करने तक ही सीमित है।

## ग्राम शासन की रूपरेखा

यहां मने इस बात का विचार नहीं किया है कि इस तरह के गांव का अपने पास-पड़ोस के गांवों के साथ या केन्द्रीय सरकार के साथ, अगर वही कोई सरकार हुई क्या सम्बंध रहेगा। मेरा हेतु तो ग्राम शासन की एक रूपरेखा देना करने का ही है। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। 'यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। उसके सरकार भी वह दोना अहिंसा के नियम के बंध होकर चलेंगे। अपने गांव के साथ वह सारी दुनिया की शक्ति का मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि हर एक देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांव की इज्जत की रक्षा के लिए मर मिटे।

## पूरी जिंदगी खत्म हो जाए

समय है ऐसे गांव को तयार करने में एक प्रादमी की 'पूरी जिन्दगा खत्म हो जाय। सच्चे प्रजातंत्र का और ग्राम-जीवन का कोई भी प्र भी एक गांव को खर बठ सकता है और उसी को अपनी सारी दुनिया मानकर उसके काम में मगसगूत रह सकता है। निदबय ही उसे इसका अण्डा फन मिलेगा। यह गांव में बढने ही एक साथ गांव के भगी कतवये चीवीदार बंध और शिक्षक का काम शुरू कर देगा। अगर गांव का कोई प्रादमी उसके पास न पडके तो भी वह सत्तोप के साथ सफाई और बतार्ई के काम में जुटा रहेगा।

## ग्रामीण कला और उद्योग

देहात बाना में ऐसी कला और कारीगरी का विकास होना चाहिये, जिससे बाहर उनकी पदा की हुई चीजों की मांगत की जा सके। जब गांवों का पूरा-पूरा विकास हो जायगा तो देहातियों की बुद्धि

घोर धारमा को सन्तुष्ट करने वाली क्या-कारीगरी के धनी स्त्री-पुरुषों की गावां भ्रम नहीं रहेगी। गाव में भवि होगा, बिजली होगी, जिल्दी होगी, बापा के पठित और घोष करने वाले लोग भी होंगे। पाठ में जिल्दी की ऐसी कोई चीज न होगी जो गाव में न मिले। आज हमारे देहात उजड़े हुए और कूड़े-कचरे के ढेर बने हुए हैं। वन वहीं सुंदर बगीचे होंगे और आमवांसिया को ठगना या उनका घोषण करना असंभव हो जायगा।

इस तरह के गावों की पुनरचना का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिये। गावों की पुनरचना का काम कामचलाऊ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिये।

## असुख ग्राम रचना

उद्योग, हुनर, तन्दुस्ती और शिक्षा इन चारों का सुंदर सम्मेलन करना चाहिये। नई तालीम में उद्योग और शिक्षा, तन्दुस्ती और हुनर का सुन्दर सम्मेलन है। इन सब का मेल से मा के पेट में भोजन समय से लेकर बुढ़ापे तक का एक खूबसूरत फल तयार होना है। यही नई तालीम है। इसलिए मैं शुरू में ग्राम-रचना के टुकड़े नहीं बल्कि यह कोशिश करूंगा कि इन चारों का आपस में मेल बटे। इस लिए मैं किसी उद्योग और शिक्षा को भ्रमण नहीं मानूंगा, बल्कि उद्योग को शिक्षा का जरिया मानूंगा, और इसलिए ऐसी योजना में नई तालीम को शामिल करूंगा।

## मेरी कल्पना की ग्राम-डकाई

मेरी कल्पना की ग्राम डकाई मजबूत से मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गाव में १००० आदमी रहेंगे। ऐसे गाव की अगर स्वावलम्बन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाय तो वह बहुत कुछ कर सकता है।

## आदर्श भारतीय ग्राम

आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बनाया जायगा कि उसमें आसानी से स्वच्छता की पूरी-पूरी व्यवस्था रहे। उसकी भाषाओं में पर्याप्त प्रकाश और हवा का प्रबंध होगा और उनके निर्माण में जिस सामान का उपयोग होगा वह ऐसा होगा जो गाव के पास पास पाव भीत की विज्ञान के आदर माने वाले प्रदेशों में मिल सके। इन भाषाओं में आगन या मुला जगह होगी, जहां उस घर के लोग अपने उपयोग के लिए साग भाजियां लगा सके और अपने भविष्यों की रख सकें। गाव की गलियां और सड़कें, जिस धूल को हटाया जा सकता है उससे मुक्त होंगी। उस गाव में उसकी आवश्यकता के अनुसार हुए होंगे और वे सबके लिए खुले होंगे। उसमें सब लोगों के लिए पूजा के स्थान होंगे, सबके लिए एक सभा भवन होगा, भविष्यों के करने के लिए गाव का चारागाह होगा, सड़करी डेरी होगी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे जिनमें मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायगी और भगवत के निपटारे के लिए ग्राम-व्यायत होंगे। वह अपना अपना साग भाजियां और फल तथा खाने खुद पैदा कर लेगा।

## आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए (पचायत राज)

आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये। हर एक गाव में जयहूरी सत्तन्त्र या पचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। जिसका मतलब यह है कि हर एक गाव को अपने पास

पर खड़ा होना होगा—अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर लेनी होगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहाँ तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके। उसे तालीम देकर इस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमले के मुकाबले में अपनी रक्षा करते हुए मर मिटने के लायक बन जाय। इस तरह आखिर हमारी दुनियाद व्यक्ति पर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय, या उनकी राजी-खुशी से दी हुई मदद न ली जाय। मत्पना यह है कि सब लोग आजाद होंगे और सब एक दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे, जिस समाज का हर एक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिये और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिये, वह समाज जरूर हो बहुत ऊँचे दर्जे की सम्पत्ता वाला होना चाहिये।

## गाव की ज़िदगी समुद्र की लहरों की तरह

ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा, उसका फल एक के ऊपर एक के ढग पर नहीं, बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ति में होगा। ज़िदगी मोनार की शकल में नहीं होगी जहाँ ऊपर की तग छोटी की नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहाँ तो समुद्र की लहरों की तरह ज़िदगी एक के बाद एक घेरे की शकल में होगी और व्यक्ति उसका मध्यबिंदु होगा।

## एक के लिए सब, सबके लिए एक

यह व्यक्ति हमेशा अपने गाव के खानिर मिटन को तैयार रहेगा। गाव अपने इतिहास के गावों के लिए मिटने की तैयार होगा। इस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगों का बन जायगा, जो उनल बनकर किसी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं, और अपने में समुद्र की उस गान की महसूस करते हैं जिसके वे एक जड़ती भग हैं।

इसलिये सबसे बाहर का घेरा या दायरा अपनी ताकत का उपयोग भीतरवालों की कुचलने में नहीं करेगा बल्कि उन सबको ताकत देगा और उनसे ताकत पायेगा। मुझे ताना दिया जा सकता है कि यह सब तो खयाली तस्वीर है इसके बारे में सोचकर बहुत क्यों बिपादा जाय? युक्तिवाद की परिभाषा वाला बिंदु कोई मनुष्य खींच नहीं सकता, फिर भी उसकी नीमत हमेशा रही है।

## यह खयाली तस्वीर नहीं है मेरी तस्वीर

उसी तरह मेरी यह तस्वीर की भी नीमत है। इसके लिये मनुष्य जिंदा रह सकता है। अगरचे इस तस्वीर की पूरी तरह बनाना या पाना सम्भव नहीं है तो भी इस सही तस्वीर को पाना या इस तक पहुँचना हिंदुस्तान की ज़िदगी का मकसद होना चाहिये। जिस चीज को हम चाहते हैं उसकी सही-सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिये, तभी हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज पाने की आशा रख सकते हैं। अगर हिंदुस्तान के हर एक गाव में जमा पचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सचाई साबित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोई पहला होगा न आखिरी।

## हर धर्म की बराबरी की जगह

इस तस्वीर में हर एक धर्म की अपनी पूरी और बराबरी की जगह होगी। हम सब एक ही आशीर्वात पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ की जड़ हिलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुँची हुई है। जबरदस्त से जबरदस्त आघात भी उसे हिला नहीं सकती।

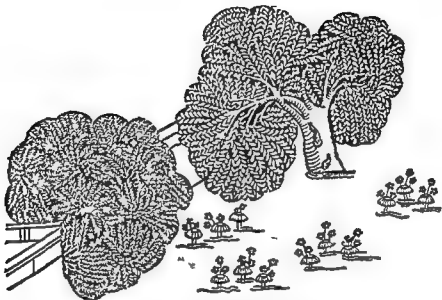
## मशीनों के लिए कोई जगह नहीं

इस तस्वीर में उन मशीनों के लिये कोई जगह नहीं होगी, जो मनुष्य की मेहनत की जगह लेकर कुछ लोगों के हाथों में सारी ताकत इकट्ठी कर देती हैं। सम्य लोगों की दुनिया में मेहनत की अपनी अपनी जगह है। उसमें ऐसी मशीन की गुंजाइश होगी जो हर धर्मों को उसके काम में मदद पहुँचाये। लेकिन मुझे बतल करना चाहिये कि मैंने अभी चिन्तन यह सोचा नहीं कि इस तरह की मशीन बनी हो सकती है। सिवाई जो मशीन मशीन का खयाल मुझे आया था। लेकिन उसका जित भी मैंने माँ ही कर दिया था। अपनी इस तस्वीर को पूरा बनाने के लिये मुझे उसको खरबत नहीं।

जब पचायत राज स्थापित हो जायेगा तब लोगमत ऐसे भी अनेक काम कर दिलायेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकता जमींदार, पूँजीपति। और राजाओं की मौजूदा सत्ता सभी तब बल सनती है जब तक कि सामान्य जनता की अपनी शक्ति का भान नहीं होता। अगर लोग जमींदारों और पूँजीवाद की बुराई से सहयोग करना बन्द कर दें, तो वह पोपल के अभाव में खुद ही मर जायगी। पचायत राज में केवल पचायत की आत्मा बानी जायगी और पचायत अपने बनाये हुए कानून द्वारा ही अपना काम करेगा।







## भारतीय सविधान के सदर्भ में पंचायती राज की गरिमा

—श्री जयप्रकाशनारायण

भारतीय पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति की वर्णना करना चाहूंगा। जैसा कि सर्वविदित है पंचायती राज का प्रारम्भ और विनाश आधुनिक विकास कार्यक्रमों के क्रिया-व्ययन में अनुभूत क्षतिपूर्ति विचारों का लक्ष्य हुआ। मुद्रास्फीति, जनविकास में देरी, प्रतिवेदन में लोकतांत्रिक विवेकीकरण की वर्तमान प्रक्रिया की गति आदि। इस प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में आधुनिक संशोधनों की विकास-गति की तीव्रतर करना ही प्रधान लक्ष्य रहा है। इस प्रसंग में भारतीय सविधान सभा की सर्वाधिक कार्यक्रमों का स्मरण करना चाहूंगा। १९४७ को १० मई को सविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने यह विचार प्रकट किया कि सविधान का आधार ग्राम पंचायतें हानी चाहिये और अत्यन्त चुनावों के आधार पर स्तर पर स्तर बनाकर सविधान का निर्माण किया जाना चाहिये। इस विचार पर मेरी समझ में प्रायः एक ही प्रकार के संकट संशोधन रख गए। संवैधानिक परामर्शदाता श्री बी. एन. राव की यह सम्मति रही कि इस सुझाव के अनुसार समूचे

सविधान को फिर से दोहराने में अब बहुत विलम्ब हो गया है, और यह राय दी गई कि इस विषय को बाद में केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय विधान सभाओं के विचाराधीन स्थिति कर दिया जाए। १९४८ की २२ नवम्बर को श्री सधानम् का एक सद्योपन श्री अम्बेडकर द्वारा स्वीकार किया गया और बाद में उसे ४० वीं धारा के रूप में सविधान में अंगीकृत किया गया, जिसमें कहा गया कि 'राज्य स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठायेगा।'

सविधान में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता की इकाइयां बतायी गयी हैं। इसका अर्थ है कि पंचायतों का अस्तित्व और कार्य एकात्मिक रूप में न होकर, स्वायत्तता की बड़ी इकाइयों के अंगीकृत रूप में होगा, जो स्वयं बृहत्तर इकाइयों के भाग होंगे। इस प्रकार संघ में पंचायतीराज का अन्तिम सविधान की बातोंसे धारा में सन्निहित है।

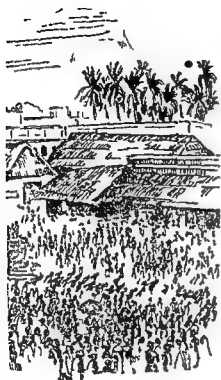
मैं इस विषय का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त और उसके सम्बन्धित समस्याएँ सामुदायिक विकास सम्बन्धी अनुभवों से ही नहीं उद्भूत होती बल्कि सीधे सविधान सभा के लिए से ही होती हैं। विषय का यह पक्ष अत्यधिक राजनीतिक महत्व का है क्योंकि यह पंचायतीराज को एक निश्चित भिन्न प्रकार से प्रकाश में लाता है और इस एक महान् प्रश्न और कई परिणाम प्रदान करता है।

समस्त यह अनिवार्य ही था कि भारतीय सविधान में मूल रूप से यह अत्यधिक केन्द्रीकृत राज्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजों राज्य में केवल केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें ही थीं। ये दोनों ही उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण की योजना थी। यही पद्धति हमारे सविधान में भी ग्रहण की गई। तभी तथा राज्य सरकारों आज व्यवस्थापक मंत्रालयों के आधार पर ही बनती हैं—यह तथ्य भी उनके विकेन्द्रीकरण की सच्चाई में कोई परिवर्तन नहीं लाता। सामान्यतः राज्य भी लोकमत से जुने और स्थापित हुए मुने जाते हैं। सविधान तो सामाजिक तथ्यों को प्रतिबिम्बित मात्र करते हैं। वे उन्हें गढ़ नहीं पाते। सविधान बताते समय उल्लिखित सामाजिक तथ्य समस्त यह प्रमाणित नहीं करते कि राज्यस्तर से ऊपर भी शासन के विकेन्द्रीकरण का कोई आधार था। आजादी की लड़ाई ने नीचे से लोकमत के एस प्र ग खड़े नहीं किए जिन्हें राज्यसत्ता सौंपी जा सकती। स्थानीय स्वायत्त शासन की उस समय वर्तमान समस्याएँ पूरातया दाग मात्र थी और उनमें किसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं था तथा न ग्राम, मण्डल और जिला स्तरीय कांग्रेस समितियों को ही लोकमत की प्रतिनिधि समस्याएँ मान कर उन्हें विधान के साथ शासनविकास सौंपा जा सकता था।

किन्तु पंचायतीराज के प्रारम्भ से ही, कुछ न कुछ सामाजिक तथ्यों की रचना प्रवर्ध हो रही है, बाढ़ इनके पीछे लम्बे कुछ भी रहा है। गांव से जिले तक त्रिस्तरीय स्वायत्त शासन समस्याएँ स्थापित की जा रही हैं। इस प्रति आवश्यक विकास की प्रति गौरव ही दस के सविधान में समुचित रूप से उल्लिखित कर स्थान देना होगा और इस प्रकार प्रामाणिक रूप से सविधान सभा की मनसा भी पूरी हो जाएगी। वर्तमान सविधान में शासन के दो क्षत्रीय अंग ही मान गए हैं—केन्द्र और राज्य। स्वायत्त शासन के तीन स्तरों—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को भी सविधान में उनका समुचित स्थान दिया जाना चाहिए और उनके अधिकारों दायित्व तथा राष्ट्रीय मामलों में उनके भाग की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिये।

यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसी ही सिफारिश १९६० में भारत सरकार द्वारा यूगोस्लेविया भेजे गये उस अध्ययन दल ने भी की थी जिसमें राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह मेहता तथा केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्रालय के पचायत आयुक्त श्री जी एफ मनकोटी सम्मिलित थे। यहां भी प्रासंगिक रूप से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यूगोस्लेविया के राजनतिक और ग्रामिक विकेद्रीकरण के असाधारण रूप में साहसिक प्रयोग, जिन्हें वे सामाजिक व्यवस्था की सज्ञा देते हैं हमारे देशवासियों के लिए बहुत भूत महत्व के हैं और हमें उनका अत्यंत निवट से अध्ययन करना चाहिये।





# नवीन भारत में पंचायतों की भूमिका

—श्री उच्छयराय डेवर

**भा**रतीय संविधान की धारा ४० में कहा गया है  
“राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसे अधिकार और कार्य सुपुर्द करने के लिए कदम उठायेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इच्छाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनावेंगे।”

हममें से कुछ लोग यह सोचने या विश्वास करने लगे हैं कि संविधान की भावना के अनुसार, ग्राम पंचायत राज्य की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का आधार और उसका प्रधान स्रोत है, जिससे सभी क्रियाशीलताएँ प्रवाहित होती हैं। फिर कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इस विश्वास के अन्तर्गत कार्य करते रहे हैं कि यद्यपि यह न तो केन्द्र है और न हो हो सकती है फिर भी यह राज्य की एक अपरिहार्य विकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य प्रशासनिक माध्यम होगी। अन्त में, वे लोग भी हैं, जो यही कहते रहे हैं कि पंचायत का निर्माण चाहे जसी भी भावनात्मक या सुन्दर घोषणाओं के साथ हो वह राज्य की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की प्रथम व्यवस्था में केवल एक सामान्य इकाई ही रहेगी—यह स्वयं

आधार नहीं होगी वल्कि समूचे ढांचे के आधार पर स्थित होगी। नागरिक के लिए समस्या यह है कि वह देश की राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के भीतर पंचायत की भूमिका और उसके स्थान को सही सही निश्चित कर ले। प्रथम श्रेणी के लोग इसे केन्द्र और आधार मानते हैं दूसरी श्रेणी के लोग इसे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझते हैं जबकि तृतीय श्रेणी के लोग इसका स्थान प्रशासनिक परिधि के निकट वहीं पर मानते हैं।

## इंग्लैंड में स्थानीय सरकार

ब्रिटिश स्थानीय सरकार के विषय में चर्चा करते हुए प्रो जी डी एच कोल ने कहा है

“ब्रिटिश स्थानीय सरकार का कार्य मुख्यतः प्रशासनिक है अर्थात् उसका सम्बन्ध संसद द्वारा स्वीकृत कानून, अधिनियम प्राचीन घोषणापत्रों और वायद, प्राधुनिक कानूनों द्वारा सुगुंठित किये गए कार्यों को कार्यान्वित करने से है।”

अब शब्दों में यह तृतीय श्रेणी के लोगों के दृष्टिकोण का समयक है। प्रशासनिक परिधि पर स्थित होने पर भी, इसे, निश्चय ही, सफाई, सड़क व्यवस्था आदि प्राविधिक समस्याओं को सुलझाना पड़ता है और साथ ही राज्य व्यवस्था से अथवा ज्यादा सही अर्थ में उन व्यक्तियों से जो उसका संचालन करते हैं, निश्चयता भी पड़ता है, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या नीतिशास्त्रज्ञ। इस सम्बन्ध में इसे ऐसे शासकों द्वारा शासन करने का दुष्परिणाम भगना पड़ गया जिनकी स्वयं अपनी धारणाएँ या अभिलाषाएँ हैं। यदि सरकार प्रतिनियोगवादी हुई तो इस बात का प्रयत्न करेगी कि स्वायत्त स्वायत्त शासन संस्थाएँ कमजोर और अव्यवस्थित माध्यमों के रूप में ही नियायी जा सकें, और इस प्रकार, वे एक स्वायत्त शासन ढांचे के गति कोल स्रष्टा बिंदु बंदावि न बनने पायें। केवल वे सरकारें ही स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं पर पूरा पूरा विश्वास करने और जनता के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष अनिवार्य मामलों के प्रस्ताव, अथवा अंतिम सत्ता प्रदान करने का साहस कर सकती हैं, जिन्हें अपने नागरिकों की आधारभूत राज्य भक्ति और दंड सामाज्य मान पर अन्धकी तरह विश्वास हो। इन संस्थाओं की पंचायता के कार्यों के सम्बन्ध में गांव के जन साधारण की प्रतिनियोग पर भी अन्धकी तरह गौर करना पड़ता। अतः पंचायता की स्थिति प्रशासनिक परिधि पर मानने से भी कार्य सरल नहीं होगा। कभी न कभी यह बात स्पष्ट हो जायगी कि अधिकार मामलों में ग्राम पंचायता के प्रत्यक्ष अधिकार इतने कम और उनके साधन इतने सीमित हैं कि ग्राम पंचायत का सारा व्यवसाय इस निश्चय कीज की बढ़ावा देने में लगाये गये प्रयत्नों की क्षतिपूर्ति बंदावि न कर पायेगा।

सन् १९४७ में लिखते हुए प्रो जी डी एच कोल ने इंग्लैंड की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की थी

मेरा सुझाव यह है कि स्थानीय सरकार की समस्या में इस समय जो दिक्कतों की कमी दिखलाई पड़ती है उगता कारण भिन्न सफाई सम्बन्धी कार्यों की जिनसे प्राधुनिक स्थानीय सरकार का विकास हुआ है अर्थात् ही नहीं है वल्कि स्थानीय सरकार के सम्बन्ध में एक सच्चा निराधार धारणा भी है जिसे हमने उस समय से विरासत में पाया है जबकि धाम तोर पर यह माना जाता था कि इसके कार्य अनिवार्य रूप से स्थानीय हो होने चाहिये। — उसे ऐसी गन्दगियाँ और बुराईयाँ की सफाई करने वाला भगी समझने की बजाय जिन्हें कोई अन्य समस्या न तो कर सकती है, और न करेगी, हम उसको सामुदायिक

जावन के ताने-बाने का कूशन गिल्पी मानना चाहिये । ~ यह पूछन की बजाय कि ग्राम सस्याएँ 'एक चलन' के रूप में मया करने के लिए प्रेरित की जा सकती हैं, हम, दरअसल, यह पूछना चाहिए कि स्थानीय समाज, सम्पन्न की जाने वाली सेवा के स्वभाव के अनुसार ज्यादा विस्तृत या सङ्कुचित शत्रु म प्रपन कल्याण के लिए सवधेष्ट ढग पर क्या कर सकता है । हम चाहिये कि हम शत्रु पूरा करने या क्षान्द्या भरन का काम ग्राम सस्याओं पर छोड़ दें, न कि उन सस्याओं द्वारा छोटी गयी कमियाँ को दूर करन के साधन के रूप में स्थानीय सरकार का इस्तेमाल करें ।'

## प्राचीन भारत में

यद्यपि यह बात ब्रिटिश स्थानीय स्वायत्त शासन सस्याओं के सम्बन्ध में सही है किन्तु इस तर्क की भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ग्राम पंचायतों पर दून ओर के साथ दुहराया जा सकता है । साइ मन बमोशन में ग्रपनी रिपोर्ट में कहा है

'विश्व, भारतीय ग्राम जीवन के मूल सस्या का अस्तित्व नायम है और उसका महत्त्व बधानिक सुधारक और कृषि परामशदाता, दोनों ही समान रूप से मान्य होना चाहिये ।'

ब्रिटिश माल 'ग्राम और पुलिस प्रशासन के भारत में अतगत अवस्था होन के पूव भारतीय ग्राम एक गतिशील सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करता था । डा एस राधाकृष्णन् के शब्दों में यह राष्ट्र को 'एक उद्देश्य, एक मन्तव्य और एक विश्वास प्रदान करता था । वाल्स मैटकाफ के शब्दों में

'ग्राम पंचायतें छोटे लोकतन्त्र हैं जिनके स्वयं अपने भीतर ग्राम प्रत्येक चीज जिसकी उन्हें जरूरत हो सकती है, मौजूद है, और जो किसी भी विदेशी सम्बन्ध से लगभग मुक्त है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे नश्वरों के बीच अनश्वर हैं । शासन पर शासन चरत होते जाने हैं, शक्ति के बाद शक्ति आती है, लेकिन ग्राम पंचायत का अनवरत श्रम जारी है । 'अतः मैं कहना हूँ कि ग्राम सम्बन्धी विधानों में परिवर्तन न किये जायें । मैं ऐसी प्रत्येक चीज से असमर्थ हूँ जिसमें उन्हें मग कर देने की प्रवृत्ति पायी जाती है ।

फिर भी, जान-बूझकर ग्राम्य-समुदाय को नष्ट भ्रष्ट करने का बोलिया की गयी । सरकारी अभि कारिया के हाथों में कार्यकरिणी तथा 'ग्राम सम्बन्धी अधिकारों के अत्यधिक बे-होकरण तथा जमींदारी प्रथा न गावा के सामुदायिक जीवन के छोटे और बड़े विभाजक का कार्य किया । युवा से चली जाती उनकी समानता तथा ग्रामी और ग्रामीणों के मसलों पर उनकी सत्ता और उनके प्रभाव उनसे छीन लिये गये । जिन बार्ता की निरहुंग राजाओं के शासन तथा शक्ति के बाद आने वाली शक्तियाँ भी नष्ट न कर सरीं, उन्हें जान बूझकर, चुरी नीमत से आयोजित प्रयासों द्वारा नष्ट कर डाला गया ।

डा राधाकृष्ण मुक्जी ने ग्रामों पर इस प्रकार का सबूत आने के पूव पाये जाने वाले भारतीय ग्रामोण प्रशासनिक ढांचे का चित्र प्रस्तुत किया है । वह कहते हैं

'भारत राज्य और समाज के ऐसे सठ अस्तित्व का प्रदुभुन और उन्नेखनीय चित्र प्रस्तुत करता है, जिसके अतगरा प्रत्येक दूसरे से पृथक और कुछ अलग में स्वतन्त्र होता है और साथ ही, स्पष्ट तथा पृथक इकाई भी होता है । इस चित्र में समाज और राज्य, दोनों ही

राष्ट्रीय, लोकप्रिय और सामूहिक जीवन तथा काय के स्वतंत्र केन्द्र होते हैं। ये दोनों ही स्वतंत्र सगठन हैं और इनका ढांचा भी एकदम प्रत्यक्ष और सुनिश्चित था। इनके विचार और प्रगति के नियम भी अपने अपने थे।

आगे जब हम ग्राम पंचायत प्रशासन की समस्या के साथ दो दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे, तो इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे।

## सही दृष्टिकोण

यदि ग्राम पंचायत को श्री जो डी एच कोल के शब्दों में, गांव का लोगो के भाग्य का 'हुताशिल्पी' होता है यदि उसे सामूहिक-जीवन-यापन का उदाहरण प्रस्तुत करना है यदि उसे डा राधाकृष्णन मुकुर्जी के शब्दों में राष्ट्रीय, लोकप्रिय और सामूहिक जीवन का केन्द्र होना है यदि उसे डा राधाकृष्णन के शब्दों में राष्ट्र को एक उद्देश्य, एक सात्वता और एक विश्वास प्रदान करना है, यदि उसे अपनी मदद प्राप्त करने और आमनिर्भर होने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करनी है तो हम अपने विचारों में पुनर्जीवनीता लाती होगी और पंचायत में अधिकारों उसकी सत्ता और उसके साधनों की समस्या पर स्वायत्त शासन की स्थानीय निम्नतम इकाई का दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वायत्त शासन की एक ऐसी इकाई के दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा जिस पर कुछ बुनियादी जिम्मेदारियों का भार रखा गया हो। गहन की जरूरत नहीं कि इस अर्थ में उसे कुछ बुनियादी अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। ये अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं, अथवा सविधान तथा ग्राम पंचायत संस्थाओं को अनुशासित करने वाले कानूनी ढांचे में, ये अधिकार और कर्तव्य क्या होने चाहिए—इन पर हम आगे चल कर विचार करेंगे।

आइए, हम द्वितीय दृष्टिकोण पर विचार करें। प्रशासन के विकेंद्रित ढांचे की धारणा अनेक स्पष्ट दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती है। प्राधुनिक राज्य की प्रवृत्ति केन्द्रीयकरण की दिशा में अग्रसर होने की होती है, चाहे वह लोकतंत्रीय सविधान पर आधारित होगी हो या अधिकार और सत्ता की एकात्मिक धारणा पर। शहरी और औद्योगिक समाज की जटिल समस्याएं जनता द्वारा रहन सहन और सुविधाओं के कुछ आधारभूत स्तरों की मांग तथापि स्वतंत्र सत्ता में जोकि मुद्रास्फीति और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय राजकोषीय नीतिमय की समस्या से संयुक्त है मुद्रा बाजार की गहन संवेदनशीलता आणविक अस्त्रों के संचयन में राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याएं तथा संयुक्त राष्ट्र सच जैसे सगठनों के माध्यम से मुद्रा सुरक्षा, बीमारी और गरीबी की बहुत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न—ये सभी बातें हम अनिवार्य रूप से केन्द्रीयकरण की ओर ले जाती हैं। यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

## विकेंद्रीकरण • परस्पर विरोधी पक्ष

सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने वाले उपाय के रूप में विकेंद्रीकरण की धारणा, उसकी उस धारणा से भिन्न है जो केन्द्रीकृत सरकार की निष्पक्षता का परिणाम होती है। एक का जन्म एक सिद्धान्त की सचेत मायता का फल है, जबकि दूसरी धारणा केवल उस सिद्धान्त से परिचित होती है, और सिर्फ उसी हानित में विकेंद्रीकरण करती है जब आवश्यकता सुविधा अथवा अधिक क्षमता की दृष्टि से ऐसा करना अनिवार्य होता है। हम ग्राम पंचायत प्रशासन

के सदम में इस प्रश्न को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मामले में तो यह विश्वास और श्रद्धा की बात होती है, जबकि दूसरे में केवल परिणामजन्य। अगर हम इस प्रश्न पर नियंत्रण करने की दृष्टि से विचार करें, तो यह प्रश्न अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नियंत्रण करना प्रशासन का सार तत्व है। हमेशा सवाल यह उठता है कि 'किसे और किस स्तर पर नियंत्रण करना है?' नियंत्रण के अन्तर्गत, उच्च नीतियों से सम्बद्ध नियंत्रण, साधारण नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर नियंत्रण, प्रशासन सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण तथा इन बातों के सम्बन्ध में नियंत्रण कि इन नियंत्रणों की किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय, शामिल होते हैं। मोटे तौर पर, हम उनकी परिभाषा करते हुए कह सकते हैं कि ये बुनियादी नीतियों प्रशासनिक नीतियों और कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतियों के बारे में किये जाने वाले नियंत्रण होते हैं। हमेशा यह सत्य बनता रहता है कि कौन से नियंत्रण करेगा और कौन इन्हें कार्यान्वित करेगा। समाधान का बुनियादी प्रश्न, जिसकी जवाब मन ऊपर की है, उस समय निराश्वस्त होता है, जबकि नियंत्रण करने के अधिकार पर मतभेद हो। नीतिरक्षाहीन समाधान की प्रवृत्ति समाधान, प्रमाणीकरण और इस भय के नाम पर बिना ठोस या वास्तविक ढंग पर नहीं की जायेंगी, कि निम्नतर सत्ताप्राप्त विच्छेदकारी शक्ति-बैद्ध विवक्षित हो जायेंगे, कि प्रगति बहुत ही धीमी होगी, बहुत कुछ निम्नतम अधिकार हस्तांतरित करने के पक्ष में होगी है। इसी प्रकार, कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। पितृ प्रधान नेतृत्व की ओर एक भक्त प्रेरित प्रवृत्ति भी होती है। नेतृत्व के प्रतीक जिन पर नेतृत्व की प्रतिष्ठा निर्भर करती है, कानांतर से व्यक्ति के अविच्छिन्न भग्न बन जात है। किंतु इन सब के पीछे भावनात्मक प्रीतिता की हम विश्वास को कमो है कि जो बात सभी के हित में है वह सर्वश्रेष्ठ तथा सभी के लिये सदाप्रद है पर केवल सभी को आसपत्ती है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति उसे हासिल करने में हिम्मा ले। जब यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी व्यक्ति का प्रतिपक्ष उच्चतम पद पर है, तो यह तय है कि तब पक्ष कोई व्यक्ति दबा आवश्यक है और उस हानि में सम्मिलित प्रयत्न के भीतर साधु दायित्व या पचावती निराश्वस्तता का तत्व नहीं मिलेगा। जब तक कि उपयुक्त क्षमता साधनों के पारस्परिक विरोध दुस्त नहीं कर लिये जायेंगे, तब तक प्रधान कार्यान्वयन निराश्वस्तता और क्षेत्रीय निराश्वस्तता और प्रशासन के लिए समस्याएँ उत्पन्न करनी ही रहेंगी। कार्य क्षमता को चिन्ता के नाम पर हम हमेशा प्रतियोगिता की गति का उत्पन्न करते रहेंगे, जिससे सत्ता के सम्बन्ध में गलत धारणाएँ पैदा होती रहेंगी, जबकि प्रशासन का काम यही है कि वह इन सत्ता की जनता की सेवा के नाम पर सन्तुष्टि और सहृदयता बनाये रखे। प्रशासन का काम सरकार के नियमित कार्यों को ही सम्पन्न करना नहीं है। उसे अधिक व्यापक सामाजिक काम भी पूरा करना है। सचयन के पक्ष में उसे भावनात्मक, सामाजिक और धार्मिक स्तरों पर अविच्छेद-पूर्ण प्रवृत्तियों को, कम से कम, घटाने, चाहे वह उन्हें पूर्णतः भले ही विनष्ट न कर सके, राज्य की स्थिरता को सुरक्षित रखना पड़ता है, और साथ ही साथ, 'गति', व्यवस्था तथा प्रगति की समस्याओं से सन्तुष्ट पड़ता है। प्रबंध पक्ष में, उसे भाग-दण्डन, समन्वय और नियंत्रण करना पड़ता है। यह प्रतिनिधित्व तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक की सरकारों ताने-बाने का प्रयत्न थागा प्रत्यक्ष होकर काम न करता हो और स्वायत्त से ऊपर उठ कर समाज में उत्साह और सेवा भावना से प्रेरित न हो।



## सत्ता और अधिकार

सत्ता के सम्बन्ध में यह याद रखना भी जरूरी है कि सत्ता के एक पक्ष में प्रान्तरिक सामाजिक नियंत्रण और दूसरे पक्ष में, राज्य में निहित सत्ता होती है। समाज अपने अंगों—यक्ति परिवार, गांव, राज्य और केन्द्र—के माध्यम से कार्य करता है। अतः ग्राम इस क्रियाशीलता का केन्द्र होता है। मुख्यतः शासन और परम्परा पर आधारित बाध्यनीय दृष्टिकोण प्रेरित करके उसे प्रान्तरिक सामाजिक और सामूहिक नियंत्रण का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक सम्बन्धों में व्यवस्था की निश्चित प्रतिष्ठा करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस सम्बन्ध के सन्दर्भ में ही हम डॉ० राधाकृष्णन मुवर्जी के उस कथन का पाठ करना चाहिये जिसका उद्धरण मैं ऊपर दिया है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत प्रशासन को एक अधिक व्यापक उद्देश्य में पूर्ण होना चाहिए, जिसे एक विशेष प्रकार के कार्यों द्वारा पूरा करना समाज और राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। इन कार्यों में से कुछ स्वभावतः सामाजिक कार्य होंगे और शेष प्रशासनिक कार्य। अतः प्रशासनिक स्तर पर पंचायती के सम्मुख पंच सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में नियंत्रण करने के अधिकार बगैर अथवा प्रशासनिक और क्रियाशीलता सम्बन्धी नीतियों के बारे में नियंत्रण करने का अधिकार बगैर सत्ता और कार्यों की बात करना उस एकदम निम्नतम अधिकार की इकार करने के समान है जो पंचायत द्वारा अपनी भूमि का भ्रष्टाचार के लिए आवश्यक है। इस तरह की लड़की या निर्जीव सत्ता से यह अपेक्षा होगी नहीं की जा सकती कि वह उन कार्यों को कामयाबी से पूरा कर लेगी जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। यह कार्य है 'अविवेक' पूर्ण प्रवृत्तियों को दबाना, या 'धार्मिक' और मध्यमस्था की समस्याओं से लड़ना या 'मांग-दशन' सम्बन्धों और नियंत्रण करना। इस प्रारम्भिक अनुविधा से प्रारम्भ करने पर उससे यह अपेक्षा होगी नहीं की जा सकती कि वह 'बाध्यनीय दृष्टिकोण' प्रेरित करेगी या 'प्रान्तरिक नियंत्रण' का विमाण करेगी या सामाजिक सम्बन्धों में निश्चित व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी लगी।

इस पृष्ठ भूमि में चाहिये हम देखें कि आज से २० वर्ष पूर्व गांधी जी ने हरिजन से क्या सिखाया था।

'मैं यह कहता रहा हूँ कि अगर छूतछात का भावना कायम रही तो हिन्दू धर्म का प्रतिष्ठित खतम हो जायगा, उसी तरह मैं कहूँगा कि अगर गाँव बिगड़ गया तो भारत भी नष्ट होकर रहेगा। भारत नहीं रहे जायगा। विश्व में स्वयं उसका अपना भान्ग खतम हो जायगा।'

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देश की भावी रूपरेखा में गांधीजी ग्रामों से किस तरह की भूमिका भेदा करने की अपेक्षा करते थे। सामुदायिक खयालों के भारतीयों की उनके विचार में बहुत ही सीमित विचार था, क्योंकि गांधीजी जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करते थे उसमें उसका सीमित विचार था। सामुदायिक खयालों के भारतीयों की अपनी धारणायें अपनी कल्पनाएँ, यी। वह गाँव के विकास के लिए मर्यादित सब कुछ करने को तैयार था। किन्तु उसके सक्षम का मूल तत्व यह था कि वह देहातों का गहरी-करण करना चाहता था। अतः उसके लिए पंचायत एक छोटी प्रशासनिक इकाई

को—अधिक से अधिक एक छोटी नगरपालिका का प्रारम्भिक रूप। उसने दुबारा मोचने पर गांधीजी को सलाह से संविधान में यह व्यवस्था शामिल करना मजबूर कर लिया।

इतिहास का निर्माण जनता द्वारा होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह भी जनता का स्वरूप निर्माण करता है। इतिहास की प्रत्येक घटना, इस प्रक्रिया में प्राप्त प्रत्येक अनुभव, न सिर्फ कुछ बाहरी परिणाम उत्पन्न करता है बल्कि आम जनता को भावार्थक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। इतिहास के माद अपनी छाप छोड़ जाते हैं और जनता के मस्तिष्क को एक ऐसा मोड़ देते हैं, जो कि उन भौतिक परिणामों की अपेक्षा जिन्हें ऐतिहासिक घटनायें प्रत्यक्ष उत्पन्न करती हैं, अधिक शाश्वत और स्थायी होता है। वे नागरिकों के मस्तिष्क और हृदय के कुछ गुणों को सबल बनाते तथा कुछ को दबा देते हैं, ठीक उतना ही जितना वे कुछ कमजोरियों को बढ़ाते और कुछ को दबा देते हैं। नतीजा यह होता है कि एक विशेष दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। राष्ट्र केवल एक समूह नहीं होता। भारत आज जो कुछ है, वह उन सभी बातों का सम्मिलित रूप है, जो उसे इतिहास से विरासत में मिली हैं और जिन्हें उसने अनुभव किया है।

## एक नवीन चिराट अभियान

भारत ने एक नवीन लम्बा अभियान प्रारम्भ किया है। उसने एक नवीन अभियान खोला है, जो कि न पहला है और न अंतिम। हम अपने भाग्य के भाग का सर्वेक्षण और नक्शा तैयार कर रहे हैं। इसमें मानव प्राणियों के छोटे हिस्से का भाग्य शामिल है जिनमें से ८० फी सदी गांधी में रहते हैं। मशीन या 'यवस्था' एक माध्यम होती है। यह सिर्फ वाहक है—एक साधन। अतः, प्राइमरी, हम इस सवाल पर कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में हम ग्राम पंचायत की कौनसा स्थान देते हैं, एक सन्तुलित नियुक्त करें। मने राष्ट्रीय की निम्न प्रवृत्ति की चर्चा की है। मने ग्राम पंचायत की भूमिका का उल्लेख किया है। जब गांधीजी ने भारत और बिदेस में भारत के आदर्श के जीवित रहने की बात कही थी, तो उनके अभियान में ये दोनों ही बातें थीं।

यह सामान्य तर्क की बात है कि मनुष्य के अनुभव और ज्ञान में प्रत्येक वृद्धि के साथ, चाहे वह सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में हो, उन संस्थाओं में परिवर्तन अवश्य हुआ, जो लोगों के जीवन की अनुशासन करती हैं। किन्तु इसमें एक बात भी है। इस प्रकार परिवर्तन में बढ़े हुए पाल और अनुभव से उत्पन्न शक्ति प्रतिबिम्बित होनी चाहिये। इसका मतलब अनिवार्य रूप में लोगों की सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के आधार को 'पापक बनाना होता है। यदि राजनीतिक और आर्थिक उद्धान के प्रत्येक कदम पर भारत में समाज के जीवन की अनुशासन करने वाली संस्थाओं का आधार व्यापक होता रहता तो गांधीजी को कोई ऐतराज न होता। उन्होंने एक बार कहा था कि

असम्भ्य ग्रामों ने निमित्त इस ढांचे में अनवरत विस्तारशील वृत्त हागे जो कदापि उध्वगामी नहीं होंगे। जीवन एक चिरामि नहीं होगा जिसका गिरावले पर अवलम्बित होता है। उसका घातक तो होगा महासागरीय वृत्त और परिधिओं जो कि उस महासागर की विभाजिता का अग्र हागे, जिसकी वे प्रविष्टिपूर्ण अग्र हैं।

और उन्होंने आगे कहा

‘बाह्यतम परिधि इसलिये सत्ता का उपयोग नहीं करेगी कि वह आन्तरिक वृत्तों को क्षम कर दे, बल्कि उन सभी को शक्ति देगी जो उसके आदर होंगे और उनसे स्वयं शक्ति हासिल करेगी।’

तो, तीसरा दृष्टिकोण है जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह दिखसाना है कि प्राधुनिक विचारधारा भी हम इसी निष्कर्ष तक ले जाती है। इसमें ये अधिकांश, जिनमें मैं भी हूँ के सामने कुछ बाधाएँ हैं। हम अपने आपको, कुछ हद तक ग्रामीण जीवन से बौद्धिक और भावनारमक स्तर पर पृथक समझते रहे हैं। हालांकि शारीरिक स्तर पर हम में से कुछ लोग ग्रामी भी उससे सम्पर्क बनाये हुए हैं। अतः ग्रामीण व्यक्ति के विचारों को समझने में कुछ प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है जो कि निश्चय ही सोचने नहीं। प्रकृति को धूम्रता से घना है। उसका अस्तित्व नये विचारों को ग्रहण कर रहा है, और बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है जसा कि होना स्वाभाविक भी है। वह आजादी के प्रतिफल तथा नया निव और प्राविधिक विकास के सामने मं हिस्सा घटाने में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। उसको प्रकृति भी गहरी हो रही है। अगर भारत की भौतिक स्थितियाँ वर्तमान जसी न होती तो ऐसा होने दिया जाता। किन्तु अस्तित्व का गहरीकरण और जीवन की ग्रामीण परिस्थितियाँ ऐसे तनाव पदा करेंगी, जिन्हें हम मुला नहीं सकते क्योंकि हम चाहते पर भी ऐसी परिस्थितियाँ पदा करने की आशा नहीं कर सकते, जो एक निश्चित समय के भीतर हमारी सभी उचित आशाएँ पूरी कर सकें। अतः इन तनावों पर जो कि एक प्रकार के विस्फोट के रूप में विकसित हो रहे हैं एक सम्भव विचारण यह है कि हम ग्रामीण व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रयास के बड़ ताने धान में मिलाकर बुन लें ताकि वह राष्ट्र के सामने पैदा इस महान् काय में हिस्सा लेने वाले की क्षमता से यह जान सके कि सचमुच यह एक महान् काय है और कोई भी उसे पीछे रहने देना नहीं चाहता। इस उद्देश्य को पूरा करने का एक मात्र सम्भव माध्यम ग्राम पंचायत है।

## आत्मनिर्भरता

दूसरे मिसा भी देश का विकास उन साधना पर निर्भर करता है जिन्हें वह विकास में लगाने सके। एक पट्ट विकसित देश के लिए जो कि अपनी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हो कुछ समय तक दूसरा पर निर्भर रहने की स्थिति से बच पाना मुश्किल है, किन्तु एक सीमा होती है जिससे बाद इस तरह की निर्भरता, अगर उसकी आजादी को नहीं तो कम से कम, सामाजिक और प्राथमिक क्षेत्र में अपनी नीति लागू करने या उसका अनुगमन करने की उसकी स्वतन्त्र इच्छा पर प्रभाव डाल सकती है। वह क्षीमा क्या होगी—यह एक निराश का प्रश्न है। किन्तु पिछले तीन महीनों के दौरान ग्राम सभने एक ऐसा वातावरण देना होगा जिसमें सामान्यतः विवेकशील व्यक्ति भी ‘अस्तित्व के लिए सहायता’ के रूप में सोचने लगे थे, अवशिष्ट उन्हें “अस्तित्व के लिए सर्वोच्च आन्तरिक प्रयास के रूप में सोचना चाहिये था।

पूँजी निवेश का कार्यक्रम जो कि निश्चित जिम्मेदारियाँ पदा करता है देश में ही कुछ प्राधिकारों का, अथवा विदेशी सहायता की उपस्थिति की, बलपना करता है। भारत में हमारे पास इन क प्राधिकारों की कमी है और हमें अनिवार्य रूप से अक्सर दूसरे विकल्प का सहारा लेना पड़ता है हालांकि हम ऐसा स्वेच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों से बाध्य होकर करते हैं। लेकिन इस विचार में उपयुक्त जोखिम भी होता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हम क्या करना चाहिये? मैं ग्रामीण नहीं हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ कि हम अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता के रूप में सोचना शुरू कर देना चाहिये।

इसका मतलब यह हमिज नहीं कि हम बड़े पमाने के स्तरीयों पर पूजी लगाना बंद कर देंगे। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम किसी ऐसे काय के रूप में साधने ही नहीं जिसमें विदेशी विनिमय की जबरत होगी। जहाँ तब में ऐल सगता हूँ उन योजनाओं को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में विदेशी विनिमय की जरूरत होगी, जिन्हें हम पहले से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम अपनी पूजी का कोई भी बंद कर रखना नहीं चाहते। तब, फिर भी विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपने देश के आन्तरिक साधनों के अधिक उपयोग के रूप में सोच रहा हूँ। हमारे पास मानव शक्ति का अपार अग्रगुण साधन पड़ा हुआ है। हमारे पास दूसरे भी साधन बनी मात्रा में बिलर पड़े हैं जिनका उपयोग हम अभी तक इसलिए नहीं कर सके हैं कि हम ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। मेरा खयाल है कि जब गांधीजी ने आधुनिकता को धर्मोपनिषद् धर्मोपनिषद् के पक्ष पर जोर दिया था, तो उनके विचार के पीछे अग्रगुण बिलर साधन और बेकार या अग्र-बेकार बिल्कुल अग्रगुण सम्भाव्यता वाली अपार मानव शक्ति ही थी। इनका उपयोग राष्ट्रीय और राज्य सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि वे एक दूरी से काय करती हैं और ऐसा करने में काफी विस्तारपूर्ण ध्यान देने की जरूरत होगी है।

## साधनों की प्रचुरता

बिलर हुए साधनों की विभिन्नता मुख्यतः पत्तों तथा धातु के तैलीय पदार्थों से बनी साधन के द्वारा से लेकर जन मानस के आधुनिक साधनों तक फैली हुई है। उपयोग में लाये जाने वाले साधनों का एक बड़ा भंडार हमारे पास है, किसी न किसी को उसे इस्तेमाल में लाना ही होगा। यह काय केवल धाम पचायतों ही कर सकती है। जब तक सारा देश ग्राम्य जीवन के मूल्यों को भारतीय स्वराज्य की हमारा लक्ष्य बनाने में आधारभूत भावना के रूप में अपना नहीं लेता, तब तक क्या वे ऐसा करने में दिलचस्पी लियेंगे? यदि भारत के ग्रामीण समुदायों में निहित शक्ति का अधिकतम उपयोग करता है तो हम यह मानना पड़ेगा कि हमें एक दीर्घकाल तक गांधी पर आधारित रहना होगा, हम जीवन में ऐसे सुधारों को बर्बाद नहीं कर सकते जोकि ग्राम्यजीवन से टूटकारा पाना चाहते हैं।

तब सहकारी, सामाजिक व आर्थिक क्रांति में गांधी एक सम्भव बन जाता है, उनके लिये ऐसा बनना सम्भव नहीं है, जब तक कि इस आवश्यकता शुरूआत या विकास करने के जरूरी अवसर प्रदान नहीं दिये जाते तथा इसे अनिवार्य आवश्यकताओं, जैसे सहूलियतों, प्राविधिक सहायता, वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्ति उपलब्ध नहीं की जाती। आजीविकाप्राप्त करने वाले और धनीप्राप्त करने वाले सहायक शक्ति, इन दोनों में अंतर है। एक उपासक है, और दूसरा शोषित। गांधी को स्तर और शक्ति, दोनों ही तरफ अपने आपको ऊपर उठाना है। इसे पुनः शक्तिवान बनाना होगा ताकि यह राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक सम्मान का प्रतिम आधार बन सके।

मन्त्र, गांधीजी ने ससार की परिस्थितियों के सन्दर्भ में भारत की विचार देने के बारे में लिखा था। केवल मही सञ्चालित जीवन रहने की धारणा कर सकती है जिनका लक्ष्य मानवजाती का सम्पूर्ण विकास करना हो, और इस विकास का माध्यम हर प्रकार के विचार और मता के प्रति सहिष्णुता हो। अभी कुछ ही समय पूर्व तक भारत का प्रत्येक ग्राम स्वयंसाहाय्यता सहकारिता और पंचायत के दान था प्रतीक रहा है। हमारा लक्ष्य इस पुनर्जीवित करना है। इसके पुनर्स्थापन के साथ ही सारे मसले को पुनः

स्पष्ट रूप से समझ लेना है, जिस दानात्मिक और प्राविधिक युग में हम रह रहे हैं, उसकी यह मांग है। सामाजिक रूप से समन्वित जाति ही इस उत्तरदायित्व को निभा सकती है। इस प्रकार के अभिप्राय के लिए हम गांधी की जनता को एक बड़ी इकाई के अंश के रूप में सामाजिक, आर्थिक तथा भ्रष्टाचारों से मुक्त स्थानीय उपलब्ध साधनों से और उनकी अपनी पसन्द द्वारा विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराने चाहियें। हम इस बात की उचित ही आशा कर सकते हैं कि इस प्रकार के सम्मानयुक्त रचनात्मक प्रयत्न द्वारा अपनी अभियानित करने पर वे एक समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त कर लेंगे। जनतन्त्र केवल अस्वास्थ्यपूर्ण आधिकार का ही शासन नहीं होता। यह तो बाह्य और अस्वास्थ्यपूर्ण द्वारा अष्ट हुए बिना सम्पूर्ण समाज की आकांक्षाओं और कार्यों की अभिव्यक्ति है जिसका परिणाम रचनात्मक प्रयत्न में भाग लेने इससे पूर्व उसके आयोजन में भाग लेने, और अंत में उससे प्राप्तियों के बराबर वितरण करने से हुई सन्तुष्टि में होता है। जब तक इस भावना का अभाव रहेगा तब तक प्रशासनिक या विचार सम्बंधी कार्यों में शारीरिक प्रयत्न चाहे जिसकी भी मात्रा में किया जाय, जनतन्त्र में हमारा यह तबुर्बा गहरी नींव नहीं पक्का करेगा। हम इसी प्रकार विश्व शान्ति और विश्व-जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने में भाग लेना चाहते हैं।

हम जो भी कामकाज या स्वीकृत बनाते हैं, उसे इन मूलभूत सध्यों को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिये, न कि इनके रास्ते में रुकावट डालें।

## आदर्श पंचायत प्रशासन

ग्राम्य ढाँचे की जिस धारणा का उल्लेख मैंने ऊपर किया है उससे पंचायत प्रशासन की धारणा पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ना चाहिये। यह केवल ऐसा अधिवारी नहीं होगा जो कि परिधि पर काम कर रहा हो। यह राज्य के प्रशासनिक ढाँचे का विकेंद्रित अंश भी नहीं होगा। इसे जीवन के विविध मूल्यों के आधार पर नयी सामाजिक व्यवस्था की नींव बनना है। इसे शान्तिमय सामाजिक आति का एक प्रभावपूर्ण प्रोजेक्ट बन कर कार्य करना है। इसे राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रिकरण का माध्यम बनना है। इसकी समन्वित जनतन्त्र का एक ममूना बनना है। और यह सभी कुछ इसे एक विविध रचनात्मक दृष्टिकोण द्वारा ही प्राप्त करना है।

म अच्छी तरह समझता हूँ कि मैंने जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह फौरन ही कार्योचित नहीं दिया जा सकता। गांधीजी न भी कहा था —

मुझ पर यह ताना बसा जा सकता है कि यह सब अत्यन्त कल्पनाजय है, और इसलिए इसका मूल्य भी विचार के बराबर नहीं। यदि यूनिट का बिंदु जिस अंकित करना किसी भी मानव के लिए असम्भव था आवश्यक महत्व रखता है तो मैं जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका भी मानवता के अस्तित्व के लिए अपना आवश्यक महत्व है। भारत इस सच्चे चित्र के लिए कार्यरत रहे, हालांकि यह पूर्ण रूप में अज्ञात हासिल नहीं किया जा सकता। इसके पहले कि हम अपनी आकांक्षा जसा चित्र उपलब्ध कर सके हमारे सामने जो कुछ हम चाहते हैं, उसका सही चित्र होना ही चाहिए। यदि भारत के अनेक ग्राम जो लोकतन्त्र बनना है तो मैं अपने आदर्श के अभाव का दावा करूँगा, जिसमें अन्तिम का महत्व प्रथम के समान ही है, या अर्थ श' में, किसी को भी न प्रथम होना है न अन्तिम।'

लोगों को चेतना के विवास और उनके बीच एक सामाय विस्म के नेतृत्व के विवास के साथ-साथ इस प्रकार के प्रयोग को भी विकसित होना चाहिये। पश्चिमी विस्म का चुनाव स्वयं गन्ती करने और सुधारन की सच्ची प्रशिक्षा का अन्तिम स्वरूप है। गावा में पायी जाने वाली चेतना को दमस्त हुए हम यह कह सकते हैं कि इसे इसके प्रतिरिक्त गणितीय महत्व के अभाव में प्रशिक्षा सम्भवा नहीं जा सकती। गाव की जनसंख्या तो घटती रही, हममें से भी चित्तों को अभी लोकतन्त्र का यह पहलू समझना है। अन्त गावों के लोगों के लिए इसे समझना कितना ज्यादा कठिन होगा। मैं न प्रयत्न कहा था —

“अतः अन्तर्गत द्वारा जनता के प्राप्ति सम्भव को विच्छिन्न होने नहीं दिया जा सकता। अपनी कही मानसिक सीमाओं के कारण राजनीतिक दल, कम से कम वर्तमान परिस्थिति में, सामाजिक विनय और एकीकरण की इस दुनियादी आवश्यकता को तिलाज्जिन दिये बगैर, तथा सामुदायिक अस्तित्व की प्रशिक्षा को सति पहुँचाये बगैर श्रियाशील ही नहीं हो सकते। अतः मैं जिना हिचक कह सकता हूँ कि अन्तों के आधार पर होने वाले चुनाव गावों की जनता के प्रति की गई सब से बुरी सेवा सिद्ध होगी।

प्रो जी डी एच कोन ने पेरिस कौंसिल की दलगत राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा है —

‘यदि हमारा दल चुनाव में पेरिस कौंसिल की सभी जगहों पर सफलता हासिल कर ले, तो पेरिस कौंसिल सायद ही अच्छी तरह कार्य कर सके। इसके लिये समूचे रूप से स्थानीय सामुदायिक सरकार के स्वरूप का प्रतिबिम्बित करना तथा अपने सदस्यों में, उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहकारिता का संगठन करना बेहद जरूरी है।’

मैं इस तरह के चुनावों के विरुद्ध बर्धानिक रोक लगाने का अनुरोध करने की सीमा तय माना चाहूँगा।

मैं ने उस समय यह भी कहा था —

हालांकि चुनाव जनता की इच्छा का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता कि इच्छा का मूल्यांकन किम तरह किया जाय, न कि कोई विशेष तरीका। अतः मैं जनता कि इच्छा का निश्चय करने के इस सवाल के मौलिक समाधान पर जोर दूँगा। अगर हम गावों में एकता कायम रखने पर जोर देते हैं तो हम अभी भी हर गाव में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जिनमें आम समान अपना विश्वास दृढ़ रखने के लिये तैयार होगा। जरूरत है ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कि ग्रामीण जनता के विचारों और प्रचलित धाराओं को अच्छी तरह समझने हों, न कि सिर्फ चुनाव सम्भवों का मूल्यांकन की प्राविधिक गणित को ही सन्तुष्ट करते हों।’

निम्नदेह, मनन का मतलब सत प्रतिगत एकता नहीं होता है। यदि पचायत को अपनी भारी जिम्मेदारियाँ निभाना हैं, तो गाव के वासिन्दा का उसके साथ रहना साजिमी है। प्रत्यक्षा उल्लेख काशी समय और शक्ति मण्डे और विद्वेष में ही बीन जायगा। अन्तिम रूप में परिणाम विचित्रता और असंतोष होगा। इस हासत में हम वैयक्तिक तथा दलगत भावनाओं की वेदी पर महान् और विनाश लक्ष्य को प्राप्ति चढ़ा देंगे और एक गन्दे विस्म का नेतृत्व उत्पन्न करेंगे जो कि दोष आवश्यक गुणों की भी धूस सेवा।

## एकता की सफलता

इस दलील का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है कि ग्रामी म मौजूद पूट के बीच एकता कैसे हासिल की जा सकती है। सोराष्ट्र का उदाहरण देकर मैं केवल अपनी प्रमाणिकता प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन, इसके अलावा, मैं ग्रामीण की अनिवाद्य बुद्धिमत्ता में अपने विश्वास को मिटा नहीं सकता। यदि उचित ढंग से उन तक पहुँचा जाय और उन व्यक्तिगतों द्वारा जिनमें व विश्वास रखते हैं, तो वे विवेक और बुद्धिमत्ता की आवाज को सुनेंगे। शांतिपूर्ण, सतुष्ट और लाभप्रद अस्तित्व के लिये प्रेम उनके हृदयों पर प्रसर करता है और उनके विचारों पर शासन करता है।

मैं भी पंचायतों के वर्गीकरण के पक्ष में रहा हूँ। जैसे-जैसे वे अधिक अनुभवशील और परिपक्व होती जाय, उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्थान प्रदान किया जाय। इस सिद्धांत में भी प्रयत्न किया गया और सोराष्ट्र में यह सफल साधित हुआ। 'स' श्रेणी की पंचायतें सामान्य स्वच्छता तथा ग्राम काय सम्पन्न करती हैं। 'ब' श्रेणी की पंचायतें राज्य का सरकारी बकाया वसूल करती हैं, जिसमें मालगुजारी तथा छोटे तथा बड़े ऋणों के अनुदान भी शामिल हैं तथा पटवारी या सखिल निरीक्षकों के ग्राम काय करती हैं। 'घ' श्रेणी की पंचायतों पर ग्राम सम्बंधी कार्यों का भार है। जिस अनुपात से वे काय सम्पन्न करती हैं उसी अनुपात से सरकारों का अनुदान में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से 'ब' श्रेणी की पंचायतों तक पहुँचने के लिये 'स' श्रेणी की पंचायतों से दो बरस लगते हैं और एक या दो से अधिक 'ब' श्रेणी की पंचायतों को 'घ' श्रेणी तक पहुँचने के लिए। मेरा ऐसा विचार है कि ग्रामीण की उत्तरदायित्व की दृष्टि से केवल उसी हद तक प्रभावित किया जा सकता है जिस सीमा तक राज्य के नृत्व में पंचायत की जिम्मेदारी हस्तान्तरित करने का उद्योग होता है। यह तथ्य कि सरकार वास्तविक उचित तथा बहुमत सम्भव अधिकार हस्तान्तरित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा है, पंचायतों को प्रभावपूर्ण बनाने तथा उससे श्रेष्ठतम प्राप्त करने में बहुत प्रभावकारी रहा है।

ग्रामीण प्रशासन लोगों के निवृत्ततम रह कर ही काय करता है। उसमें अधिकार या सत्ता के अनावदी रोह को बनाने या भय पैदा करने की कोई गुंजायमी नहीं जो कि मंत्रियों या अधिकारियों में है। ग्रामीण लोगों तथा ग्रामीण नेतृत्व दोनों के हित में निरंकुश शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि उन्हें स्वीकार करने की जरूरत पड़ सकती है। एवमात्र प्रभावपूर्ण तरीका समझाना बुझाना तथा हृदय परिवर्तन ही हो सकता है। उचित ढंग से भीष्म ने एक नये सहयोगी तथा सम्य तरीके के मूल्यों के प्रति बफादारी पदा करना है। ग्राम पंचायत की सामाजिक शिक्षा तथा सामूहिक जीवन का तथा उससे लिए अवसर प्रदान करने का माध्यम बनना चाहिए।

गांव की पुलिस के प्रबंध से भर देन की गुंजायमी नहीं। भ्रान्तिक या आत्म समय एक गांव का सामाजिक जीवन में एवमात्र सुरक्षा यंत्र है। एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र में भी लोगों को अपने पूर्वजों की आस्था से शिक्षा ग्रहण करने और अपने बच्चों के चरित्र के लिये बुनियाद तयार करने की गुंजायमी है। हम धर्म का भजाव नहीं उठा सकते। ग्रामीण स्तर पर धर्म कम से कम विविधता या उथल-पुथल मचायेगा।

## पंचायतों के कार्य

पंचायत के कार्यों को अच्छी तरह बताया जाना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में योजना आयोग ने यही बताने का प्रयत्न किया है। उनमें कार्यों को दो व्यापक वर्गों में बांट दिया है, जैसे प्रशासनिक तथा 'याय' सम्बन्धी। 'याय' सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत नागरिक तथा आपराधिक न्याय का प्रशासन, श्रम कानून, खास तौर से कृषि मजदूरों में न्यूनतम वेतन का अधिनियम तथा भूमि से सम्बन्धित साधारण भग्नों में उनका लागू किया जाना आता है। प्रशासनिक कार्यों में नागरिक कानून तथा भूमि व्यवस्था तथा विकास सम्बन्धी कार्य शामिल हैं। नागरिक कार्यों में ग्रामीण स्वच्छता, देव रेख तथा जन्म और मृत्यु के लेखन कार्य आते हैं। देव रेख सम्बन्धी कार्य गांव के बड़ों द्वारा सम्पादित होने चाहिए। एक पंचायत के 'याय' सम्बन्धी अधिकार उनके न्याय और प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। मालगुजारी का सग्रह तथा उसका सदुपयोग और 'याय' पंचायत से लोगों पर उसका आवश्यक प्रभाव आयेगा। अध्याय ३ के अनुच्छेद १२ में इस पर विस्तारपूर्वक विचार करते हुए योजना आयोग ने इन बातों की व्यवस्था की है।

- ( अ ) भूमि-सुधार लागू करने में पंचायतों का सहयोग;
- ( ब ) भूमि के उपयोग का नियमन, और खास तौर पर प्रतिमान, अच्छे प्रबंध और कृषि के तरीके अपनाना
- ( स ) खेती और गांव में उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित करना,
- ( द ) सहकारिता और सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना,
- ( य ) कुटीर, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, तथा
- ( र ) संप्रभु रूप में योजना कार्यान्वित करने के लिये जनता के सहयोग का उपयोग।

इन सम्बन्ध में, स्वभावतः हम अपना ध्यान राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजनाओं की ओर ले जा सकते हैं। निस्संदेह यह भूतकालीन विचारधारा के भागे बड़ा हुआ कदम है। भारत की गरीबी और उसके निश्चयेपन की प्रत्यक्ष वास्तविकता से जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिखलाई पड़ती है, यह बात जरूरी हो जाती है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास किये जाय जिनके द्वारा देश की ग्रामीण जनता का इस बात के लिए आह्वान किया जा सके कि वह देश के जीवन के भावतात्मक, सांस्कृतिक और उत्थान के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करे।

## वित्त और कर्मचारी

प्रशासन के सन्दर्भ में जिस समस्या पर विचार करना सही है, वह वित्त और कर्मचारियों से सम्बद्ध है। यह सही है कि राज्य सरकारों के पास धन की कमी है। मने ऊपर यह बताया है कि ग्रामीणों को धन के प्रत्यावा ऐसे बहुत से साधन गांवों में खोज बिखरे पड़े हैं जिनका उपयोग नहीं हो सका है। इस समय जरूरत यह है कि इस तरह बिखरे मानव शक्ति और भौतिक साधनों का उपयोग किया जाय। प्रशासनिक क्षमता की कमी इस मामले की सफ़ाता का साथ हल करने में निहित है। इन सन्दर्भ में धन-पर विचारणीय हो सकता है जिसकी क्षमताओं के सम्बन्ध में यह स्वेच्छा हो कि उसे चाहे नए ढंगों से दिया जाय या धन का बहुत से रूप में। १० करोड़ प्रोजेक्ट जनसंख्या एक साल में २४ दिन के धन



की दर पर ( जो कि पुराने जमाने में प्रचलित था ) थम के रूप में १०० करोड़ रुपये प्रदान कर सकती है वरतें कि एक दिन के थम का मूल्य आठ आना हो । इससे, और उन साधनों का उपयोग कर जो कि बेकार पड़े हुए हैं या बर्बाद हो रहे हैं, जिनमें बेकार जमीनें और जंगल वन, घाट भी शामिल हैं, काफी मात्रा में पूँजी का निर्माण हो सकता है । हो सकता है कि भ्रष्ट-शासनावादी होऊँ लेकिन भ्रष्ट निराशावादी की उत्तर देना है । हम अभी शुरुआत भर कर सकते हैं । इसके बाद कार्यकर्ताओं का सवाल आता है जिनमें पंचायतों से सम्बद्ध सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के कार्यकर्ता शामिल हैं । जब तक कि पंचायतों की समस्या और सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच वह भावनात्मक सदभावना न होगी, तब तक हम आसानी से साथ तरक्की करने की आशा नहीं कर सकते । मने ऊपर उस क्षण में उपलब्ध एक प्रकार की ऐसी अच्छी सरकारी या गैर-सरकारी व्यवस्था की स्थापना की जरूरत का सुझाव दिया है जो कि नियंत्रण करने या आदेश देने की बजाय ग्राम पंचायत की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो जहाँ प्रशिक्षण करना उचित हो, और हमेशा उसके मांग के वाक्य तर्कों को दूर करने से सम्बद्ध उसकी जिम्मेदारियाँ में हाथ बटाने के लिए सहायता करने को तैयार भी । हमें निराशा का त्याग कर देना चाहिये । हम उसका आलोचक नहीं होना चाहिये । ग्राम भारत की भाषा है । हमें स्वयं आशावादी बनकर आशा उत्पन्न करने की गिरावट सेना होगी ।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों का पारस्परिक सम्बन्ध है । यदि ग्राम पंचायतों को राष्ट्र के समूचे ढाँचे का अंग मानना है, यदि उसे राष्ट्रीय उन्नति के लिए किये गये कुल प्रयत्नों में हिस्सेदार समझना है, तो संपर्क या समानांतर न्यायोचितता का सवाल ही नहीं उठता । अन्त में, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की समस्या भी है । हमें मानना पड़ेगा कि वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली बेकार सी है । भारत अभी भी रहता है । अंत में प्रशिक्षण में इस सत्यता को प्रतिबिम्बित होना है तो प्रशिक्षण का कार्य स्कूल से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए । अथवा स्कूल स्तर पर युवकों को इस दिशा में कुछ प्रशिक्षण मिलने लगे तो ग्राम पंचायतों की आवश्यकताएँ थोड़ा दृढ़ रूप पर पूरी हो सकती हैं ।

( २६ नवंबर १९५७ को पटना विश्वविद्यालय के 'इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में किया गया भाषण )



# पंचायती राज के लिए श्री बलवंतराय मेहता कमेटी की प्रारंभिक सिफारिशें

धारा १

## मूल धारणा व लक्ष्य प्राप्ति

ग्रामिक विकास के पहलुओं पर अति शीघ्र अधिक ध्यान दिया जाकर कार्यक्रम के विभिन्न अंगों में प्राथमिकता की दृष्टि से हस्तगत करना चाहिये जैसे जन विउदण, कृषि की प्रगति, पशुपालन, सहकारी प्रतिविधियाँ ग्रामोद्योग तथा स्वास्थ्य आदि ।

धारा २

## लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

सरकार को कुछ कार्यों में जिम्मेदारियों से अपने आपको पूर्णतः भलग मानकर कार्यक्रमों का बाधित एक ऐसी सत्ता को सौंप देना चाहिये जिस पर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का पूरा जिम्मा हो और अपने आपको निर्देशन, निरीक्षण और आयोजन के कार्यों तक सीमित रखना चाहिए ।

ब्लॉक के स्तर पर एक ऐसी स्वचासित सत्ता का गठन किया जाये जिसका कार्यक्रम विकास ब्लॉक से जुड़ा हुआ हो ।

ग्राम पंचायतों से अल्पवयस्स चुनावों द्वारा एक पंचायत समिति का निर्माण हो ।

ब्लॉक के क्षेत्र की नगर पालिकाओं अपने सदस्यों में से एक को पंचायत समिति का सदस्य चुने । राज्य सरकारें ग्राम नगरपालिकाओं को पंचायतों में परिवर्तन करें ।

जिस 'लाक' के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय सहकारी संघटन अधिक महत्वपूर्ण हों वहाँ निर्वाचित स्थानों के १० प्र० व १० स्थान निर्वाचित अथवा नियुक्तियाँ द्वारा सहकारी समितियों के डायरेक्टरों से भरे जाने चाहिये । समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का हो और पंचवर्षीय योजना के समय के तीसरे वर्ष में इसका गठन हो ।

पंचायत समिति के कार्य कृषि के हर अंग का विकास पशुपालन में प्रगति, स्थानीय उद्योगों का बढ़ावा, जन स्वास्थ्य, कल्याणकारी कार्य, ग्रामिक पाठशालाओं का संचालन तथा मानकों के सग्रह आदि

हों। समिति राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई विकास सम्बंधी योजनाओं को काय रूप में परिणित करने में उसके प्रतिनिधि के रूप में भी काम करें।

जब पंचायत समितियाँ प्रजातांत्रिक पद्धति पर दखता पूरा काम करना शुरू कर दे तो उन्हें प्राप्ति जावर और भी काम सौंपे जाने चाहिये।

पंचायत समिति को निम्नलिखित कामदनी के साधन प्रदान किये जाने चाहिए।

- (१) 'लाक' के क्षेत्र के बाहर से आने वाले भू राजस्व का कुछ प्रतिशत।
- (२) 'यवसाया' पर कर।
- (३) स्थायी सम्पत्ति लेने देने पर कर।
- (४) स्थानीय संपत्ति से आने वाला साम व किराया।
- (५) यात्रा कर, मनोरंजन कर।
- (६) मैले व बाजारों से बमूल होने वाला कर।
- (७) मोटर गाड़ियाँ पर लगे कर का कुछ भाग।
- (८) स्वेच्छित जन सहायता।
- (९) सरकारी सहायता।

प्राथमिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार समितियों को शर्तों पर व बिना शर्तों के प्राथमिक सहायता प्रदान करे।

'लाक' के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य कोष का व्यय पंचायत समिति द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हो परन्तु समिति की सिकारिश पर सीधे ही किसी सस्था को भी व्यय का अधिकार दिया जा सकता है।

समिति के प्राथमिक अधिकारी जिला अधिकारी के प्राथमिक नियंत्रण में रहे लेकिन उन पर प्रशासनिक नियंत्रण समिति के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का हो।

समिति का प्राथमिक बजट जिला परिषद् द्वारा मान्य हो।

समिति पर कुछ नियंत्रण आवश्यक रूप से सरकार का हो तथा जन हित के मामलों में पंचायत समिति में निहित शक्ति पर नियंत्रण।

पंचायत या सविधान निर्वाचन पर आधारित हो जिनमें दो महिला सदस्याओं तथा अनुसूचित व जन जातियों के एक-एक सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था हो। इनसे मिलाया किसी वग को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जावे।

पंचायत की प्रायः के मुख्य स्रोत आवास कर, बाजार व सवारी कर, अश्वत्थ या टरमीनल कर, जल व विद्युत की दरें, पशुपाक पानी पिलाने के ताखास के कर, पंचायत समिति द्वारा दिया गया अनुदान तथा पशुओं की बिनी कर।

ग्राम पंचायतों का उन्मोह भू राजस्व संग्रह करने के लिये किया जाये जिसे राजस्व का कुछ हिस्सा वसुधैव कुटुम्बक के तौर पर दिया जाये । उपरोक्त काम के लिये उन्हें पंचायतों को उपयुक्त माना जाय जो प्रशासन व विकास क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर चुकी हों और उन्हें ही यह अधिकार प्रदान किया जाये ।

ग्राम पंचायतों पंचायत समिति से भू राजस्व का निर्धारित भाग प्राप्त करें ।

ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय रूप से जुटाये गये ग्राम के साधन जो भव निगरानी व सुरक्षा व भवचारिता पर खर्च किये गये हैं व भविष्य में विकास कार्यों पर व्यय किये जायें ।

जो व्यक्ति एक वर्ष तक बर भदा न करे उसे नियमानुसार आगामी पंचायत व चुनावों में भाग लेने से वंचित रखा जाये और यदि ऐसा व्यक्ति पंचायत का सदस्य हो जा ६ महीने तक बर भदा न करे उस भी उपरोक्त नियमानुसार उतना ही जिम्मेवार ठहराया जाने और उपरोक्त आधेनार से वंचित किया जाय ।

ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति की जाच व भायता पर आधारित होगा । समिति का प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत पर उपरोक्त विषयक उन सभी अधिकारों का उपभोग करेगा जो पंचायत समिति पर जिलाधीन करेगा । ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में केवल राज्य सरकार ही जिला परिषद् की सफारिशों के आधार पर हस्तक्षेप कर सकेगी ।

ग्राम पंचायतों के और कार्यों के साथ भविष्य काय हूँगे, जल विवरण सफाई, रोडनी, सड़क की समान भूमि प्रबंध, बाकड़ों व रेकॉर्ड का संग्रह व सामूहिक प्रबंध तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि । इसके साथ ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति द्वारा निमित्त किसी योजना को कार्यान्वित करने में उसका प्रतिनिधित्व करेगी ।

पंचायत का ग्राम क्षेत्र एक ग्राम सेवक के क्षेत्र से अधिक बड़ा भी हो सकता है जिसमें ग्राम कार्य के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित सूची में से सब डिवीजनल अधिकारी या जिलाधीन ऐसे लोगों को चुन जो पंचायत का ग्राम क्षेत्र समाल सके हैं ।

पंचायत समितियों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक जिला परिषद् का गठन किया जाये जिसके सदस्य समितियों के अध्यक्ष तथा उस क्षेत्र के विधान सभाई व सदस्य और जिला स्तर के अधिकारी हों । इस जिला परिषद् का चयरमेन वहाँ का कलक्टर हो तथा उससे भवोन कई भी अधिकारी उसका सभाई हों ।

यदि हमें प्रजातांत्रिक विवेकीकरण के अनुभव के दृष्टि से दृष्टि परिलक्ष्य निदान है तो यह भावश्यक है कि हमारी इस क्रमबद्ध योजना की तीना उपरोक्त समितियों का यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का गठन किया जाये साथ ही त्रयश पूरे जिले में यह योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये ।

स्थानीय समस्याओं के लिये निर्वाचित या निर्वाचित होने के उम्मीदवार लोगों के लिये प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस मूल भावना का किसी भी माध्यम में उद्देश्य प्राप्त हो सके जो अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है ।

धारा—तीन

## कार्य-पद्धति आयोजन-कार्यक्रम

आयोजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में ऐसे समय जब कि राज्यों ने विस्तृत लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं सुरक्षा व आर्थिक समुत्पन्न तथा प्राविधिक व निरक्षरता को सम्भव सहायता प्रदान की जानी चाहिए और यह काम जनता के प्रतिनिधियों को सौंपा जाना चाहिए जो इसको विस्तारपूर्वक विचार व मन्त्रिणा की सहायता से पूरा करें।

बजट का विस्तार पूर्वक विभाजन व बंट द्वारा निर्धारित हो। इस योजना के अनुसार हर राज्य अपने योजनाबद्ध बजट को केन्द्रीय मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद निश्चित करे।

जिला व ब्लॉक स्तर के स्थानीय प्रतिनिधि सभाओं को निर्धारित कार्य के पहलुओं को प्राथमिकताओं तथा कुछ निम्न शक्त व निषेधात्मक सिद्धांतों के आधार पर कार्यक्रम में परिणित करना चाहिए।

धारा—चार

## केन्द्रीय व राज्य-सरकार में परस्पर समन्वय

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकार विषयक कार्यों में आर्थिक, उच्च स्तरीय लोच कार्य व उच्च प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायताएँ प्रदान करे तथा इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता पर नियन्त्रण रखे क्योंकि राज्य सरकारें स्वयं ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर एक देश-व्यापी विभिन्न राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाएँ क्रियात्मक की जानी चाहिए।

जहाँ केन्द्रीय सरकार को कोई देश-व्यापी नई योजना प्रारम्भ करनी हो वह राज्य सरकारों को विस्तृत रूप से सलाह दे और उन्हें उसे कार्यक्रम में परिणित करने दे यदि वे चाहे तो कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ भी।

धारा—पाँच

## प्रशासनिक ढाँचा-राज्य के अन्दर समन्वयता

ग्रामसेवकों के कार्य-क्षेत्र को कम किया जाये तथा हर ब्लॉक में २० ग्राम सेवक और बढ़ाये जायें।

धारा—सात

## महिलाओं व बच्चों के बीच कार्य

महिला-सत्याग्रह के कार्य व मोर्चा देश-व्यापी स्तर पर एक ही दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए। इन कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सलाहकार केन्द्र व वित्तीय एजेंसियों की हो।

विभिन्न सत्रों के लिये युष्मा रहित उपयोगी चूल्हा का निर्माण किया जाये, न कि सारे देश के लिये एक ही प्रकार के चूल्हे हों ?

ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण कक्षा में सफाई के सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक ध्यान न दिया जाकर रोजमर्रा की दिनचर्या में तत्सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाये।

ग्राम महिला कार्यक्रमों को ग्रामीण महिलाओं के प्रति दिन के कार्य जैसे पशु पालन, रसोई उद्यान व भूगर्भी पालन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

ग्रामीण व अग्र ग्रामीण क्षेत्रों के दसवीं कक्षा पास अध्यापकों में से ग्राम सेविका की भरती की जानी चाहिए।

महिलाओं व बच्चों में स्वास्थ्यकारी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले वार्षिकी स्थायी रूप से नियुक्त किये जायें।

द्वारा आठ

## जातीय क्षेत्रों में कार्य

अस क्षेत्रों के आबादी की भाँति जातीय क्षेत्रों की भाँति जातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये ६ मंथ के लिये बजट बनाया जाये।

लाक का बजट बनाने से पूर्व उस क्षेत्र का सर्वेक्षण व गहन अध्ययन किया जाना चाहिये।

जातियों के बारे में जानकारी व सहानुभूति रखने वाले स्थानीय लोगों को जातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाना चाहिए।

इस कार्य के लिये छाटे गये व्यक्तियों को इन क्षेत्रों की स्थानीय भाषा, रीति रिवाज तथा वहाँ के निवासियों के जीवन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।

सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए कृषि श्रम देने की विचार में बंदन चठाने चाहिए।

इन क्षेत्रों में शिक्षा की मूल पद्धति प्रारम्भ की जानी चाहिए ताकि शिक्षितों व अशिक्षितों के बीच की खाई दिनों दिन पटती जाये।

द्वारा ग्यारह

## कृषि कार्य

अधिक उत्पादन के निधारित लक्ष्य ज्ञान व ग्राम सेवक क्षेत्रों के सम्मुख होने चाहिए।

कमलों के लिए सिंचाई की प्रगति की जानी चाहिए।

ग्राम सेवकों को नये व विकसित प्रदर्शन करके कम से कम हर ग्राम में ५ प्रदर्शन करने चाहियें जो गावों में प्रचलित तरीकों से भिन्न हों।

जिला कृषि अधिकारी कृषि के नये उपकरणों का ज्ञान प्रदान करने के निमित्त ग्राम सेवकों के लिए मूल जालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

सहायता के सहकारी संस्थाओं को कृषि के उपकरणों की खरीद, बेचान व किराये पर देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फलों व सब्जियों के अधिक उत्पादन की दिशा में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

फलों की सुरक्षित रखने के बतमान तरीके अधिक आसान व सस्ते बनाये जाने चाहिये।

सिंचाई के लिए बिजली वितरण की दूर औद्योगिक बिजली वितरण की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे क्षेत्र जहाँ घान की पदावार होती है उनका विकास होना चाहिए।

बस्ती व शहरों में दुग्ध सहकारी समितियाँ सहो लपरेखा के आधार पर बनाई जायें।

घरों की नस्ल के विकास के लिए प्राविधिक निदेशनों की आवश्यकता है।

मछली उद्योग के लिए अधिक आर्थिक सहायता व प्रशासन द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सुगमता पर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में।

धारा बारह

सहकारी

एक व एक से अधिक गाँवों के बीच में बहुत उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण हो जो स्थानीय या पषायता की सहायता से सही आधार पर कार्य करें।

आवश्यकता के समय किसान को ऋण देने की व्यवस्था के साथ ही उसे ऐसी सहायता प्रदान की जायें कि वह फसल के समय ऋण की अदायगी कर सके।

सहकारी कृषि पद्धति को पहले अपने प्रथम अनुभवों से गुजरने दिया जाना चाहिए ताकि तुरन्त ही चुने हुए सामुदायिक विकास योजनाओं के हर बिन्दु में एक सहकारी कृषि क्षेत्र का निर्माण किया जायें।

हाइस्कूलों में पाठ्यक्रम की पुस्तकें व स्टेशनरी के वितरण के लिए विद्यापिठा द्वारा सहकारी समितियों का निर्माण किया जाना चाहिये।

धारा तेरह

ग्रामोद्योग

कुटीर, ग्राम व संप्रु उद्योगों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाय ताकि वे एक दूसरे के पोषक बन सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सत्सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें।

जिला क्षेत्र या उसके एक भाग के ग्रामोद्योगों के लिये प्राथमिक सहायकार हों जिन पर उस उद्योग का विकास निर्भर करे।

हर ब्लोक में प्रमुख भाटिजनों को एंजोसियन्स बनाई जायें।

धारा चौदह

स्वास्थ्य

महिला स्वास्थ्य निरीक्षणिका के प्रशिक्षण केंद्रों में परिवार नियोजन शिक्षा का अध्ययन भी शामिल किया जायें।

एच प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जायें।

हर राज्य सरकार इस बात का विस्वास दिलाय कि नजफाब, सिगर पूना में ही स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में हर राज्य के लिये निर्धारित स्थानों के लिये उम्मीदवार भर्ती रहे।

इन तीनों प्रशिक्षण केंद्रों में दिये जानेवाले प्रशिक्षण का बीस एक सौ हो।

जो लोग इन केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हें विकास स्तरों में नियुक्त किया जाय।

राज्य सरकारों को इन स्वास्थ्य केंद्रों में सभायित प्रशिक्षण की जाय करनी चाहिए तथा मलेरिया, राज्य क्षमा, गुल्फ कोष्ठ तथा चर्म रोगों आदि के प्रशिक्षण में लिये विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ की जाय।

ग्रामीण क्षमा में स्थित आवासीय न राशनदान आदि युक्त उनके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

साप्ताहिक मधु शालाओं का नाम न एच छोड़ पर निर्माण किया जायें ताकि पशु ग्रामीण जन संख्या के बाहर रह सकें।

धारा पंद्रह

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा प्रशासन इत्यादि को ब्लोक के आधार पर व्यवस्थित किया जायें।

हर ब्लोक में ब्लोक सहायकार समिति हो जिसकी व्यवस्था न स्कूलों के वाय का उत्तरदायित्व पचायत समिति पर हो।

ब्लोक क्षेत्रों के लिये आवश्यक कोष तथा कुशल कार्यवृत्तों की व्यवस्था हो जिसमें नि गुरुक व परिवार प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

महिला अध्ययनिका के लिए निवासस्थान की व्यवस्था भी जानी चाहिये।



पंचायत व सहकारी संस्थाओं को कृषि के उपकरणों की खरीद, बेचान व किराये पर देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फलों व सब्जियों के अधिक उत्पादन की दिशा में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

फलों को सुरक्षित रखने के वतमान तरीके अधिक आसान व सस्ते बनाये जाने चाहिये।

सिंचाई के लिए बिजली वितरण की दरें औद्योगिक बिजली वितरण की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे क्षेत्र जहाँ घान की पदावार होती है उनका विकास होना चाहिए।

कच्चा व घाहरो में दुग्ध सहकारी समितियाँ सही रूपरेखा के आधार पर बनाई जायें।

घरों की नस्ल के विकास के लिए प्राविधिक निदेशनों की आवश्यकता है।

मछली उद्योग के लिए अधिक आर्थिक सहायता व प्रशासन द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने का आवश्यकता है मुख्यतः पर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में।

धारा बारह

सहकार

एक व एक से अधिक गाँवों के बीच में बहुत उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण हो जो स्थानीय या पंचायत की सहायता से सही आधारों पर कार्य करें।

आवश्यकता के समय किसान की ऋण देने की व्यवस्था के साथ ही उसे ऐसी सहूलियतें प्रदान की जायें कि वह फसल के समय ऋण की प्रदायगी कर सके।

सहकारी कृषि पद्धति को बहुत अपने प्रथम अनुभवों से गुजरने दिया जाना चाहिए ताकि तुरंत ही जुने हुए सामुदायिक विकास योजना प्लान के हर बिन्दु में एक सहकारी कृषि क्षेत्र का निर्माण किया जायें।

हाइड्रोलिक में पाठ्यक्रम की पुस्तकें व स्टेशनरी के वितरण के लिए विद्याभियान द्वारा सहकारी समितियों का निर्माण किया जाना चाहिये।

धारा तेरह

ग्रामीण

कुटीर, ग्राम व समुदाय क्षेत्रों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाये ताकि वे एक दूसरे के पोषक बन सकें,

ग्रामीण क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें।

जिला क्षेत्र या उसके एक भाग के ग्रामीणों के लिये प्राविधिक सप्ताहवार हों जिन पर उस उद्योग का विकास निभर करे।

हर ब्लोक में प्रमुख आर्टिजनों को एसोसियन्स बनाई जायें।

### घारा चौह

### स्वास्थ्य

महिला स्वास्थ्य निरिक्षिकाओं के प्रशिक्षण केंद्रों में परिवार नियोजन शिक्षा का अध्ययन भी शामिल किया जायें।

एच प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जायें।

हर राज्य सरकार इस बात का विश्वास दिलाय कि नजफगढ़, शिगर भूना मत्ती स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में हर राज्य के लिये निर्धारित स्थानों के लिये उम्मीदवार भेजती रहे।

इन तीनों प्रशिक्षण केंद्रों में दिये जानेवाले प्रशिक्षण का बोस एच सा हो।

जो लोग इन केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हों उन्हें विकास ब्लॉक में नियुक्त किया जायें।

राज्य सरकारों को इन स्वास्थ्य केंद्रों में समाविष्ट प्रशिक्षण की जांच करनी चाहिए तथा मलेरिया, राज्य क्षमा, शुष्क कोष्ठ तथा चर्म रोगों आदि के प्रशिक्षण के लिये विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ की जायें।

ग्रामीण क्षमा में स्थित आवासा में रोजनदान आदि सुक्त उनके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

सामुदायिक पशु शालाओं का ग्राम के एक छोर पर निर्माण किया जायें ताकि पशु ग्रामीण जन-संख्या के बाहर रह सकें।

### घारा पाँच

### प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा प्रशासन इकाईया का ब्लोक के आधार पर व्यवस्थित किया जायें।

हर ब्लॉक में ब्लोक सप्ताहवार समिति हो जिसकी व्यवस्था व स्कूलों के कार्य का उत्तरदायित्व परामर्श समिति पर हो।

ब्लोक क्षेत्र के लिये आवश्यक कोष तथा कुशल कार्यकलापों की व्यवस्था हो जिसमें नि गुरु प परिवारा प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित समय की प्राप्ति की जा सके।

महिला अध्यापिकाओं के लिए निवासस्थान की व्यवस्था की जानी चाहिये।

ग्राम सेवक व ग्राम सेविकाओं का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे उन क्षेत्रों में जहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है ग्रामीणों को उनके बच्चे पाठशालाओं में भर्ना करने की सलाह दें।

राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा प्रारम्भ करने सम्बन्धी नीति को स्पष्ट करना चाहिए।

राज्य सरकारों को चाहिये कि वे जन-साधारण को इस बारे में जानकारी दें कि बेसिक स्कूल ग्राम प्रकार के स्कूलों से अधिक श्रेष्ठ व उपयोगी होते हैं।

बेसिक पाठशालाओं के लिए शिक्षकों व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाये।

जिन राज्यों में बेसिक अध्यापक के प्रशिक्षण का समय एक साल निर्दिष्ट किया गया हो वहाँ उनकी अवधि २ बर की जानी चाहिये।

## भारा सौलह

### समाज-शिक्षा

समाज शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नागरिकता सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करना प्रजा तन्त्र की कार्य पद्धति से अवगत करना, (ब) उन्हें पढ़ना व लिखना सिखाना (स) उनकी हर प्रवृत्तियों का सही दिशा में विकास करना (द) तथा उनमें सहिष्णुता की भावना का संचार करना है।

समाज शिक्षा समूह (एस ई ओ) की सेवायें इस काम में ली जानी चाहिये कि वह लोगों को सामाजिक कुराईयों का ज्ञान करावे तथा उनके बारे में जनमत तयार करे।

एस ई ओ का पथ निर्देशन करने के लिए जिला या राज्य स्तर पर विशेषज्ञ होने चाहिये तथा शिक्षा विभाग में जोइन्ट-डायरेक्टर समाज शिक्षा के अधीन अलग विभाग खोला जाना चाहिये।

सोशल एजुकेशन आरगेनाइजर तथा ग्राम सेवक के बीच परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए तथा वे समाज शिक्षा की सब प्रकार की गतिविधियों में पूर्ण दिलचस्पी लें।

ग्राम अध्यापक इस कार्य में भाग लेने के लिये एस० ई० ओ० द्वारा काम में लिये जा सकते हैं।

समाज शिक्षा के प्रसार में प्रचलित ग्राम नेताओं की सूची तयार की जानी चाहिये।

एस० ई० ओ० कमल नेताओं को सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सहायता प्रदान करे।

नेता और नेतागिरी जैसी प्रचलित धारणाओं को समाप्त किया जाये।

सहायकी समितियों के सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर एस० ई० ओ० प्रगति दोष ग्रामीणों को ऐसी समितियों के सदस्य बनने में सहायता प्रदान करे।

विकास देने, सिविल, प्रशिक्षण केम्प आदि के आयोजन किये जायें जो ग्रामीणों के सम्मिलित रूप से भाग लेने की दिशा में उपयोगी हैं ।

ग्रौट शिक्षा के लिये उपयोगी पुस्तकें तैयार की जायें और शिक्षा देने के सही तरीके ग्राम अध्यापकों को सिखाये जायें ।

सभी स्त्रियों में ग्रौट शिक्षित लोग के सबेरे सायं के बाद स्त्री व पुरुषों के लिये शिक्षा के काम क्रम प्रारम्भ किये जायें ।

पुस्तकालय उपयोगी सिने बिर्षों आदि का व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाय । ए० ६० ६० के पास एक प्रोजेक्टर ( सिनेमा की मशीन ) होनी चाहिये तथा फिल्मी को नियमित भजते रहना चाहिये ताकि गांव वालों को दिखा सके । साथ ही ग्रामीणों के लिये रडियो की व्यवस्था की जाये । ग्राम नेताओं से बातों पर सारित करने का कहा जाना चाहिए तथा बातों व ग्राम शिविरों आदि में हुए विचार विमर्श के रखाड भरे जाने चाहिए ।

घारा सत्रह

## कुछ विशेष कार्यक्रम-सर्वोदय सघन क्षेत्र व ग्राम दान

सर्वोदय क्षेत्र समिति केवल मात्र सत्रहवार समिति न होकर उसे पूरा अधिकार होने चाहिये ताकि संचालक व वार्षिक चयनमेत हो सके ।

सर्वोदय क्षेत्र का क्षेत्र सम्पूर्ण ए० ६० ए० ६० ब्लोक वर बढ़ा दिया जाये ।

सर्वोदय योजना के कार्यक्रमों के अभाव संचालक को वे सभी काम अपने हाथ में लेने चाहिए जो ए० ६० ए० ६० ब्लोक के अन्तर्गत आते हैं ।

व वार्षिक समिति व सर्वोदय के मध्य पारस्परिक सम्बंध निश्चित किये जाने चाहिये तथा विकास काम क्रम को नियमित करने के लिये कुछ पारस्परिक समझौते तय हों ।

सघन क्षेत्र समिति के काम कता ग्रामीणों काय क्रम को अपने हाथ में लें तथा अपनी शक्ति को कुटीर ग्रामीणों के विकास की दशा में समायें वे ब्लोक के सभी विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेकर उन आधारभूत रेखाओं पर काम कर जो सर्वोदय के कार्यक्रमों के सामने प्रस्तुत की गई है ।

सघन क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिये ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामदान यादोलन में मिलाजुला रहना चाहिए । ग्रामदान वाले क्षेत्र नये ब्लोक के लिये चुने हुए लोगों में प्राथमिकता प्राप्त करें ।

घारा अठारह

## वित्त कार्य दक्षता तथा काय कुशलता

ब्लोक स्तर पर किया गया व्यवस्थित वित्त ब्लोक के बहार खर्च नहीं किया जाना चाहिए उसे राज्य व मुख्य कार्यालय के कमचारियों पर ।

ब्लॉक से बहार की विसी भी योजना पर 'लोक कौष' में से धन खर्च नहीं किया जाना चाहिए जिस पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च हो जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल अनिवार्य ही न हो ।

जन सहयोग जो किसी भी काम के लिये प्राप्त हुआ हो धीरे धीरे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रगति के साथ-साथ अधिक प्राप्त किया जाये ।

हर ब्लॉक में ५० प्रतिशत उत्पादक की दिशा में खर्च किया जाये तथा ५० प्रतिशत सुविधाओं पर । यह 'यय' सीमा एक प्रस्ताव के रूप में है जो स्थानीय समस्याओं व परिस्थितियों के अनुसार राज्य द्वारा बदली जा सकती है ।

---



## लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को अमरज्योति

—श्री जवाहरलाल नेहरू

[ २ अक्टूबर १९५६ को नागोर में राजस्थान की पंचायती राज योजना का समारम्भ करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश ]

आज आपको मातृम हूँ कि हमारे भारत में, और मैं तो कहूँ कि सारी दुनिया में एक गुन दिन है महात्माजी का जन्म दिन है। आज से ६८ वर्ष हुए, वो कम सौ वर्ष हुए जब गांधीजी का जन्म भारत भूमि में हुआ था। ठीक है कि हम उस दिन को याद करें क्योंकि हजारों वर्षों के इतिहास में महा पुष्प आए हैं, कई सौ वर्ष हजार वर्ष बाद बड़े बड़े पुष्प प्रवृत्त हुए हैं यह हम कहना जाता है। अपने जीवन में भी हमने एक बड़े महापुरुष को देखा उसने साथ कुछ काम किया, कुछ सोचा और भारत भर को उसने उठाया और स्वतंत्र किया और उससे प्रेरित यह कि हम सीने रास्ते पर उठाने पड़ना पड़ा, गवत रास्ते पर नहीं लड़ाई झगड़ के रास्ते पर नहीं बीरता के रास्ते पर। लेकिन बीरता कभी, प्रहिता की, शांति की बीरता, सभी सिर नहीं किसी के सामने झुकावें कमर नहीं झुकावें डर से सत्य का पालन करें और देश की सेवा करें बीरता से और प्रेम से और इस तरह से उन्होंने दुनिया के इतिहास में पहली बार यह दिखाया कि शांति के रास्ते पर चल कर प्रेम और एकता से कैसे एक देश, महान देश अपने को प्राप्ता कर सकता है और एक बड़ा साम्राज्य का मुकाबला करके आजाद कर सकता है।

×

×

×

×

अपने इस क्षण को गुरु किया। जनतन्त्र का यहाँ फलावा पंचायती राज्य जो कुछ प्राप्त करें। और मैं सोचता कि महात्माजी को कितनी प्रसन्नता होती अगर इस समय होते और देखते कि महा राजस्थान में जो कि भारत का एक माने में हृदय है भारत का नक्शा भी देगे सब भी एक उसका दिल सा है सौतन चल रहा है। राजस्थान के लोग एक एक मिल से, एक एक गांव से आये और यह निश्चय किया कि इस भार को सौतन को वो उठावें और यहां को सरकार न बनाना उसने जनता के

ऊपर ये इम्तिदारी सौंप दो। बड़ा काम है। ऐतिहासिक काम है। तो जितनी उन्हें प्रशंसा होती। इस लिये धीर भी यह उचित है धीर मुनासिब है कि आज, महात्माजी की जयन्ती के दिन हम धीर आप मित्रें धीर यह महान ऐतिहासिक काम शुरू करें।

×

×

×

×

स्वराज्य आने के समय एक धीर बड़ी भारी बात थी कि देग में विप्लवकर यहाँ राजस्थान में, मध्यभारत में धीर-धीर जगह भी बहुत सारे रजवाड़े थे। अब अगर देश के बहुत सारे भ्रष्ट भ्रष्ट दुकानें ऐसे ही भ्रष्ट भ्रष्ट कायदे बान्धन हो, तो इस तरह से देग की शक्ति नहीं बनती। तो पहला काम यह हो गया कि हम रजवाड़ा का जो यहाँ एक तब था उसका अन्त करें। यह जब पुराना ढंग था पुराने जमाने में एक जमाने में यह भी अच्छा रहा। लेकिन जैसे सत्तार का चक्र चलता है तो नये नये रूप धारण करता है समाज का संगठन नये नये रूप में होता है। समाज बदलता है, आपका एक बच्चा बड़ता है। आप एक बच्चे को सुंदर कपड़े पहना दें तो उन कपड़ों में अच्छा लगता है बच्चा लेकिन साल दो साल बाद बच्चा बड़ा हो जाता है उस उसके कपड़े उसकी रायत हैं धीर अगर आप समझें कि बुद्धि से काम लें तो आप उससे बहुत कम कपड़े, बदल दें वह कपड़े पहनायें, तब वह बड़े बड़े। तो तरह समाज बनता है, समय के मुताबिक उसका संगठन भी बदलता जाता है। उसका रूप बदल जाता है। वह बड़े सिद्धांत नहीं चल जाते हैं। लेकिन ये ऊपर की बातें हैं। तो रजवाड़ा का जमाना था ठीक है वही भी बरस हुआ। वह भी एक उचित जमाना था धीर महापुरुष हुए यहाँ के राजा महाराजा इसमें कोई सन्देह नहीं वह अच्छा था हमें गव है। उन लोगों का नाम लेकर हम दुःखी होती है। लेकिन वो जमाना खतम हुआ। यह चीज जो पहले दो तीन मी बप अच्छी रही वा प्राज्ञिक के जमाने में ठीक रही रही।

×

×

×

×

दूसरी तरफ आप देखें राजनीति की तरफ। यहाँ स्वराज्य आया। हमने कहा कि जनता का राज्य है धीर सब लोग को बोट मिला। बोट ज़रो भाई दिल्ली की विधान सभा के लिए लाख सभा के नियम बयपुर की विधान सभा के लिये। अपने अपने प्रतिनिधि भेजो, चुनकर। ठीक है, एक तरह से जनता का राज्य हुआ। लेकिन फिर भी इतना राज्य हुआ कि तुम अपने प्रतिनिधि चुनो किन्तु मुझारे हाथ में रोज का अधिकार नहीं है। बड़े बट अफसर हैं कमी बभी आपसे सत्ता है बर लें ता ठीक है। हम यह फिर रही कि भारत तभी उठेगा जब कि यहाँ लाख गांव उठेंगे क्योंकि भारत में सौ आदमियों में ८० आपके गांव में रहते हैं। जब गांव उठेंगे तो भारत असल में मजबूत हो जायेगा तब उसका कोई रोक नहीं रहेगा। इसलिये हमने विकास योजना शुरू की। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्रांच बनाये। सात बप हुये इसकी धीर भारत के करोड़ों लाख गांव में यह फला है, इसमें भी अधिक। कहीं अच्छा काम हुआ, कहीं नहीं। सब मित्रों के अच्छा ही हुआ क्योंकि काम बहुत बड़ा है। याद रखो लाख गांव की उठाना कोई छोटा काम नहीं है। करोड़ों आदमी उठें। लेकिन फिर भी जितना हम चाहते थे उठता नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमने देखा यह काम ऐसा नहीं है कि पालो ऊपर के अफसरों के करन से पक्की तोर से हो सके, चाहें वे जितने ही भले अफसर हों। अफसर की जरूरत है क्योंकि सीखा हुआ आदमी है। वह बता सकता है। लेकिन यह काम ऊपर का नहीं है। यह काम सभी चलेगा जब जनता के हाथ में बाण्डोर हो। अब लोग १ दहा भाई, जनता के हाथ में बाण्डोर आप दो तो जाने गलत चले सही चले धीर काम सराब कर दें धीर उस पर भरोसा कैसे हो? यह बान बनत है। क्योंकि कोई आदमी अगर काम किये सीखता

नहीं है, ता फिर हमारे सामने यह गई बात हो गई, नई नहीं यह नया कदम हो गया कि अब ऐसा प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक जनता के हाथ में काम करने की शक्ति लायें। खानी देखने की नहीं, सलाह देने की नहीं। और इस सलाह पर बहुत विचार हुआ। तो हमारे कमेटीवा हैं और कायस महामन्त्री है, समझे भी बड़े-बड़े प्रस्ताव हुये और कुछ बातें उठाने निश्चित कीं। उन्होंने निश्चय किया कि हरे गांव में एक पंचायत होनी चाहिये और पंचायत को अधिकार अधिक मिलने चाहिये। दूसरे, सहकारी सघ होने चाहिये और उसको भी अधिकार मिलने चाहिये।

×

×

×

×

अब पंचायत की समझो, वह इन्तजाम करने की है—राजनीति इन्तजाम, और सहकारी सघ आर्थिक प्रबंध करता है—काम बंटवारा का प्रबंध। सहकारी सघ के माने क्या हैं? सहकारी सघ क मासूली माने हैं? कि लोग जरा मिल-जुलकर काम करें, एक दूसरे की सहायता करें। मोटी बात है कि मिल-जुल कर काम करने में शक्ति आती है। यानी खाली बड़ बड़े अफसरों के ऊपर बाय नहीं पड़े बल्कि काम करने का बोझ जनता पर पड़े और एक दफा हमारी ४० करोड़ जनता पर पड़े तब कोई बड़ी शक्ति उसकी होती है। कोई अफसर दे सकता है वह शक्ति? हमारी बात ठीक है कि जनता को साथ लेकर चलना है—समाहकार के रूप में भी। तो यह हमने निश्चय किया और जोर हमने दिया इन बातों पर पंचायत के ऊपर सहकारी सघ पर। सहकारी सघ का माने क्या है? बहुत सार दंग से हात हैं अब कार्र ज़रूरत नहीं कि हम एक दंग का ही भारत में रहें। जता जहा टोन्शन घसा बहा रहा। लेकिन मोटी तौर पर सहकारी सघ का मान अब तक समझो जाते थे—जहा रपया कर्जो लिया बाय किसानों को वह तो आवश्यक बात है होना चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि सहकारी सघ का द्वारा मोद बहुत सारे काम हा आपन बेबन क आपन खरीदने क। आपकी उबरन, बीज चाहिये, आपकी खाद चाहिये आप जा भन पदा करें उसको बेचने का प्रबंध होना चाहिये।

अब आपकी जमीन अलग रहेगी है। आपकी की जमान है जमीन कभी नहीं मिटने। आपकी का मर्यादा है और आप की जमीन का हिस्सा है। लेकिन इन सब कामों के करने से जो रपया और सोया की जेब में जाता था, वा आपने ही पास रहता है और इससे आप उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। दुनिया में करोड़-करोड़ सब देशों में सहकारी सघ से किसान इधर लोग काम करते हैं और इससे बट्टी का लाभ होता है। उसमें एक और बात भी आ जाती है कि वे अपने छोटे छोटे कारखाने बनाते हैं काम करने के लिये और खेती के अनावा। वो विद्यालय बनाते हैं वो अस्पताल बनाते हैं, वो छात्रावास बनाते हैं। सब का लाभ होता है। उनके बच्चों को लाभ होता है। काम-काज मिलता है। राजगार अधिक मिलने लगता है। खेती से अधिक पैसा होता है। सब का लाभ होता है। देख का भी होता है। यह तो मोटी बात है। हरेक की जरूरत है। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि सहकारी सघ अपने आप नहीं बन जाता। १०० आदमी आयें, हम सहकारी सघ बनायें, बता भी लें। उसमें सोचना पड़ता है कैसे करें। किन्तु सीधा हुआ आदमी नहीं है ता आप काम शुरू करें काम सारा हो जाय तो फिर आप परेशान हो और लोग कहेंगे दखो य बाध करना भी नहीं जानते इसलिए हमने प्रबंध लिया कि लोग सिखाये जायें। आपको पक्क आम सेवन बगरह यह बूढ़े सीखें और भी छोटी भी लोग यह सीखें ताकि हर सहकारी सघ में सीखे हुये लोग हा। तो मामूली सहकारी सघ जो हम रल रहे हैं इसमें हर एक की भलग-भलग जमीन रहेगी, भलग-भलग खेती रहेगी।



एक और दंग भी इसका है जिस पर आप विचार करें। बात नई नहीं है। बाद की बात है कि जहाँ थोड़ी थोड़ी जमीन लोगो के पास होती है एक एकट दो एकट यदि हमारे पास बहुत है, वहाँ वहीं ज्यादा भ्रसान हो जाता है अगर ५ आदमी १० आदमी २० २५ ३० ४० आदमी मिलकर खेती उस जमीन पर करें जमीन का अलग अलग हिस्सा रहे जमीनों उाकी रहें। मिलकर करने से उनका लाभ होता है खर्चा कम होता है फायदा ज्यादा होता है। तो इसलिए मिलकर खेती करना भी अच्छा है लेकिन वो बात बाद की है और जो चाहे करें, चाहे न करें। इस समय जो मैं आपसे कहता हूँ वो यह है कि आप सहकारी सभ ऐसा बनाइये जिसमें ये सब काम जो मने आपको बनाये दें हो सकें। आपकी जमीन अलग रहे आपकी मिलनियत है। आप जमा चाहें इसको करें और आपसे स सहकारी सभ में लोग मिल कर जा किसी-सुभी याते ह। उनको करें, बेचना, खरीदना अगरह। इससे आपका बहुत लाभ होगा और उसको सीखिये। तो दो बातें मने आपको बताई—एक तो पचास या इतनाम करे दूसरी सहकारी सभ जो अधिक बातों में गाव की मदद करे।

× × × ×

ये सब बातें खाली पुरपा के लिए नहीं हैं सिन्या के लिए भी हैं उनको भी स्कूल में जाना है, पढ़ना है। लड़के लड़कियाँ का क्याकि दंग आगे बढ़ता नहीं जब तक कि सारे देश वाले उसमें हाथ न लगायें। अब वो जमाना गुजरता, पुराना समय चला गया जिसमें घूँघट काढकर औरतें और काम न करें खाली घर के कामों में ही पड़ें। घर का काम तो करेंगी ही बहु ठीक है लेकिन काम भी करें। देश के कामों में लगे। इस तरह से दंग बड़े क्याकि हम दंग को और जल्दी बढ़ाना है। समय नहीं है। आबादी हमारी बढ़ती जाती है। बाँझ बढ़ता जाता है इसलिए सबो को यह काम करना है।

× × × ×

ये कम्युनिटी डेवलपमेंट "लाव" क्या हैं "खास गावों के विकास के लिये हैं और अब समय आया कि उसका नाम, विकास योजना का, नाम अगरह का आपके कचे पर रखा जाय। आप उस बोझ का उठावें और उसी के साथ अपना आमदनी जो हो वो भी आप लें और अगर आप चाहें तो आप आमदनी बनायें। आपका पब्लिकर है क्याकि जा आप आमदनी बनायेंगे तो आप ही खुद खर्चेंगे अपने गाव की तरफका में। अपने बाल बच्चा की पढ़ाई में। तो इस दंग से हम चलना है तो बड़ी भारी जिम्मेदारी आपने ली है, आपको दी गई और आपन ली है। निमी कदर और भारत के लोगो की धारें भी आपकी तरफ हामा कि इन्हें किस के चलाने हैं। लेकिन मुझ तो विश्वास है खाली राजस्थान के लिये नहीं बल्कि सारे भारत के लिये कि जहाँ इस तरह से जिम्मेदारी दी जायेगी तो उसका नतीजा अच्छा होगा और देश तेजी से चलाए।

× × × ×

तो आपने यह बड़ा काम किया। बड़ा बदल उठाया और एक बड़े शुभ दिन इस कदम को सामने उठाया है तो मैं आपका बधाई देना हूँ और आशीर्वाद है यह तो ठीक है लेकिन आपको बधाई और आशीर्वाद खाली क्या हूँ। मैं कौन और आप कौन। हम सब साथ मिलकर एक बड़े काम में लगे हैं। हम एक दूसरे की पीठ ठाम लें अच्छा है दिन तो खुश होता है। जब सफलता होती है तब दिल खुश होता है। उमंग जब अपने सारे काम फल देने हैं तब दिल खुश होता है क्योंकि उमंग हमें लाभ होता है, देश को लाभ होता है और कोई बड़ा काम आप उठावें और हिम्मत से करें और उसमें कामयाबी हो तो आप थक जाते हैं और आपकी शक्ति बढ जाती है। हमने स्वराज्य का प्रश्न उठाया

या। जब स्वराज्य मिलता हमारी शक्ति बढ़ गई। दुनिया में हमारा आदश हुआ और इस तरह से ये जो बातें हमने उठाई वो हुईं। हमने पंचवर्षीय योजना उठाई। उसमें सफलता हुई। हम अपने ऊपर भरोसा हो गया। इस तरह से हमारी शक्ति बढ़ती है। और भरोसा बढ़ता है। आप इस काम को यह पचायत और पचायत समिति और जो नकशा बना है, इस काम को आप जोरा से चलायें, जिम्मेदारों से चलायें और आप सहकारी सब चलायें तो आप देखेंगे कि देखते देखते राजस्थान का कुछ रूप बगलना है। आपकी जाना अधिक अच्छी होती है और उससे साथ सब से बड़ी बात आपकी शक्ति बढ़ती है। भरोसा बढ़ता है, मिर ऊंचा हाता है और इस तरह से श्रौं भी तरक्की होती है। तो आप सब जमा हुये, जमा हो के आप इन सब बातों पर विचार करेंगे। मेरा आशीर्वाद तो जरूर है आपको और बधाई है, और मुझे विश्वास है इस काम से राजस्थान की काम होगा, याद रखें कि ऐतिहासिक कदम है।

×

×

×

×

पचायत के मान क्या? पचायत हा, पचायत समिति हो या ब्लाक हा और ये सब जो इसमें बहुत सारे लोग हैं इन सब लोगों को समझना है हम एक बड़ी विरादरी के लोग हैं। ऊंच नीच नहीं समझना है और ऊंच नीच के लिये भी आप सोचलें कि अब जो जमाना चला गया हमारे देश से। जैसे मैं आपस कहा राजा लोगों का अधिकार गया, जागीरदारों के भी अधिकार बहुत कुछ गये, राजाओं का हम आदर करने हैं जागीरदारों का भी लखन अधिकार नहीं। तो सब ये जो हमारा जाति भेद है, और कोई जाति धर्म समझ कि हम दूसरे की छाती पर उठे हैं या कंधे पर तो यह बात ठीक नहीं है। आजकल राजनीति में दूरे के बराबर के अधिकार हैं। पचायत में बराबर के अधिकार हैं, पुष्ट स्त्री कोई जाति हो जानि के डग पर नहीं बनी, इस तरह से काम करें। घम में घाा हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हा, पारसी हा, ईसाई हा, जन हा जो कुछ आप हा जो कोई आपकी जाति हो, जो कुछ आपका धर्म हो, आप रखिये खुशी से। लेकिन घम के माने मत नहीं है कि आप दूसरे घम की धकेलें और घसस घुरा बर्ताव करें।

×

×

×

×

तो इस तरह से हमें चमना है और हम नये कदम को जो आपने उठाया मजबूती से उठाना है, ध्यान पर भरोसा करने उठाना है। लेकिन हमारा याद रख कि आपने जो नया कदम उठाया तो सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। अगर आप अपनी प्रतिभा भूल गये, अगर आपस में दबबानी बरन लग लड़ने लग तब आप काम को सराब करेंगे और आपकी बदनामी होगी। बड़े काम को उठाते हैं तो हमको भी बंधादमी बन जाना चाहिये। छोटे आदमी की तरह न काम नहीं करना चाहिये। तो आपने बड़ा कदम उठाया। यहा आप सब पंच सरपच और प्रमुख लोगों ने एर बटा कदम उठाके बड़ी जिम्मेदारियां छोड़ी हैं—सारे राजस्थान की जनता का बढाने की। बड़ी बात है ना बड़े श्व की बात है। बड़ी जिम्मेदारी की है और आपको बनी गलत बात नहीं करनी है जिसमें बदनाम करें अपने का और अपना पचायत को या अपने राजस्थान को बदनाम करें। जरा ऊंचा रहना है। ऊंची भित्तिन सबा का देनी है। ऐसे करियेगा तो आपका नित भी टहा होगा, मजबूत होगा और तरक्की होगी।

# युगोस्लाविया में सत्ता की विकेंद्रित व्यवस्था

—श्री भगवतसिंह मेहता

युगोस्लाविया की सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझने के लिये कुछ प्रारम्भिक बातों का जानकारी आवश्यक है। चौन्हवीं शताब्दी में जब कि यूरोप पर तुर्कों के आक्रमण हुए तब से युगोस्लाविया एक स्वतंत्र राजनितिक इकाई नहीं बन सका। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही सबसे प्रायः और स्लोव्न्स लोग को मिलाकर एक राज्य की स्थापना की गई और उसकी एक ही केन्द्रीय सरकार राजतन्त्र के रूप में बनाई गई।

( २ ) १९१७ में हुए रूस की राज्य प्राप्ति का प्रभाव इस देश के लोग पर भी पड़ा, और सन् १९१८ में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई पर इस पार्टी को हमारा सङ्घ की दृष्टि से ही देखा गया और १९२८ में ता इस सङ्गठन को गर कागूनी भी घोषित कर लिया गया। फिर भी यह पार्टी अल्पसंख्यक रूप में निरन्तर काम करती रही और जिला स्तर तथा प्रायः स्तर पर समितियाँ सङ्गठित करने में सफल हुई। राजतन्त्रोप शासन जब तक जर्मन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप नष्ट नहीं हो गया, चलता रहा। इस अवधि में पार्टी यमिकों का विश्वास प्राप्त कर चुकी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में पार्टी की शक्ति और उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। यहाँ तक कि गावा तक में इस पार्टी के सङ्गठन और सशस्त्र सेनाप्रा में छोट २ बर (Cells) कायम हो गये। पार्टी ने लोगों में विश्वास कर युवकों और युवतियों में अपने स्थानीय सङ्गठनों के जरिये, उत्साह पैदा किया और देश को उन राष्ट्रों के साथ युद्ध करने के लिये तैयार किया जिन्होंने जर्मनों और इटालियनों के बीच देश का बटवारा कर दिया था। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इस पार्टी के नेताप्रा में न केवल आक्रमणकारियों के साथ ही युद्ध करने का निश्चय किया बल्कि भूतपूर्व सिबिर सत्ता को भी समाप्त करके उसके स्थान पर नई सत्ता कायम करने का निश्चय लिया। प्राचीन पद्धति में और उस पद्धति में जो कि पार्टी के समय निर्धारित थी कोई एक सूत्रता बनाये रखने की योजना नहीं थी।

( ३ ) युद्धा और जिला स्तर की कमेटियाँ युद्ध काल में काफी चक्षुशाली बन गईं। आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रतिरोध गति सङ्गठित करने का दायित्व इन कमेटियों पर था। ईहाई बमान केवल सामान्य

निर्देश जब सम्भव हो, दिया करता था। इस प्रकार ये संगठन वृत्तमान स्वायत्त शासन के आधार बन गये।

(४) दीर्घ काल तक होते रहे विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप जो विदेशी प्रभाव पड़ा उसके उपरान्त भी, यूगोस्लाविया ने अपनी परम्परागत संस्कृति की रक्षा का है जिस पर कि स्वदेशीयता की स्पष्ट छाप है और जो एक क्षत्र से दूसरे क्षेत्र में मिन है।

(५) यूगोस्लाविया का संघीय जनवादी गणतन्त्र (१) सर्बिया (२) क्रोशिया (३) स्लोवेनिया (४) बोस्निया एब हर्जोगोविना (५) मसीडोनिया और (६) मांटनेग्रो का जनवादी गणतन्त्रों से मिलकर बना है। बोस्निया और हर्जोगोविना को छोड़कर इन जनवादी गणतन्त्रों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर किया गया है। सर्बिया के जनवादी गणतन्त्र में दो स्वशासित इकाईयाँ हैं एक बोजोविना का स्वशासित प्रान्त और दूसरे कोसोवो—मेथोहिया रीजन की स्वशासित इकाई। ये इकाईयाँ मूल्यव्यवस्था वगैरहों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करने के लिये संविधान के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं। क्रोशिया और स्लोवेनिया पर दीर्घकाल तक आस्ट्रिया का प्रभाव रहा जिसका असर वहाँ की प्रशासनिक एवं कानूनी परम्पराओं पर पड़ा। राजतन्त्रियों (Monascrist) प्रशासन पर फाम का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्हीं प्रभावों के कारण फडरल तथा रिपब्लिकन मुन्नीम कोर्ट के अन्तिम क्षणायिकार के अधीन, प्रशासन कार्यों में प्रशासनिक विधि की सुदृढ परम्परा बनी हुई है।

(६) द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की गई जिसकी प्रबल प्रवृत्ति राजनैतिक और प्रशासनिक केन्द्रीकरण की ओर थी। राज्य ने कई आधारभूत प्रशासनिक कार्यों को अपने हाथ में लिया जिनमें खास तौर पर एक कार्य ये जिनका संबंध वहाँ की अर्थव्यवस्था से था। इस अर्थ में प्रशासन को सुदृढ बनाया गया और सत्ता ढ़द पार्टी द्वारा बिखित नहीं समाज-व्यवस्था का आर्थिक आधार स्थापित किया गया। युद्ध के अपराधियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई और उद्योग राष्ट्रीय बन, वाणिज्य आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। कृषि सुधार इस सिद्धान्त पर कि भूमि उन्हीं की है जो उसे जोतते हैं किये गये। समाजवाद का यह प्रारम्भिक समय यूगोस्लाविया में एक आवश्यक परिवर्तन-काल माना जाता है। उनके विचार में इसी तरीके से भावी विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने के लिये और आधारभूत कार्यों के लिये भीतिक साधन एकत्रित करना सम्भव हो सकता था।

(७) दूसरा काल १९४६ से प्रारम्भ होता है। जिसकी विषयता यह है कि इसमें सरकार तथा प्रशासन का बिकेन्द्रीकरण किया गया। स्थानीय निकायों को १९४६ में राज्य सत्ता के अधो के रूप में अधिक माय्यता दे दी गई थी। अब, उनका कार्य क्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया और इसमें मुख्य बात यह रही कि सत्ता को जहाँ तक हो सका कम्युनी (Crmonunes) को सौंप दिया गया। उत्पादकों को उत्पादन और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वशासन प्रदान किया गया।

(८) यूगोस्लाविया के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन की सही व्याख्या १९५४ के संविधानिक विधि के तीन अनुच्छेदों से प्रतीत होती उद्धृत है —

## अनुच्छेद—२

यूगोस्लाविया के सघीय जनवादो गणतन्त्र मे सम्पूर्ण शक्ति श्रमजीवी वर्ग मे निहित है ।

यह वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग और अपने सामाजिक मामलों का प्रबंध, अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करता है जिन्हें वह पीपुल्स कमेटिया मे पीपुल्स असेम्बलियों मे श्रमजीवी कौंसिला मे तथा अन्य स्वायत्त निकायों मे भेजता है और इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप मे, निर्वाचनों, निर्वाचित व्यक्तियों की वापसी जननिर्देश (रीफ़ेण्डम), मतदाताओं की मीटिंग, नागरिकों की कौंसिला नागरिकों द्वारा प्रशासन एवं न्याय कार्यों मे योगदान के जरिये एवं स्वायत्त शासन के अन्य तरीकों से करता है ।

## अनुच्छेद—३

उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व अन्य व्यवस्था में उत्पादन का वर्ग का स्वायत्त शासन और नगरपालिका कम्प्रे और जिलों मे श्रमजीवी वर्ग का स्वायत्त शासन देश की सामाजिक और राजनतिक व्यवस्था की आधार-शिला है ।

निम्ना संहति और समाज सेवा के क्षेत्र मे श्रमजीवी वर्ग के स्वायत्त शासन को गारंटी दी गई है ।

उत्पादन वर्ग तथा श्रमजीवी वर्ग द्वारा स्वायत्त शासन की शक्ति का प्रयोग सामान्य समाज के उन हितों के अनुरूप किया जाता है जिनका वर्गन कानून मे तथा श्रमजीवी वर्ग की प्रतिनिधि संस्थाओं, पीपुल्स असेम्बलिया एवं पीपुल्स कमेटिया के अन्य नियमों में किया गया है ।

## अनुच्छेद—४

निम्नलिखित के सम्बन्ध में गारंटी दी गई है —

सोवियत, राजनतिक, आर्थिक, सामाजिक, वनानिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, कलात्मक, व्यावसायिक, खेल-कूद सम्बन्धी और अन्य सामान्य हितों की पूर्ति के लिए श्रमजीवी वर्गों का स्वतन्त्रतापूर्वक पारस्परिक मिलना जुटना ।

## काम करने का अधिकार

कम्प्यून् और जिला ऐसे दो स्तर हैं जिन पर यूगोस्लाविया मे स्वायत्त शासन प्रणाली से कार्य होता है जिला या कम्प्यून् में निहित सत्ता का प्रयोग एक संस्था द्वारा किया जाता है जिस पीपुल्स कमेटी कहते हैं । कम्प्यून् एक आधार एवं मूलभूत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और राजनतिक संगठन है । कानून की दृष्टि से समस्त कम्प्यून् की स्थिति एक ही है चाहे वह बड़ा या छोटा अथवा शहरी या गाँवों में ।

सिवाय ऐसे अधिवासी तथा वन-या के जो सबिधान अथवा कानूनों के अनुसार राज्य सत्ता के अन्य शक्तियों अंग भूत संगठनों के लिए सुरक्षित कर लिये गये हैं सरकार के समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कृतव्या का पालन कम्प्यून् की पीपुल्स कमेटी करती है । क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में सामान्य

धारणा स्थानीय शासन की सबसे नीचे की संस्था अर्थात् कम्यून के पंचम है। पीपुल्स कमेटी, चाहे वह कम्यून की हो या जिले की किसी उच्च स्तर के निर्देशा और आज्ञाभा के अधीन काम नहीं करती। ऐसे तथा राज्य प्रशासन के समस्त अग्रगण्य संगठन उसके अधीन होने हैं सिवाय एम जे हैं कानून द्वारा गणतान्त्रिक या संधीय कार्यों का पालन करने के लिये अधिकृत किया गया है। वास्तव में सिवाय पुलिस को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा संगठन है ही नहीं। पुलिस भी उन कार्यों के पालन में जिसमें कि उसे कम्यून की सहायता की आवश्यकता होती है, कम्यून की गर्जों के अनुसार ही कार्य करती है।

पीपुल्स कमेटी के दो सदन होने हैं, हाउस आफ सिटीजंस तथा हाउस आफ प्रोड्यूसर्स हाउस आफ सिटीजंस में नागरिकों का प्रतिनिधित्व है। इसके सदस्यों की संख्या कम्यून का जनसंख्या के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। किंतु कम से कम संख्या सामान्य तौर पर ५० होती है। हाउस आफ प्रोड्यूसर्स में उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं, इसके सदस्यों की संख्या प्रायः हाउस आफ सिटीजंस के सदस्यों की संख्या की ७५ प्रतिशत होती है।

चुनाव—कम्यून के हाउस आफ सिटीजंस के सदस्यों का चुनाव १८ वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त नागरिक (श्रम तथा नगरी दोनों) गुप्त मतदान द्वारा करते हैं।

हाउस आफ प्रोड्यूसर्स के लिए भी निर्वाचन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव उत्पादकों के दो ग्रुपों द्वारा किया जाता है। एक ग्रुप उद्योग, वाणिज्य तथा हस्तशिल्प के उत्पादकों का होता है और दूसरा कृषि-उत्पादकों का जिसमें सहकारी संस्थाओं के उत्पादक एवं समाज-फार्मों पर काम करने वाले श्रमिक शामिल होते हैं। इन दोनों ग्रुप्स के सदस्यों की संख्या गत वर्ष में कम्यून के कुल उत्पादन में उनके योगदान के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है।

जिले में हाउस आफ सिटीजंस का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक कम्यून से आने वाले सदस्यों की संख्या समस्त जिले की जन संख्या के अनुपात के अनुसार होती है। वैसे ही हाउस आफ प्रोड्यूसर्स का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।

दोनों सदनों के सदस्यों का विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वे अपने अपने कामों की तथा जिस पीपुल्स कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व है उसके काम के बारे में अपने निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं को जानकारी देते रहें। जो सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं उन्हें सख्त प्रतिनिधि विनियम संस्था द्वारा चेतावनी दी जा सकती है।

कम्यून या जिले की पीपुल्स कमेटी की साधारणतः बैठक महीने में एक बार होती है जो कि साधारण के लिये खुली होती है। प्रत्येक सदन का अलग अधिवेशन आर्थिक योजनाओं वजह या अन्य महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों को छोड़कर अन्य कार्य के लिये होता है। ऐसे प्रश्नों पर संयुक्त अधिवेशन पीपुल्स कमेटी के प्रेसीडेंट की अध्यक्षता में होता है।

हाउस आफ सिटीजंस के सदस्यों में से प्रधान चुना जाता है और उसके कई सहायक उप-प्रधान होते हैं और उनकी संख्या तीन होती है। प्रधान पीपुल्स कमेटी का प्रतिनिधित्व करता है और कम्यून या जिले के अधिक प्रतिनिधित्व करता है परन्तु कम्यून या जिले के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

पोपुलर कमेटी को उसके कार्य में कई सलाहकार नायबारी तथा प्रशासी संगठन द्वारा सहायता दी जाती है। प्रत्येक पोपुलर कमेटी में आवश्यक रूप से पांच सलाहकार एवं विभागों निकाय होते हैं जिन्हें स्टेलिंग कमीशन कहते हैं इनमें से दो अर्धन चुनाव तथा मनोनयन कमीशन और पिटांगन एवं गिकायन कमीशन दोनों सदस्य से सम्बन्धित प्रश्नों का निपटारा करते हैं। इनके अलावा दस से पंद्रह तक वॉसिल हानी है जो कि नायबारी तथा प्रशासी कार्य करते हैं। इनमें हाउस आफ सिटीजंस या हाउस आफ प्रोड्यूसर्स के सदस्यों के अलावा। कई विभाग तथा बुद्धिमान नागरिक बाहर के भी होते हैं।

पोपुलर कमेटी के मिश्रण के पालन और उसके कानून को लागू करने के लिये। कम्प्यून का अपना एक प्रशासी संगठन होता है जिसका मुख्य अधिकारी एवं सेक्रेटरी होता है। इसका मुख्य कार्य निम्न निम्न विभागों के कार्य का संगठित तथा उसकी देख रेख करता है और उनके कार्यों का समन्वय करना होता है। कम्प्यून या जिले के स्थायी कमिश्नरियां पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है और उनकी तुलना एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी अथवा जिन्हा परिषद के सेक्रेटरी से की जा सकती है। जिले की संगठन सम्बंधी व्यवस्था करीब करीब कम्प्यून के समान ही होती है।

गासन और जनसाधारण में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिये और जनता को शासन में अधिकारिक भाग लेने का अवसर देने के लिये, कम्प्यून के क्षेत्र में जो गांव होते हैं उनकी एक स्थानीय समिति होती है। इस समिति का निर्माण किसी कानून के अन्तर्गत नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र की वोटर असेम्बली करती है। यह सामान्यतया निर्माण कार्यों, इमारतों और सेवाओं की सुव्यवस्था सावजनिक सम्पत्ति, स्थानीय चरानाहो और उनके उपयोग का प्रबंध, स्थानीय बाजार का सफाई और सुव्यवस्था इत्यादि का कार्य सम्भालती है।

कम्प्यून का मुख्य कार्य नागरिकों के व्यक्तिगत हितों का समाज के व्यापक हितों के साथ समन्वय करना है और इस कारण, वह अपने क्षेत्र की भाषा को बढ़ा की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करती है जिससे आर्थिक संगठनों के हितों और कार्यों का समन्वय के 'यादव' हित व साथ सामंजस्य बना रहता है। इसी अभिप्राय से वह आर्थिक संस्थान स्थापित करती है तथा जनोपयोगी सेवाएं जैसे कि सड़कें यातायात जल व्यवस्था, नालियां स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बंधी संगठन और स्थापित करती है, अपने क्षेत्र में स्थित भूमि और इमारतों का प्रबंध लोगों के रहने के लिये मकानों का निर्माण जल मूल्य व धाक, कानून और गानि की व्यवस्था तथा लुटिगियन ब्यामालयों का संगठन अपने हाथ में लेती है।

जिले का पोपुलर कमेटी का नायकता साधारण तथा नीचे की संस्थाओं की वायव्याहियों की वकालत या ऐबन, कम विस्तृत कम्प्यून के विकास एवं व्यवस्था का स्थापना या कम्प्यून की क्षमता का बाहर का टक्कोटन सम्पादन व संगठन और स्थापना तथा अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित विभिन्न कम्प्यूनों व सामान्य हित व कार्य करने तक सीमित है।

अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिये स्वयं कम्प्यून व पास ग्रामस्थों के साधन होते हैं। इन साधनों में मुख्य बजट भाग और निधि व भाग के साधन हैं। बजट भाग अथवा अलग नागरिकों से (निर्वाजक द्वारा दिये गये सामाजिक अदान के रूप में) करा में आर्थिक संस्थानों को होने वाले लाभ से तथा जिला रिपब्लिकन या गैडरल सरकार के अनुदानों से प्राप्त होती है।

कृषि, वन, मृत् निर्माण इत्यादि की उन्नति के लिये कुछेक साधना से जैसे वर आदि से होने वाला आय में से कुछ आय नियत करने विशेष पंड स्थापित किये गान हैं ।

जिल का आय के साधन आर्थिक सस्याना के साथ का हिस्सा आयकर, नियोजको द्वारा प्रगणन, टक्स आदि हैं ।

आर्थिक व्यवसाय और सस्याना तथा सेवाएं जैसे शिक्षा जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि का प्रबंध सामाजिक प्रबंध नामक कार्य पद्धति के अनुसार किया जाता है । सामाजिक प्रबंध में निम्न-लिखित समाविष्ट हैं—

(१) स्वकीय प्रबंध अर्थात् आर्थिक सस्याना का प्रबंध अमजोवा बग की समीतिता द्वारा किया जाना, और

(२) सामाजिक प्रबंध (अथवा सार्वजनिक प्रबंध) अर्थात् सस्याना और सवाभा का एक व्यक्ति और एसोसियेशनो द्वारा प्रबंध किया जाना जिनको उनमें रुचि है ।

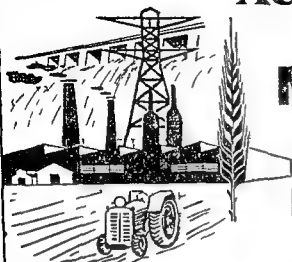




**FOR NEEDS OF TOMORROW  
ACT TO-DAY**

**SAVE  
MONEY**

**FOR  
YOURSELF  
AND  
NATION'S  
NEEDS**



**STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR**

## राजस्थान वित्त-निगम

- ★ सभी प्रकार के उद्योगों के विनाम के लिये
- ★ १५ हजार रुपये से १० लाख रुपये तक के ऋण देने में आपकी सहायता करने की तत्पर है।
- ★ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को २० लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।
- ★ निगम द्वारा होटल एवं ट्रांसपोर्ट उद्योगों को भी ऋण दिया जाने लगा है।
- ★ ऋण के नियम तथा शर्तों के लिए निम्न पते पर मिलिए अथवा लिखिये —

प्रबंध संचालक

**राजस्थान वित्त-निगम**

“सूर्य निवास”

सी-१८ भगवानदास रोड

जयपुर



सूच-४

## ग्राम-सभा

१	ग्राम-सभा का ऐतिहासिक पक्ष	श्री बन्धुमार सुकुमार	१-६
२	ग्राम-सभा के कार्य की व्यावहारिक भूमिका	श्री मनोहर प्रभाकर	७-१५
३	ग्राम सभा और उसके शक्ति	श्री आमुत्तम	१६-२०
४	सोव सभा की रचना का आधार ग्राम-सभा ही	श्री गोविन्दप्रसाद	२१-२६



# ग्राम सभा का सैद्धान्तिक पक्ष

[ श्री चन्द्रकुमार मुकामार ]



सम्पूर्ण दायित्वों से युक्त अपने उच्चस्तरीय त्रिवृत्तात्मक ग्राम-पंचायतों की स्थापना के पीछे यदि कोई भावनाएँ कार्य कर रही थी, तो वे ये थी कि —

- १ स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जहाँ कि शासन अब स्वयं जनता द्वारा मंचालित होगा अधिक से अधिक स्वल्प 'यबस्था का अवसर देना —
- २ क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विनियत त्रिवृत्तात्मक पंचायतों के निचले स्तरों पर गाव के लिए विकास कार्यों की प्रगति और उन्नति तथा
- ३ विकास योजना के साधारणतम स्वरूप में सामुदायिक व क्रियाशील लोकतन्त्रात्मक उत्तर-दायित्व की भावनाओं का प्रसार करना ।

इस दृष्टि से पंचायतों राज की स्थापना सत्ता व अधिकारों का विभेदित साधारणीकरण मान ही नहीं है वरन् खोस्तत्र में सक्रिय योगदान की ओर भी एक हठ बंदम है। त्रिस्तरीय शासन में निचले स्तर पर उपलब्ध सोना द्वारा प्रशासनिक विकास उससे 'पंचायत' कहे जाने वाले स्तर पर ही है। सचता है क्योंकि पंचायत का गठन निर्वाचन द्वारा स्वयं ग्रामवासी ही करते हैं। परिणामतः ग्रामवासियों की प्रवृत्ता होने के नाते क्षत्रीय खोतों द्वारा क्षेत्रीय और सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति

हेतु ग्राम पंचायत को ही सामने रखा जा सकता है और सर्वेक्षण, किया जा सकता है। उच्च स्तर पर प्रशासन द्वारा नीति संचालन उन मुद्दों पर होता है जिनका निम्न प्रति के जीवन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। फिर राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर बनने वाली प्राविधिक व मिश्रित योजनाओं पर कार्यक्रमों में देश की अग्रिम जनता (भीड़) की सहमति को न तो कोई अनिवार्यता हो सकती है और न अपेक्षा हो। इस हालत में पंचायत स्तर के कार्य ही ऐसे हैं जो कि दैनिक जीवन से वास्तविक धर्मों में प्रत्यक्ष सम्बन्धित हैं। इस स्थिति में सामुदायिक प्रशासनिक इकाई को जांच और सर्वेक्षण ही सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों के दैनिक जीवन की आवश्यकता और उनकी पूर्ति हेतु तैयार कार्यक्रमों की सही दिशा और दिशा के लिए सही तरीका है। किन्तु यह सभी सम्भव है जब कि अधिकतम व्यक्ति उस (इकाई) से सम्बद्ध हो। ग्राम स्तर पर उपलब्ध स्रोतों का प्रशासन के सम्बन्ध हाथों द्वारा न तो सही सर्वेक्षण ही किया जा सकता है और न ही उनका उपयोग फिर भले राज्य की राजधानी से प्रयत्न किए जाय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्योंकि उनके और व्यक्ति के मध्य सामाजिक मनोव्यवस्थाएँ एवं प्राकृतिक बाधाएँ कुछ ऐसी दूरियाँ हैं जो घटाएँ हैं। इसीलिए यावहारिक लोकतन्त्र की जहाँ उस क्षेत्र में छोटे सामुदायिक शक्त के मध्य पाएँ हैं जहाँ कि व्यक्ति व्यक्ति का सम्बन्ध साधन और दायित्वों का निर्वहण प्रत्यक्ष हो सकता है। जहाँ तक योजना और विकास धर्मों के लिये ग्राम स्तर पर मिलने वाले साधनों का सवाल है चाहे वह भूमि सम्बन्धी हो या धर्म या पूजा सम्बन्धी उनमें धर्म ही ऐसा साधन है जो भारतीय ग्रामों के धार्मिक पक्ष की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पर योजना में सक्रिय सहयोग के साधन धर्म का यह अर्थ बड़ापि नहीं कि वह केवल उसकी सद्दान्तिष्क जल्दता ही को पूरा करता है वरन् यही वह गारंटी है जो कार्यकर्ताओं को धर्म साधनों की उपलब्धि की सम्भावना भी बताता है। ऐसा योगदान मात्र सहयोग ही को उन्नत नहीं करता वरन् साधनों के सही सही मुल्यांकन और उपयोग के अक्सर भी प्रदान करता है।

## ग्राम-सभा

अगर ग्राम-स्तर पर पंचायतों की संरचना भारत में लोकतन्त्रात्मक शासन एवं जीवन-पद्धति का नींव को धारण प्रदान करती है तो ग्राम के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा गठित ग्राम सभा की सक्रिय योग, निष्पक्ष और त्रिवर्षिकी की सामर्थ्य देनी होगी क्योंकि यही पंचायती राज संस्थान को प्रोत्साहित प्रदान कर सकती है। अगर ग्राम समुदाय का प्रत्येक वयस्क सदस्य या जितने अधिक से अधिक हो सके व सब ही ग्राम विकास और ग्राम प्रशासन के कार्यों में संलग्न हो सके ता तत्सम्बन्धी साधनों का उपयोग और उपभोग भी किया जा सकता है, और उनमें स्व-सेवा तथा स्व शासन की धारणा भी जमाई जा सकती है। स्व-सेवा और स्व शासन की धारणा स्वयं ही लोकतन्त्र की भौतिक एवं नैतिक नींव को सशक्त बना देगी। विकास कमिशनरों की समय समय पर हुई बैठक और स्थानीय स्वायत्त-शासन की केन्द्रीय समिति की बैठकों में भी यहो माना गया है कि समावित सम्पूर्ण उन्नतता प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य की विधान सभा द्वारा 'ग्राम सभा' को स्थाई मान्यता प्रदान की जानी चाहिये कि जिससे यह अपना स्वरूप और तेजस्विता प्राप्त कर सके।

स्थानीय-स्वायत्त-शासन की केन्द्रीय समिति की १९५६ में हैनराबाद में हुई बैठक में भी यही अनुभव किया गया था कि—

मान कुछ ही राज्यों की विधान-सभाओं ने पंचायत क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा गठित ग्राम-सभा की वधानिक इकाई के रूप में मायता प्रदान की हुई है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई ग्राम-सभा' है ही नहीं जब कि माय मतदान सूची में बड़ा की स्त्रियों और पुरुषों के नाम अंकित हैं। पर ये विधान-सभाएँ तो इन मतदाताओं तक की माय नहीं स्वीकार करती। पर जहाँ विधान सभा ने ग्राम सभा की वधानिक इकाई के रूप में मायता प्रदान की है तथा जहाँ ग्राम-सभा की बैठक वष में दो बार आयोजित की जाती हैं और पंचायत अपने आय-व्यय का लेखा-जोखा तथा अपने कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट उस (ग्राम-सभा) के समक्ष प्रस्तुत करती है वहाँ पंचायत की अपने कार्यों के लिए स्वीकृति समुक्त बल तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का अवसर लाभ भी मिलता है। इसीलिए यह अनुभव किया जाता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा द्वारा ग्राम-सभा को वैधानिक इकाई के रूप में मायता देना और वष में कम से कम दो बार उसकी बैठक आयोजित करने की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।'

यदि बिहार और उत्तर प्रदेश में मई १९४७ से यह संस्था (ग्राम-सभा) कार्यरत है और ग्राम ग्राम सभी राज्यों में भी अब इसकी स्थापना हो चुकी है, तब इसकी सफलता या विफलता के आधार भूत कारणों को जसा कि सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान के सलाहकार म १९६० में मसूरी में हुई संमीक्षा में भी 'ग्राम-सभा' नामकी संस्था के विकास की संभावनाओं को खोज बीन की प्रतिपाद्यता स्वीकार की गई थी जाब आवश्यक होनी चाहिये।

### ग्राम-सभा के विघटन कारक तथ्य

ग्राम-सभा की असफलता या विघटन के कारणों को कि ग्राम अनुभव किये जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं —

१. चेतना का अभाव—ग्राम भी ग्रामवासियों द्वारा पंचायत से भिन्न 'ग्राम सभा' नामक संस्था के अस्तित्व तक से अपरिचित है उन्हें यह ठक भान नहीं है कि पंचायत क्या है? ग्राम सभा क्या है और उनमें क्या अंतर है? जहाँ ग्रामीण जन इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप और अन्तर से भिन्न हैं वहाँ वे ग्राम-सभा के सदस्य के नाते अपने दायित्वों और अधिकारों से अनभिज्ञ हैं तो दूसरी ओर ऐसे भी हैं जिन्हें इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप में अंतर का भान भी है तथा जो अपने अधिकारों से परिचित भी हैं उनमें अपने कर्तव्य तथा अधिकारों की उत्तरदायिता के साथ समझ में लाने की चेतना नहीं है।
२. ग्रामीण राजनीति की व्यक्ति-परक प्रकृति—पंचायत के चुनावों के अवसरों पर यह देखा गया है कि मतदाता ग्रामतौर पर अपनी मत व्यक्ति की देने हैं। वे मत देने वक्त भी नि कार्यक्रम और आर्थिक-पारणायों के बारे में लगातार या विचार नहीं करते। अतः इस स्थिति में जब कोई विशिष्ट व्यक्ति पंचायत का नेता निर्वाचित हो जाता है तो वे लोग यह सोचकर कि उनके लिए अब यह निर्वाचित व्यक्ति कार्य करेगा—अपने कर्तव्य की इति धीमान बैठे हैं। उपर उस सामुदायिक में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो या तो किसी दूसरे व्यक्ति का नेतृत्व हेतु समर्पण कर रहे होते

हैं प्रथम जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ गया है उसका विराध कर रह होते हैं, वे जब यह देखते हैं कि उनका ( समर्थित ) व्यक्ति पंचायत के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता है तो वे खुद भी पंचायत प्रथम ग्राम सभा के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते ।

३. मुनिश्चित स्थान का अभाव—प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये मुनिश्चित स्थान का अभाव भी ग्राम-सभा के विघटन का एक उत्तरदायी कारण है । प्रायः कई ग्राम एक पंचायत के अन्तर्गत आ जाते हैं और इस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ जाने के कारण ग्राम सभा का बैठना न भिन्न भिन्न मौकों वाटों या ग्रामों में घाये लोगों को बैठन का मुनिश्चित स्थान प्राप्त नहीं होता है ।

४. समय-अभाव—जब ग्रामाणु-जन अपने कार्यों में व्यस्त हों ऐसे अवसर पर यदि ग्राम सभा का बैठना प्रयास किया जाय तो भी ( या हो जाय ) तो वे उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते । पर यदि वे बैठें किंवा "गोहार" में मौके पर या जब वे काम-पस्तता से मुक्त हों तब आयोजित हो तो स्थिति कुछ भिन्न हो होगी ।

५. प्रधान प्रथम पंचायत के सदस्यों की अनिच्छा—प्रायः पंचायत के व्यक्ति-संघटक ग्राम-सभा की ओर झुलाने का प्रयत्न विशेष कर इसलिए कि ग्राम सभा में विराधी पक्ष के सदस्य जिन ज्ञान-वान प्रश्न करेंगे वे तो उदासीन रहते हैं प्रथम यदि बैठक बुलाने भी हैं तो उसकी स्थिति समय-एव स्थान की मुनिश्चित व समुचित सूचना प्रसारित नहीं करत । अथवा विरोधी पक्ष के सदस्य-गण या "गोहार" करने के लिये कि उनका द्वारा प्रभावित ग्राम सभा का बैठना उनका ( स्वयं ) कोई निश्चय नहीं है उसका बहिष्कार करत हैं । इस प्रकार दाना ही स्थितिग्राम सभा की अमर्यता की कारण बन जाते हैं ।

६. ग्रामीणों द्वारा असहयोग—ग्राम सभा की अस्थिर एवं सन्तुष्ट स्थिति से भिन्न ग्रामीणों का ग्राम-सभा की बैठक में सम्मिलित होने की बजाय अपने ही किसी व्यक्ति-एव उत्पादक काम में लगने रहते प्रथम काम न होने पर घरों में बैठे सुख की साधन लेते रहते हैं ।

इसी प्रकार अन्य जन-सामाजिक व राजनीतिक स्थितियाँ हैं जो ग्राम सभा की सरल राह में बाधा बन कर पड़ती हैं और इसीलिए ग्राम सभा की अनिवार्यता अनुभव किए जाने के बावजूद भी उनके शक्ति-स्वरूप में अपने शक्ति सम्पन्न होने और स्थाई अधिकारों के प्रदान किए जाने में समय लगता जा रहा है । अतः यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि कुछ स्थायी शक्ति प्रदान करने मात्र में ही ग्राम सभा सत्ता का पूर्ण विकास नहीं दिया जा सकता है । अतः पंचायती राज का आधारभूत इरादा के रूप में मायावा प्रदान करने के साथ ही साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रथम ग्राम सभा के क्या कार्य हैं तथा उनकी क्या विशेषता है ? इस दृष्टि में 'पंचायती राज की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार प्रथम चरण भी नियत करना होगा । पर यह भी सत्य है कि अगर अभी भी 'ग्राम-सभा' अपनी विराटता, जनता और सक्षम-व्यक्तियों का प्राप्त कर लेगी तो यह विश्वास होता है कि उस दिन देश का प्रत्येक व्यक्ति सौभाग्य में शक्ति प्राप्त करेगा तथा मार-धाड़ और उसी दिन पंचायती राज द्वारा प्राप्त किये जाने वाले बड़े काम और सर-उत्तरते दृष्टिगत होंगे । अतः जब यह सत्ता इस रूप में पूर्ण स्वरूप में प्राप्त करने तक ही हम और अधिक जन-एव अधिकारों का दायित्व लेना जा सकता है । और ही सकता है कि

एक समय ऐसा आये जब आगे बढ़ यह सत्ता स्वयं ही अपने उच्च स्तरीय संस्थानों से अधिक दायित्व सौंप जान की माग करन ।

पुनरचना और उसने उच्च—ग्राम समुदाय को पुनरचना का महत्व ग्राम समा में निहित है । यह धारणा तो किसी भी प्रकार उचित नहीं कि आशाजनक मात्रा में पुनरचना इस सत्ता के निर्माण पर ही प्राप्त हो जायेगी अथवा उपरोक्त कथित कथ्य और अधिकांश के अमल में साथे जान से होंगे, क्योंकि सर्वमाय पुनरचना सत्ता के अधात्मिक गठन मात्र पर ही निर्भर नहीं करती । इस प्रकार का उत्कर्ष स्थान एक प्रकार के किसी भीमा तक देश भर में विस्तृत विशिष्ट वातावरण पर भी आधारित है मुचित म ही प्राप्त किया जा सकता है । इसीलिए लोकतन्त्र में हमारी कथ्य विषय धारणाओं में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने के लिए भी कहा जाता है, वरन् कि हम अपने देश में सच्चे अर्थों में प्रजापति राज का प्रतिष्ठापना चाहते हो । इसका सीधा सम्बन्ध देश की राजनैतिक पाटियों की गतिविधियों की पुनर्जाब व जनता के सामान्य व्यवहार के स्तर को पूरा अमाय करार देन और वल्लभ के नियम से है । एक सत्ता के रूप में ग्राम समा इस दिशा में यह कर सकती है लेकिन अगर किसी भाति ये आदेश या ये नियतिया इन सत्ताओं के गरीर में जड़ जमा वठी तो फिर तत्कालीन उच्च स्तरीय सत्ताओं एक वही ही सम्बद्ध अथ सत्ताओं में भी अपना प्रभाव स्थापित करने का मौका प्राप्त कर लेंगी । समाजवादी गामन के विचार और स्वयं समुदाय को भी साम्य-समाज के सदस्यों में ही समझन की आवश्यकता, भौतिक साम्यवित्त की अपेक्षा नैतिक धारणा ही अधिक है । आज ग्राम-समुदाय अधिकांशतः वर्गों में विभक्त है जिनकी भिन्न भिन्न वहा तक कि परस्पर विरोधी अभिरुचिया हैं । इन साम्य अभिरुचियों की वृद्धि-वर्धन आता जा, कि इन वर्गों पर नियन्त्रण रखती है सामाजिक स्वरूप में और अधिक दूर डालती हैं, और वही कोई इन विचारे वर्गों की एकता में बाधन का कार्य भी करती हैं तो उन एकता को भी यह प्रभावित करती है । जहाँ इस क्षेत्र में यह विश्वास कि एक ही सहकारी समिति गाव के विभिन्न वर्गों की विभिन्न रुचियों वाली व्यवहारधार आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, ऐसी हमारी परम्परागत विचार-धारा की दन स्वरूप कुछ मूलभूत धारणाओं में परिवर्तन करना पड़गा । वर्गों और उपवर्गों की घाटी तिरछी दरारा वाली सामुहिक धारणाएँ ऐसी सभी ग्राम-सत्ताओं के विकास को मदेहास्पद बना देती है । एक सत्ता और एक विचार के रूप में ग्राम समा को किसी एक विशिष्ट वर्ग या उपवर्ग की समस्या का ही समाधान नहीं करना है बल्कि पूरे गाव का एक मान कर कार्य करना है तब अगर सामुहिक धारणा मूलभूत रूप में अपने आप में ही पूर्ण नहीं है तो पूरे गाव की एक सत्ता विषय धारणा तो गूढ़ सात्विक हो ही नहीं सकती । इसलिए विभिन्न वर्गों को एक मूल में मिलाव के लिए दिए जान वाले प्राथमिक प्रयत्नों के पून गाव की विरोधी तत्वा वाली प्रवृत्ति को सफल सेवा प्रत्यक्ष मूलपूर्वक माय है । तब ही ग्राम समुदाय के दिन में किसी भीमा तन एकात्मिकता के पनन तथा सगठित और योजना बद्ध प्रयत्नों की शिमा में आगे बढ़न उठाया जा सकता है । इस प्रकार का सत्याम हो यथान और माय हा साथ क्रमानुगत भी ग्राम समुदाय में पूरे गाव की एक सत्ता के रूप में आगर और महत्व प्रदान करना सम्भव हो सकता है ।

यहो उपरोक्त कथित व मूलभूत दरार है जो सामुदायिक विकास आन्दोलन का सामाजिक एवं राजनैतिक विचारधार के समक्ष आ खड़ी होता है । इसलिए ग्राम समा जहाँ सत्ता जिसका कि एक



सामाजिक आधार हा 'उच्च स्तरीय त्रिरूपात्मक' संस्थानों की अपेक्षा घामी गति से ही विकसित होता ज्यादा स्पष्ट है। विभिन्न राज्यों में वायव्य ग्राम संघों की गति विधियों ने इन निष्कर्षों को पुष्टि हा प्रविष्ट किया है। ग्राम संघों नामकी संस्था का दीर्घकालीन विकास, ग्राम-समुदाय की एकात्मकता का दीर्घकालीन धारणाया, जिन्हें कि अभी ग्राम स्वयंसेवा प्राप्त करना है और जिन्हें एक लम्बी अवधि के बाद ही अनुभव भी किया जायगा पर ही निर्भर करता है। पर प्रशासन के विभिन्न स्तरों द्वारा विभिन्न श्रेणीय-गतिविधियों पर आधारित ऐसी सामुदायिक संस्थाओं को पूर्ण सुरक्षा दिया जाना अनिवार्य है। इस दिशा में अरुणि जाति ग्राम या धन-सम्पन्नता पर आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रभाव करने एक अवसर की समानता प्रदान करने वाली अनुसूचित की नवीन भावनाओं के जन-सामान्य में प्रसार द्वारा यह कार्य सहज ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से ग्राम संघों से हम थोड़े से समय में ही ग्राम की कामना व्यक्त है।



# ग्राम सभा के कार्य की व्यावहारिक भूमिका



—श्री मनोहर प्रभाकर

ग्राम सभाओं के आयोजन का विचार चायद कुछ लोगों की आधुनिक सोचतन की उपज प्रतीत हो सकती है, किन्तु यह एक मनोरंजक तथ्य है कि ग्राम सभाओं का इतिहास उतनाही पुराना है जितना बौद्ध कालीन मठों या मीय कालीन स्तूपों का ।

बिहार प्रदेश के इतिहास में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है । कहने हैं कि एक बार बंगाली के बाहर किसी उपवन में भगवान बुद्ध अपने शिष्य शिष्य भानन्द के साथ बौद्ध सभों का जनतांत्रिक अधासन की व्यवस्था पर विचार विनिमय कर रहे थे । जिनासा वद भानन्द ने तपागत से पूछा—' भगवन् ! लिच्छवी गणतन्त्र की समृद्धि और सम्पन्नता का क्या कारण है ? तपागत ने कुछ क्षण सोचने के बाद धान्त स्वर में उत्तर दिया ' भानन्द ! लिच्छवी गणतन्त्र की सफलता का रहस्य वहा की ग्राम सभामें है । जब तक ये ग्राम सभायें बराबर छुटती रहेंगी और वहा के लोग अपने निरापों में सबसम्मत रहेंगे, लिच्छवी गणतन्त्र चलता चलता ही रहगा । '

इतिहास साक्षी है कि जब तक भारत में शासन का यह ढांचा काम करता रहा, तब तक समा धार कुछ शांति का वास्तविक साम्राज्य स्थापित रहा ।

इसा पूव भाउवी शताब्दी से लेकर ईसा की चौथी शताब्दी तक देश के विभिन्न भागा में स्वतन्त्र गणराज्य प्रचलित थे । कपिलवस्तु के शाक्य पावा और कुशीनगर का मल्ल, मिथिला के विदेह, और वयाणा के लिच्छवी, ये सभी इसी गौरवपूर्ण परम्परा की स्वतन्त्र कड़िया थी । प्रत्येक गण में इन बातियों

को एक सभा होती थी जिसके निर्देशानुसार एक मुखिया शासन संचालित करता था। ये ग्राम सभाएं ग्राम की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का अध्ययन कर ग्रामीणों के लिए तो काम करती ही थीं जरूरत होने पर 'याम' और सुरक्षा का दायित्व भी इनका होता था। जिन स्थानों पर सभाएं होती थीं उन्हें समष्ट्यारा कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपने गौड मध का जनतांत्रिक ढांचा इसी आधार पर बनाया था।

युवक और वृद्ध सभी इस सभा में उपस्थित हुआ करते थे। प्रस्ताव को कमवाच्य कहा जाता था और समूहों सभा के समक्ष रख जाने से पूर्व उसकी 'समाप्ति' अर्थात् सूचना। सभा के कोरम इत्यादि के सम्बंध में निश्चित नियम थे। इस परिषद को केवल औपचारिक ही नहीं वास्तविक अधिकार थे और अपने अधीन क्षेत्र पर सम्पूर्ण अधिकार इसी का होता था। हर महत्वपूर्ण मामला इन परिषदों के सामने विचारार्थ आता था। नये कानून बनाने पुराने कानूनों को बदलने या हटाने का अधिकार इसे था। यदि विचारणीय प्रश्न उठित होता या किसी प्रश्न पर परिषद के सदस्यों में बहुमत से काफी मतभेद होता तो ऐसे प्रश्न को तम करके के लिए कुछ सदस्यों को एक सभित को सौंप दिया जाता था। यह परिषद राज्य की राजधानी या केन्द्र में होती थी।

भारत में इन प्राचीन गणसभाओं के नष्ट हो जाने के बाद भी सभी जगह पंचायतों अपने किसी न किसी रूप में जन्म रही। इनने लोगों में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। वे अपना सारा काम स्वतंत्रतापूर्वक करती थीं। गांव का प्रबंध सुचारु रूप से हो, इसका जिम्मेदारी ग्रामीण जनता के ऊपर होती थी। पंचा के चुनाव या तो योग्यता के आधार पर अथवा साटरी द्वारा हुआ करते थे। पंच का पद और पंचों का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली होता था कि खोला के मस्तक शब्दा से प्राप्त ही भुक्त जाते थे। पंच परमेश्वर समझा जाता था और पंच का नियम ईश्वरीय था। पंचायतों का कार्य शान्ति भी सीधी सादी थी। पंचायतों पार्षदिक एवं सामाजिक जीवन की प्रेरणा केन्द्र थी। ब्रिटिश शासन ने सामंत शाही का पीपण करने तथा सभाओं के एक वर्गव्यवस्था का और अधिक उठान के लिए एक पक्षीय लाभ के भूमि कानून बनाकर इस ढांचे का धन २ दिन भिन्न कर डाला।

## भारतीय सविधान और पंचायती राज

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के पार्षदिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इन सबका अंतर ग्रामीण जीवन पर भी स्वाभाविक रूप से हुआ। जागीरदारी उन्मूलन भूमि सुधार के कानूनों तथा पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ग्रामीण जनता में नवीन चेतना जागृत हुई। भारतीय सविधान की धारा ४० में पंचायती राज गठन और उन्हें अधिकार देने के बारे में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इसमें हम यह मानने समझने के लिए काफी अवसर मिलता कि ग्रामीणस्तरी पर हम प्रजातंत्र के किस स्वरूप का चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है—सोच बलपूर्वक ग्रामीण राज्य की स्थापना। और यह तभी सम्भव है तबना है जब सत्ता का विनियोजन हो। इसीलिए हम पंचायती की सारी योजनाओं का के २ बिन्दु बनाना पना और पंचायती राज की गुरुवात इसी विचार से हुई।

## पंचायती राज की आधार शिला—ग्राम सभा

पंचायती राज का उद्देश्य स्वतंत्रता का आधार पढ़ने से अधिक स्थापन बनाना और पद

स्थापित करना है कि लोखतत्र म जनता ही सत्ता का सच्चा स्रोत है। ऐसी अवस्था में यह बिन्दुन तक मर्ममन है कि पंचायतो को गांव की सारी जनता के प्रति ग्राम सभा के रूप में उत्तरदायी रखा जाय। समय और चेतनाशील लोग सत्ता न होने के कारण आज भी पंचायतों में दलबन्दी पाई जाती है। दलबन्दी से सत्ता की स्वायत्तता बढ़ता है, जिससे गांव में मन मुटाव का दानावरण सहज ही पटा जा जाता है। इस स्थिति पर मनुष्य रखने के लिए ग्राम सभाओं का प्रायोगिक निमित्त रूप से प्रयोग महत्व का है।

अब यह भली प्रकार अनुभव कर लिया गया है कि पंचायतों के प्रशासन का निर्दोष बनाना तथा लोक शक्ति का अपनी मूल सुविधा के लिए मजबूत करने का माध्यम केवल ग्रामसभा ही हो सकता है। इसी से हम प्रशासन में कुशलता प्रभाव पर विजय प्रापिक और सामाजिक पाय की प्राप्ति तथा सुयोग्य नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। ग्राम सभा सही मायने में कर्तव्य और अधिपति की अभि शक्ति का आधार है। इसके माध्यम में पंचायत, जो स्थानीय जनता की सरकार है, उस नियमित गतिशील और निगाहील बंधाया जा सकेगा। ऐसा करने पर हो हम ग्रामस्तर पर सच्ची लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना कर सकेंगे। जब तक जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते तब तक सच्ची लोकतन्त्रात्मक सरकार नहीं बन सकती।

कुछ वर्षों पहले भाग्यदायिनी विकास मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित 'देहराबाद सम्मेलन' में ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्पत्ति लिये गये। प्रथम बार ग्राम सभा का वधानिय मायता प्रदान करने का सिफारिश का गई। सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि ग्राम सभा की साल में कम से कम दो बैठकें प्रायोजित की जानी चाहिए, जिनमें वज्रट, करा के नये प्रस्ताव, तथा पंचायत द्वारा दिये गये कार्यों की प्रगति का सिद्धान्तोक्त किया जाये। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत को दायीय समुदाय की सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जायगा तो पंचायत के सदस्यों की पारस्परिक दलबन्दी तथा स्वायत्तता शन २ म्बन हो मष्ट हो जायगी।

## ग्राम सभाओं का स्वरूप

ग्राम सभाओं का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य है गांव के सारे स्थानीय और प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। अतः इसमें गांव की अधिक से अधिक जन शक्ति को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। ग्राम सभा गांव के ऐसे सभी लोगों की सभा है जिनकी वाट देन का अधिकार है। ऐसे सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।

ग्राम सभा की सदस्य संख्या के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इनके इतने सत्य भी नहीं होना चाहिए कि वे एक दूसरे को जान भी न सकें। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सदस्यों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना कठिन हो जायगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक गांव में सुझाव या वादों के आधार पर अनेक ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। यदि एक पंचायत क्षेत्र में कई गांव हैं तो उन गांवों में अलग-अलग ग्राम सभाओं की आयोजित की जा सकती है। इस प्रकार एक ही पंचायत क्षेत्र में अनेक ग्राम सभाओं आयोजित करने से जहाँ विचार विमर्श करने में बहुत सुविधा मिल सकती है, वहाँ कुछ कठिनाइयाँ भी सामने आ सकती हैं। ये कठिनाइयाँ

केवल धायो की प्राथमिकता को संकर हो सकती है। इसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि जिस नियम को ग्राम समर्थों का बहुमत प्राप्त हो उस हो कार्यान्वित किया जाय और प्राथमिकता भी वही आधार पर निर्दिष्ट की जाय।

## राजस्थान पंचायत अधिनियम और ग्राम समर्थों

राजस्थान पंचायत अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों में धखीन यह व्यवस्था की गई है कि मात्र ५ प्रतिशत ५ गांवों पंचायत क्षेत्र के समस्त प्रोढ़ निवासियों की दो ग्राम समर्थों प्रमथ मई और अक्टूबर में बुलाई जायें। यह बठक पंचायत के सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा बुलाई जानी चाहिए। बठक का स्थान साधारणतया उस गांव में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जहां पंचायत का कार्यालय स्थित हो।

बठक के दिन तथा समय की सूचना वाय कम की सदस्यित रूपरेखा के साथ बँठक होने के कम से कम पाँच दिन पहले निम्नलिखित रूप में प्रकाशित या विनाशित करदी जानी चाहिए—

- (१) पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक या अधिक प्रमुख स्थानों पर विपका कर तथा
- (२) पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बोल बजाकर सावजनिक घोषणा करके—

ग्राम समर्थों की बठक का सम्भाषितत्व सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा किया जाना चाहिए। यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो बड़ा उपस्थित पंच में से कोई एक जो उपस्थित निवासियों द्वारा चुन लिया जाय ग्राम समर्थों का सम्भाषितत्व करेगा।

किसी वित्तीय बंधन होने वाली इस प्रकार की बठकों में से पहली बठक में पंचायत का बजट पेश किया जायगा और उस पर वयस्क निवासियों के विचार विनिबद्ध किये जायेंगे। दूसरी बठक में पंचायत द्वारा हाथ में लिये गये निर्माण कार्य प्रमथों की जानकारी दी जायगी और उनमें की गई प्रगति से अवगत कराया जायेगा। जिन कार्य प्रमथों पर विचार विनिमय होगा उनमें कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग आदि प्रमुख हैं।

प्रत्येक एसी बठक की वायबाहिया का विवरण हिन्दा में लिखा जायगा और उस पर सम्भाषित करने वाले व्यक्ति के प्रस्तावित होंगे। इस प्रकार जो विवरण लिखा जायगा उसे सम्भाषित करने वाले सदस्य द्वारा पंचायत की प्रमथों की बठक में प्रस्तुत किया जायगा। इस प्रकार की बठक पंचायत क्षेत्र के निवासियों की मांग पर भी बुलाई जा सकती है बगलें कि पंचायत क्षेत्र के कम से कम १०० वयस्क व्यक्ति या कुल वयस्क व्यक्तियों के एक चौथाई (जो भी कम हो) लिखकर बठक की तिथि तथा प्रयोजन सहित अपनी अधिप्राचना बठक के निर्धारित दिन से कम से कम बीस दिन पूर्व पंचायत कार्यालय में किसी भी विम्वार व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर द। यदि ऐसा करने के सान दिन के भीतर भी सरपंच बठक बुलान में धूर परे तो अधिप्राचना या मांग रखन बात व्यक्तियों द्वारा राजस्थान पंचायत तथा ग्राम पंचायत (मामाच) नियम १९६१ के नियम ६६ के अनुसार जसा कि पहले बताया जा चुका है तिथि तथा समय की सूचना देकर बठक बुलाई जा सकती है। ऐसा बठक उस गांव को छोड़कर जहां पंचायत का कार्यालय स्थित है और वही नहीं बुलाई जा सकती।

## ग्राम समाजों के कार्य संचालन का स्वरूप

सामान्यतया ग्राम सभा की बैठक के कार्य संचालन में ये बातें सम्मिलित की जानी चाहिये।

- (१) गत ग्राम सभा के विवरण का वाचन
- (२) ग्राम सभा की पिछली बैठक में जो नियुक्त किये गये हैं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण व सम्पन्न किये गये कार्य पर विचार
- (३) ग्राम सभा की बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण नियुक्त किए गये हों उनकी जानकारी
- (४) प्रश्न करने का समय
- (५) प्राय तथा व्यय का विवरण तथा बजट का वाचन के उत्तर
- (६) बजट, करारोपण विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम प्रादि
- (७) ऐसे विषय जो पंचायत समिति जिला पारंपद जिला कलेक्टर प्रादि ग्राम सभा के समक्ष रखना उचित समझें
- (८) भूमि बितरण तथा नवी बितरण व सावजनिक योगदान भी ग्राम सभा में ही किया जावे तो ग्राम सभा अधिक प्रभावशाली हो सकेगी।

यही सही है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में ग्राम सभा की केवल दो बैठकें बुलाना आवश्यक है। किन्तु लोगों में सहयोग और धनिकता की भावना पैदा करने के लिए ग्राम सभा की अधिक बैठकें होना जरूरी है ग्राम सभा की बैठकें अधिक बार बुलाने से एक बड़ा लाभ यह है कि पंचायत की अपनी नीति और कार्यक्रम के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देने का मौका बार-बार मिलता और परिणाम स्वरूप उन्हें गांव का सहयोग अधिक मिल सकेगा इन ग्राम सभाओं में लोगों को उत्पादन कार्यक्रम की महत्ता बताई जानी चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता समस्त मानवीय तथा भौतिक साधनों को जुटाने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवादल निर्मित किए जा रहे हैं। ये सेवा दल ग्राम में उचित वातावरण बनाये रखने, ग्राम लोगों में अनुशासन की भावना बढ़ाने और ग्राम की उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में योग दे सकेंगे। ग्राम सभाओं में लोगों की ग्राम सेवा दलों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उत्पादन की सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया जाना चाहिए। इस दिशा में मरसक प्रयत्न होना चाहिये कि प्रत्येक कुटुम्ब, गांव, खड, राज्य और देश का उत्पादन बढ़े। इस सम्बन्ध में यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्रों के लिये उपयोगी भूमि सीमित है और इस कारण से हमको मौजूदा भूमि से ही अधिक पैदावार करनी होगी। सक्षम, हमारी प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि होना आवश्यक है।

राजस्थान में अधिकतर कृषि प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है जिसका परिणाम अभी अभी यह होता है कि कठिन से कठिन परिश्रम करने पर भी उपज का मिलना अनिश्चित सा रहता है। इस लिए निचाई के साधनों द्वारा कृषि के क्षम में स्वावलम्बी होना सबसे पहली आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्री जी के निम्न उद्गार जो उन्होंने पंचायती राज अध्याय विद्विज अम्बपुर के उद्घाटन के समय प्रकट किये थे उल्लेखनीय हैं—

पंचायतो व पंचायत समितियाँ को मदद यह बात ध्यान में रख कर चलना चाहिये कि उनके विकास की जड़ उत्पादन है। उनको यह योजना गावा में क्रियान्वित करनी है। अतः इस कार्य क्रम का सबसे प्रमुख अंग होगा—छेती और पशु पालन। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में प्रति एकड़ जमीन में जितनी पैदावार होती है प्रति मास जितना दूध शीसतन होता है या भेड़ा से ऊन पैदा होती है वह दूसरे देश की अपेक्षा कम है। हम यह देखते हैं कि अपने ही देश में अपनी ही पंचायत अथवा गाव में एक व्यक्ति ज्यादा पैदा करता है जबकि दूसरा कम। अतः इन सब का कारण क्या है? यदि उत्पादन में भ्रम है तो प्रत्यक्ष इसके मापने हैं कि वही न वही काम करने के तरीका में कमी है। एक परिवार किस प्रकार अपने साधन व शक्ति के अनुसार उत्पादन बढ़ा सकता है इसको ऊपर उठा हुआ, गहन तन्त्र नहीं समाल मकता। इसके लिये तो जितनी पंचायत या पंचायत समितियाँ सम्भारती और सततता से काम करें उनको उसमें उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। मेरी राय में पंचायत राज का प्रमुख कार्यक्रम तो यह है कि उसको अपने गाव के प्रत्येक परिवार को कृषि उत्पादन की योजना बनानी चाहिये जिससे कि जो साधन उस परिवार के पास हैं उनको ध्यान में रखते हुए अच्छे ढंग से खर्च करने में जितना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वह मालूम किया जा सके और इसके अनिश्चित बहा पर जो सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जैसे सिंचाई के साधन, अच्छे बीजार, रासायनिक खाद इत्यादि उसको उपलब्ध किया जाय तो जितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं? इस प्रकार की योजना प्रत्येक गाव के लिये बना कर उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।

ग्राम सभा की बैठकें जन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरा करने में भी सहायक होंगी। वय में कुछ बैठकें केवल जन प्रशिक्षण के उद्देश्य से भी बुलाई जा सकती हैं। इन बैठकों में निम्न विषयों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये।

(१) पंचायत राज की पृष्ठ भूमि और उसकी स्थापना के कारण

(२) पंचायती राज का स्वरूप अर्थात् पंचायत, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषद का गठन। उनकी सदस्यता कर्तव्य और दायित्व।

(३) पंचायती राज की बुनियादी संस्थाएँ—पाठशाला, सहकारी समिति और पंचायत के पारम्परिक सम्बन्ध।

(४) ग्राम सभा का महत्व और उसके प्रति पंचायती राज कार्यकर्त्ताओं का कर्तव्य।

(५) पंचायती राज में स्वच्छिद्व मत्स्याध्या, असे नवयुवक मठल महिला मठल आदि का स्थान और उनसे कर्तव्य।

(६) योजना के लक्ष्य।

(७) उत्पादन कार्यक्रम का महत्व, कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता और उसके उन्नत साधन।

## ग्राम सभा और प्रशासनिक अधिकारियों का समन्वय

चूँकि प्रतिनिधि मस्याएँ और प्रशासन दोनों एक-दूसरे के पूरक बन गये हैं, इसलिए ग्राम सभा वस्तु विभाग के कार्य-क्रमों को वाय रूप में परिणित करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि प्रशासन के स्तर को उन्नत और कुशल बनाने की जनतांत्रिक पद्धति भी है। अतएव यह आवश्यक है कि जिला स्तर के अधिकारियों समय-समय पर ग्राम पंचायतों में भाग लें। तहसील तथा पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों में तहसीलद्वारा जगसात विभाग के रेन्जर विकास अधिकारियों एवं प्रसार अधिकारियों का अधिक में अधिक ग्राम सभाओं में भाग लेना चाहिये। जिला कन्क्टर का समय-समय पर ग्राम सभाओं में भाग लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्राम सभाओं में भाग लेने से जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को जन मानस के और अधिक समीप आना का अवसर मिलेगा वहाँ ग्राम सभा की जनता-उपस्थिति में सह-लाभ भी होगा कि प्रशासन की कठिनाई के कारण ग्राम सभा के जो कई कार्य रुक पड़े हैं उन पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मोक्ष मिलान किया जा सकेगा।

## अधिक से अधिक लोगों पर योजना की जिम्मेवारी

यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों पर योजना की जिम्मेवारी डाली जा सके। इसके लिए ग्राम सभाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग विकास कार्य-क्रमों के लिए समितियों का गठन करें। सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिए विभिन्न परिवारों के मुखियाओं का कम से कम पाँचवाँ भाग इन समितियों का सदस्य हो जाये। इस प्रकार गाँव के अधिक से अधिक लोग किसी न किसी रूप में उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेंगे। इस प्रकार अधिक-अधिक जन-शक्ति नव-निर्माण के लिए सगठित हो सकेगी। ये विभिन्न समितियाँ ग्राम की आवश्यकताओं और साधनों के आधार पर योजना का निर्माण करेंगी। प्रत्येक परिवार की मानसिक रूप से उसके उत्तरदायित्व का भागान करा दिया जायेगा। ग्राम सभा में नियुक्त ऐसे लिए जायें, जिनका प्रभाव समस्त मतदाताओं का अधिक स्थिति पर पड़ता है और उन भौतिक सत्त्वों पर विचार कर दिया जाये जो स्थानीय साधनों से पूरे हो सकते हैं। पंचायत की आय के स्रोत उत्पन्न करने पर या सामाजिक सेवा आदि के ग्राम साधनों की वृद्धि पर भी विचार करा दिया जाय।

## जानकारी की सुविधा

पंचायत का काम सुधिया विभाग का तरह गुप्त गति में नहीं चल सकता। पंचायतों की प्रयोग-जनता का विश्वास सम्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी समस्त कार्यवाही की जानकारी ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करें। पंचायत के गिनया का प्रकाशन भली भाँति होना चाहिए। पंचायत की कार्यवाही, हिसाब-किताब-न्याय के कामकाज और रजिस्टर-किंमो भी ग्राम सभा के सदस्यों के निरीक्षण के लिए निश्चित समय व जगह पर उपलब्ध रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यवाही रजिस्टर में सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनकी लिखी हुई कार्यवाही की प्रमाणित करना चाहिए। पंचायतों की बैठकों की देखने व सुनने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। नैबल शक्ति की व्यवस्था ठीक रखने और गुप्त विषयों पर विचार विमर्श के समय श्रोताओं को प्रवेश दिया जाय। इस प्रकार पंचायतों को प्रभाव दिया जाय। इस प्रकार पंचायतों के कार्य की अधिक से अधिक जानकारी जनता को प्रदान का प्रयत्न होना चाहिए।



## अनुसरण पद्धति

ग्राम सभाओं में केवल नियुक्त लोग ही पर्याप्त नहीं। यह नियुक्त किस सीमा तक पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं इस पर ग्राम सभाओं की सफलता निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो नियुक्त लिया जाय उसमें क्रिया-व्ययन के लिए समुचित अनुसरण पद्धति (कोलो ग्रुप मेटड) अपनाया जाय। ग्राम सभाओं को बैठकों में अनुसरण पद्धति के फलस्वरूप होने वाली काम प्रगति की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के जो नियुक्त पंचायत सचिवित स्तर पर कार्यान्वित के लिए भेजे जायें उनका पूरा करने का दायित्व विचार अधिकारी इस प्रकार के नियुक्त के फलस्वरूप होने वाले कार्यों की प्रगति का विवरण ग्राम सभाओं की बैठकों में स्वयं उपस्थित होकर दे सकते हैं।

## ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की रुचि कैसे पैदा की जाय

ग्राम सभाओं की औपचारिक बैठकों में अधिकतर ग्रामीणों की रुचि नहीं रहती इस कारण उपस्थिति का बड़ा प्रभाव रहता है। कई बार तो स्थान का गलत चुनाव भी इसका कारण होता है। इसलिए ग्राम सभा का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लोग सुविधा पूर्वक पहुँच सकें। सामान्यतया उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिनेमा भवन या साउथ-वेस्टीयर पर रिकार्ड इत्यादि बजवाना का प्रयोग किया जाता है। इससे ग्राम सभा अधिक ध्यान या मनोरंजन स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इससे जन मानस को परिवर्तित और प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह सावधानी रखना जरूरी है कि न तो ग्राम सभा किसी मेले का रूप हो ले और न एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का मंच ही बने। ग्राम सभा का आवश्यक बनाने के लिए उनकी मजबूत बनाना आवश्यक है और यह सजीव सब ही बन सकती है जबकि गांव बासियों का प्रत्यक्ष भाग पहुँचाने के लिये उनकी शिक्षाप्रदाय को दूर करने के उपायों पर विचार किया जाय। यह सब ही सम्भव है जब जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जाकर उनकी कठिनाइयों का हल उचित तरीके और सहानुभूति पूर्ण ढंग से निकाले। यदि विभिन्न विभागों के बिना अधिकारों की दृष्टि से स्तरीय अधिकारी अपने अपने काम का कार्यक्रम सत्रपचों से सम्पर्क स्थापित करके बनायें, तो ८० प्रतिशत ग्राम सभाओं में भाग ल सकते हैं। ग्राम सभाओं में जनता की अपनी भावनाएँ और विचारों का प्रकट करने की खुली छूट दी जाय और उन्हें प्रश्न करने की पूरी अधिकारी रहे। ऐसा करने से जब लोगों का ग्राम सभाओं में विश्वास जम जायगा तो फिर वे उसकी बैठकों में लगातार रुचि लेंगे और उपस्थिति का प्रभाव नहीं रहेगा।

ग्राम सभाओं का मूल उद्देश्य सामूहिक हितों पर विचार करना होता है। यदि इसके विपरीत लोग ग्राम सभाओं की व्यक्तिगत स्वार्थ निहित प्रश्नों और छिछली बातों के मंच बनाने तो एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी। ग्राम सभा स्थल पर बैठकर ऐसी बातों पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है कि किस प्रकार ग्राम व अनुदान दिया जाय। तत्कालीन वोज की सफाई कैसे हो। परन्तु उससे ग्राम ही यदि ग्राम सभा के सभी सदस्यों ने यह नहीं सोचा कि हम और हमारा गांव मिलकर किस प्रकार स्वयं सन्धी हो सकते हैं सामूहिक योजना के लिए निर्धारित समय कितने कम रुपये में पूरे किये जा सकते हैं तो ग्राम सभाओं का सारा उद्देश्य ही असफल हो जायगा। कई ग्राम सभाओं में सामुदायिक विभाग के प्रति

लेना और निजी स्वार्थों की सर्वाधिकार के समाचार भी मिले हैं। जहाँ स्वावलम्बन का ध्येय था, वहाँ वास्तविक और प्रयत्नशील सब सरकार पर इतने प्रभावित हो गये हैं कि जो विकास की शक्ति उनमें पहल भी बट भी खो बठे हैं। वस तो ग्राम समा में हर एक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है, हर प्रस्ताव का स्वागत है परन्तु जिन महान् उद्देश्यों के लिए यह सब आयोजन हो रहा है उससे बारे में विचार विमर्श करने में बड़ी विविध उपेक्षा देने को मिलती है। कई बार जो ग्राम समा में लिए जाते हैं उनको भी कार्यान्वित करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता इसलिए यह आवश्यक है कि ग्राम समा की बैठक में सबसे पहले उन पहलुओं पर विचार किया जाय जिन पर पहले की ग्राम समा में निश्चय लिया गया था। पचायत और पचायत समितियों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि वे ग्राम समा के निश्चयों को हर माह दोहराये और क्या प्रगति हुई है इसका विवरण तयार करें।

ग्राम समाओं की सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि उसक सदस्यों ने सामुहिक सुविधा के लिए कितने आपस में साधन जुटाये और उन साधनों तथा मानव शक्ति का पूरा उपयोग सभी परिवारों के बराबर २ लाभ के लिए किया गया हो रहा है।

यदि लोकतन्त्र का इस शक्तिशाली इकाई ग्राम समा को उचित रूप से संचालित किया गया तो यह शक्तिशाली संस्था निश्चित रूप से व्यक्ति का गरिमा राष्ट्रीय समृद्धि एवं एकता की अनन्तता तक विस्तारवादी बना सकेगी।





## ग्राम सभा और उसके दायित्व

ग्राम सभा

—श्री आशुताप

ग्राम सभा की दृष्टि से विचार करने में यह सम्भव प्रतीत होता है कि १००० से १५०० तक का या सत्या के द्वारा ग्राम-सभा का गठन आमानी से और सही तरीके से किया जा सकता है और जहाँ किसी गाँव की जन-संख्या अधिक भी है तो ग्राम सभा की मीटिंगें बाई बाई बाइल आयोजित की जा सकती हैं। ऐसी या-मीटिंगों को 'उप-ग्राम-सभा' नाम दिया जा सकता है। पर अगर कहीं पंचायत के अन्तर्गत कई गाँव हैं और उनमें कासना भी अधिक है तो उप-ग्राम-सभा की मीटिंग प्रत्येक ग्राम में अलग से आयोजित की सकती है। पर उप-ग्राम सभा की मीटिंग किए जाने का तात्पर्य ग्राम सभा

की मीटिंगें समाप्त कर देना नहीं है बल्कि इसका अर्थ उन सारी कमियाँ और कुराइयो को दूर कर देना है जो कि ग्राम सभा की मीटिंग में प्रायः विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण रह जाते हैं।

## ग्राम सभा की साधारण अथवा विशेष बैठकों के लिए कोरम

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपनी प्रारम्भिक अवस्था में होने के कारण ग्राम सभा की मीटिंगों में अधिक से अधिक उपस्थिति सम्भव नहीं है ग्राम सभा की साधारण एवं प्राग्रह पर प्रामाणिक विशेष बैठक के लिए औरम के रूप में एक सामान्य उपस्थिति (संख्या) स्वीकार ली जाये, जो कि पचासत क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं का १० प्रतिशत हो सकती है। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि ग्राम सभा की मीटिंग स्थगित न होने देने के लिए सरपंच उपस्थिति बनाए रखेगा। इसी प्रकार ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए माग करने हेतु भी पचासत क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं की कुल संख्या का १० प्रतिशत प्रतिपाद स्वीकार किया जा सकता है।

## ग्राम सभा की ओजस्वता

पचासत की शक्ति सम्पन्न करने का सीधा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा की शक्ति सम्पन्न करना है। क्योंकि तब ग्राम सभा के सदस्य अपने दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली बाधाओं और निषाधता को पचासत के समक्ष रख सकेंगे और उससे पूर्ण सतोष प्रद समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। फलतः ग्रामवासी ग्रामसभा में रुचत हो रुचि लेने लगेंगे। प्रायः ग्रामवासियों का दैनिक जीवन में अनुभव का जाने वाली शिकायतें, नीकरझाटों के अभाव, करो सम्बन्धी मुद्दित्तों, भू आवंटन, जंगल के उपयोग के अधिकार अथवा विकास योजनाओं की निषाधित जैसे कि सिंचाई योजना आदि स सम्बन्धित होती हैं। शत यदि ग्रामवासियों को यह विद्वान हो जाये कि ऐसी किसी भी समस्या या भगडे भ्रमट से छुटकारा दिनाम में ग्राम सभा समय है तो निद्वान ही वह अपनी समस्या या शिकायत विचारण ग्राम सभा के समक्ष रखेगा भी और परिणामतः स्वयं उसमें रुचि भी लेगा ही। उधर प्रायः ग्राम सभा में ग्रामवासिया (वयस्कों) द्वारा रुचि न लिए जाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि ग्राम सभा उनकी किसी भी तात्कालिक मुसीबत से उनको राहत देने में असमर्थ है। अब तो इतना सा फाय करने की आवश्यकता है कि एक तरफ तो पचासत शक्ति सम्पन्न कर दिया जाय और दूसरी ओर ग्रामवासियों को इस विषय की पूर्ण जानकारी प्रदान करके सजग कर दिया जाय, फिर तो वे स्वयं ही इस दिशा में सक्रिय हो जायेंगे।

## ग्राम सभा का निर्णय दातृ-स्वरूप

जैसे तो ग्राम सभा की मीटिंगों में उपस्थित सदस्यों की राय जान कर ही निर्णय लिया जा सकता है। पर जिन रायों में प्रायः ग्राम-सभा का अस्तित्व है उनकी अतमान प्रणाली तो यह है कि पचास तो उठे हुए हाथों की गिनती करके, स्थान परिवर्तन करने या एक मत अथवा कम ज्यादा मतों की आवश्यकता प्राप्त करने निर्णय लेते हैं। एक मुद्दा यह भी है कि यदि एक मीटिंग में राय जानकर निर्णय नहीं लिया जा सके तो मीटिंग स्थगित कर दी जाय जिससे कि हर सदस्य की शक्ति से सोचन का मौका मिल जाय और भगवो मीटिंग में सहमति सम्भव हो जाय। पर यदि मतदान द्वारा ही निर्णय

लिया जाता है तो कुछ उपस्थिति की दो तिहाई सदस्या का एक मत होना अभिय यत स्वीकार किया जा सकता है ।

## ग्राम समा के अधिकार

पचायत अपने कार्यों और उनका प्रगति के बारे में अपनी त्रमासिक रिपोर्ट ग्राम समा के समक्ष प्रस्तुत करे, जिन पर कि ग्राम समा की मीटिंगों में विचार विनिमय हो तथा किए गए प्रतिवादों व सुझावों का लिखित विवरण हो जिन पर कि पचायत विचार करे । स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि से ग्राम समा को अपनी छुट्टी की तरफ से भी प्रस्ताव रखने की छूट हो । पचायत को चाहिए कि वह सामान्य निम्नलिखित मुद्दों पर ग्राम समा का राय मांगे और उधर से ही ग्राम समा के विचारणीय मुद्दे भी हों —

- १ पचायत द्वारा निमित्त योजनाएँ और उनका आय-व्यय विवरण
- २ गांव के लिए उत्पादन वृद्धि-योजना की प्रगति और उसकी क्रियाविधि पर टिप्पणी
- ३ विभिन्न कार्य-समितियों की कार्य प्रगति के बारे में अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट
- ४ पचायत की वार्षिक रिपोर्ट और आय-व्यय विवरण
- ५ पचायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट का संक्षिप्त सार
- ६ ग्राम स्तरीय वृद्धि काम की गतिविधियाँ के बारे में अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट
- ७ सामुदायिक विकास के निर्माणयोगी कार्यों की प्रगति पर आधारित अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट
- ८ मध्याह्नि एवं दीपावलि ऋणों के उपयोग पर आधारित अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट
- ९ ग्राम स्वयं सेवक संघ और सुरक्षा भ्रम कीय के कार्यों का सर्वेक्षण—

ग्राम समा पचायत या पचायत समिति के किसी विशेष कार्य की जांच परखाल करने अथवा उसका सही समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी निवेदन कर सकती है । यह एक नियम हो कि पचायत या पचायत समिति अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य की करने के निमित्त काम उठाने के पूर्व ग्राम समा की राय जान लें । सक्षम म इतना ही कहना काफी है कि पचायत, प्रत्येक कार्य के लिए अपने आपकी ग्राम समा के प्रति उत्तरदायी समझ । क्योंकि पचायत ग्राम समा की कार्यकारिणी है मत उसके कार्य और कार्य प्रणाली निश्चित की जाकर उस संगठन बनाने और ग्राम समा के साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर दिए जाने के प्रतिष्ठान ग्राम समा की शोचस्वता प्रधान करना होगा ।

## ग्राम पचायत की आय व्यय पर ग्रामसमा की स्वीकृति और नियंत्रण

ग्रामसमा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पचायत द्वारा तयार किए गए वार्षिक आय-व्यय विवरण (बजट) पर विचार करना है । जिस किसी राज्य में ग्रामसमा का अस्तित्व कायम हो चुका है वही राज्य उनसे इसकी उम्मीद की जाती है । पर पचायत के द्वारा निमित्त आय-व्यय विवरण वृद्धि उत्पादन-योजना की भाँति ही, सामान्य ग्रामीण 'यति' के लिए सुग्राह्य नहीं होता और इसीलिए इसपर विचार करने वाली समा के लिए यह हर दशा में प्राश्नोत्तर या विधि-सम्मत हो गया है । पर यदि किसी भी भाँति इस महत्वपूर्ण कार्य में 'समा की रवि हा हो तो फिर इसे (बजट) सरल से सरल बनाना अनिवार्य होगा जिससे

कि ग्रामसभा इसकी मान्यता को पूरा रूपेण ममभ सके और इसपर विचार कर सके। ग्राम-व्यय विवरण (वज़न) पर पहले 'उप ग्राम सभा' की मीटिंग में विचार विमर्श किया जा सकता है तब विचार करने के लिए 'ग्रामसभा' के समक्ष रखा जा सकता है। पचासत यह भी बत सज़ती है कि मूल ग्राम-व्यय विवरण के साथ ही साथ उसका सार भी तैयार करले और तब विचार करने हेतु ग्रामसभा के समक्ष रखे। ग्राम व्यय विवरण की प्रतिलिपि सूचना-पट्ट पर भी लगाइ जानी चाहिए जिससे कि उसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति ग्रमवा मनुष्य या ग्रम्य सस्था उसका अध्ययन व मनन कर सन और सभा की मठक में विचार करत वक्त ग्रमिण दोस राय दे सके। इस प्रकार ग्राम-व्यय को समझ लेना ग्रामसभा सदस्यो के लिए अधिक सहज हो जायगा। लवर धाड बाइज को जाने वाली 'उप ग्राम सभा' की मीटिंग में विचार करने हेतु वृत्ति-ज्वाइन-योजना, सुरक्षा धम शीप ग्राम स्वयं सेवक, सेना तथा स्त्रिया और समुदाय के कमजोर तबवा के वलय हेतु योजना आदि रखी जा सकती है।

## कार्य-समितियाँ

ग्राम समितियाँ का मुख्य काम ग्राम सभा की सलाह दात्री रूप का होना चाहिए। इनके चुनाव और राय, विचार विनिमय हेतु पचासत द्वारा ग्राम सभा के पास प्राप्त कर दी जानी चाहिए।

## ग्राम सभा में प्रश्न करने के लिए समय

ग्राम सभा के प्राप्त प्रत्येक कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं इसलिए ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में प्रश्न पूछे जाने का एक मुनिश्चित समय हो जब सभा के प्रत्येक सदस्य वहाँ उपस्थित सरव व पचासपायिकारी ग्रमवा व वा से प्रश्न पूछ सकने के लिए स्वतन्त्र हो। इस प्रकार ग्राम सभा का विशाल समस्या-समाधान कारक सस्था के रूप में हो सकेगा और यदि यह इस प्रकार कुछ ही हूँ तक सही पर यदि किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके तो यह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगी।

## ग्राम सभा के अन्य कार्य

### ग्राम सभा और कृषि उत्पादन योजना

ग्राम तो देखा यह जाता है कि गाव के लिए वृत्ति-उत्पादन की जो भी योजना बनती है, न तो उसने धनान में ही ग्रामीण-जन कोइ रुचि लेते हैं और न ही वह योजना सही माने में गाव की वृत्ति-उत्पादन का बढान में ही कारगर सिद्ध होगी है परिणामत इस दृष्टि से भी ग्रामीण जन इसमें कोई रुचि नहीं लेते। गाव की वृत्ति उत्पादन के लिए आज जा ऐसी योजनाये बनती हैं वे किसी भी दृष्टि से गाव के लिए पूरा नहीं होगी। इन योजनाओं का निर्माण ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों द्वारा सरव व ग्रमवा गाव में नतायिरी करने बात कुछ इने मिते लोगों की सलाह के आधार पर कर लिया जाता है।

जहा तक गाव की वृत्ति-उत्पादन योजना का सम्बन्ध है, ग्राम सभा मुख्य रूप से जहाँ योजनाओं में रुचि ले सकती है —

- 1 जो धनदान ग्रमवा किसी ग्रम्य विधि से गाव के अतिरिक्त धन के उपयोग का माग लोन से, और

२ साथ ही यह भी देखा जाता रहे कि कृषकों को ठीक समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार, बीज खाद और अन्य साधन उपलब्ध हो रहे हैं [कि नहीं] ।

## सहकारी समिति : पंचायत और ग्राम सभा

आज पंचायत और सहकारी समिति जो प्रायः प्रत्येक राज्य में अपना अस्तित्व पायम कर चुकी हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं करती हैं। पर यदि पंचायत ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाई है तो सहकारी समिति भी ग्राम स्तर पर आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त कराने व करने हेतु कार्य सम्पादित करने वाली इकाई है। अतः पंचायत और सहकारी समिति के मध्य सहयोग की भावना का होना ही परम अनिवार्य नहीं है बल्कि गांव की सभी याजनाया और कार्यों के पूर्ण करने में इन्हें एक दूसरे के साथ पूर्ण सन्निध सहयोग स्थापित करना भी परम अनिवार्य है। इस दृष्टि से ग्राम सभा ही वह कड़ी हो सकती है जो पंचायत और सहकारी समिति के मध्य प्रत्येक कार्य में एक दूसरे से सन्निध सहयोग मने की भावना की स्थापना कर सकती है। इसके लिए एक सुझाव है कि पंचायत का सरपंच सहकारी समिति की व्यवस्थापिका का सदस्य हो और उसे ग्राम सभा के प्रतिनिधि के रूप में पक्ष या विपक्ष में अपना मत देने का पूर्ण अधिकार हो।

## ग्राम सभा के लिए कार्यपालिका

ग्राम सभा और पंचायत के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप देने की दृष्टि से, जिन्हें कि पुनरचना के बाद और अधिक कार्य करने पड़ेंगे ग्रामसभा के रेकाड की हिफाजत और उसे समुचित मात्रा में सन्निध रखने के प्रयत्नों को चालू रखने के लिए ग्रामस्तरीय कार्यकर्ताओं और पंचायत सचिव को इस दिशा में भी कार्य करने को कहा जाना चाहिए। यदि हो सके तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इस हेतु पूरे समय के लिए प्रसिधित कार्यकर्ताओं को नियुक्त भी कर सकती है।

# लोक सभा की रचना का आधार ग्राम सभा हो ।

—श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा

लोकसभा का भवन इत घोर अमेघ हो इसके लिए उसके ऊपरी स्तरो का उसके बुनियादी ढांचे पर खड़ा होना अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन इसके विपरीत आज हम देखते हैं कि भारीभारत ढांचा केवल जिलास्तर तक ही उठाया जाता है । इसके बाद अथवा राज्य और संघस्तर पर एक बिहङ्गल भिन्न ढांचा हमें देखने का मिलता है यह ढांचा अथवा प्राथुनिक लोकसभा का ढांचा व्यक्तिगत और समयावधिबद्ध मतदाताओं के रूप में बालू के ढेर पर टिका हुआ है । इस स्थिति का परिणाम यह होना है कि देश के मतदाता अपने आपको लोकसभा के शासन प्रक्रिया से बाहर छोड़ देते हैं । तथा इस प्रकार की धारणा हमारे लोकसभा के लिए ठीक नहीं है । यह किसी भी समय अच्युत स्थिति पदा कर सकती है । प्राथुनिक प्रजातन्त्र में लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अनुसार देश के मतदाताओं को मतदान करने का अवसर प्राप्त होता है मतदान मिल जाता है वरन् लोकसभा के कार्यन्वयन में उनका कोई योगदान नहीं होता है । अतः हम देहात के लोगों से यह सुनते हैं कि हमारे देश में स्वशासन प्रणाली अथवा, लेकिन अभी वह उनके पास नहीं पहुँच पाया है । उसकी निश्चित है कि उन पर उसी ढांचे से और उसी क्रम के लोगों द्वारा शासन किया जाता है जसा कि ब्रिटिश शासनकाल में हुआ करता था । वे कहते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासन में भी उनका कोई हाथ नहीं है और छोटे से छोटे पंचायती भी किसी भी रूप में उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है । इसके अलावा वे देखते हैं कि यह छोटे से छोटे पंचायती भी ऊपर हुकूमत का रोब मारता है और पुराने शासन की भाँति ही उनके साथ व्यवहार करता है । इससे स्पष्ट है कि देश की जनता ने अभी पूर्णरूपेण स्वशासन को बचू न नहीं किया है । इसके लिए हमारे वर्तमान लोकसभा में शोध सभा की चुनाव प्रणाली जिम्मेवार है । इस प्रणाली के निम्न दोष प्रतिलक्षित होते हैं —



यह प्रणाली यत्तिगन मतदाताओं पर आधारित है इसलिए इस प्रणाली में अनिवार्यतः उच्चस्तर पर सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो सत्ता का नाचे जनता की ओर विचार कर सक। मतदाताओं के पास, उनकी सभा चाह करोटी ही करो न हो शक्ति का ऊपर की ओर खींचा जाना रोखने के लिए कोई मध्यात्मक साधन नहीं है। कुछ लोग का मत है कि इसके लिए शक्ति का दल है। यह बात अभी बिल्कुल सही है। लेकिन यह प्रवृत्ति कुछ को सन्तुष्ट कर गट में शामिल है। इसके अलावा कुछ विचार स्वाभाविक होते हैं जिस कारण भी सत्ता का केन्द्रीकरण होना आवश्यक हो जाता है।

२—इस पद्धति के अंतर्गत कुछ राजनतिक दल जो कि सघटित हैं जिनका कि नियंत्रण थोड़ा सा विविध लोग के हाथों में होता है नियमित भूमिका होती है।

३—इस पद्धति में मतदाताओं का अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नियंत्रण करने का कोई साधन नहीं है। कुछ लोग का मत है कि यदि मतदाता जान उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर रहे हैं तो मतदाता उन्हें फिर नहीं चुन सकते हैं। बात सही भी है और नियंत्रण की प्रणाली भी उचित है लेकिन यह बहुत दूरस्थ और प्रभावहीन छग का नियंत्रण है।

इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों का कहना है कि जन प्रतिनिधियों के अपने राजनतिक दल भी उन पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि दल का नियंत्रण मतदाताओं के नियंत्रण से बिल्कुल भिन्न वस्तु है।

४—इस प्रणाली में देश की जनता का यांगदान मत देने तक ही सीमित होता है। देश की वायप्रणाली में उनका कोई भाग नहीं होता है जिससे कि उनमें देश की नियाओं के प्रति उदासीनता आ जाती है।

५—इस पद्धति में चुनाव प्रत्यक्ष सर्वांगी होते हैं तथा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम चाहिए और उस प्रकार में अत्यन्त मोबाइल और भावात्मक उत्तेजा पैदा हो जाती है जो कि समाज के लिए विपत्कार होती है।

६—इस प्रकार की पद्धति का म अधिकांश मतदाताओं के लिए अधिक सम्भावना यही रहती है कि चुनाव के समय में जो प्रश्न उनके सामने रखे जायें उन्हें वे ठीक प्रकार से समझ नहीं पायें। क्योंकि उन प्रश्नों से सम्बंधित सामग्री से उनका कोई सरकार नहीं होता है।

एक प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हमारा वर्तमान लोकतन्त्र अत्यन्त दोषपूर्ण एक अशुचित ढांचे पर आधारित है। यही कारण है कि अभी तक हमारे जनता की स्वराज्य का सन मनी पैदा करने वाली भावना का अहसास नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जनता का हमारे इस राजनतिक प्रणाली में कोई योगदान नहीं है, हाँ केवल शक्ति वर्ग का थोड़ा सा ही लोगों का और उनमें से भी उनका ही जिनका सम्भव प्रत्यक्ष राजनतिक निया-यत्तापन से है कुछ योगदान हमारा लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रिया में है।

हमारा आधुनिक लोकतन्त्र जो कि लोक सभा का दीर्घपुत्र प्रणाली पर आधारित है एक एस उलट पिरामिड की भांति है, जो गिर के बल खाता है। इस उलट पिरामिड से हमारा तात्पर्य एनी पासन प्रणाली से है जिसका आधार स्वयं तो अत्यन्त बलवन्त है और ऊपरों व्यवस्था ज्यादा मजबूत है। इस प्रकार वे बच्चे का घरानापी होना का बच्चे भी भय हो सकता है। इस बात का स्पष्टीकरण यह एक उदाहरण लेकर लिया जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ चार या पांच व्यक्ति एक ग्राम में पड़ म स ग्राम खाने के चन्द्र हैं। लेकिन वह पड़ ऊंचा है। प्रत्येक स्वयं व्यक्ति उस पड़ में स ग्राम उपलब्ध नहीं कर सकता है। इन पांच के लिए व सब एकत्रित होने या सम्मिलित होने हैं या सहयोगी बनते हैं। पड़ में से फल प्राप्त करने का उनका सम्मेलन म केवल एक ही साधन है और वह है एक के ऊपर एक पर रखकर घटने से यानी एक पिरामिड बनाकर व फल प्राप्त कर सकते हैं। नाचे वाला व्यक्ति कमजोर है और ऊपर वाले मजबूत। ऊपर वाला नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर पर रखकर चढ़ जाता है और ग्राम उपलब्ध कर के स्वयं ही खान लग जाता है तथा नीचे वाला व्यक्ति इसका नाराज होकर जवा बोलता पड़ जाता है जिससे कि ऊपर वाला व्यक्ति भाग या त्रिधा सहित नीचे भाकर गिर जाता है। और इस प्रकार उनका सहयोग का कार्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार का बात लोकतन्त्र के साथ भी लागू होती है यदि नीचे वाला व्यक्ति कमजोर है तो ऊपर वाला अवश्य ही एक न एक दिन गिरता ही। इसके लिए आधार स्वयं अत्यन्त दृढ़ एवं अश्रेय होना चाहिए।

केवल यह तथ्य कि हर व्यक्ति भारतीय को मत प्रदान करने का हक है शासन प्रणाली के पिरामिड को व्यापक आधार नहीं प्रदान कर सकता है। करोड़ों की तादाद में बिखरे हुए व व्यक्तिगत मतदाता बाबू कण के एक ऐसे ढेर की भांति हैं जो किसी भी रचना की दृष्टि पर अश्रेय सुनिश्चित नहीं बन सकते हैं। इसलिए यदि वास्तविक या कम्पायणकारी लोकतन्त्र की स्थापना हमारे देश में करती ह, तो हमें इस बाबू क बिखरे हुए कणों को ईंटा का रूप देने के लिए मिलाना होगा या ककरोट जैसे सांचे में डालना होगा तभी ये नीचे के परतों का रूप ग्रहण कर सकेंगे। किसी भी इमारत का उनका रूप निश्चय ही विनाशक न हो, स्थायित्व उसकी सुनिश्चित और निरन्तर स्तरी की मजबूती पर निर्भर होता है। यदि इमारत का आधार मजबूत होगा, तो किसी भी ढांचे का किसी सांस्कृतिक के छूट भर स सहारा कर गिरने का क्षमता नहीं रहेगा। लोकसभा की रचना जोकि वर्तमान लोकतन्त्र का स्वयं है ग्राम सभा के आधार पर होनी चाहिए। यह प्रणाली उपराक्त प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। वह इसलिए कि इस लोकतन्त्र का ढांचा ग्राम सभा के आधारभूत स्तर से शुरू होकर सोवसना तक कई स्तरों पर होता है और हर स्तर के प्रतिनिधि, कार्य कर्ता और साधन स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट होते हैं, इसलिए इस पद्धति में सत्ता का वितरित होना लाजिमी है। साथ ही ऊपरी स्तर निचले स्तर की समस्याओं के प्रतिनिधियों का मंचन होने के कारण बनाए ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर की ओर सत्ता लागू किये जान की सम्भावना रहती है। इस तरह ऊपरी स्तर के प्रतिनिधियों पर निचले स्तर की समस्याओं की सतत दृष्टि रहती है और इसलिए इन समस्याओं का उन प्रतिनिधियों पर नियंत्रण भी रह सकता है। महा यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि किसी भी स्तर पर ये समस्याएँ सहज ही यंत्रियों का सामग्रित मात्र नहीं होना बल्कि ऐसी सुसंयोजित सर्वाधिक संख्या होती है जिनके निश्चित आनुवंशिक प्रकार और कर्तव्य होते हैं।

ग्राम-सभा के आधार पर लोक सभा की रचना पर स्थित लोकतन्त्र प्रणाली में निम्नलिखित गुणों का समावेश होता है —

१—इस प्रणाली में सत्ता के विकेंद्रिकरण की ओर झुकाव रहता है क्योंकि इस प्रकार के लोकतन्त्र का ढांचा, प्राथमिक व आचारमूल स्तर से गुंथ होकर लोकसभा तक कई स्तरों में होता है और हर स्तर के अधिकार, कार्य वक्त-व्य और साधन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं। इसके प्रतिनिधित्व ऊपरी स्तर निचले स्तर की समस्याओं के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होने के कारण बचाए ऊपरी स्तर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर सत्ता लाने की जाती है।

२—इस पद्धति में प्रथम पद्धति के विपरीत नीचे के स्तर में काम करने वाले समुदाय और सामुदायिक प्रतिनिधि संस्थाओं निर्णायक प्रभान डावती हैं।

३—इस पद्धति में निर्वाचन करने वाली संस्थाएं अपने द्वारा उपर भेजे गये प्रतिनिधियों पर लगातार नियंत्रण रखती हैं क्योंकि निम्न स्तर की संस्थाओं की सतत दृष्टि उच्चस्तर के प्रतिनिधियों पर रहती है।

४—इस पद्धति में ग्राम सभा के द्वारा पूरी जनता का प्रत्यक्ष योगदान रहता है और उच्च प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा भी काफी घनिष्ट योगदान रहता है।

५—चुनाव खर्चीले नहीं होते हैं तथा बुरादया कम से कम होने की संभावना रहती है।

६—इस प्रणाली में यह मांग की जाती है कि जो प्रश्न चुनावकाल में मतदाताओं के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें, उनको वे ठीक प्रकार से समझें क्योंकि भविष्य में उनको उन प्रश्नों से सम्बंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना पड़ता है।

उरोक्त दोनों प्रकार की पद्धतियों की तुलना करने के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि विधान सभा ■ आचार पर क्या विधि अपनाई जानी चाहिए जिससे कि लोकतन्त्र की नींव को हट एवं अमेध बनाया जा सके। इस प्रश्न के उत्तर के हल में निम्न विधि का विवेचन किया गया है —

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित साधारण बैठक में निवाचक मंडल के लिए, जिसे निर्वाचन परिषद् भी कहा जा सकता है, इस विधि से दो प्रतिनिधि चुने। इस बैठक में उम्मेदवारों के लिए नाम मागे जाए और प्रस्तावित तथा समर्थित नामों की सूची संघेष्ट रूप से वहां रखे द्यामपट्ट पर अंकित की जाए। यदि दो नामों से अधिक का प्रस्ताव न हो तो वे आप से आप निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं। अन्य स्थिति में प्रत्येक नाम पर मतदान होना चाहिए। यह मतदान हाथ उठाकर होना चाहिए। हर उम्मादवार द्वारा प्राप्त मता की द्यामपट्ट पर अंकित किया जाना चाहिए। दो से अधिक उम्मादवारों की स्थिति में ऐसा मतदान बार-बार होना चाहिए। और सब से कम मत पान वाले उम्मादवारों को छात्रे जाना चाहिए। यह विधि चुनाव की प्रत्यक्ष रूप खर्चीली विधि है। जया जया ग्राम सभाओं बैठने आयोजित करने बजट पास करने और ग्राम सामूहिक निर्णय के रूप में अनुभव प्राप्त करती जायेंगी यह चुनाव पद्धति उनके लिए आसान बात हो जायगी। निर्वाचन करान में बारम्बार में जो कठिनाइया आये वे भी पचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में लिए गए पूर्वान्यास द्वारा दूर की जा सकती हैं।

यह चुनाव हो जाने के बाद निर्वाचन परिषद आयोजित की जानी चाहिए। क्षेत्र के किसी केन्द्रीय स्थान में विधानसभा या लोकसभा के सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र की ग्रामसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक की जानी चाहिए। निर्वाचन परिषद को निर्वाचन के नियम उम्मीदवारों को मनोव्यय करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाए —

सब प्रथम उम्मीदवारों के नाम धारित जाए और तब हर प्रस्तावित और समर्थित नाम पर मत (वोट) दिए जाए। एक निर्धारित प्रतिशत—उदाहरणतया 30 प्रतिशत से अधिक—मत पाने वाले व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार घोषित किये जाने चाहियें।

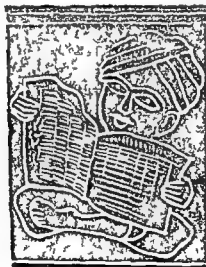
लोकतन्त्र की चरितापत्ता के लिए, यह लोकतन्त्र चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी प्रक्रिया में जितना कम मत विभाजन हो उतना ही अच्छा है। अधिक स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वहाँ जहाँ तक सम्भव हो सके, एकतामूलक हो इसलिए विविध शास्त्रात्मक और वैधानिक उपायों द्वारा निर्वाचन-परिषदों को एक सीट के लिए एक उम्मीदवार से ज्यादा न लड़े करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। आखिरकार अन्तिम रूप में पूरे निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति ही करता है उम्मीदवारों की संख्या चाहे जितनी हो और चुनाव की विधि चाहे भी क्यों न हो। यहाँ अपना सत्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से है। शास्त्र में यह बात बहुत सराव है कि एक बार जो प्रतिनिधि चुन लिया गया और उसका चाहे कितना ही प्रबल विरोध क्यों न हुआ हो, वह पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वह उनकी भी सेवा करता है, जिन्होंने उसका विरोध किया था। यदि निर्वाचन परिषदों को केवल एक ही उम्मीदवार का चयन करने के लिए राजी किया जा सके, तो यह असंगति और व्यय की उत्पत्ति उत्पन्न होगी और ऐसे की बर्बादी बचायी जा सकती है। यदि कुछ क्षेत्रों में यह व्यावहारिक न हो, तो कथन बताए गए से चुने गए व्यक्तियों के नाम उम्मीदवारों के रूप में घोषित कर दिए जाए और अन्तिम निर्वाचन निम्नलिखित रूप से किया जाना चाहिए —

निर्वाचन परिषद द्वारा चुने गये उम्मीदवारों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं के पास भेज दिए जाए। फिर हर समाग्राम बैठक का आयोजन करे और हर उम्मीदवार के नाम पर मतदान कराया जाए। उसके बाद निम्नलिखित दो विधियों में से एक अपनाया जाना चाहिए —

( १ ) सबसे अधिक संख्या में वोट पाने वाले की घोषणा—ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिस सम्बद्ध 'ग्रामसभा' अपने प्रतिनिधि के रूप में उच्च 'सभा' में भेजना चाहती हो। ऐसे सब व्यक्तियों में से जिसने सभी ग्राम सभाओं में सबसे अधिक मत मिले उस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा या लोकसभा ( जिसके लिए भी चुनाव हो ) का सदस्य घोषित किया जाए।

( २ ) विह्वल प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा की साधारण सभा में पाए गए मतों को ध्यान में रखा गया जाना चाहिए। तब प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा पूरे निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न ग्रामसभाओं की बैठकों में प्राप्त मतों को जोड़ लिया जाए। इस प्रकार सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचनक्षेत्र का सदस्य हो जाता है।

1 इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम सभा के आधार पर लाभकारी रचना को चुनाव प्रणाली के द्वारा स्वराज्य की संरचना की भावना देश के छान छोटे गांवों तक पहुंच जायगी और हमारे राजनीति की नींव अत्यधिक ठोस हो जायगी तथा परिवर्तन के लोकोत्तमों से यह मिश्र एवं श्रेष्ठतम होगा। इस तरीके द्वारा हमारी कई मनचाही बातें पूरी हो जायेंगी। प्रथमतः यह है कि लोकतन्त्रवादी ढांच के ऊपरी स्तर को रचनात्मक ढंग से नीचे के स्तर से सम्बद्ध कर देना और ग्रामसभाओं की स्थानीयता के दलदल से उठा कर उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान और सोद्देश्यता प्रदान कर देंगे। दूसरे यह कि प्रत्यक्ष वाणिज्य नागरिक को लोकतन्त्र की ऊँची से ऊँची संस्थाओं के निर्वाचन में भागदान करने का अवसर मिलता है और वह यह कार्य सगठित रूप में ग्राम सभाओं और निर्वाचन परिषदों द्वारा करते हैं जिससे वे अपने प्रतिनिधियों पर उपयुक्त प्रभाव डाल सकते हैं। सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाशनारायण ने इस सम्बन्ध में कहा है 'कि इस रूप में व्यक्तिगत मतदान बालू के षण्णों की तरह बिखर जाये और असहाय न होकर परस्पर के दृढ़ खण्ड बन जाते हैं। परस्पर के खण्डों की नींव पर बना हुआ मकान बालू पर बन मकान से भिन्न होता है।'



सु-५

# पंचायती राज की वित्त-व्यवस्था



- १ मधान्त समिते के सदस्य मे पंचायती राज की वित्तीय व्यवस्था का सिद्धान्तोक्तन  
—श्री हरिपाद शार सुब्रह्मण्य चव्पर १-३
- २ पंचायती राज वित्त निगम-समठन, स्वरूप और दायित्व—श्री रेवाशकर ४-७
- ३ पंचायती राज के आय के साधन और व्यय के प्रावधान ८-१५





## संथानम् समिति के संदर्भ में पंचायती राज की वित्तीय व्यवस्था का सिंहावलोकन

— श्री हरिपाद आर० मुन्नमण्य अय्यर

★

● बलबनराय मेहता समिति की नियुक्ति पिछले वर्ष इस बात के लिए हुई थी कि पंचायती राज का कामकाज का विस्तृत अध्ययन कर के ऐसे उपाय सुझाए जाएँ जिससे पंचायती राज संस्थाओं की ईमानदारी भी बनी रहे और उनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो जाए। समिति कानून में सघोषण करने का सुझाव भी दे सकती थी। यदि समिति की सिफारिशों पर सही ढंग से क्रमल किया गया तो उनका दग म पंचायती राज के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस समिति की दो महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी—

(क) राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सम्बन्ध एस हो होने चाहिए जसे कि फ्राइबल केन्द्रीय और राज्य सरकारों के हैं।

(ख) राज्या में लगान से जितनी भी आमदनी हो, वह पंचायता राज्य संस्थाओं के लिए रख दी जाए।

उपरोक्त सिफारिशों में जिस दिशा की ओर इंगित किया गया है उसमें के० सन्थानम् अध्ययन टोली की सिफारिशों की ही बल मिलता है। इस टोली की नियुक्ति पंचायती राज के वित्तीय स्थापन बढ़ान के प्रश्न पर विचार करने के लिए की गई थी।



यह दखना अभी बाकी है कि केन्द्रीय सरकार न सिफारिश का वहाँ तक और किस रूप में स्वीकार करती है परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण पचायती राज सस्थाओं के कामकाज में बहुधा बाधा पहुँचती है।

भारत में, और खास कर गांवों में स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ सदा से ही गरीब रही हैं। पचायती राज सस्थाओं के कामकाज का पचायतों की वित्त व्यवस्था से घनिष्ठ सम्बंध है। इसलिए उनके वित्त समस्या पर विचार कृत समय उनके कामकाज पर विचार करना भी जरूरी हो जाता है। भारतीय संविधान की एक खास बात यह है कि उसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बंधों का स्पष्ट वर्णन है। इससे अनुसार केन्द्रीय राजस्व के साधनों का केन्द्र और राज्या में बंटवारा किया गया है। परन्तु स्थानीय निकायों का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन निकायों को भी अधिकांशतया उही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो राज्यों के लिए निर्धारित हैं। इसके प्रतिरिक्त पहले इन स्थानीय निकायों को कर लगान के बहुत से अधिकार दाने थे। परन्तु उन्हें अब राज्य सरकारों ने छीन लिया है। स्थानीय वित्त का प्रयोग न सिफारिश की भी कि करो कुछ निश्चित साधनों से प्राप्त आय का पूरी तरह स्थानीय सस्थाओं का ही सौंप दो जाय या उन्हीं के लिए खर्च कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में हम सुवर्ण राज्य अमेरिका में प्रचलित प्रणाली अपनानी चाहिए जहाँ स्थानीय सस्थाओं के अपने ही प्रत्यक्ष साधन होते हैं।

जोवन्ती की विकेंद्रिकरण के बारे में एक प्रमुख सिफारिश यह भी कि पचायती राज सस्थाओं को मन्चे वर्षों में सत्ता और उत्तरदायित्व सौंप जाए और साथ ही उन्हें पर्याप्त वित्तीय साधन भी सौंपे जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभा सकें। परन्तु ऐसा अब तक भी नहीं किया गया। हर राज्य में पचायती राज सस्थाओं के वित्तीय साधनों का दावा भिन्न भिन्न है। पचायती राज योजना लागू होने से कई समस्याएँ पैदा हो गई हैं और इनमें सबसे बड़ी है वित्तीय साधनों का प्रभावहीनता। पचायती राज के अधीनस्थों के साथ ही देहाती इलाकों के अधिकांश विकास कार्यक्रम पचायती राज सस्थाओं को सौंप दिए गए हैं। यह दोहरान में कोई फायदा नहीं कि पचायती राज सस्थाओं के साधन बहुत सीमित और अनमनीय हैं। इसके प्रतिरिक्त स्थानीय सस्थाएँ भी मकान कर व्यवसाय कर बाहन कर आदि लगान में बहुत हिचकिचाती हैं यद्यपि इन्हीं से ही स्थानीय सस्थाओं की आय बढ़ती है। यह स्थिति वास्तव में निराशाजनक है परन्तु और तौर पर इसका कारण यही लगता है कि गांव बांध धांपिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। गरीबी के कारण गांव वाले भी इस स्थिति में नहीं होना कि घर के सफे और स्थानीय सस्थाएँ भी घर लगा कर अपनी आय बढ़ा सकें। अब एकाग्र करने के प्रयत्न सामान्य भी चले हैं। इसलिए पचायती राज सस्थाएँ चक्कर में पड़ जाती हैं कि अपनी भारी जिम्मेदारियाँ को किस तरह निभावे। इनके प्रतिरिक्त कई और भी कठिनाइयाँ होती हैं। पचायती राज सस्थाओं के भी सरकारी अधिकारियों में ईर्ष्या और होठ की बहुत भावना रहती है जिसका बुरा प्रभाव उनके कामकाज और विचारों पर पड़ता है। कर निर्धारण करने और लगाने में भेदभाव के वृत्तों में मामलें घाते रहते हैं। परन्तु सब से बुरी बात यह है कि निर्धारित कर को वसूल नहीं किया जाता। इसी कारण देश की स्वायत्त शासन की प्रायः समस्त सस्थाओं की बकाया करों की भारी रकम पड़ी रहती है। भारी मात्रा में बकाया रहने का एक कारण तो यह है कि बकाया कर वसूल करने वाले कामचोरों के समय पर कर वसूल करने में देरी होता है और दूसरे ऊँचे अधिकारियों दोषी लोग को सजा

दन में हितनिष्ठाने है। इसके अतिरिक्त कर्मचारीगण ग्रामतौर पर अकुशल होते हैं और उच्च अधिकारी प्रभावकारी ढंग से उनकी देखभाल नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में बर बसूल करने का काम बड़े असंतोष जनक ढंग से होता है। फिर कर निर्धारण की वर्तमान प्रणाली भी दोषपूर्ण है। कर निर्धारण का काम तकनीकी होता है और यह काम अपने विषय का अच्छी तरह समझ वाले विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। साथ ही ऊँचे अफसरों को भी बड़ी देखभाल रखनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज इन सभी बातों का अभाव है। इस स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब ग्रामिकारी अधिकारी कुछ व्यक्तिगतरूप से कर उगाहने का जिम्मेदारी उठाए और बकाया वसूल कराने के लिए भी कदम उठाए जाए और तुलान कार्रवाई की जाये।

संस्थानम समिति की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाए जो ग्रामवती देने वाले कामों के लिए कज दे जसे मण्डी दुकानों थियेट्रो होटल आदि का निर्माण। परन्तु कुछ राज्य सरकारें और जीवन बीमा निगम प्रस्तावित निगम से सम्बंध जोड़न में हिचकिचा रहे हैं। हाल में केन्द्रिय सरकार ने दो या तीन राज्यों में प्रयोग के तौर पर पंचायती राज निगम बनाने का फैसला किया है। जब ये सफलतापूर्वक कामकाज करने लगेंगे तो अन्य राज्यों में भी इनकी स्थापना की जायगी। यद्यपि संस्थानम समिति ने सिफारिश की थी कि मकान कर व्यवस्था कर और बाहन कर पंचायती द्वारा लगाए जान वाले अनिवार्य कर होने चाहिए परन्तु हमने देखा है कि कुछ राज्यों में अधिकारीगण ये अनिवार्य कर लगाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके गांव वालों का आर्थिक दशा बहुत पिछड़ी हुई होती है। इस तरह वर्तमान परिस्थितियों में यह बहुत सदेहजनक ही है कि स्थानीय अधिकारी संस्थानम समिति की इस सिफारिश को मान लेंगे। दूसरे ग्रामतौर पर गांववालों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कर न चुकाए जाए क्योंकि उन्हें कर चुकाने और बदले में होने वाले लाभों में कोई सम्बंध दिखाई नहीं देता। इसलिए जब तक गांववालों के चुकाने का विरोध करते रहेंगे तब तक संस्थानम समिति की सिफारिश से उचित समस्या सुलभेगी नहीं। जब तक इस विरोध को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कर न तो प्रभावकारी ढंग से वसूल ही किये जा सकेंगे और न ही उनसे पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों में कोई वृद्धि होगी। जो लोग कर चुकाते हैं उन्हें उनका प्रत्यक्ष लाभ मिलना ही चाहिए। जब ये प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगेंगे तब लोग कर चुकाते समय इतनी हील हूज्जत नहीं करेंगे। ऐसा तभी होगा जब कुछ खास कामों के लिए कर लगाए जाए और करों में प्राप्त रकम उही खास कामों पर खर्च की जाए। स्थानीय वित्त व्यवस्था की यह एक खास बात होती है।

सब बात तो यह है कि यदि स्थानीय अधिकारी गांववालों से कर वसूल नहीं कर पाएंगे, तब पंचायती राज संस्थाएं भी कुशलतापूर्वक और प्रभावकारी ढंग से काम नहीं कर सकेंगी। सरकार का यह उद्देश्य होता चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं के हाथ मजबूत करे ताकि गांववालों को आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारी जा सके। इस परिस्थिति में महता-समिति कि यह सिफारिश देखकर प्रसन्नता होता है कि केन्द्रिय सरकार को ही पंचायती राज संस्थाओं की मदद करनी चाहिए क्योंकि आजकल राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे पंचायती राज संस्थाओं की समुचित अनुदान दे सकें।



## पचायती राज वित्त निगम

# संगठन, स्वरूप और दायित्व

\*

—श्री रेवाशङ्कर

आज देश के लगभग सभी राज्या में पचायती राज संस्थाओं का जन्म हो चुका है और अपने अपने तरीके से वे सभी आगे बढ़ रही हैं किन्तु सभी राज्यों में आज इन संस्थाओं के समस्त वित्तीय साधनों का अभाव एक भ्रष्ट चिह्न बना हुआ है और सरकारी अनुदान तथा ऋणों के बोझ से यह संस्थायें किसी तरह अपने अस्तित्व बनाये हुए हैं। यद्यपि संबंधित कानूनों में पचायती पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में नए नए लगाकर वित्तीय साधन जुटाने के प्रावधान रचे हुए हैं किन्तु अपने ही हाथ में नए लगाकर साधन का सोखी आभोचना तथा असतोष का खतरा माल लेकर साधन जुटाने के लिए बहुत ही छोटे-छोटे प्रतिनिधि तयार हो पाते हैं। नए नए लगान की तो बात ही दूर रही मोड़ना करों की बमूली भी जितनी बड़ाई से नहीं की जाती जितनी अनिष्ट है और इसी का परिणाम है कि पचायतें तथा पंचायत समितियाँ सदा ही साधनों की कमी का रोना रोती रहती हैं। राजस्थान में तो इन पंचायत समितियों के समस्त अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन जुटाने में भी कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। अगर जो भी एक राज्य सरकार से पंचायत समितियों को अपने

क्षेत्र में पचायती की मारफत खर्च करने के लिए अनुदान अथवा कर्जों के रूप में मिलती है उसे वितरित करने में राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाये जाने तथा पक्षपात से काम लेने के कारण स्थिति और भी बदतर हो जाती है। वही आवश्यकता से भी अधिक खर्चा पहुँच जाता है, तो कमी अनिवार्य खर्चों के लिए भी खर्चा नहीं होता। परिणाम यह होता है कि साधना का वितरण योग्य पूर्वक नहीं होना और विकास की प्रगति समान रूप से नहीं हो पाती है।

समस्या का एक पहलू और भी है। राज्य सरकारों द्वारा जिला परिषद पचायत समितियों तथा पचायती को दी जाने वाली रकमों की भी आखिरकार अपनी मर्यादा होती है। सीमित रकम को समूचे राज्य की इन संस्थाओं में वितरित करने पर प्रत्येक लोकतांत्रिक इकाई के हिस्से में इतनी थोड़ी राशि मिलती है कि उससे संबंधित क्षेत्र के विकास की योजनाएँ प्राथमिक रूप से भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार वित्तीय साधना की कमी तथा उपलब्ध राशियों के असमान एवं पक्षपात पूर्ण वितरण की जो स्थिति पिछले वर्षों में सामने आई है उन्हीने पचायती राज की सफलता को ही सदिग्ध बना दिया है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। यही कारण है कि भारत सरकार ने पचायती राज की उपलब्धियों के अध्ययन के लिए जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट (१९६३) में यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि इन स्वशासन संस्थाओं को ऋण और अनुदान दिए जाने का काम किसी ऐसे स्वतंत्र वित्तीय संगठन को सौंपा जाना चाहिए जिसके पास अपने भरपूर साधन भी हों और जो इस काम को निष्पक्षता पूर्वक भी कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या ३७) में कहा है —

‘हमारी यह दृढ़ धारणा है कि पचायती राज संस्थाओं को अपनी याचनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण राज्य सरकार के विभागों द्वारा पूरी तरह नहीं दिये जा सकते हैं, और जहाँ यह पर्याप्त मात्रा में भी दिये जाते हों वहाँ भी यह उपयुक्त होगा कि ऋण वितरण का यह काम किसी स्वतंत्र वित्तीय संस्था की मारफत किया जाय जो शुद्ध रूप से वित्तीय संगठन के रूप में काम करे और वित्त भी तरह के राजनीतिक दबाव से भी मुक्त रह सके।

## पचायती राज वित्त निगम

समिति ने अपनी रिपोर्ट में केवल यह सुझाव देकर ही अपने कर्तव्य की इति श्री समझ की हो ऐसी बात नहीं है। उसने कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक पचायती राज वित्त निगम का गठन किया जाना चाहिए जिसके लिए पूँजी की व्यवस्था राज्य सरकारों तथा इन संस्थाओं के मिले जुले साधनों से की जानी चाहिए। उक्त निगम की अधिकृत पूँजी के संबंध में राज्य सरकारों को निर्णय करना होगा और यह एक करोड़ से पाँच करोड़ रुपये के बीच में निर्धारित की जा सकती है, इस पूँजी को छुटाने के लिए जो सी सो रुपये के हिस्से जारी किए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार खरोदने के लिए दिए जा सकते हैं —

प्रतिशत

(१) पचायत, पचायत समितियाँ तथा जिला परिषदें	२०
(२) राज्य सरकार	२०
(३) केन्द्रीय सरकार	२०
(४) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम	२०
(५) सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनियाँ तथा राज्य में काम कर रहे अन्य वित्तीय संस्थाएँ	२०

यदि प्रत्येक पंचायत को एक सीयर तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए १० से १०० हिस्से रखे जावें तो वे घामानो में यह बरीद सकते हैं। राज्य सरकार को इस बात की गारंटी तो लेनी ही पड़ेगी कि निगम में लगवाई गई मूल रकम तथा न्यूनतम डिबीटेंड निश्चित समय पर मिल सकेंगे। निगम के हिस्सा की स्वीकृत प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटी) की सहमति दी जाए। निगम को यह भी अधिकार दिया जाए कि वह अपनी कार्यगोल धुजी की बढ़ान के लिए समय समय पर बांड्स तथा डिबेंचर भी जारी कर सकेगा और सरकार इनकी गारंटी करेगी।

## संचालक मंडल

निगम के संचालक मंडल का गठन निम्न प्रकार से होना चाहिये —

- (१) प्रबंध संचालक की नियुक्ति रिजर्व बैंक की सलाह से राज्य सरकार करेगी।
- (२) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा एक-एक संचालक (कुल तीन) नाम जद किये जावेंगे।
- (३) दो संचालक, एक तो जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा तथा एक पंचायत समितियों के प्रधानों द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (४) एक संचालक उन ग्राम संस्थानों द्वारा चुना जायगा जिनका उल्लेख पांचवीं अनुसूची में किया गया है।

निर्वाचित संचालकों का कार्यक्रम जहां चार वर्ष का होगा वहां नामजद किये गये संचालक उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि उन्हें नामजद करने वाली संस्थाय जारी रखना चाहे।

संचालक मंडल का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जायगा पर वह प्रबंध संचालक के प्रतिनिधित्व होगा।

निगम पंचायत पंचायत समिति अथवा जिला परिषद को उन सभी कामों के लिए ज़रूर दे सकेगा जिनका उत्तरदाय पढ़ने दिया जा चुका है इसकी अवधि ५ से २५ वर्ष तक सम्बंधित योजना के लिए आवश्यक समय के अनुसार हो सकती है। निगम को ऐसे विद्यमानों के प्रशिक्षण का काम भी हाथ में लेना चाहिए जो पंचायत राज संस्थाओं द्वारा समय समय पर हाथ में ली जाने वाली उन योजनाओं के सम्बंध में सवनाकी मार्ग दर्शन दे सकें जिनके लिए इस निगम से ऋण लिए गए हैं।

उक्त निगम के गठन की योजना का मुभाव सभी दृष्टियों से सवधा उपयुक्त तो है ही पंचायती राज की सफलता के लिए यह अनिवार्य भी है। यही कारण है कि सभी राज्य सरकारों ने इसे न केवल सिद्धांत रूप से स्वीकार ही किया है बल्कि इसका स्वागत भी किया था किंतु निश्चय ही यह बात निराशाजनक ही मानी जायगी कि अभी तक वही से भी इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के सक्त नहीं मिले हैं।

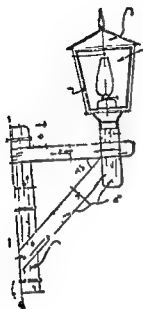
## लाभ देने वाली योजनायें

अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामदली वाली अनेक योजनायें पचायतों द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं इस प्रकार के प्रयोग उद्दीष्टों में विभे गये हैं, किन्तु इनके लिए वित्तीय माधन जुटान का काम भी कम कठिन नहीं है। राज्यों के स्तर पर अथवा केन्द्रीय सरकार में, ऐसा कोई वित्तीय सहायता दिखाई नहीं देती जो इस प्रकार की योजनाओं के लिए पचायती राज सहायताओं को सहायता दे सके। इस जिम्मेदारी को उपरोक्त नियम ही उठा सकता है। राज्य सरकारें इस नियम को जन्म देने के लिए राज्य वित्त नियम अधिनियम की तरह ही कानून बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

## सहायता पहले करे

यह तो सही है कि राज्य सरकारों ने इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है किन्तु इसमें भी अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अध्ययन दलको स्पष्ट सिफारिश और उसके पूरे स्वरूप पर पकाव डाले जाने के बाद भी स्वयं उन सहायता की ओर से भी ऐसा कोई पुरजोर प्रयत्न इस दिशा में नहीं किया गया जान पड़ता है जो इस योजना के कार्यान्वित होने पर लाभान्वित होने वाली है। यह बात प्रसिद्ध रूप से कही जा सकती है कि यदि पचायती राज सहायता तथा उनके सहाय सगठन इस दिशा में सज्ज होकर सरकार पर दबाव डालें तो इस प्रकार के नियम अथवा वित्तीय सहायता का गठन शायद ही असंभव हो सकता है।





# पंचायती राज के आय के साधन और व्यय के प्रावधान

भारत के संविधान में राज्या १११ के स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होंगे तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त गामों की इकाइयाँ के रूप में सफरतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। स्पष्ट है कि इस निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार पंचायतों को कम से कम इतना समर्थ बनाना ही बलपूर्वक ही की गई थी कि वे गाँव की स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में खड़ी हो सकें। गाँव की विकास योजना बना सकें तथा उस अपन ही बल पर क्रियान्वित भी कर सकें। गाँव की योजना के प्रकार और स्वरूप के लिए सरकार के निर्णयों की प्रतीक्षा तथा उन्हें मुख्य रूप से देने के लिए सरकार की कृपा पर निर्भर रहने की स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण राज भी बनी हुई है, असंदिग्ध रूप से उपरोक्त निम्नलिखित तत्व के प्रतिबल है इसे सभी स्वीकार करेंगे। इस दृष्टिकोण में पंचायतों को आय के साधनों तथा व्यय के प्रावधानों सम्बन्धी पहलुओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि लोकतन्त्र की इस बुनियादी इकाई को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह मुख्य मुद्दे हैं।

## विभिन्न राज्यों की स्थिति

पंचायतों की भाय के साधन की मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है — (१) अपने साधन (२) सरकार से प्राप्त राजस्व (३) अनुदान तथा (४) ऋण। पंचायतों के अपने साधनों को भी चार भागों में बांटा जा सकता है—(अ) अनिवार्य कर (ब) ऐच्छिक कर (स) मुल्य तथा (४) धन्य धाय जैसे कि लाभ के लिए किये जा रहे धंधों से प्राप्त राजस्व आदि। यद्यपि धाय के साधनों का स्वरूप सभी राज्यों में लगभग एक सा हो है फिर भी कहीं कहीं एक राज्य की स्थिति दूसरे से थोड़ी भिन्न होती है। लगभग सभी राज्यों में पंचायतों की मुख्य भाग मिलता है या कहीं कहीं लगान पर सस लगाये जाने की भी व्यवस्था की हुई है। पंचायतों की अनिवार्य प्रकार के अनिवार्य तथा ऐच्छिक कर लगाने के भी अधिकार प्राप्त हैं। अनिवार्य करों में मुख्यतः सम्पत्ति तथा व्यवसाय पर लगाये जाने वाले कर उल्लेखनीय हैं। बाहनों पर लगाये जाने वाले कर लगभग सभी राज्यों में ऐच्छिक ही हैं। धन्य साधनों को छोड़ी में वे सभी रखने आती हैं जो भावारा पशुओं को बंद करने के बाड़ा बाजार बसाई-साला आदि से प्राप्त होती हैं। सिवाय चक्की जमीनों तथा मछली पालन सम्बन्धी बायों से होने वाली आमदनी को पंचायतों के विभिन्न भागों में से मुख्य होती है। कानून व अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करके भी पंचायतों कुछ राशि प्राप्त कर लेती हैं। कुछ राज्यों में पंचायतों के लिए ग्राम के भीतर भी प्रतिरिक्त साधन रख गये हैं जहाँ-जहाँ के लिए मद्रास तथा आंध्र में सम्पत्ति व हस्तांतरण पर अधिकार का प्रावधान है जो पंचायतों को मिलता है। मद्रास में पंचायतों को गृह-कर द्वारा अर्जित राशि व बराबर राज्य सरकार से अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कहीं कहीं मनोरंजन कर में से भी पंचायतों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकारें केवल विकास योजनाओं के लिए ही पंचायतों को अनुदान नहीं देती बल्कि उनकी उपलब्धियों तथा कुशल भाव संचालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी कुछ रकमें देती हैं। राजस्थान तथा पंजाब में इन पंचायतों को विपणन अनुदान दिये जाने हैं जिनके अधिकार सदस्य निर्विरोध चुनकर आते हैं। महाराष्ट्र में पंचायतों को राजस्व वसूली में विशेष योगदान पर भी अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

## राजस्थान में भाय के स्रोत

राजस्थान में पंचायतों की भाय के साधन मुख्य रूप से तीन भागों में बाँट जा सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं—

### (अ) राज्य सरकार से अनुदान—

२० पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंचायतों को सरकार से अनुदान मिलता है पर यह राशि अधिक से अधिक ४०० रुपये होती है। तथा उपग्राम सामाजिक व्यवस्था सच में किया जाता है।

### (ब) पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर—

#### (१) गृह-कर



## विभिन्न राज्यों में अनेक कर

ऊपर बताये गये कर जहाँ लगभग सभी राज्यों में लिये जाते हैं वहाँ कुछ कर केवल किन्हीं राज्यों में ही वसूल किये जाते हैं। आध्रप्रदेश के कुछ जिलाओं पचायतों अपने क्षेत्र में बिकने वाली चीजों पर तोल घोर नाप के आधार पर कर वसूल करती है। मसूर गुजरात, महा राष्ट्र तथा राजस्थान में पचायतों को चुनो लेन का अधिकार प्रदान किया हुआ है, पर यह पचायतों की इच्छा पर है कि वे इसे लगायें या न लगायें इसी प्रकार महाराष्ट्र गुजरात जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा बिहार में पचायतों को तोर्य यात्रो कर लगान का अधिकार भी दिया हुआ है, पर यह बदल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहाँ धार्मिक तीर्थ स्थान हैं। जम्मू और काश्मीर में पचायतों को जान-बरो पर भा कर लगान का हक प्राप्त है। जलपूर्ति नालियाँ बनाने सड़कों को रोशनियाँ तथा सफाई कार्य के लिए भी पचायतों गुल्क लगा सकते हैं। यद्यपि यह ऐच्छिक ही है क्योंकि पचायतों का काम है कि वे अपने इलाक़ा में न सभी बातों का न्त ज़ाम करें पचायतों को यह भी हक है कि वे (१) अनाधिकृत बन्ना (२) लाइसेंस न लान तथा निर्धारित नक्का का विपरीत मकान बना लेने पर जुर्माना भी कर सकती है। गांधी में स्थित बारहमासी तालाबों में मछली पालन को व्यवस्था करके पचायत इस काम में लगे हुए लोगों से भी कर वसूल कर सकती है। गांधी के बाजारों को पचायत तथा पचायत समिति क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्रों से विभाजित करके अपने इलाक़े की दुकानों से कर लगा कर भी पचायत अपनी धाय बढ़ा सकती है। आध्र तथा मद्रास को तरह ही अन्य राज्य भी जायदाद के हस्तांतरण तथा बिजली के समय की जान वाली फीस के एक अंश को पचायत के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मद्रास में बिकने वाले चाय विभाग सम्बन्धी टिकटों का बिजली पर भी अधिकार लगाया जा सकता है, जो सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम विकास के लिए खर्च किया जा सकता है एक प्रदन यह भी उठता है कि टिकटों की बिक्री का कर केवल पचायतों को ही दिया जाय अथवा पचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी इस में से हिस्सा दिया जाय।

## मनोरजन कर

अपने क्षेत्र में होने वाले मनोरजन सम्बन्धी आयोजनों मेलों तथा प्रदर्शनियों से होने वाली आय पर भी पचायतों कर लगा सकती हैं। उड़ीसा में केन्दू के पक्ष की बिजली से होने वाली सारी की सारी आय पचायतों तथा पचायत समितियों को जाती है।

बरा की पूरों बगूनी तथा ठीक ढंग से कर लगाने के काम में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मन्त्रालय सरकार को तरह ही अन्य राज्य भी बरावर की रकम पचायतों को अनुदान के रूप में दे सकती है जिस कार्य से बालन एवं राजस्व की पूरों बगूनी पर भी कई राज्य सरकारें पचायतों को इनाम देती है।

## सरकारी सहायता

इन सभी करों के बावजूद पचायतों को धामनी बहुत हो थोड़ी होती है और इतनी ही रकम से वे अपनी प्रासंगिक व्यवस्था भी ठीक ठीक नहीं कर सकती हैं। अतः हर पचायत के लिए राज्य

सरकार की प्रार से कम से कम एक स्थायी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिये और यह भार राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार को भाषा भाषा अपने ऊपर लेना चाहिये, अभी हमारे दश म पचायती की आय आय राष्ट्रो की तुलना में बहुत ही कम है, अतः आने वाले कई वर्षों तक राज्य सरकारों को यह भार वहन करना ही होगा ।

सामुदायिक विकास सस्याओं ने ग्राम क्षेत्रों में भले ही अभी तक पर्याप्त प्रगति न भी की हो, पर इतना तो मानना ही होगा कि क्षेत्रीय योजनाओं के लिए जैसे स्कूल भवन सड़कें अस्पताल, साव-जनिक गोचालया, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पचायत घरों आदि के लिए स्थानीय लोगों से धन अथवा धन के रूप में सहयोग प्राप्त करने में इन सस्याओं की जो उपनधियाँ सामने आई हैं उनका महत्व कम नहीं माना जा सकता है । अतः सभी राज्य सरकारों को कानून बनाकर पचायतों को यह अधिकार देने चाहिये कि वे धनिदाय धर्म के रूप में स्थानीय लोगों ॥ किसी भी सावजनिक काम के लिए जन सहयोग प्राप्त कर सकें ।

## व्यय के प्रावधान

ग्राम के साधनों की तरह ही खर्च की मदें भी पचायती राज की उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख आधार हैं । मोटे तौर पर तो अत्येक पचायत पर इस बात की जबाबदारी है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों और पशुओं के लिए पीन के पानी की व्यवस्था करे, सड़का का निर्माण तथा मरम्मत कराये तालाबों और नहरों का इन्तजाम करे, सफाई रोशनी तथा प्रारम्भिक चिकित्सा आदि की देखभाल करे । पचायत समितियाँ द्वारा निर्धारित विकास कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी भी पचायत पर ही है और पचायत पर की व्यवस्था भी पूर्णतः पचायत को ही करनी पड़ती है ।

इन मदों की ध्यान में रखते हुए ही पचायत के सदस्यों को यह निर्णय लेना होगा कि ग्राम की मंठों में स कुल कितना भाग वे प्रशासनिक खर्च पर तथा कितना विकास कार्यक्रमों पर खर्च कर सकते हैं । मोटे तौर पर कुल आय का २५ प्रतिशत भाग ही पचायत को अपने प्रशासनिक खर्च पर खर्च करना चाहिये । जिन पचायतों की आय बहुत कम हो वे पाँच सात मिलकर भी अपनी समुक्त प्रशासनिक व्यवस्था चला सकते हैं ।

## लगान वसूली की जिम्मेदारी

इस प्रसंग में यह सवाल उठता है कि लगान वसूली की जिम्मेदारी पचायतों को सौंपना उचित होगा अथवा नहीं । ग्राम तौर पर यह भाग बाँकी ओर गार के साथ उठाई जा रही है कि पचायतों को ग्राम निर्भर बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजस्व वसूली का काम पचायतों को सौंप दिया जाना चाहिये । इससे एक ओर जहाँ गाँव के स्तर पर दुहरी प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो सकेंगी वहाँ पचायतों की आय भी बढ़ सकेंगी । इस सम्बन्ध में यही उचित रहेगा कि जहाँ-जहाँ राजस्व अधिकारी इस बात के लिए आह्वान करें कि पचायतें यह काम कर लेंगी और पचायतें यह जिम्मेदारी लेने को सहमत हों वहाँ लगान वसूली का काम पचायतों को सौंप देना उचित ही होगा । इस पर से यह प्रश्न

उठता है कि ग्राम सेवक पटवारी तथा पंचायत के सफेदरी के बीच क्या स्थिति होगी ? इन सम्बन्ध में उचित यही होगा कि हर पंचायत का अपना सफेदरी असल हो जो लगान सहित सभी कर वसूल करेगा और ग्राम सेवक का काम केवल विकास कार्य क्रम को देखभाल करना रहेगा ।

## पीने के पानी की समस्या

गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना पंचायतों को प्राथमिक जिम्मेदारी है । राजस्थान में तो ग्रामीणों को मोला चलकर पानी खाना पड़ता है और इस समस्या को केवल गाँवों में पानी के कुए खुदा कर तथा नल लगा कर ही दूर किया जा सकता है । राज्य सरकारों को चाहिए कि पंचायतों को इस काम के लिए काफी रुपया भ्रूण और अनुदान के रूप में दे ।

गाँव का सफाई का काम पंचायत को ठेके पर देना चाहिए तथा जो भी बूझा करक इन्तान हो उसका साज बनाने जान की व्यवस्था करनी चाहिए । गाँव की सड़क की मरम्मत तथा नई सड़कें बनाने का काम भी पंचायत को ही करना है । गाँव में नालियाँ बनाकर गंदे पानी को गाव में बाहर निकालने की व्यवस्था भी पंचायत को ही करनी चाहिए क्योंकि इनके बिना गाँव में सफाई नहीं रह सकती । सफाई न रहने पर गाँव में कई प्रकार के रोगों का खतरा रहता है । गावों में रोगों की व्यवस्था भी पंचायत की जिम्मेदारी है । जहाँ रिजली न पहुँचो हो वहाँ मिट्टी के तल स ही खाने लगाई जानी चाहिए । गाव के लिए सामुहिक रेडिया पंचायत पर का निर्माण तथा देखभाल बच्चों के लिए पाक तथा खेल कूद का मदान का व्यवस्था भी पंचायत की ही जिम्मेदारी है पंचायत को ऐसी स्थायी संपत्ति बनाने के लिए भा सफेद रहना चाहिए जिससे पंचायत का स्थायी भामन्नी हो सके । ऐसा होने पर पंचायत को बार बार कर लगान के सिर दर्द से थोड़ी बहुत मुक्ति मिल सकती है ।

## स्वावलम्बन पर जोर

ऊपर पंचायतों के आय के साधनों तथा व्यय के प्रावधानों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है पर हम यह नहीं भूलना चाहिए कि पंचायतों की स्थापना का लक्ष्य एक बार जहाँ ग्रामीणों को स्वशासन के अधिकार देना है वहाँ साथ-साथ उन्हें प्राथमिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की योजना भी इस व्यवस्था में सम्मिलित है । गाँव आज तक गहरी की धार दाने रहे । गाव के पड़े सिधे नौजवान जब तक रोजगार के लिए गहरा की ओर गेठ रहेगे, गावों की मानो हाथत सदिया तक भी ठोक नहीं हो सकेगी । अतः सबसे अधिक जार इस बात पर दिया जाना चाहिए कि अपने दानिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाँव की गहरा की धार बिलकुल न देखना पड़े ।

इस व्यवस्था के लिए सबसे पहले हर पंचायत को अपने अपने क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि उस इलाके के लोगों की आवश्यकताओं का तथा माधना दायताया तथा लक्ष्यों का स्पष्ट चित्र सामने आ सके । इसके बाद पंचायत तथा ग्राम सभा के प्रमुख लोगों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि गाँव में ऐसे कौन कौनसे काम हैं जिन्हें हाथ में लाने से गाँव का नक्का बदल सकता है उनके लिए साधनों की व्यवस्था कैसे किये कहाँ से की जा सकती है और उस जिम्मेदारी को गाँव के कौन कौनसे लोग

मत्तो-माति पूरा कर सकते हैं। पचायत को यह भी देखना चाहिए कि गांव के जो अल्पविव पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें विवेक रूप से राहत प्रदान के लिए क्या क्या काम किये जा सकते हैं ?

जसा कि हम ऊपर भी सकत चुके हैं गांव के विकास के लिए कुछ ऐसे साधन भी जुटान पड़ सकते हैं जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार न होकर समूचा पचायत का अधिकार हो। पचायत के लिए स्थायी ग्रामपंचो का जुगाड ऐम साधनो स ही सम्भव होगा। उडीसा सरकार न अपन दशा म अनक पचायतो का छोटे छोटे उद्योग चालू करन के लाइसेंस दिये थ ताकि उनकी आय म पचायतो को आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

### अपना महत्व समझे

पचायतो और ग्राम सभाओ को अपना महत्व समझना चाहिये। लोकतन्त्र का सारा महल इही पर टिका है। जब तक यह अपनी जगह निश्चल खड़ा है लोकतन्त्र के लिए कोई खतरा नहीं है पर ज्योंही क्षणमात्र के लिए भाड़े अपनी सबसे का महत्तास दुष्मा, लोकतन्त्र के प्रति इनकी आस्था उगमगाई तो हमारा सारा लोकतन्त्र ही लडखडा सकता है। अतः पचायतो और पंचों को बुनोनी पूरक अपन कणधारा स यह बात कहनी होगी कि वे अनिश्चित समय तक अपने राजनीतिक एवं आर्थिक सोपान को बर्दास्त करन को तयार नहीं हैं। उन्हें हनुमान की तरह अपन पौरुष का प्रह्वानना होगा केवन सभी ऊपर बठने वाल मत्ताधारी पचायत का परवाह करेंगे। देश म राजनीतिक स्वराज के बाद आर्थिक स्वराज का सपना साकार करन का काम पचायतो को ही पूरा करना है, यह बात हमें नहीं भूलनी है। इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो हम सरकार का साथ लोहा लन की तयारा भी करनी पड़ सकती है, पर लोकराज की सच्ची स्थापना के लिए यह करना ही पड़ेगा।



## पंचायती राज और राजकीय नियंत्रण

- १ पंचायती राज के प्रति सरकार की अपेक्षापूर्ण नीति  
—श्री जयप्रकाशनारायण १-३
- २ सोरठाही बनाम मोरगाही  
—श्री कुमाराम ग्राम ४-६
- ३ पंचायती राज के प्रशासन की समस्या—  
एक प्रश्न-एक उत्तर —श्री मधुरादास माधुर ७-११
- ४ पंचायत राज आयोग १-१४
- ५ निष्क्रिय ग्राम पंचायतों को सन्निव कसे  
बनाया जा सकता है —श्री गोपीनाथ गुप्त १५-१६
- ६ पंचायती राज संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण  
—श्री मदनगोपाल शर्मा २०-२०
- ७ पंचायत राज में जन प्रतिनिधि और  
सरकारी कर्मचारी —श्री दीनदत्तमहाय श्रीवास्तव २६-२८
- ८ पंचायत राज और बान्धव  
—श्री रामकरण जोशी ३३-३४



[ शायर कवि वाल्ट विल्डमन ]  
मैं सौमध खाता हूँ कि मेरे लिए  
वह सब निरर्थक है,  
जिसमें व्यक्ति उपेक्षित हो।  
मुझे लोगों के चेहरे, और  
सड़क देलने दो।  
हजारों की तादाद में  
साथी और प्रेमी दो।  
वही नगर महान् है,  
जिसमें महाननम नर-नारी हैं,  
चाहे उसमें कुछ टूटी कटो  
भोपडिया ही क्यों न हो।  
वह सारे ससार का  
स्व से महान् नगर होगा  
वहा नागरिक ही  
सदैव प्रधान और आदर्श हैं।  
और प्रेमिडेट, मेयर और  
गवर्नर वेतन पाने वाले  
चाकर मात्र हैं,  
यही है वह महान् नगर।

22

2

2  
2  
1

# पचायती राज के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति

—श्री जयप्रकाशनारायण

पचायती राज व्यवस्था देश के सम्पूर्ण प्रशासन का एक आधार बन जाए इस हेतु कुछ वर्ष पहले उदयपुर में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। जिसमें केन्द्र के सामुदायिक विकास मन्त्रालय के मंत्री श्री एम० के० डे उपमन्त्री श्री बी० एस० सूति, दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं अन्य राज्यों के पचायत मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सेमिनार में सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि पचायती राज संस्थाएं ग्रामीण ग्राम पचायतों जनपद ग्रथवा स्तरों पचायतों और जिला परिषदों ग्राम ग्राम स्तर में स्वशासन की इकाई हैं। भले ही कुछ मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के रूप में कार्य करें किन्तु पचायती राज का जो बिज हमारे भविष्य में रहा है वह पचायती की ऐजेंसी के रूप में नहीं बल्कि स्वशासन की संस्थाओं के रूप में स्वीकार करता है। सेमिनार की सिफारिश यह भी थी कि इस परिसरत्व का इस स्वरूप को केवल स्वीकार करने से ही नहीं बल्कि संविधान में इस तरह का संशोधन करना चाहिए कि इन संस्थाओं को एक पाँच तहरीय राज्य के मंच के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। और जिन क्षेत्रों केन्द्र और प्रदेश के मध्य अधिकार और दायित्व का बंटवारा किया गया है, वैसे ही केन्द्र, प्रदेश, जिला, ब्लॉक, और ग्राम स्तरों के मध्य बंटवारा किया जाय। परन्तु आज की स्थिति देखकर ऐसा महसूस होता है कि उदयपुर के परिसरत्व को मौखिक रूप में ही स्वीकार किया गया था। मैं सुना है कि मन्त्र विधान सभा में पचायती राज के मन्वयित्व विषय में पचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक सरकार की एजेंसियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तो उदयपुर सेमिनार के बाद हुआ और सेमिनार में श्री हेडगे भी मौजूद थे।

नेहरूजी जब तक जीवित रहे पचायती राज प्रणाली के व हमारे थे, और इस और उड़ने शासन की नीतियों की निरन्तर प्रभावित किया था। उनके बाद के पदचार्ज जहाँ तक शासन ग्रथवा शासकीय नीतियों का मुद्दा था उसमें अभी कुछ हद तक स्पष्ट होकर हुई। यद्यपि गांधीजी के काल में यह नहीं कर सकते कि पचायती के प्रति उनका मुद्दा कुछ कम था किन्तु नेहरूजी जिस णि में सोचते



आज ऐसा लगता है कि सरकार पचायती राज की दिशा से कुछ मुह मोड़ लेना चाहती है। पचायती व्यवस्था के विषय में उसका सक्रियात्मक भुकाव सामने नहीं आ रहा है।

पिछले कुछ दिनों केन्द्रीय व राज्य सरकारें पचायती राज के विषय में निरन्तर शिथिल एवं उत्साहहीन नीति पर चल रही हैं, और यह परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यह कहना मेरे लिये मुश्किल है।

ये उसका स्पष्ट रूप या प्रक्रिया शास्त्रीजो काल में परिनिहित नहीं हो सकी। यद्यपि वे बलवन्त भाई के निकट के सहयोगी रहे हैं। और बलवन्त भाई का इस सत्ता से गहरा सम्बन्ध रहा है। पलस्वरूप जो भी कार्य शास्त्री जी के सामने आया बलवन्त भाई के परस्पर विस्वास एवं स्नेह की वजह से वह बराबर साथ देते रहे सहयोग देते रहे। किन्तु आज ऐसा लगता है कि सरकार पचायती राज की दिशा से कुछ मुह मोड़ लेना चाहती है। पचायती व्यवस्था के विषय में उसका सक्रियात्मक भुकाव सामने नहीं आ रहा है। यद्यपि केन्द्र अधिका राज्यों में, जो नष्ट है वह कोई नया नहीं है नष्ट काल से ही वह चला आ रहा है। केन्द्र में अधिका राज्यों में सरकार में अधिका कांग्रेस पार्टी में बड़ी लोग हैं जो नेहरू जी के पुराने साथी हैं। उनकी नीतियों को उन्होंने स्पष्ट समझा है। इन्दिरा जी तो स्वयं उनकी पुत्री हैं। ये दोनों लोग नेहरू जी की नीतियों से पचायती राज के विषय में नेहरू जी की भावनाओं से अपरिचित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके नष्ट में पचायती राज की गति मद हो, नई पचायती राज व्यवस्था में आस्था न हो ऐसा नहीं लगता और न ही लगना ही चाहिए, किन्तु यह हो रहा है। पिछले कुछ दिनों केन्द्रीय व राज्य सरकारें पचायती राज के विषय में निरन्तर शिथिल एवं उत्साहहीन नीति पर चल रही हैं और यह परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यह कहना मेरे लिए मुश्किल है। इसका सही उत्तर तो कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं। उनकी भाषोचना करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि राजनीति छोड़ चुका है कुछ भजीब सा लगेगा और वह भी एक दल विरोधी की-कांग्रेस पार्टी की। किन्तु कांग्रेस एक बड़ा दल है अतः भारतीय स्तर का व्यापक समर्थन है। केन्द्र और राज्यों में इसकी सरकारें हैं जनता में विश्वास रहता है। अतः पचायती राज के विषय में दूसरों की अपेक्षा उसका अधिक उत्तरदायित्व है। यद्यपि जहाँ जहाँ मन राज्य अधिका केन्द्र सरकारों से सम्पर्क किया पचायती राज व्यवस्था के विषय में मुक्त सहयोग मिला है। उस सीमा तक सहयोग मिला है जिस सीमा तक उसका पात्र नहीं है। किन्तु समग्र रूप से पचायती व्यवस्था को हतोत्साहित करने का, उसकी उपयोगिता को कम भावना का आरोप सरकार पर लगाया जा सकता है।

अन्य राज्यों में अतः यहाँ त्रिस्तरीय प्रणाली अभी तक लागू नहीं की है। पचायती का क्या स्थान है, यह राज्य सरकार के सचिव स्पष्ट नहीं है। कुछ राज्य सरकारें तो पचायती

संस्थाओं का एक ऐजेंट के रूप में मानती हैं। कुछ मुख्य मंत्रियों ने तो मुझ इस विषय में स्पष्ट लिखा था कि पंचायती का स्थान हमारे राज्य में एक ऐजेंट अथवा एजेंसी का रूप में है। न केवल केन्द्रीय अथवा राज्य में मंत्रियों ने पंचायती व्यवस्था के विषय में अनुत्साह-व्यक्त रूप अपनाया है बल्कि विधायकों एवं संसद सदस्यों का रव भी आश्चर्यजनक रहा है। वे अब तक इसलिए सचेत करते रहे कि पंचायती संस्थाओं में उन्हें भी सदस्यों के रूप में ग्रहण किया जाए। उनका सारी शक्ति इसी तथ्य के ऊपर आधारित रही थी और वह प्रयास करते रहे कि वहाँ पंचायती राज संस्थाओं में उनका कोई अधिकार न रहे। हमारे विधायक एवं संसद सदस्य विधान सभाओं और संसद की संस्थानों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य भी बन रहना चाहते हैं। मुझे यह प्रसन्नता हाथों यदि इसका कारण पंचायती राज व्यवस्था के रचनात्मक पक्ष से सम्बन्धित होता या इन समस्याओं का संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए वे ऐसा कहते। उसका कारण तो दूसरा ही है और वह परिपक्वता एवं परिभाषिता की स्थिति का पोषित नहीं करता। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों में संसद अथवा विधान सभाओं के सदस्य होने की मांग नहीं की है। यदि परिवर्तन में वह भी ऐसी मांग करें तो स्थिति क्या होगी ? हम पंचायती राज के सदस्यों के लिए एक सहिता तैयार करना चाहिये कि यदि कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य हों तो उनके लिए छूट हानी चाहिए—जिनसे लेने की। पार्टी अनुगमन उन पर लागू नहीं होना चाहिए पार्टी आदेश उनके लिए प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए तथा पंचायती राज व्यवस्था दलगत राजनीति से ऊपर उठ सकेगी।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। जिनका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देना ताकि वह पंचायती राज के लिए उपयोगी सिद्ध हो एवं ग्रामीण नस्ल प्रदान करें और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आभोगीकरण के मार्ग में सहायक हों। किन्तु वेद हैं कि इतनी उपयोगी संस्थाओं को भी सरकार समाप्त करने जा रहा है। ऐसा जान हुआ है कि कुछ राज्य सरकारें पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता को नहीं मानती और उन्हें समाप्त करने का निर्णय ले चुकी हैं। कुछ लेने जा रही हैं। उसके अनुदान में कटौती की जा रही है। उसका परिणाम क्या होगा, पंचायती राज प्रणाली को उचित नेतृत्व को कि उचित प्रशिक्षण के अभाव में संभव नहीं है प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिसका तत्काल प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। ग्रामीण समाज के उत्थान में होने की आशा में हो जायेगी। ग्रामीण उद्योगीकरण की आशा धूमिल पड़ जायेगी। अब वहाँ जहाँ संसद सदस्यों एवं विधायकों के प्रशिक्षण की बात प्रारम्भ हो रही है जो, घटायें विधान सभाओं एवं संसद के पक्ष पर पड़ते हो रहे हैं, उनकी देखरे, हुए, उनके प्रशिक्षण की बात अस्वभाविक नहीं लगती। किन्तु इन विधायकों एवं संसद सदस्यों को सुलना में पंचायती राज संस्था के सदस्यों का प्रशिक्षण तो और भी आवश्यक है। इनका प्रशिक्षण तो इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है क्योंकि इन्हीं प्रशिक्षित घर सरकारी सदस्यों की भूमिका से ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण उद्योगीकरण की दिशा को निर्णायक सहयोग प्राप्त होगा।

# लोकशाही बनाम नौकरशाही

१

—श्री कुम्भाराम आय

सत्ता विवेकीकरण के अन्दर विधायक और नौकर को रखा जाये अथवा नहीं यह एक महत्व का प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार विधे बिना सत्ता के विवेकीकरण की दिशा में ग्राये बढ़ना खतरा से खाली नहीं है।

सत्ता के विवेकीकरण का अर्थ लोकशाही की स्थापना तथा उसके द्वारा देश और समाज की सन्नति करना है। लोकशाही राजनीति के स्थान पर लोकनीति की स्थापना चाहती है। राजनीति में पक्ष विवाद और विरोध मुख्य रूप से काम करता है। लोकशाही में सशक्त सद्भावना और सहयोग मुख्य रूप से काम करता है। दोनों का कहीं मेल दिखाई नहीं देता। राजनीति भय चिन्ता और दूसरे के विनाश की तरफ खींचती रहती है। इस कारण इसमें निर्भयता विश्वास और दूसरे के हित की सभावना बहुत कम रहती है। लोकनीति निर्भयता सद्भाव तथा विश्वास के साथ सशक्त में विश्वास रखती है। इसलिए सत्ता के विवेकीकरण में राजनीति को पृथक् रखा जाना चाहिये। विधायकजन जो राजनीति के प्रतीक हैं लोक नीति से जितनी दूर रहे जाएंगे उतना ही सत्ता का विवेकीकरण सफल होगा। देश में प्राज केन्द्र और प्रान्त के नाम से दिल्ली तथा प्रान्तीय राजधानियों में राजनतिक लोग अपने अपने पक्ष के लिए अथाह में खतरते हैं। इससे अतिरिक्त यह दयन और कही नहीं। सत्ता के विवेकीकरण में इन विधायकों की प्रवेश मिल गया तो देश में इस प्रकार की खकों हजारी राजनीति के अथाह से खुल जायेंगे जहाँ पर पक्ष विपक्ष की भाषा के दौर चलेंगे और देश तथा समाज की सेवा भीण हो जायेगी।

प्रशासनिक इकाइयों की राजनीति का केन्द्र बना देना शासन और सेवा दोनों दृष्टियों से अनुचित है। प्रशासनिक इकाई की कमजोरी सुरक्षा और धार्मिक काम नहीं रख सकते जिनका रखना अत्यन्त आवश्यक है। सुरक्षा व धार्मिक के बिना सेवा तो खोचो ही नहीं जा सकती। इसलिए सुरक्षा और धार्मिक के बिना प्राजादी किस काम की। राजनीति और लोकनीति का मेल विरोधी भाव उत्पन्न करने वाला होगा

लोकसाही के नाति-ज्जाब  
श्री कु भाराम आर्य  
बधपन राजस्थान पचायतराज मध



जिससे शासनिक इकाइयां मजबूत होने के स्थान पर कमजोर होंगी। इसमें देश और समाज का हित नहीं बन सकेगा। इस कारण 'राजनीति' जनो का लोकनीति सधाम प्रविष्ट नहीं होना चाहिये। प्रशासनिक इकाइयों में विधायक के प्रविष्ट होने से दूसरा स्वाभाविक विरोध यह और उत्पन्न हो जायगा कि किसी इकाई में शासन करने वाली पार्टी के विरोधी आ गये तो दोनों तरफ खिचाव धायेगा। छद्मकारी को छद्मकारी नहीं भाती। इसी भाँति एक राजनीतिक दूसरे विरोधी राजनीतिक को देख नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में अपनी शक्ति लगायेंगे और समाज सेवा दोनों भूल जायेंगे। राजनीति विरोधी को बल प्रदान नहीं कर सकती, विरोधी का बल खींच करती है। इसलिए जिस किसी इकाई में शासन करने वाला पार्टी से विरोध करने वाला विधायक आ गये वहाँ तो निश्चय ही एक दूसरे को कमजोर बनाने में शक्ति का प्रयोग करेंगे। देश भक्ति और समाज सेवा का स्थान उस समय पार्टी हित हो जायेगा। सत्ता के विवेकीकरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देन के लिए यही उचित है कि विधायक दल में प्रवेश न करें।

## कर्मसत्ता और जिम्मेदारी

विधायकों के साथ ही नौकर का प्रश्न आता है। आज कर्मसत्ता जिसे हम अधिकार कहते हैं नौकरा का पाम है। जन प्रतिनिधियों के पाम कर्मसत्ता की भारी कमी है। जन प्रतिनिधियों के पास जिम्मेदारी और नौकर के पास अधिकार, यह अजीब प्रकार की स्थिति है। जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास अधिकार नहीं। जिसके पास अधिकार है उसका पास जिम्मेदारी नहीं। परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि जनता जिससे आशा लगाये बठी है वे कर्महीन हैं। सत्ता के उपासक बने बैठे हैं। इसलिए जनता की आशा पूरी नहीं कर सकते। जिनके पास कर्मसत्ता है वे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बर्ताव के जनता के प्रतिनिधि नहीं। अधिकार और जिम्मेदारी को धूमक् पृथक् बाँटने की भूल सत्ता विवेकीकरण में कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल जिम्मेदारी लाद देन से काम नहीं चल सकेगा, जब तक कि इसे पूरा करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा।

## लोकशाही व नौकरशाही

सत्ता के विवेकीकरण में कर्मसत्ता (अधिकार) नौकर के हाथ में अधिवाधिक रखी गयी तो विवेकीकरण की योजना असफल होगी। नौकर का हित लोकशाही में नहीं नौकरशाही में है। वह अपने हित के बिना काम चल सकेगा? इसलिए सत्ता विवेकीकरण में जिम्मेदारी और अधिकार दोनों समान रूप से देने की आवश्यकता है। नौकरशाही और लोकशाही में रात दिन का अंतर है। नौकरशाही हमारी आजादी की रात है जिससे हमारा वर्तमान अचिरे से घिरा है। लोकशाही हमारी आजादी का दिन है जिसमें हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रकाशमय हैं। दिन और रात का समय सध्या बेला कहलाती है। राजनीति और लोकनीति का मेल सध्या कास बनेगा। हम सध्या बेला के इच्छु नहीं। सध्याकाल की स्थिति अच्छी नहीं होती वह बड़ी विविध होती है। उसमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। किसी वस्तु के सही दिखाई न दन का दाप न भाँस का दिया जा सकता है और न बुद्धि को। इसका दोष सध्याकाल को है। सध्या काल का स्थिति ऐसी ही है। उसमें न पूरा अंधेरा होता है और न पूरा प्रकाश। कुछ पुष्पता घु घमा रहता है, कहीं साँप रस्सी दिखाई देता है जो कहीं रस्सी छीप। इस सध्या काल में कितनी ही साव-

पानी बरती जाय फिर भी रस्सी सम्भरकर साप के हाथ लगन वाले के प्राणा की रक्षा हो सक्ता बहुत कठिन है। लोकगाही और नौकरगाही का मेल जिस स्थिति को उत्पन्न करेगा वह इस सच्चा यत्ना से कम घातक नहीं होगी। इसलिए नौकर के हाथ में अधिकार की आवश्यकता स्तरनाक है।

अधिकार वही रहना चाहिए जहाँ जिम्मेदारी है। बिना अधिकार के जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए सत्ता के विवेकीकरण के अन्दर इस बात का खास ध्यान रखन की जरूरत है कि जितनी जिम्मेदारी दी जाय उतना ही अधिकार भी उस मिल जाना चाहिए। जिम्मेदारी को निभान के लिए अधिकार की भारी आवश्यकता है।

## अधिकारी और सेवक

सत्ता के विवेकीकरण में जन प्रतिनिधियाँ को नौकरगाही की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सत्ता के विवेकीकरण में सत्ता और अधिकार दोनों जन प्रतिनिधियों के पास रहना चाहिए। नौकर के पास केवल सेवा रहनी चाहिए। सेवा की साधना के लिए जिनसे अधिकार की आवश्यकता पड़े उतना अधिकार नौकर के पास रहना चाहिए।

सत्ता विवेकीकरण के अन्दर नौकर अधिकारी बन कर नहीं माना चाहिए। संभव बनकर माना चाहिए। इसके लिए वर्तमान सेवा आयोग द्वारा नियत सेवाएँ उपयुक्त नहीं क्योंकि वह अधिकार की प्रतीक हैं। सत्ता का विवेकीकरण अधिकार के स्थान पर सेवक चाहता है। इसलिए सत्ता के विवेकीकरण के सिलसिले में काम करने के लिए पृथक सेवा आयोग नियुक्त होकर उसके द्वारा सेवका (नौकरों) का चुनाव होना चाहिए। प्रशासनिक इकाइयों नौकरों से प्रभावित न हों सब से इस बात का पूरा ध्यान रखें बिना सत्ता के विवेकीकरण की दिशा में आगे काम रहना सफलता की सूचना नहीं। सत्ता के विवेकीकरण में शासनिक इकाइयों (जन प्रतिनिधि मण्डल) नौकरों से प्रभावित होने लगी तो फिर नौकरगाही का बोलबाला हो जायेगा, लोकगाही का नहीं।

सत्ता विवेकीकरण के अन्दर जितना अधिकार और जिम्मेदारी जन प्रतिनिधियों का दी जा सकेगी उतनी ही सफलता मिलन वाली है। इसलिए लोकगाही को स्थापित करने के लिए सत्ता के विवेकीकरण में विधायक को पृथक रखा जाय तथा जिम्मेदारों और अधिकारों जन प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए। नौकर के पास केवल सेवा रहे और सेवा को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक अधिकार की आवश्यकता हो उससे अधिक अधिकार न रहे।

# पचायत राज के प्रशासन की समस्या एक प्रश्न - एक उत्तर

—श्री मथुरादास माथुर

पचायती राज का विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में पचायती राज का जन्म हो विशिष्ट प्रकार से हुआ था। यह प्रणामन की ऐसी पद्धति नहीं है जिसे जनता के अनुरोध पर लागू किया जा रहा है पचायती राज की प्रशासन की पद्धति के रूप में अपनायत सं लिए सामोरी जनता द्वारा कभी कोई प्रयास भी नहीं किया गया। प्रारम्भ में तो यह एक राजनीतिक आवश्यकता भी नहीं थी।

वास्तव में पचायती राज योजना के मूल में प्रशासनिक सुविधा ही मानी जानी चाहिए। पचायती राज का वास्तविक स्वरूप क्या हो, इस पर विचार करने के लिए महान् राजनीतिज्ञ व नेता स्व० श्री बलवंतराम महता का अध्यक्षता में जो 'दल' नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट पर डॉ० भर म व्यापक रूप से चर्चा की गई। अन्त में देश के विभिन्न राज्या में विद्यमान सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों व अनुरूप विभिन्न रूपों में पचायती राज की स्थापना की गई।

फिर भी प्रत्येक राज्य द्वारा कुछ मौखिक सिद्धान्तों का अनुसरण अवश्य किया गया जिनमें पचायती राज या मूलभूत सिद्धान्त यह था कि सामान्य भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधि सभठनों द्वारा राष्ट्र के सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार अपने आम सुश्रुत्या का विकास करना चाहिए।

## त्रि-स्तरीय व्यवस्था

राजस्थान में पचायती राज की त्रि-स्तरीय पद्धति को अपनाया गया है तथा भारत में बहुत से राज्या ने भी इसा को अपनाया है। कुछ राज्या ने द्विस्तरीय पद्धति को अपनाया है तथा वहाँ जिला परिषदा का जिला प्रणामन के प्रशासकीय साधन के रूप में संगठित किया गया है। लेकिन किसी भी राज्य ने ग्राम पचायत को पचायती राज की प्रशासकीय इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी है।



राजस्थान सामंतिवाद की प्राचीन परम्परा के कारण पिछड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पचायती राज का सम्बन्ध है यह उत्तर-भारत में इसी प्रकार से पहला राज्य है जिस प्रकार दक्षिण में आंध्र राज्य है। लेकिन लोगों की जनता में प्रगाथ थड़ा एवं विश्वास होने के कारण हमने पचायती राज को एक नए कदम के रूप में अपनाया था न कि प्रशासन में एक नए प्रयोग के रूप में।

भारतीय संविधान के निर्देश तत्वा में ग्राम पचायती को समृद्ध करने का उद्देश्य है लेकिन जब तक इसमें पचायती राज को प्रशासन की पद्धति के रूप में मायना प्रदान करने के लिए विशेष रूप से संशोधन नहीं किया जाता तब तक इसका स्थान प्रशासन के ध्वस्तरी की प्रपेक्षा में ही रहेगा। पचायती राज प्रशासन का एक भाग है तथा किसी भी प्रजापंचायी शासन में प्रशासन का लोकतांत्रिक आधार होता जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता इस पद्धति की सफलता में संदेह हो रहेगा और हो सकता है देश में आने वाली नयी क्रांति की चपेट में यह समाप्त हो जाये।

## पुराने प्रशासन से भिन्नता

प्रशासन की परम्परागत पद्धति एवं वर्तमान पचायती राज के बीच केवल है ?

यदि प्रथम प्रकार का प्रशासन केवल कर्मचारियों द्वारा ही चलाया जाता है जो या तो चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं जबकि हमारे प्रकार के प्रशासन में जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व को निर्वाचित प्रतिनिधि भी बांट लेते हैं। इस प्रकार प्रशासन की इस पद्धति में विशिष्ट रूप से जिला प्रशासन में जन प्रतिनिधियों एवं सेवकों दोनों का समन्वित रूप होता है। मेरे मन में आज प्रशासन के रास्ते में जो एक मात्र कठिनाई होती है वह यह है कि वह जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर कार्य करने में अपनी मन स्थिति को ठीक प्रकार से विकसित नहीं कर पाता जो कि हमारे समाज में प्रजापंच के नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जनता में से चुन कर आता है। राज्याधिकारों और कर्मचारी यद्यपि अपने अधिकारों को नए परिवर्तन के अनुरूप ढाल रहे हैं लेकिन उन्हें उन लोगों के साथ अच्छी तरह संतुलन कायम करने में अभी समय लगेगा।

उन लोगों के लिए, विद्यार्थी सेवा के पुराने तरीकों के लिए जिनको कि भिन्न प्रकार की सामाजिक पद्धतियों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया था उन समाज की नयी आवश्यकताओं तथा प्रशासन के वर्तमान तरीकों के अनुसार प्रशिक्षण करना एक बड़ा भारी परिवर्तन है जिससे कि उनके व्यक्तित्व में एक तरह से पूर्ण परिवर्तन आ जाये। नव निवृत्त नवयुवकों में जो गांव में काम करने जाते हैं उचित दृष्टिकोण पढ़ा करना आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हमारा प्रशासन सामाजिक विचारों में प्रवृत्त रहे निर्देशों के अनुसार पूर्णतया सुसज्जित हो।

यदि वे लोग वास्तव में यह सोचें कि वे इस प्रजापंच के कर्मचारी हैं यदि प्रशासक गण सही मन स्थिति का विकास कर लें तथा लोगों में विश्वास करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि वे लोगों का हित कर सकेंगे। परन्तु यदि इससे विपरीत उनमें यह धारणा हो कि जनता प्रशिक्षित है और वे (प्रशासकगण) ही स्थिति के मालिक हैं तो वे किसी भी प्रकार में अपनी ओर से हित साधक नहीं होंगे।

विरवविद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों को कुछ शृंखलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करती है

लेकिन जो मनुष्य गावा में रहते हैं वे ही समस्याओं तथा उनके हल को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं। प्रशासन समस्याओं के हल को सीधेतापूर्वक निपटान के लिए परिवर्तनकारी सहायक साधन का तरह बख्तर सकता है तथा उसका वित्तिक हल भी प्रदान कर सकता है। गांव में रहने वाला मनुष्य सभी दृष्टि से अर्थात् सामाजिक, राजनतिक, आर्थिक दृष्टि से अपनी समस्या का समझता है। उस केवल सहायक हाथ का ज़रूरत होता है।

हम इन समस्या पर सम्मीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि यदि दस की नाति सही है तो ये योजनाएँ इतना फलप्रद परिणाम क्यों नहीं दे रही हैं? हमारा लक्ष्य बड़ा ही स्पष्ट है। समाजवादी संदर्भ लोकतांत्रिक तरीका एवं कल्याणकारी सिद्धान्त इन सबको हमन सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया है तथा यदि भी यह नहीं कह सकते कि इस समस्या को ठूल करने में भारत का प्रयास अवज्ञानिक है। लेकिन इन वर्षों में समाज में घनवान व्यक्ति अधिक सम्पन्न हुए हैं। तथा गरीब व्यक्ति यदि वह अधिक गरीब नहीं हुआ है तो गरीब गरीब उसकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार भी नहीं हुआ है। (यदि इस स्थिति में एक प्रतिशत लोग का दगा इधर से उधर हो जाय तो उसका कोई महत्व नहीं है)

## प्रशासन द्वारा कुठाराघात

पचासवीं राज में लोगों को धन स्वयं के अनुभव के प्रवास में अपने गांव के निर्माण का धन सर एव प्रति प्रान्त की गई थी अतः उन्हें उस धन में एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करना चाहिए था लेकिन धन पचासवीं राज प्रशासन की भीषण शीर्षियों के द्वारा अपने भाग में प्रवेशों का सामना कर रहा है।

जिला प्रशासन अभी तक पूर्ण रूप से एकीकृत दृष्टिकोण को विवक्षित नहीं कर पाया है क्योंकि देश में वा समानांतर प्रशासनिक संगठन कार्य कर रहे हैं जिनमें एक का कार्य सामन्तवादी प्रकृति का है तो दूसरे का आधुनिक प्रकृति का। इस तरह जिला स्तर पर दो विभिन्न ऐसी धाराएँ चल रही हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को एक दूसरे में नहीं मिलाया है।

समाहरण के लिए विकास खण्ड के समानांतर स्तर पर जपराख अधिकारी, सहस्रीलदार या सहायक सहमासदार तथा राजस्व निरीक्षक एवं पंचायती है। इन सबको सितारकर प्राधान्य राजस्व प्रशासन का संगठन होता है। यह पद्धति सम्पूर्ण देश में है। यह राजस्व वसूल करने की व्यवस्था का एक ढाँचा है क्योंकि जिला प्रशासन प्राथमिक रूप से दो कार्य कटन के उपयोग में लाया जाता था—एक तो शांति एवं व्यवस्था बनाय रखने के लिए तथा दूसरे राजस्व का संग्रह करने के लिए।

## राजस्व संग्रह

रेजिस्ट्रार ऑफ़ स्टैंडर्ड, जो कलेक्टर के नाम से अधिक लोकप्रिय है, पुराने दिनों में केवल रेवेन्यू कलेक्टर (राजस्व संग्रहकर्ता) था, एवं राज्य का प्रमुख कार्य उस समय राजस्व संग्रह ही था इसलिए यह स्वाभाविक था कि उस समय यह जिले का मुख्य अधिकारी सम्मानित होता था। लेकिन आज कलेक्टर को राजस्व संग्रह करने के बजाय अन्य कार्य करने पड़ते हैं जिनकी तुलना में राजस्व वसूली का महत्व बहुत ही नगण्य है। विचार कर राजस्थान में तो पूरा राजस्व की वसूली बहुत ही सीमित है तथा लोगों के अभाव प्रयोग राजस्व संग्रह की अनेक अधिक ध्यान आकर्षित करत है।

अतः राजस्व कलेक्टर ( सग्रहकर्ता ) को एक नया नाम देना चाहिए क्योंकि उसे राजस्व सग्रह के वनिस्पत प्रायोजना एवं विकास की ओर अधिक ध्यान देना होगा । कलेक्टर से लकर पटवारी तक के इन अधिकारियों के वर्तमान नामकरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जब पंचायती राज प्रपना लिया गया है तो हम सभी तर्क समत प्रशासनिक राजनतिक एवं सामाजिक परिणामों को भी स्वीकार करने के लिए तयार होना चाहिए ।

सचिव हम इससे सामंती घृष्ट भूमि म संगठित राजस्व सग्रह के इस व्यवस्था यंत्र को या नौकरशाही को जो कि पुराने दिनों में संगठित की गई थी समाप्त करना नहीं चाहते । पटवारी के पद को हटाया जाय या उसे गांव के विकास का प्रतिरिक्त काय दिया जाय उसे पंचायत का सचिव बनाया जाय, उसके लिए यह सब विचारणीय विकल्प हो सकते हैं ।

वर्तमान में पटवारी को जो हमने महत्व दे रखा है वह इतना अधिक है कि उसके बारे में विचार करने के लिए एक बहुत उच्च स्तरीय समिति बनानी होगी जिसमें राज्य के मंत्रिमण्डल का एक मंत्री अध्यक्ष हो तथा उसमें विकास आयुक्त, मुख्य सचिव या प्रतिरिक्त मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल आदि उच्चस्तरीय अधिकारी सदस्य हों । इनको इस प्रश्न पर विचार करने के लिए देश का भ्रमण करना होगा ।

भाज हमारी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं । योजना आयोग का कहना है कि नान-प्लान व्यय नहीं होना चाहिए और कमी करने के लिए सबसे पहले हमें यही मद प्राकृषित करनी है । मध्य प्रदेश सरकार ने विकास अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया है तथा कहा है कि इस प्रकार का काय करने वाली सत्ता को प्रापत्कालीन स्थिति में विल्कुल आवश्यकता नहीं है । तब पंचायती राज की हस्त्या करने के बदले क्यों नहीं हम राजस्व प्रशासन, पटवारी, तहसीलदार को समाप्त करना चाहिए ।

राजस्थान में विकास अधिकारी राज्य स्तरीय सेवा का सदस्य है । राजस्थान ही केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें विकास अधिकारी को यह स्तर दिया गया है । वह तहसीलदार का काय तथा भू राजस्व सग्रह करने का काय भी प्रकार कर सकता है तब फिर भू राजस्व सग्रह करने का कार्य पंचायती को क्या नहीं सौंप दिया जाय ?

## नौकरशाही का उन्मूलन

हम राजस्व सग्रह करते हैं तथा इसके बाद इसमें से निधियाँ पंचायती राज प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं को देते हैं । प्रश्न उठता है कि प्राप पंचायती को सीधे भू राजस्व सग्रह करने का कार्य क्यों नहीं सौंप देने जिससे कि पंचायतें अपने हिस्से की निर्धारित रकम अपने पास रख लें तथा आप को राज्य सरकार को लौटा दें ? राजस्व सग्रह जैसे आधारणीय काय के लिए संगठित की गई इतनी बड़ी नौकरशाही की आधारणीय पर फिर हमें इतना अधिक व्यय क्या करना चाहिये ?

जब तक कि पटवारी से लगाकर कलेक्टर तक के क्रमिक पदा को समाप्त नहीं किया जाता है । तब तक पंचायती राज सच्चे अर्थों में प्रागे नहीं बढ़ सकता ।

गावों में धात्र पटवारी चोते से भी अधिक भय का प्रतीक है। यदि गाँव में कोई चीता या भालू तो गाँव वाले सीधे उसे गोली मार सकते हैं लेकिन पटवारी को नहीं। यहाँ तक कि गाँव की राज नीति भी इस महान् पटवारी के ह्माँरे पर नावा करती है।

मेरा प्रतीत होता है कि ऊपर से लगा कर नीचे तक पचायती राज के बारे में हम सदिह प्रस्त हैं। यदि पचायती राज विकास का नया यंत्र है तथा राज्य के कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए है तो फिर सम्पूर्ण कार्यक्रम को पचायती राज पर ही आधारित किया जाना चाहिए। पचायती राज सम्पूर्ण स्थानीय स्वशासन संस्था एवं विकास की एजेंसी के रूप में स्थिर हो चुकी है क्योंकि यह स्वयं की नीति और स्वयं की धाय के साधन सृजित करती है।

## सविधान में मान्यता

हमारे यहाँ तीन सूचियाँ हैं—एक समवर्ती सूची दूसरी सच सूची और तीसरी राज्य सूची। लेकिन अब इसमें एक चौथी सूची पचायत सूची भी जोड़ी जानी चाहिए। जब तक कि पचायती राज संस्थाओं के बारे में भारत के सविधान के अन्तर्गत शक्तियाँ का उचित रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है तब तक ये संस्थाएँ उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होंगी जिनकी कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं।

दुर्भाग्य से भारत में योजना को केन्द्रोद्भूत कर लिया गया है। देश में राज्य योजना और राष्ट्रीय योजनाएँ हैं। लेकिन अब पचायती राज की स्थापना हो गई है अतः प्रायः के मायने में जनता के जुते हुए प्रतिनिधियों की आवाज का सम्मान करना होगा। जिस स्तर का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उस स्तर पर उन्हें योजना बनानी चाहिए। यह उनकी उचित भाग है तथा केन्द्रोद्भूत योजना एवं राजकीय योजना में कुछ ऐसे खण्ड मौजूद हैं जिनमें कि ग्राम आयोजनाओं या पचायती राज संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक गाँव की अपनी एक योजना हानी चाहिए सभी राष्ट्रीय सव्या को प्राप्त किया जा सकता है।

## पंचायती राज आयोग

देश में पंचायती राज व्यवस्था के श्री गणेश को सात वर्ष पूरे होने को हैं। राजस्थान से प्रारम्भ कर सत्ता के विभेदीकरण का यह प्रयोग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तरप्रदेश और पंजाब आदि राज्यों तक फैल गया है। यद्यपि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप व कृत्य विधान की व्यवस्था आ भिन्न भिन्न ही है किन्तु एक भय जो सबन व्याप्त है वह यह कि क्या सत्तवीय गार्सन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न बहुमत वाले राजनीतिक दलों की सरकारें निस्वाय और निर्लिप्त भाव से पंचायती राज संस्थाओं को आगे बढाने में योग द सकेंगी ? क्या कोई भी कदम उठाने से पूर्व ये सरकारें उस कायवाही का उनके अपन दल पर क्या प्रभाव पडगा यह नहीं सोचेंगी ? यदि इसे और भी सखीएँ दायरे में लेकर सोचा जाय तो क्या सरकार में बैठने वाला राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या उच्च प्रशासनिक अधिकारी खुशो खुशो सत्ता किसी अन्य क हाथ में सौंपने को तैयार हो जायेंगे ? जाना कि पंचायती राज व्यवस्था का सारा कानूनो ढांचा विधान मडलों द्वारा पारित अधिनियमों की सीमा में होता है जिसमे विरोधी दल के सदस्य भी सम्मिलित रहते हैं। या व्यवहार में उन अधिनियमों के आधीन नियम या नियम बनाने तथा उनके प्रासंगिक अर्थ और व्याख्या दल का काम शासन तंत्र में सगे राज नीतिक दल के प्रतिनिधियों तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के हो हाथ में रहता है। अतः इसे बात की क्या गारंटी है कि ये दल नियमों की व्याख्या अपन दल या अपन वर्ग के हित में नहीं करेंगे।

यह अच्छी बात ही रही कि हाल के पंचायत के चुनावों में न तो प्रत्यासिद्धा को दलीय आधार पर निश्चित ही दिये गये और न उन्हें इस आधार पर चुनाव चिह्न ही प्रदान किये गये। किन्तु फिर भी इस सभावना से डर नहीं किया जा सकता कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन या सहयोग अवश्य मिला हो और निर्वाचन में सफल होने पर वह व्यक्ति उस दल के साथ अपनी सहानुमति अवश्य रखेगा। ऐसी भी शिकायतें सामने आई हैं कि एक गुट विरोध के हाथ में पंचायत या पंचायत समिति की सत्ता आ जान पर विपक्षियों को वि इस कार्यो के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करना असम्भव हो गया। इस प्रकार याव का समिति क्षेत्र का विकास एकांगी ही रह जायेगा। इसके अतिरिक्त इस व्यवहार से जो प्रतिनिया पदा होंगे यह कटुता, वमनस्य, ईर्ष्या और षड्य का प्रसार करेगी और इसका परिणाम हम यादवा के छोट छोट गणों के इति हास की याद दिलाता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत नस प्रकार की बुराइयों का प्रतीकार कही भी नहीं है।

वर्तमान परिस्थितियों में हम पचायती राज सस्थाओं से बहुत अधिक की उम्मीद भी नहीं कर सकते। एक तो यह गांवों में स्वायत्त शासन का प्रारम्भ मात्र है और गांवों में अभी इसकी स्वस्थ परंपराओं का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरे ऊंचे स्तर पर भी सावजनिक जीवन के गिरते हुए नैतिक स्तर को देखकर उनसे यह अपेक्षा करना कि वे निस्वार्थ और दनगत सहायता से ऊपर उठकर ग्राम समुदाय की सेवा कर सकेंगे, बहुत अधिक होगा। इसलिए हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पचायती राज के लिए चुन हुए जन प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों दोनों को ही मार्ग निर्देशन देने और उनके कार्यों की देख-रेख के लिए एक राज्यस्तरीय मध्यम का होना आवश्यक है।

एक प्रश्न उठता है कि यह सस्था का स्वरूप और संगठन कैसा हो? कम मात्र भी इन समस्याओं तथा इनके कर्मचारियों की अनियमितताओं पर नकारी तब का अङ्गुष्ठ है। ऐसी अनियमितताओं की जाँच हाथी है और प्रपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था है। पर यह सब सरकार की नौकरशाही के अधिकार में है। नौकरशाही के बिना कितनी ही कार्य हो रहे हैं क्या न भरे वह नौकरों या कर्मचारियों का पक्ष ली जाती है। फिर अधिकार सम्पन्न अधिक होने पर जन प्रतिनिधियों को स्वायत्तता और स्वतन्त्रता में भी बाधक हो सकती है। अने ही, प्रत्यक्ष रूप से यह उनके काम में बाधा न डालता हो पर जन प्रतिनिधियों में प्रबुद्ध भय तो विद्यमान रहता है और इस प्रकार वे स्वयं का नौकरशाही से होने मानने लगते हैं।

इसलिए सस्था भी पूर्णतः स्वायत्त होनी चाहिए और काफ़ी व्यापक अधिकार इसके पास होने चाहिये। वास्तव में इसे हम पचायती राज की स्थापना कह सकते हैं। यह सस्था लोक सेवा आयोग, निर्वोचन आयोग, विद्वद्विद्यालय अनुदान आयोग, सचिवता आयोग जैसी सर्वाधिकार सम्पन्न सस्था होनी चाहिये। यह सस्था हम बात का प्रयत्न करेगी कि पचायती राज सस्थाएं अपने वैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का सभी प्रकार पालन करती है। इन सस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए यदि स्वायत्त सस्था का ही उत्तरदायी बनाया जायगा तो उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को भी कोई विघात नहीं पहुँचेगा और न इससे उनकी स्वायत्तता में ही किसी प्रकार की बाधगी। किन्तु इस मस्या में कोई अवकाश प्राप्त 'पंचायती' या सावजनिक क्षेत्र का ऐसा तप हुआ व्यक्ति होना चाहिये जिसके नैतिक व चरित्रिक पक्ष पर किसी को घण्टी उठाने की हिम्मत न हो। इस प्रकार यह आयोग पचायती राज सस्थाओं की अट्टा व सम्मान का भाजन भी बन सकेगा।

यह आयोग यह भी ध्यान रखेगा कि राज्यों के क्षेत्र से जो जनराज पचायती राज सस्थाओं को अपने वायव्य व योजना पूर्ण करने के लिए दी जाती है वह समय पर उपलब्ध हो जाती है। प्रकृता तो यह होगा कि यह जनराज इन आयोगों को ही सौंप दी जाये और फिर आयोग विभिन्न कार्यक्रम व योजनाओं की लागत, जन सहयोग की मात्रा और उन कार्यक्रमों से होने वाले लाभ को देख कर उपयुक्त जनराज पचायती राज सस्थाओं को बांट दे। सामग्री योजनाओं के ऊपर होने वाले खर्च पर यह आयोग इन सस्थाओं से व्यय भी वसूल कर सकता है। इसी प्रकार जीवन बीमा निधि वित्त निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इसी प्रकार की अन्य मस्याओं से भी यह आयोग रुपया प्राप्त कर पचायती राज सस्थाओं का मार्ग विचार कार्य में सहाय। इससे न केवल विकास की गति में ही तीव्रता आयगी बल्कि वार्षिक और वित्तीय मार्गों में भी पचायती राज सस्थाएं सरकार या नौकरशाही का कुछ न ताबेगी और अपने कार्य में स्वतंत्र रहेंगी।

पर यह ध्यायोग केवल इन समस्याओं को धनराशि उपलब्ध कराकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ लेगा। उसका यह भी दायित्व होगा कि सस्थाएं प्राप्त धनराशि का उचित ढंग में तथा उचित मद में ही प्रयोग करती हैं या नहीं यह देखे। यदि इस बात को निगरानी नहीं रखी गयी तो पंचायती राज बरदान देने के स्थान पर अभिशाप बन जायेगा।

ध्यायोग को यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे इन समस्याओं के सरकारी हस्तक्षेप तथा बाधितता से मुक्त रखना आवश्यक है उसी प्रकार उन्हे एक दूसरे पर बाधित छोड़ना भी खतरनाक है। कही 'मरहम' याय के अनुसार बड़ी सस्थाएं छोटी सस्थाओं पर अनुचित रूप से हावी होकर उन्हे समाप्त ही न कर दें। बल्कि होना यह चाहिए कि बड़ी सस्थाएं निम्न स्तर की सस्थाओं को आवश्यक मार्ग दर्शन और सहायता देकर प्राये बड़ों और ऊँचा उठने में योग दें। इसलिए पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप ऐसा हो कि एक सस्था दूसरे का आधार तो हो पर वह उसमें आत्मसात् न हो सके। इससे प्रत्येक सस्था का अपना स्वतंत्र दापर बन जायेगा और इन प्रकार की शिवायन का मौका न मिल सकेगा कि समिति में एक पक्ष का बहुमत हो जान पर दूसरे पक्ष की पंचायती को विनाश के लिए साधन सुविधाएं नहीं दी जाती।

जिस प्रकार संसदीय लोकतन्त्र व्यवस्था के संचालन के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच आपसी सीमनस्य और समन्वय आवश्यक है उसी प्रकार निम्न स्तर की लोकतांत्रिक सस्थाओं के लिए भी यह अनिवार्य है। इन प्रतिनिधियों का काम नीति निर्धारण करना होता है। उन नीतियों को क्रमशः जमा पहनाने का काम प्रशासनिक तंत्र का है।

यदि प्रशासन के ये दोनों पक्ष एक रसता व सामञ्जस्य से काम नहीं करते तो सरकार की नीतियाँ चाहे कितनी ही सुदृढ़ व सोच विचार और नव-नीयता पर आधारित हों उनसे जन कल्याण नहीं हो सकता कारण कि उनका क्रिया बचन व अनुपालन उसी भावना के साथ नहीं किया जाता। इसलिए पंचायती राज की शीर्ष सस्था का यह भी दायित्व होना चाहिए कि वह नीच का लोकतांत्रिक सस्थाओं में जन प्रतिनिधियों व प्रशासनिक कर्मचारियों में आपसी समन्वय व सीमनस्य बनाये रखे। इसके लिए इन दोनों वर्गों के दायित्व व अधिकारों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी होगी। इस प्रकार के नियम निर्धारित करने होंगे जिससे दोनों का बाव बिसा भी मुद्दे को लेकर आपसी सीव तान व मत मुटाब की गुंजाइश न रहे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चाहे वह राज्य कर्मचारी हो या जन प्रतिनिधि सबके लिए आयोग द्वारा कड़े दण्ड का विधान होना चाहिए।

दण्ड विधान के साथ ही उनका हितों के संरक्षण का भी इस शीर्ष सस्था को पूरा ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके हितों की पूरी तरह देखभाल की जाये। उन्हे जन प्रतिनिधि गए दनवर्षों का झिझार कर व्यर्थ में परेशान न करें। ऐसा भी न हो कि निर्वाचित प्रतिनिधि समिति की बैठक में तो उन नीतियों को क्रमशः रूप देने की झिझारिंग करें और बाद में अपने अपने शत्रुओं में उन्हे कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न करें। कर्मचारी जनों की निर्धारित नीतियों को म्रियाचित करने का पूरा छूट होना चाहिए और मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए पूरे अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। उन्हे बाव बात के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का मुंह न

ताकना पड़े। ताकि निर्धारित नीतियाँ व कार्यक्रमों की क्रियावृत्ति में यदि कमी रहे तो कर्मचारियों से ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। इससे एक ओर जन प्रतिनिधियों को नीति निर्धारण के लिए पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त होगी तो दूसरी ओर उनका क्रियान्वयन भी तत्परता व क्षमता के साथ हो सकेगा।

इस प्रकार पंचायती राज का यह एसी शीप सस्या होगी जो उन्हें आवश्यक मांग दर्शन व सहायता तो देगी ही आवश्यकता के समय वित्तीय माघन भी उपलब्ध करेगी। जन प्रतिनिधियों व प्रशासनिक कर्मचारियों को अनुशासन बद्ध रखेगी तथा उनकी पूर्ण स्वायत्तता की रक्षा भी करेगी। ग्रामी जो अपोल और निगरानी के अधिकार राज्य सरकारों के पास है उनसे इन्हें बहुत हद तक अपयश का मागादार बनना होता है। राजनीति विरोधी पक्ष इन्हीं बातों को लेकर सरकार को कोमा करते हैं। इस स्वायत्त शीप सस्या के अधिकार क्षेत्र में इन अधिकारों के दे दिए जाने पर सरकार इस प्रकार की झालोचना से बच सकेगी।





# निष्क्रिय ग्राम पचायतों को क्रियाशील कैसे बनाया जा सकता है?

—श्री गोपीनाथ गुप्ता

पचायती राज की त्रिसूत्री योजना चालू हुए लगभग सात साल का भर्सा हो गया है। या तो किसी भी राष्ट्र के जीवन में सात साल कोई विनाय सम्बन्धी अवधि नहीं होती। लेकिन विकासो मुख देण क लिए सात साल का समय कम अवधि भी नहीं मानी जा सकती। इसलिए अब समय था गया है जबकि हम पचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के सदर्थ । यह विचार करना है कि पचायती राज का आधार-ग्राम पचायतें किस सीमा तक लोकतन्त्र का सदेव घर-घर पहुँचान में सफल हुई हैं और ग्रामाण जीवन के पुनरुत्थान में उनका योगदान किस सीमा तक असरकारी नतीजें लाने में सफल हुआ है ? साथ ही हमें पचायत राज की दूसरी संस्थाओं-पचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्य एवं उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के सदर्थ में उन्हें भी अधिक सक्षम और सक्रिय बनान के उपाय सोचते हैं।

अब यह बात किसी से छिपी नहीं रही है कि प्रस्तावित पचायत राज योजनाओं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था पचायत समितियाँ रही हैं। उनके पास विकास योजनाओं के संचालन के लिए धनराशि रही है इसलिए सर्वाँ दृष्टि अग्र-केन्द्रित होकर रह गई है। ग्राम पचायतों की मदद वृद्धा कोई बैठक हो जाये और पचायत समितियों से प्राप्त गरीबों पर कोई चर्चा हो जाये तो और बात है। गाँव में स्वेच्छिक जन सहयोग या धनदान प्राप्त करने अथवा गाँव की प्राथमिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में जनम प्राय नहीं के बराबर चर्चा होती है। ग्राम सभाओं की बैठकों में भी प्रोत्साहितता

कता ज्यान्त रहती है। उनमें बहुत कम उपस्थिति रहती है और वहाँ होने वाली चर्चाओं को मुनफर ऐसा महसूस होता है मानो ग्राम ग्रामीणों को पचायती राज को इस महत्वपूर्ण इकाई से कोई सराकार नहीं है, उनके कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है।

जब तक ग्राम सभाओं एवं पचायतों को प्राणवान एवं आत्म निर्भर नहीं बनाया जायगा तब तक देश के बहुमध्यक लोगों में लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा पदा नहीं हो सकेगी। इसलिए इन सस्थाओं में व्याप्त निर्धनता दूर करने के लिए उपाय सोचना जरूरी है। इस दिशा में सबसे पहला कदम है पचायतों की आय बढाने के लिए नये साधन पदा करना। आय बढाने का सबसे आधारभूत साधन धात की परिस्थिती में लगान है। यदि पचायतों को अपने क्षेत्र की भूमि पर पूरा अधिकार हो जाये एवं उस भूमि से प्राप्ति होने वाले लगान को प्राप्त करने एवं उसे खच करने का अधिकार मिल जाये तो न केवल पचायत आत्म-निर्भर बन सकती है बल्कि ग्राम सभा एवं पचायत के मध्यम मभी की उनके कार्यों में दिलचस्पी बढ सकती है। आय बढाने पर प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा नये रूप निर्माण पुराने कुआ की मरम्मत, रास्ता का निर्माण ग्रामीण जन एवं उद्यान की स्थापना आदि शायद उस पर डाले जा सकते हैं। जहाँ उक्त दायित्व पचायत पर पड़े कि ग्रामवासियों की उसमें प्रति र्वि बढे। जाहिर है कि केवल लगान की आय में उक्त सभी पदा पर हान वाले खर्च की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए पचायत एवं ग्रामसभा को ग्रामाण समाज की उदार भावनाओं को जागृत करके धनदान एवं दायित्व दान प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। इस कार्य के निमित्त उन्हें हर महीने पंद्रह दिन में गांव के सब लोगों को एकत्र करना पड़ेगा और उनके सामने अपनी माँगें एवं सुझाव पदा करने होंगे। ग्रामीण समाज की उस समय पचायत की कमिया एवं स्वामिया पर खर्च करने का अनुकूल प्रवृत्ति मिलना और पचायत के सम्बंधों की अपनी आचरण सुधारन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आय बढाने के लिए पचायतों को कुछ कृषि भूमि आबादी में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। यह कार्य सब की सहमति से ही हो सकता है इसलिए गांव सभा की र्वम सिससिन में भी अधिक आचार हो जायेंगे।

प्राज सरपच पचायत का अध्यक्ष नहीं, पचायत समिति का अध्यक्ष है। वह जरूरतमद ग्रामीणों का दरखास्त सिकारिग करके पचायत समिति के कार्यालय तक पहुँचाता है और पचायत समिति से जा कुछ कर्जा या अनुदान मिल जाये, उस संबंधित लोग सब पहुँचाकर अपने कर्तव्य की इति दान मान सता है। लेकिन जहाँही पचायत को अपने क्षेत्र की भूमिपर आधारित मिलता कि उसकी पचायत समिति का एनी-सा समाप्त हो जायेगी। उसका अधिकार समय गांव में बालगा और उस वहाँ के कुछ मुख के साथ एकाकार होना पड़ेगा। सरपच का महत्व बढाने की दृष्टि से यह तरीका भी अपनाया जा सकता है कि पचायत समिति की हर बैठक के लिए ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति बहा जायें। इस व्यवस्था से हर तान महीने में ग्राम सभा की र्वम में र्वम एक बार मिलने का भीषा मिलना और अधिक मशम एवं कुदान व्यक्ति को पचायत समिति में भजन का अवसर मिलता रहेगा।

पचायत को अपने क्षेत्र के मजाना, बाहनों, व्यवसाया एवं उद्योगों पर कर लगान का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। ग्राम की सहकारी कष विनय समिति की आय का एक भाग भी उस दिलाया जा सकता है। यला से भी कुछ आय को जा सकती है लेकिन पुकी धादि प्रतिगायी प्रापक खोन पचायत से वापस से लिये जान चाहिये क्योंकि इनमें बैईमानी की ज्यान्त गुजादग रहती है। पचायतें बिबाह एवं धर्म सामाजिक उत्सवों पर कुछ दान प्राप्त करने की भी अधिकारिणी बनाई जा सकती है

लेकिन उस दान का स्वरूप अनिवार्य लागू-बाग नहीं होना चाहिए। गांव में कोई व्यक्ति बिना वारिस के मर जाये प्रपञ्च कोई व्यक्ति विरासत में अपनी सम्पत्ति पचायत को देना चाहे तो यह अधिकार भी उस दिया जाना चाहिये।

उस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कानून के द्वारा पचायतों को जो कर लगान के अधिकार दिये गये हैं वे कर भी अधिकार पचायतों में नहीं गया है लेकिन आज की अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति में यह बात अवश्यभावो है। यदि पचायतों को कुछ ऐसे कार्य सौंप दिये जायें जिनके द्वारा पूरा करन के लिए रुपया जुटाना उनके लिए अनिवार्य हो जाये तो वे कर लगान में कभी विलम्ब नहीं करेंगे। आज तो वे जानते हैं कि अनिवार्य कार्यों के लिए पचायत समिति से पैसे मिल ही जायेंगे। तब फिर वे कर लगा कर अपनी लोकप्रियता क्यों खोयें? आज गांव में जो कार्य हात हैं उनका पूरा अर्थ पचायत को नहीं मिलता। यदि पचायत अपने काम का पूरा अर्थ अपनाना प्रारम्भ कर दे तो पचायत स्वतः ही अपनी आमदनी बढ़ा कर खर्चे करने लग जायगा।

## पचायत समितियों का नियन्त्रण

आज पचायत समिति को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह ग्राम पचायतों को ऐसे कार्य सम्पन्न कराने के लिए आदेश दे सकती हैं जिन्हें पूरा करन का दायित्व कानून द्वारा उन्हें सौंपा गया है लेकिन वे वास्तविक सीमा तक पूरे हाथों हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। परायण समितियों को ग्राम पचायतों द्वारा लिये गये निर्णयों की शर्तों से छुटने का भी अधिकार है लेकिन उनका मतौजा केवल मात्र पचायतों की शक्ति कम होने के रूप में ही हमारे सामने आया है। यदि पचायतों को वास्तव में क्रियाशील बनाना है तो इसके लिए पचायत समितियों को सौंपे गये उक्त अधिकार सीमित करने पड़ेंगे। उन्हें स्वयं सोचन की प्रेरणा देनी होगी और प्रेरणा देने का वास्तविक मार्ग दशम का जिम्मा पचायत समितियों पर डाला जा सकता है। आज तो पचायत समितियों में अफसरशाही का बोलबाला है और सरपंच अपना काम कराने के लिए सब अफसरों की ओर देखता रहता है। उसके लिए अक्सर लोग प्रधान से भी ज्यादा हसियत रखते हैं क्योंकि पचायत समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने की सारी शक्ति उनमें सन्निहित होती है। वे चाहे तो एक न एक अड़गल डाल कर पचायत समिति के किसी भी निर्णय को बेकार कर सकते हैं। इसलिए सरपंच उन लोगों की हानि में हानि मिलाने में अपना लाभ देखता है। इस वातावरण में तो वह क्रियाशील हो सकता है और न उसकी पचायत एवं ग्राम सभा में जान पड़ सकती है। इसका एक मात्र रास्ता पचायत समिति को सौंपे गये अधिकारों को सीमित करना है।

पचायत समितियों को अधिक कार्यक्षम एवं कुशल बनाये जान की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रसार अधिकारियों की सहायता एवं कर्तव्य एवं दायित्व पर गौर करना होगा। आज ये अधिकारी पचायत समिति के प्रशासनिक नियन्त्रण में भले ही हों लेकिन वे अक्सर भी अपने सम्बन्धित विभागों से सम्बद्ध हैं। वे दोहरी व्यवस्था में अन्तर्गत कार्य करते हैं। इसलिए उनकी स्वामिभक्ति विभाजित रहती है। वे अपने कार्य में लापरवाही करते तो उनकी खेपचाम की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल मात्र नवान्ना करवा देना उनमें कर्तव्य निर्गुण पदा नहीं की जा सकता। इसलिए पचायत समितियों को प्रसार अधिकारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने के व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिए।

इसका एक परिणाम सरपंचों में अधिक आत्म विश्वास के रूप में हमारे सामने आयेगा जिससे उस अपने पचायत को अधिक क्रिदानीत बनाने की प्रेरणा मिलगी ।

पचायत समितियों में कार्यविधि के जो नियम बनाये गये हैं उन्हें सरल किये जाने की भी जरूरत है । इन नियमों का कारण पचायत समितियों का बैठका में लिये गये नियमों की प्रभावित हो पाता है । नियम देखे से समझ में आने का परिणाम यह निकलता है कि अपने सरपंच की कार्यकुशलता एवं सामर्थ्य के प्रति ग्रामवासियों का विश्वास एक सीमा तक डिंग जाता है जिसका असर उसकी क्रियाशीलता पर पड़ता है । गांव वाले भी यह समझ लेते हैं कि लाक्षणिक विचारों द्वारा बनाए गए ठोसता है । आज भी वास्तविक ताकत सरकारी कमचारियों का हाथ में है तब फिर बेकार मजदूरी कर में क्या लाभ है ? फलतः वह पचायत एवं ग्राम सभा दोनों के प्रति उदासीन हो जाता है और उनके कार्यों में सक्रिय दिलचस्पी नहीं लेता ।

## जिला परिषद

मौजूदा कानून में जिला परिषदों के जिम्मे पचायत समितियों के कार्य में समय-बचाने एवं उनकी देखरेख करने का कार्य सौंपा गया है । उनकी बैठका में विचारों का आदान-प्रदान हो सक्ती है विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते हैं लेकिन उन लक्ष्यों का पूरा कराने का कोई तरीका उनके पास नहीं है । इसलिए अधिकतर जिला में जिला परिषदें निष्क्रिय संस्थान हैं । बैठका के अलावा बाकी के दिनों में उनके कार्यालयों में दो चार बाबू बैठे बैठे गप-प चिया करते हैं । इसलिए जिला परिषदों को अधिक सक्षम बनाई जाना ही जरूरत है । यह तभी संभव है जब कलक्टर को जिला प्रमुख का सेक्रेटरी बना दिया जाय । विकास कार्यक्रमों में समय बचाने का दायित्व सभी जिला परिषदें सहो मानें में अजाम द सक्ती हैं । आज जिला प्रमुख के साथ नियंत्रण में ऐसे अधिकारी नहीं हैं जो उसे अपने को सौंप गये कर्तव्यों को पूरा करने में मदद दें । वे जिला परिषदों की बैठक में अपने ही भाग ले लें लेकिन वे उससे निदेश के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं । या तो अपने संबंधित विभागाध्यक्षों का नियंत्रण मानते हैं या तब अमुक सीमा तक कलक्टर का । जब तक वे निर्वाचित जिला परिषद के प्रति अपने कर्तव्यपालन के लिए कानूनन बाध्य नहीं किये जाय तब तक विकास कार्यक्रमों में समय-बचाने का जो काम जिला परिषदों के सुपुर्न दिया गया है उस वे किस प्रकार पूरा कर सक्ती हैं ?

# पंचायती राज सस्थाओं पर राजकीय नियन्त्रण

— प्रो० मदनगोपाल शर्मा

०

## (१) सत्ता का विकेन्द्रोकरण उद्देश्य और नीति

पंचायती राज मस्यौदा के निर्माण के पीछे मूल उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रोकरण है। सत्ता के विकेन्द्रोकरण से ही सच्चे अर्थों में जन शासन अथवा लोकशाही संभव है और अन्ततः उसी से एक बृहत् जनसंख्या और विविध सस्कृतियों वाले देश का नित नयी बढ़ती ज्वलन्त समस्याओं के समाधान की आशा की जा सकती है। एक बाँप में चाहे कितनी ही अथाह जल-शक्ति संचित हो जब तक नहरों और उप नहरों द्वारा खेत खेत में जल पारा नहीं पहुँचाई जाती वह बाँप केवल एक अनुपयोगी दिलावा मात्र है। विसी पावर हाउस में चाहे कितनी ही शक्ति का जेनरेटर या ग्रिड रिएक्टर लगा हो जब तक घर घर में बिजली नहीं पहुँचा दी जाती नगर का अन्तःपुर दूर होन वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार समर्थ से समर्थ केन्द्रीय सत्ता भी एक अव्यक्त बाध अथवा अनुपयोगी बिजली घर की तरह बेकार है जब तक उससे विकेन्द्रोकरण की प्रणाली द्वारा जल अथवा विद्युत शक्ति को खेत खेत और घर घर में नियोजित कर कर्म-लोक को सिंचित और पानलोक को आलोकित नहीं कर दिया जाता।

ऐसा नहीं है कि सत्ता के विकेन्द्रोकरण की यह मूल प्रेरणा हमारे नेताओं और नीति निर्माताओं की दृष्टि से अशुभ रही है। योजना आयोग की समिति द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने जन तान्त्रिक विकेन्द्रोकरण की दिशा में जो सुझाव प्रस्तुत किये थे और जो राष्ट्रीय विकास परिषद् (नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल) द्वारा सन् १९५८ में स्वीकार कर लिए गये थे, उनमें स्पष्ट निर्देश है कि—

(१) देश में जनतन्त्र की रचना का मूल आधार ग्राम-जनतन्त्र होना चाहिए। ग्राम आधारित जनतन्त्र की सफलता मुख्यतः तीन संस्थाओं—ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति तथा ग्राम पाठशाला पर निर्भर है।

(२) राज्य सरकारें क्रमशः कानून बनाकर स्थानीय योजनाओं के निमाण और उन्हें क्रमशः मालान का उत्तरदायित्व, स्थानिक पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करेगी।

(३) राज्यों का पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं भी जिला तथा खण्ड स्तरों में विभक्त की जाएगी। इसी श्रृंखला में प्रत्येक ग्राम की अपनी स्वतन्त्र विकास योजना होगी जो स्थानीय आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होगी।

इसी प्रकार सन् १९५६ में स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् ने हैदराबाद की अपनी पाँचवीं बैठक में राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की नीतियों के क्रियान्वयन का लक्ष्य बताया जाते हुए इस बात पर जोर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों को सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण। यदि इस हमल सही ढंग से कर ली है तो विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप और प्रणाली में परिस्थितिगत विभिन्नता कोई विशेष भय नहीं रखती। समिति ने इस उद्देश्य के लिए जो मोटी मोटी सिफारिशें राज्य सरकारों को की उनमें स्वायत्त शासन की जैसी रचना प्रणाली (यू टावर स्ट्रक्चर) के भीतर एक भय सिफारिश में जोर देकर स्पष्ट कहा गया है कि—

(१) स्वायत्त संस्थाओं की अधिकार और दायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए।

(२) इन नव निर्मित स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए वषाप्त साधन जुटाए जाने चाहिए जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकें।

(३) समस्त विकास योजनाएं इन्हीं के सुपुर्द की जानी चाहिए तथा

(४) सत्ता के हस्तान्तरण की जो पद्धति अपनाई जाय वह ऐसी होना चाहिए कि जिससे मध्य में भी सत्ता के अधिकाधिक विवेकीकरण की गुंजाइश रहे।

जिला स्तर तक की प्राथमिक संस्थाओं पर दो बड़े शीर्षकों ० टो ० वृष्णमाधारी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “राज्य और जिला स्तरीय प्राथमिक की नई व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्य की एक मुख्य बड़ी समस्या जाना चाहिए क्योंकि सविधान में निर्धारित प्राथमिक सामाजिक भावित्यों के उद्देश्यों की सिद्धि उन्हीं पर निर्भर है।

इन समस्याओं की निम्नलिखित घटकों के अधिष्ठित उद्देश्यों से यह स्पष्ट है कि सत्ता के वास्तविक न कि नाममात्र के दिवाले के हस्तान्तरण की आवश्यकता न केवल राजनीतिक नताओं के विन्तन भाषण तक सीमित रही है वरन् पदासनों और अधिकार सम्पन्न प्राथमिक अधिकारियों तथा संस्थाओं द्वारा भी उनका समर्थन मात्र हस्तांतरण में हो चुका है। अतः वायदे से सत्ता के वास्तविक विवेकीकरण की जिज्ञा में कोई बाधा नहीं रह जाना चाहिए थी। किन्तु आइए हम देखें कि क्या सत्ता

का वास्तविक विवेचीकरण और लोकतंत्रीकरण हुआ भी है ? सत्ता के मुख्य क्षत्र दो ही हैं (१) वित्तीय तथा (२) प्रशासनिक । वर्तमान पंचायती राज सस्थापना का देशव्यापी अध्ययन हमें इस निष्कर्ष के लिए विवश करता है कि इन दोनों ही क्षत्रों में आज पंचायती राज सस्थापना पर राजकीय नियंत्रण सुदृढ़ है । उसका पकड़ ढीला नहीं हुई है । जो स्वराज्य का गया शव का जटाघोष निकल कर वहाँ है उस मार्ग में हा राजकीय नियंत्रण के नागपास न अवरोध कर लिया है ।

## (२) राजकीय नियन्त्रण वित्तीय क्षत्र

वित्तीय मामलों की भूल कुजी है बजट बनाने और स्वीकृत करने का अधिकार । यही वह चाबी है जिससे अधिकारों का तिलमो खजाना खुलता है । पंचायती राज सस्थापना के प्राथमिक साधन जुटान के प्रश्न में हम विस्तारमय स नहीं आएंगे । वह एक पृथक् प्रश्न है जिसका सम्बन्ध साधन से अधिक है सत्ता में कम । जैसे भी साधन हों और जिस किसी भी क्षेत्र से जुटाए जाए अंतिम प्रमुख प्रश्न बना ही रहेगा कि उन साधनों को क्या करने का अधिकार किसे है ?

इस दृष्टि से हम दबने हैं कि इस त्रेखे रचना प्रणाली पर आधारित देशव्यापी पंचायती राज सस्थापना के लिए इस तनिक सी बात पर चार पृथक् मापण्ड निर्मित हैं जिन्हें हम विनाश के क्रम में सोचाने के रूप में इस प्रकार रख सकते हैं—

(१) पहला वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पंचायत का बजट भी राज्य सरकार अधिकांशता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है— इसमें जम्मू कश्मीर असम पश्चिम बंगाल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के राज्य हैं । असम में तालुका बाड का चीफ एक्जिक्यूटिव अफसर दिल्ली में डिप्टी डाइरेक्टर लोक पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर तथा जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा समय-समय पर नियुक्त अधिकारी यह कार्य करता है ।

(२) दूसरा वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पंचायत का बजट राज्य सरकार अधिकांशता द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पंचायत में बड़ी किसी पंचायत राज सस्था की इकाई द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इस वर्ग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और प्रदेश असम बिहार, महाराष्ट्र उड़ीसा तथा राजस्थान राज्य हैं जिनमें ग्राम पंचायत का बजट को स्वीकार करने का अधिकार क्रमशः क्षेत्र समिति पंचायत समिति, प्राथमिक पंचायत तथा पंचायत समिति को है । संक्षेप में इन सभी राज्यों में ग्राम पंचायत का बजट उससे ऊपर की बड़ी स्वायत्त शासन इकाई करता है ।

(३) तीसरा वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पंचायतें स्वयं अपना बजट स्वीकार करती हैं । इसका अन्तर्गत केरल मध्य प्रदेश मद्रास और गोवा दमन और दीव के राज्य हैं ।

(४) चौथे वर्ग का प्रतिनिधि अनेक पञ्जाब राज्य है जहाँ ग्राम पंचायत का बजट ग्राम समिति स्वीकार करती है । यह ग्राम समिति ग्राम पंचायत को चुनने वाले क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की वय और आय सस्था है । यही ग्राम समिति है । इसके प्रत्येक मतदाता स्वयं तय करता है कि वह अपने द्वारा दिये गये पैसे का उपयोग कैसे करे । वह अपने पैसे को खर्च करने के लिए पात्र कुपात्र के चुनाव के चक्कर

म पठकर भुलाव और पक्षपाते को स्थिति में नहीं पड़ता। वह स्वयं अपने उपभाग का चुनाव करता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी पूँजी खर्चने या लगाने के लिए राजनीतिज्ञ मुनीम गुमान को नहीं चुनता बल्कि खुद अपनी इच्छा से अपनी पूँजी खर्चता है। वह ऊपर से आरोपित उपभाग के लिए बाध्य नहीं है बल्कि स्वयं एच्छिक उपभाग का स्वतंत्र अधिकारी है। इसलिए पने को वसूली और खर्च में अनिच्छा प्रभावित, बेईमानी, उपद्रव प्रभृति मजबूरी जैसी समस्याएँ दुर्गुणों का इस एक ही व्यवस्था से काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं। क्या हम आशा करें कि अन्य राज्य भी इस विषय में यही पद्धति यथाशीघ्र अपनाएँगे ?

इसी प्रकार पंचायत समितियाँ स्वयं अपना बजट स्वीकार करती हैं और राज्य सिक महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। गुजरात उत्तर प्रदेश तथा असम को भी अपने मिलते-जुलते स्थिति है जहाँ पंचायत समिति को समन्वयीय संस्थाएँ क्रमशः साधुता पंचायत, क्षेत्र समिति तथा मोटकमा परिषद अपना बजट स्वयं स्वीकार करती हैं। पंचायत समिति से बड़ा स्वायत्त इकाई जिला परिषद् जहाँ पंचायत समिति का बजट स्वीकार करती हैं ऐसे राज्यों में भी विहार मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं। मद्रास और मसूर भी इसी श्रेणी में हैं जहाँ इकाई उसी स्तर का है किन्तु नाम में अन्तर है। मद्रास में पंचायत प्रणित नौसिल और मसूर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट नौसिल कहलाती हैं। हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रकृति की ही पंचायत समिति का बजट स्वीकार करने का भी अधिकार है। इस प्रकार पंचायत समिति की विस्तृत व्यवस्था में भी सत्ता के विधि मानदण्ड हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। प्रथम श्रेणी के राज्यों के समानांतर ही अन्य राज्यों में भी व्यवस्था हो जानी चाहिए जहाँ पंचायत समिति प्रत्यक्ष मित्र नाम वाली समन्वयीय स्वायत्त संस्था स्वयं अपने बजट स्वीकार करने की अधिकारी हो।

इस त्रैल रचना को सबसे ऊँची सीढ़ी जिला परिषद् स्वयं अपना बजट स्वीकार करने में समर्थ केवल गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्यों में है। दूसरा वर्ग उन राज्यों का है जहाँ जिला परिषदों का बजट राज्य सरकारें स्वीकार करती हैं। इस वर्ग में आंध्र प्रदेश विहार तथा पश्चिम बंगाल हैं। तृतीय वर्ग ऐसे राज्यों का है जहाँ जिला परिषदों का अपना कोई बजट ही नहीं है। इस वर्ग में असम, मद्रास, मसूर तथा हिमाचल प्रदेश की गिनती है। स्पष्ट है कि एकरूपता के लिए प्रथम वर्ग के समकक्ष माने हुए सभी राज्यों में जिला परिषदों को अपना स्वतंत्र बजट बनाने तथा उसे स्वीकार करने का अधिकार दिये जान की आवश्यकता पड़ती है।

## (३) राजकीय नियन्त्रण प्रशासनिक क्षेत्र

म केवल वित्तीय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी पंचायती राज संस्थाओं पर राजकीय नियन्त्रण आवश्यकता के बड़ी अधिक है। प्रशासनिक मामलों में कर्मचारियों का नियुक्ति पदचुनि व्यापक घाटाण (भावर भाव मुर कोत्रन) निलया को बदलने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं की भव करने का प्रावधान इलाहि प्रान प्रमुख रूप से हमारे समक्ष आते हैं। इन्हें हम एक-एक करके और विचार करें।

(१) कर्मचारियों की नियुक्ति पदचुनि अनुशासन एवं दण्ड सम्बन्धी मामलों में प्रथम प्रथम राज्यों में प्रथम प्रथम प्रकार की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए राजस्थान में जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के कर्मचारियों के पदों के लिए भर्ती। इस कार्य के लिए गठित एक राज्यस्तरीय चुनाव



कमोशन द्वारा होता है जिसमें दो सदस्य राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं तथा तीसरा सम्बंधित जिले का प्रमुख । यह कमोशन योग्यता के आधार पर केवल उम्मीदवारों में से चुनाव कर केवल पात्रता सूचि (मेरिट लिस्ट) बनाता है । वास्तविक नियुक्ति का कार्य तो एक पृथक समूह जिला इस्टैब्लिशमेंट कमेटी के जिम्मे है जिसमें जिले का कलेक्टर जिचा प्रमुख तथा एक पचायत सर्विस चुनाव कमोशन का सदस्य-ये कुल तीन सदस्य होते हैं । इस प्रकार पचायत राज संस्थाओं के कमचारियों के चुनाव के लिए पृथक तीन सदस्यीय इकाई है और उनको नियुक्ति का कार्य दो पृथक समूह करने जिससे यह ही समय और साधन का उपयोग और कार्य में विलम्ब और गिथिलता हो । वास्तविक उद्देश्य तब समझ में आ जाता है जब हम इन दोनों समूहों के रचना स्वरूप पर विचार करते हैं । चुनाव कमीशन में १० सदस्य चुनाव कमीशन के तथा एक जिला प्रमुख—इस प्रकार एक निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा दो राज्य कर्मचारी होते हुए भी अपेक्षाकृत स्वतंत्र गति वाले संस्थान होते जिसमें राजकीय नियंत्रण के चिन्ने खरे की घण्टी के आसार हो सकेंगे । घट वास्तविक नियुक्ति के त्रिगुट में राज्य के सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न कर्मचारी-कलेक्टर को प्रेषित कर प्रत्येक राजकीय नियंत्रण के लिए अवसर प्रस्तुत कर दिया गया है । यह जन-प्रतिनिधि तथा कथित अपेक्षाकृत निष्पक्ष और स्वतंत्र राज्य कर्मचारी में या तो अविश्वास का द्योतक है या इसमें अपनी मनमानी करने की इच्छा का सूचक । अथवा दोनों कार्यकुशलता या कार्य संगतता का आधार इसके पीछे क्या जा सकता है ? कर्मचारियों में स अपनी पसंद के पात्र को उन के स्थान पर नियुक्ति के लिए कलेक्टर की वृत्तांश पर निर्भर रहना होगा । यह लाक्षणिक में यदि बात का ही सूचक है । गुजरात में कुछ पात्रों के लिए राज्य पचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तथा कुछ छोटे स्तर के पदों के लिए जिला पचायत सर्विस सिलेक्शन कमेटी कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति करती है । महाराष्ट्र में तकनीकी सहायता के लिए चयन और नियुक्ति डिवाजन चुनाव बोर्ड द्वारा की जाती है तथा गर तकनीकी कर्मचारियों का चुनाव और भर्ती जिना चुनाव बोर्ड द्वारा । आर्य प्रभू तथा अन्य दूसरे कई राज्यों में चुनाव जिलास्तरीय कमेटी या बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

इस सारे विवरण के बाद हमारा सुझाव यह है कि चयन तथा नियुक्ति के लिए पृथक समूह न होकर एक ही हो जा राज्यस्तरीय हो । इसमें जिला प्रमुख चुनाव कमीशन के सदस्य हों तथा सम्बंधित विषयों के विशेषज्ञों की भी आमंत्रित किया जाय जिससे तकनीकी सलाह भी मिल सकें तथा विषय के विवरण का अनुभव भी प्राप्त हो सके ।

(२) कर्मचारियों के अनुशासन और नियंत्रण की दृष्टि से, आर्य प्रदेश को छोड़ शेष राज्यों में पचायत समिति के एक्जीक्यूटिव अफसर के कार्यों की गोपनीय रिपोर्ट किसी सरकारी अधिकारी-अधिकृत कलेक्टर और वही-वही डिप्टी कमिशनर और यहां तक कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है । केवल आर्य प्रदेश में ही यह अधिकार पचायत समिति के अध्यक्ष या प्रधान को है । मद्रास में सर उडोसा राजम्पान तथा उत्तर प्रदेश में कलेक्टर यह रिपोर्ट तैयार करते समय पचायत समिति के प्रधान की राय का भी मध्य-नजर रखता है । इस प्रकार मुख्य रूप से पचायत समिति के अधिकारी को दण्ड देने का अधिकार राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी में निहित है । सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहाँ पचायत समिति को अपने अधिकारों की निंदा करने और वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार दिया गया है । इस प्रकार यहाँ की त्रिविध प्रणाली है राजकीय निर्वाचित जन प्रतिनिधियों तथा सम्मिलित । इन तीनों प्रणालियों के कार्य के परिणाम को देखते हुए इस विषय में कोई ऐसा हल खोजा जाना चाहिये जिसमें

सभी के हित रक्षित हो। कोई एक दूसरे के दबाव में धातन के लिए विवश न हो। न मोकामाहो का प्रतिनिधि कमचारी स जह खरीद युताम की तरह बर्ताव कर सवे धीर न हो नौरगारी क विज्ञात की एक प्रदना पत्न तिरछी पठ हर जन प्रतिनिधि को शह या मात दे सके। एक मोर नया सता-मद है दूसरी मोर पुराना सतामोह। एक नया चढता नया है, दूसरी मोर सुमार जो उतरना नही चाहता। मत इन दोनों की टक्कर का बचान के लिए बहुत कुशलता मोर मुक-मुक का व्यवस्था को धाव, व्यवस्था है।

जिला परिषद् के मुख्य अधिगामी अधिवारा की गापनीय रिपोट तयार करन का अधिवार कवल भाद्र प्रदेश में जिला परिषद् के अध्ययन का है। अध्ययन यह अधिवार राज्य सरकारें धमका उसके द्वारा विमुक्त धावकारी म निहित है। उडासा मोर राजस्थान म मिला-जुना व्यवस्था है। जह राजकीय अधिवारी जिला परिषद् के प्रमुख धमका अध्ययन की राय जो मोपनाय रिपोट तयार करन समय निहार म रवगा ऐसी व्यवस्था है। हमारा सुभाष इन विषय म यहा है कि पचायत राज सत्याप्रा के मोना सागानों—ग्राम, समिति तथा जिलाभार के लिए एक-सो व्यवहार्य मोर सब हित धायक मोर समाधान कारक व्यवस्था होनी चाहिये। मुख्य अधिवार जन प्रतिनिधिया म निहित रहे निम्नु कमचारी की भी उसका सहो दुलना सुवान के लिए भाई निपणस अध्ययन मुनम रहना चाहिये।

(१) जिला परिषदों के गठन मोर उनके काय धम तथा अधिवारा क सम्बन्ध म भा विभिन्न राज्या म परम्पर विरोधो मोर असमन रहना सोच पडतो है। जिला स्तर की यह पचायती राज इजई पात्र विहार महाराष्ट्र उडोसा पञ्जाब राजस्थान उत्तर प्रदेश, मोर पश्चिम बंगाल म जिला परिषद् के नाम से जानी जाता है तो गुजरात म इन्डियन पचायत मध्य प्रदेश म जिला पचायत मोर मयूर व मद्रास मे इन्डोस्ट इक्वलिटी कमिशन के नाम से। नाम म भन्तर कोई बडी बात नही है। किन्तु कार्य धम मोर रचना-स्वरूप म भी बडा भिन्नता है। मभा इन्द्राप्तराय इकाया म पचायत समिति के स्तर की सत्याप्रा क प्रतिनिधि चुन जाकर गते है मकिन उनका सहजा मोर चुन जान का दण राज्यों म पृथक पृथक है। बिधिया तथा परिगणित जातियो मोर धम जातियो के प्रतिनिधिया के बिगुप प्रतिनिधित्व की व्यवस्था म भी एकपता का धमाव है। मद्रास म स्त्रियो के विषय प्रतिनिधित्व तथा पश्चिम बंगाल, मयन मोर उडासा म परिगणित जाति तथा जन जाति के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था नही है। यह धायराल का दोहरा मानदण्ड कही तक समीचीन है ? कया मद्रास म स्त्रियां इतनी गिण्ट हैं कि उन्हें विगिण्ट प्रतिनिधित्व की धायकता ही नही है तथा कया मद्रास, पश्चिम बंगाल मोर उडासा इन सभा राज्या म परिगणित जातियो की सख्या का धमाव है धमका के परिगणित जातियो स उठकर स्वतंत्रता क प्रमाण से सुना सम्पन्न वर्ग म परिणत जातियो हो गया है ?

(४) जिला परिषदों के गठन के धर्तिरिक्त उनका काय मोर अधिवारा धम म भी विषमता है। मयूर तथा मद्रास मे जिला परिषदें कवल पचायत समितियो के काय का देखभाल करन मोर उनके मोर राज्य सरकार के बीच की बडी का काम देन वाली सभाए हैं जबकि पात्र प्रदेश मे इन वर्ग के प्रतिरिक्त जिला परिषदों पर निदिष्ट प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी है जस भाव्यमिव गिण्ट का प्रचार प्रसार मोर व्यवस्था, धौधानि तथा ध्यावगाधिक म्मुका का धमक धमि। यही नही, गर समिति विदाम सन्डा ये के ही पचायत समिति का भी काई करतो है। महाराष्ट्र मे जिला परिषदें, पचायती राज सत्याप्रा की

सबसे शक्तिशाली और सुदृढ़ बन्दी है और वे योजना बनाने विवास वार्डों को पूरा करने तथा राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करते हैं। गुजरात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी वे प्रशासनिक कार्य सम्पन्न सम्पादित हैं जबकि असम, मद्रास मसूर और हिमाचल प्रदेश में उनके लिए पृथक् बजट प्रावधान तक नहीं है। मद्रास और मसूर में तो प्रशासनिक कमचारियों को भी सवाए उन्हें सुनने नहीं है जबकि दूसरी ओर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एवं धरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों—आई० ए० एस० उनके कार्य को देखभाल करता है। अन्य राज्यों में सब दिवाजनल अफसर के स्तर का कर्मचारी नियुक्त किया गया है।

इस सम्बन्ध में विचारणीय मही है कि क्या इस विषयता को किसी सीमा तक घटायी नहीं जा सकता और यदि महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषदों को व्यापक अधिकार और दायित्व दिया जाना का अनुभव प्रतिकूल नहीं है तो अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया क्या उचित नहीं होगा ?

(५) वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमन नियन्त्रण की भाँति ही निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कर्तव्य भग्न अथवा अपक्रम की स्थिति में उनकी पदच्युति इत्यादि का प्रश्न भी उठता है। इस विषय में भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएँ हैं। प्रथम सोपान अर्थात् ग्राम पंचायत के स्तर पर पंचों की पदच्युति का अधिकार असम बिहार केरल, मध्य प्रदेश उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार में निहित है जबकि आन्ध्र प्रदेश में कमिश्नर मसूर में डिप्टी कमिश्नर पंजाब में डाइरेक्टर लोकलबाडीज उत्तर प्रदेश में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा गोवा मदन दीव में सेप्टेनट गवर्नर की यह अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार तीन चौथाई से भी अधिक राज्यों में पंच तक की हटान का अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथों में सुरक्षित रख लाने का कार्य करने वाले पंचों की अपील आदि के लिए लम्बा समय और प्रक्रिया देकर मनमाना को छूट दे रही है और उन पर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में भी इससे पराक्ष रूप से बाधा पहुँचाती है। सिफ़ दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ कि ग्राम पंचायत के पंच की पदच्युति का अधिकार राज्य सरकार को न होकर पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त है—एक तो महाराष्ट्र जहाँ जिला परिषदें पंचों की पदच्युति कर सकती हैं दूसरा मद्रास जहाँ स्वयं पंचायत अपने किसी सदस्य पंच की पदच्युति करने में समर्थ है। मद्रास की इस क्रांतिकारी परम्परा को हम तो एक डग और आगे बढ़ाने हुए कहना चाहेंगे कि पंच की पदच्युति का अधिकार ग्राम सभा में निहित होना चाहिए। वस्तुतः जो वर्ण करता है उसी को परिष्कार का भी अधिकार मिले यही तर्क मम्मट और म्यायोचित दृष्टिकोण हो सकता है।

पंचायत सार्वभौमिक के सदस्य पंचों की पदच्युति का अधिकार केवल मद्रास में उससे ऊपर की जिला स्तरीय इकाई पंचायत ग्रुनियन कोसिल को दिया गया है। अतः सब राज्य सरकारें अथवा उनके द्वारा नियुक्त कमिश्नर ही पदच्युति का आदेश दे सकता है और जिला परिषद के स्तर की अन्तिम तृतीय सोपान की स्वायत्त पासन इकाई के सदस्य को पदच्युति का अधिकार सब में केवल राज्य सरकारों को ही है।

इस सारे प्रसंग में एक ही सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए कि जो चुने वही छोड़े, जो वरण करे वही परिष्कार करे। इस दृष्टि से ग्राम पंचायत के सदस्य पंच की पदच्युति का अधिकार ग्राम सभा

को होना चाहिए तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत समिति में भजे गये ग्राम सदस्यों को प्रस्ताव पारित कर वापिस बुलाने का या पदच्युत करने का अधिकार होना चाहिए और इस प्रकार पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद में भजे गये ग्राम प्रतिनिधियों के नियंत्रण परावर्तन या पदच्युति आदि का अधिकार समिति को मिलना चाहिए। किन्तु इस विषय में एक कठिनाई यह है कि पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन सचिव एक रूप नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत महिला या परिगणित वर्ग के प्रतिनिधि तथा सह वरित प्रतिनिधियों पर नियंत्रण का प्रश्न सामने आता है। इसका उपाय यही है कि ग्राम पंचायतों से पंचायत मामलों के प्रतिनिधियों का और पंचायत-समितियों से जिला परिषदों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सोपान की पंचायती राज संस्था अपने से पहले सोपान का स्वायत्तशासी इकाई के लिए मतदाता क्षेत्र का काम करे तथा महिला परिगणित जाति आदि के लिए स्थान भले ही निर्धारित कर दिए जाय किन्तु निर्वचन इनका भी हो न कि मनोनयन प्रणाली सहवर्ण। निर्वाचकों को ही प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने हटाने या ग्राम सभाओं देन का अधिकार हो। जिसमें सारी सत्ता नीचे से ऊपर न आकर ऊपर से नीचे आती हुई ग्राम सभा तक प्रसारित ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति मतदाता तक पहुँच जाए। तभी स्वराज्य की गंगा नाले से ऊपर की बरतों दिशा को छोड़ कर ऊपर से नीचे का और की सहायता में बह सकता है। चुनाव करने वाला कोई और हो और रद्द करने वाला कोई और इसका साफ प्रश्न है दायित्व और अधिकारों का पारस्परिक और जन शक्ति, जन कृति, जन चेतना का प्रबोध। ग्राम सभा पंच को चुन और कोई सरकारी काम चारी उस हंगामे यह ठीक बसा हो है जैसे बैठा बहू का चुनाव नो करले किन्तु सात उसे घर से निकाल दें। यह स्थिति पुरानी सामंती चर्च की सूचक है। तीनों ही सोपानों पर इन निर्वाचित स्वायत्त संस्थाओं में राज्य की ओर से तकनीकी प्रणाली विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञों को नियुक्ति की जाए तो परामर्श देन का काम करें। उहें मतदाता का अधिकार नहीं होना चाहिए।

-- (६) निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अनुशासन के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के नियमों पर नियमन का प्रश्न भी उपस्थित होता है। इस क्षेत्र में भी व्यवहार-विभिन्नता दीव्य पड़ती है। ग्राम पंचायत के निर्णयों को बदलने का अधिकार प्रायः, आसाम बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश मद्रास महाराष्ट्र मसूर, उड़ीसा और पंजाब में कमिशनर, डिप्टी कमिशनर, कलेक्टर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यहाँ तक कि तालुका विकास अधिकारी (गुजरात) खण्ड विकास अधिकारी (गोवा दमन दीव) और पंचायत अधिकारी (राजस्थान) तक के स्तर के राज्य कर्मचारियों को प्राप्त है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। जब इन अधिकारियों की प्रथम-मंती और ईमानदारी का हो इनका भरोसा था कि वे पूरे पंच नियमों को रद्द कर दें तो फिर पंचायती राज के झूठे हस्त की सहायता एक बेकार का गोरख बंधा और लखौला भ्रमेका बन कर रह जाता है। निर्णय उत्तर प्रश्न में ही पंचायत के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार जिला परिषद को देकर जातिगत व्यवस्था की ओर कदम उठाया गया है। किन्तु हम तो चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार ग्राम सभाओं को ही मिलना चाहिए क्योंकि पंचायत के निर्णय से वे ही प्रभावित होते हैं। शत प्रतिशत व्यक्ति स्वयं अपना उपचार करने में समर्थ हो सके तो इससे बड़कर स्वावलम्बन क्या होगा? अधिक से अधिक यह हो सकता है कि ग्राम सभा का यह निर्णय पुष्टि के लिए जिला परिषदों के पास भेज दिया जाया करे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के स्तर की संस्थाओं के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार विभिन्न राज्यों में सरकार प्रणाली कलेक्टरों या

कमिश्नरी में निहित है। यहाँ तक कि ग्राम में जिला परिषद् के निर्णयों तक को सब डिविजनल अप्पनर के स्तर का अधिकारी रद्द कर सकता है। यह स्थिति अयायपूख और अपमानजनक है और पंचायती राज की सारी बुनियाद को हिला देने वाली है। होना यह चाहिए कि किसी पंचायती राज संस्था के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार उससे पूर्ववर्ती संस्था को होना चाहिए जिससे पुष्टि परवर्ती संस्था करे। इस प्रकार ग्राम पंचायत के निर्णयों को ग्राम सभा पंचायत समिति की सहमति से और जिला परिषद् के निर्णयों को पंचायत समिति के निर्णयों को ग्राम पंचायत जिला परिषद् की सहमति से और जिला परिषद् के निर्णयों को पंचायत समितियाँ राज्य सरकार का सहमति से। इसमें पीड़ित अधिकारी तथा कार्यकारी-तीनों पक्षों का समावेश हो जाता है। कोई भी कड़ी अपनी अगली-पिछली कड़ियों के सातमेल में हाँ दूँट सकेगा। आधार माध्यम धारण तीनों एक ही सीधी रेखा में आजात हैं जिसमें स्वयं ही कार्य सही सीधी रेखा में हमें और इस व्यवस्था से ही निर्णयों को रद्द करने की नीयत नहीं आयेगी या आयेगी भी तो बहुत ही कम।

(3) इसी प्रकार पंचायती पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदों को निलम्बित भ्रमण करने के अधिकार का भी स्वागत है। ग्राम पंचायत को ग्राम में कमिश्नर, उड़ीसा में म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली में श्री कमिश्नर तथा गोवा-मन्न-नीव में लेफ्टिनेंट गवर्नर भग कर सकता है। सभी राज्यों में राज्य सरकार में यह अधिकार निहित है तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भग करने का अधिकार सभी राज्यों में राज्य सरकार में निहित है। इस विषय में एकमात्र सामान्य निति प्रस्तावित जानी चाहिये कि केवल राज्य सरकार ही किसी भी स्तर की स्वायत्त संस्था को निलम्बित या भग कर सके वह भी विविध परिस्थितियों में तथा उचित कारणों के आधार पर ही।

**निष्कर्ष** — इस सारे तुलनात्मक विश्लेषण से जो निष्कर्ष हमारे सामने आता है वह यह कि ग्राम पंचायती राज संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण क्या वित्तीय और क्या प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में आवश्यकता से कहीं अधिक है। वर्तमान स्थिति का उद्धार से उद्धार आलोचक भी इसे स्वीकार करेगा। यह ठीक ऐसा ही है जैसे एक हाथ से लड्डू किसी की हथेली पर रखना और ग्राह्य जान से पहले ही दूसरे हाथ से उसे छीन कर अपने मुँह में रख लेना। यह भ्रम बुझाना नहीं किसी का मखौल उड़ाना ही कहा जायगा। यदि हम इस विराट जनसंख्या संकुल समस्या प्रधान देश को ईमानदारी से विकास के पथ पर उठाना है और जनता की स्वराज्य की सच्ची अनुभूति और प्रेरणा देना है तो निश्चय ही हम आत्मिक उठाकर भी पंचायत राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देना ही होगा। पंचायतीय प्रणाली वाली दलबन्धी की प्रतिस्पर्द्धों पर आधारित व्यवस्थापिका समाएँ तो वस ही सभी देशों में ग्राह्यमान-व्यावसायिक बनकर रह गयी हैं। इस देश के भूतल से अनुकूलते और जनसंख्या वृद्धि से सिमटते ग्रामिन में तोतल बर के प्रछाडे मड करने या तोता मना की तू-तू धी-धी के छोड़ें बडे पिन्ड रखन के लिए अब तिल भर भी भूमि का प्रवकाश नहीं है। अब तो हमें समर्थ, निष्ठावान, जागरूक और तत्पर कार्यकारी संस्थाओं की अहती आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाएँ ही अधिकार और अनुभव प्राप्त कर इस महान् कार्य को करने में समर्थ हो सकेंगी। यह कार्य छोड़ से छोड़ सम्पन्न किया जाना चाहिये जिससे कि प्रसिद्ध सर्वोन्मयी विचारक श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने म सत्ता का उल्टा पिरामिड सोचा जा सके और राजस्थान में जन-चेतना के अग्रणी प्रहरी श्री कुमाराम बाय ने गन्दा में लोकाही का अमुदय हाकर गौरगाही की रात का अन्त हो सके।



## पचायती राज में जन-प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी

—श्री शोतलमहाय श्रीवास्तव

भारत में सामुदायिक विधायन कार्यक्रम का उद्घाटन १९५२ में हुआ। उसका उद्देश्य यह था कि जन समुदाय के सक्रिय प्रयत्न और पहल से प्राथमिक व सामाजिक उन्नति हो सके। इस कार्यक्रम में लोगों में प्रेरणा दी गई कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं अपने साधनों का उपयोग करेंगे। प्रारम्भ में हम सम्बन्ध में सरकारी मन्त्रियों ने प्रशंसा प्रत्यक्ष किया, लेकिन कुछ समय बाद अनुभव किया गया कि गाँवों में सामुदायिक विकास कार्यों के लिए चेतना जागृत नहीं हुई और गाँवों में इस चेतना का जागृत करने के लिए बहुत अधिक शक्ति समय सम्पत्ति की जरूरत है। इसका प्रतिरिक्त विधान कार्यक्रम का इनको अधिक समस्याएँ थी कि केवल सरकार द्वारा उनका हल होना सम्भव भी नहीं था। यह केवल तभी सम्भव हो सकता था जब विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र में हटा कर जनता और उनके प्रतिनिधियों को सौंप जाए। यही लक्ष्य भी विकस्रीकरण का आधार है और इसी कारण पचायती राज का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप प्रशासन की तीन स्तरों में विभक्ति किया गया।

ये तीन स्तर इस प्रकार हैं—ग्रामा परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनका एक दूसरे से परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इन सभी स्तरों में जन प्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र के बीच

चारिया का ऐसा मिलाजुला समागम है जिसके सफल प्रयत्न पर ही सामुदायिक विकास की सफलता निर्भर करती है।

जिला परिषद् की स्थापना के पहले कुछ राज्यों में जिला बोर्ड काम कर रहे थे जिसका चेरम मन जन प्रतिनिधि होता था चेरम मन विभिन्न विकास विभागों से सम्बद्ध नहीं था, और न उनकी उसने प्रति कोई जिम्मेदारी ही थी इसी प्रकार विकास क्षेत्रों से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु अब सभी विकास विभागों के अधिकारों अधीन के प्रति जिम्मेदार होते हैं और पंचायत समितियों के कार्यों से उसका सीधा सम्बन्ध हो गया है। अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) अथवा जिला नियोजन अधिकारी ही जिला परिषद् का मुख्य कार्य अधिकारी होता है जो सभी विभागों के अधिकारियों और अधीन अथवा जिलाधीश और अधीन के बीच की कड़ी है। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह इन अधिकारियों और अधीन के सम्बन्धों को बिगाड़ दे अथवा बने दे। इन सम्बन्धों पर काफी अंश तक विकास कार्यक्रमों की सफलता निर्भर करती है। परन्तु व्यवहार से कुछ ऐसी बातें देखने में आ रही हैं जिससे विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है।

अधीन का चुनाव राजनीतिक आधार पर होता है। जिससे अधीन का अधिकारी समय राजनीतिक गुणों के भण्डों में हाँ बीत जाता है और वे अपना पूरा समय विकास कार्यों का नहीं पाते हैं। बहुत से अधीन जिन के छ तरतम भागों के निवास होते हैं। और जिन में उनके निवास की गति व्यवस्था नहीं होती अतः वे अपने कामों में प्रति द्योषित भाव नहीं कर पाते। बहुत से विकास विभागों के जिले के अधिकारियों केवल जिला परिषद् की बैठक में ही अधीन को अपनी प्रगति के बारे में बता पाते हैं। कार्यक्रमों का कठिनाई और उनके निराकरण पर अल्प समय कोई विचार विमर्श नहीं हो पाता। जहाँ तक सम्बन्धों का बात है अधीन को जिलाधीश का मुँह जोहना पड़ता है जबकि कुछ राज्यों में जिलाधीश का जिला-परिषद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। जिला परिषद् के पुराने कार्यालय और नियोजन कार्यालय अब भी अधीन जिलों में अलग अलग बन हुए हैं, इसलिए एक प्रकार का अनायास बना हुआ है। सभी अधिकारियों का जो जिला परिषद् के नियंत्रण में काम करते हैं एक जगह बैठना कार्यक्रमों के हित में होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों के ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ के अधीन कहते हैं कि हमें कि उनके यहाँ आई० ए० एस० केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो। रामभूति समिति की सिफारिश कि महाराष्ट्र की भाँति उत्तर प्रदेश में भी आई० ए० एस० केन्द्र के मुख्य कार्य अधिकारी रखा जाए जहाँ तक अधीनों की भाँति होगा और जहाँ तक दाना के सम्बन्धों से दूर रहे। साचना होगा। वहीं-वहीं अधीनों के भाँते ही सख्त विकास अधिकारियों के लिपिका के और स्कूल अधीन के स्थानान्तरण में निवृत्ति ली। उन्होंने परोक्ष रूप से यह भी प्रयत्न किया कि उनके विरोधी प्रमुखा के प्रति या तो अविश्वास का प्रस्ताव पास हो अथवा उन विकास क्षेत्रों में जिला परिषद् को कोई सहायता न मिलने पाए।

इन दुस्पूर्ण और अधीन प्रयोगों के साथ साथ ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जहाँ योग्य अधिकारियों और अधीनों को आपसी प्रेम और सक्रिय सहयोग से बड़े-बड़े कार्य सम्पन्न हुए हैं। उही जिला में जनशक्ति के प्रयोग का कार्य सफल हुआ।

१०. १० मोकतमी विनोद्रीकरण की दूसरी कड़ी पंचायत समिति है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें।

यहाँ की राज समिति के अध्यक्ष प्रमुख कहलाने हैं और ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख उनके सहायक जन प्रतिनिधि होने हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख व मत व हो हो उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में प्रमुख के लिए विकास खण्ड की योजनाओं को अपनी मानि या क्षेत्रीय समिति के निर्णय के अनुसार चलान में बड़ी कठिनाई होगी है। ऐसी विरोधी पनाविकारी प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी के बीच खाई चौड़ी करने का प्रयत्न करने रहते हैं।

बहुत-से प्रमुख यह कि राजनीतिक क्षेत्र से चुन कर धाए होने हैं इसलिए वे प्रयत्न करते रहने हैं कि उनके ग्रुप के प्रधान या सरपंच विज्ञा भी प्रकार असन्तुष्ट न रहने पाए। कुछ प्रधान या बहुत से पदाधिकारी धन का गवन करते पाए गए हैं और जब विस्तार अधिकारी उनका विरुद्ध कायदाही करते हैं, तब उन्हें रास्ता जाना है अथवा उनका ही स्थानान्तरण करान का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी स्थिति में कमी कमी खण्ड विकास अधिकारी और प्रमुख में खींचतानी होने लगती है।

जाप भी अधिकारियों और अध्यक्ष प्रमुख में संघर्ष का कारण है। उत्तर प्रदेश में महीने भर का विकास खण्ड में केवल ३०० मोल जोप चलान की सीमा है। वास्तव में यदि खण्ड विकास अधिकारी और विस्तार अधिकारी १०० मोल चला गए तो प्रमुख को गाली नहीं मिल पाई। इसी प्रकार प्रमुख यदि महीने भर में २०० मोल चला गए तो तब भी सरकारी अधिकारियों को जीप द्वारा थपथप दौरा करान की नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में जो खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख के साथ मिल नहीं बैठे पान, उन्हें प्रमुख की धार में मनहूषाग और तनाव की स्थिति सहन करनी पड़ती है। कुछ बित्तिय मामला जैसे तबाकी और अनुदान खिचान में गड़बड़ करान के लिए कहीं-कहीं बिस्व किया जाता है।

बहुत-से प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारियों के बीच उनकी निजी अहमण्यता और ऊँच नीच की भावना के कारण भी संघर्ष और मनमुटाव हो जाते हैं। कुछ प्रमुख विस्तार अधिकारियों और अन्य कमचारियों के कार्य में बाधे हस्तक्षेप करते हैं। वे प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं।

जहाँ ऐसे उदाहरण हैं वहाँ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ खण्ड विकास अधिकारी अपने प्रमुख के धनरा ही बरेबर रोन अपनी इच्छानुसार लिखा लेते हैं। इनमें बहुत से प्रमुख ऐसे होते हैं जो या तो बहुत सीधे होने हैं या खण्ड विकास अधिकारी से बहुत अच्छा सम्पर्क रखते हैं। खण्ड विकास अधिकारी या विस्तार अधिकारी ऐसी बहुत-सी स्थितियों में प्रमुख की सामान्य कायकमा और सरकारी आदेशों से अवगत नहीं करा पाने। ऐसे खण्ड विकास अधिकारी यही कहने में प्रयत्न करते हैं कि मैं भी समझ लेते हैं कि उनके यहाँ प्रमुख से कोई संघर्ष नहीं है। जन प्रतिनिधियों से अच्छा सम्बन्ध, साधन मात्र है। अन्तिम ध्येय तो विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति है।

पुन उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें। यहाँ पंचायत मंत्री पूरात क्षेत्र समिति का कमचारी है और सामान्यतया सहायक विज्ञा अधिकारी पंचायत की पंचायत मंत्री से काम लेना होता है। बहुत से निम्निय पंचायत मंत्री प्रमुख से अच्छा सम्पर्क रख कर सहायक विकास अधिकारी पंचायत से या तो सम्बन्ध ही नहीं रखने अथवा स्टाफ सीटिंग के दिन भी छुट्टी ले कर घर बैठ जाते हैं। यद्यपि ऐसे उदाहरणों की कमी है फिर भी स्थिति में सुधार की अपेक्षा है।



ग्राम सभा स्तर पर पचायत मंत्री ग्राम सभा का कार्य देवता है और ग्राम सेवक और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान रहता है। यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। पचायत मंत्री अधिकतर गाँव सभाओं के रजिस्टर तथा कागजात धरन पर रखते हैं और प्रधान से अच्छे सम्बन्ध रख कर मनमाने रूप से हस्ताक्षर ले लेते हैं। ग्राम सेवक व्यक्तिगत सम्पर्क से ता प्रख्या करते हैं परन्तु गाँव पचायतों को बँठकों में भाग नहीं लेते। सहकारी सुपरवाइजर यद्यपि सहकारी समितियों में भाग लेता है लेकिन गाँव सभा को बँठका में वह भाग नहीं पता है और इस प्रकार लोचन की इस इकाई में सरकारी कर्मचारियों का सक्रिय योगदान नहीं मिल पाता। एक और तो ऐसी स्थिति है दूसरी और जो प्रधान चलते पुत्र हैं और ऊपरी राजनीति से बिलंब रहते हैं वे सरकारी आदेशों और नियमों व ग्रामस्तरीय कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं।

इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए यह नितात आवश्यक है कि जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों में सम्बन्ध सुन्दर स्वस्थ और सुगठित हो और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा तथा आदर पूर्ण हों जिससे समुदायिक कार्यक्रमों की पूर्ण प्रपेक्षित समय से हो सके और पचायतों राज सफल हो। एक दूसरे का छिन्नावेपण व अधिकारी भावना का प्रदर्शन और योग्य अनुमोदना कभी भी श्रद्धा व आदर की भावना पैदा नहीं कर सकती। यह ममरुता चाहिए कि जोना एक दूसरे के पूरक हैं और जिसके सम्मिलित प्रयत्न के बिना पचायती राज की गाड़ी नहीं चल सकती। श्री सुदे-कुमार व न एक बार कहा था कि हम पचायती राज में जन प्रतिनिधियों का स्थान घर में बिना पट्टे लियी और बूढ़ी सास के समान है और सरकारी कर्मचारियों का स्थान पट्टे लियी बहुत कम समान है। जब बहुत अपनी सास का विश्वास धनन कर लेती है तो कुछ ही दिना में सास पर को धाँसिया बहू का दे दनी है और घर में लाना का परिणाम अपने प्राण हो जाया है।



## पंचायत राज और कानून

### —श्री रामकरण जोशी

जनतन्त्र में पंचायतें नीचे की जगह काम करती हैं। नीचे की मजबूती के ऊपर-सारे भवन का-  
दारामदार होता है। राजस्थान में प्रशासन की लोकतन्त्रीय आधार पर सुदृढ़-बनाने-के लिए विवेकदीक्षा-उ-  
क्त मार्ग अपनाया। सत्ता का विकेंद्रित होना राज्य-के नीचे-कोने में प्रशासन का जागरूक होना माना-  
जाना चाहिए। यदि सत्ता प्रयोग के लिए किसी बिन्दु पर रुकी रह-गई-तो उसनी-ही बाधाएँ  
विवेकीकरण के मार्ग में उत्पन्न होती हैं। सत्ता के, विवेकीकरण-का मार्ग इसलिए महत्वपूर्ण माना गया  
या कि उसके द्वारा सभी क्षेत्र समान रूप से सामाजित होंगे। सत्ता-प्राप्ति की अनुभूति सम्बंधित लोगों  
का सभी प्रकार होनी चाहिए जिस तरह वषा का सभी कसबों पर एक-सा प्रभाव होता-है। सत्ता की  
सूखा बहारिया पानी आग की है। बिना सभी बहारियों का उचित मात्रा में पानी वह पान की व्यवस्था  
कमना है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि लोकतन्त्र के पोषण-के लिए सभी पंचायतों को सरकार के रूप  
में गति प्रदान करे।

राज्य सरकार जनतन्त्रीय प्रशासन में मुख्य कड़ी के रूप में काम करती है। राज्य सरकारों  
का संचालन और संचालन जनतन्त्र में पुनः हुए व्यक्तिगत द्वारा होता है। पंचायती राज में नीचे की इका-  
इका में पुनः हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होता-है। प्रत्येक इकाई अपने प्रकार के रूप में अपने  
प्रकारों का प्रयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। पंचायतें, पंचायत समितियाँ, विधान-परिषद् और राज्य  
सरकार चारों के काम-धोर प्रधिकार कानून द्वारा प्रत्येक शक्ति के आधार पर संचालित होते हैं। सबके  
प्रधिकारों को सामान्य निष्पात है। सीमाओं का प्रतिनिधित्व सभी जगह समान के लिए समर्थ है। नीचे की  
इकाई का ऊपर-का मूल्य यदि फाट-पटा करने की चेष्टा करे तो पंचायत धांदलीन गुच्छित हो  
जाता है। नीचे की इकाई यदि मनमाने करे तो भ्रान्ति पैदा हो जाती है। ऊपर-की इकाई मान  
है सत्ता का सहायक पूर्वक सही मार्ग देना दे तो पंचायत राज का सफलता मिल जाती है।

उक्त कसौटी पर यदि राजस्थान के वर्तमान पचायत आंदोलन को देखे तो पता चलता है कि उक्त इकाइयाँ वांछित ताल मेल नहीं बठा हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मुख्य तो गुट और दला का होता है। जनतंत्र में चुनाव आवश्यक होने हैं। हालांकि चुनावों में बहुता उत्पन्न होने का भ्रम फैला रहता है। चुनावों की लड़ाई और हार जीत यदि खेल के मदान में होने वाली लड़ाई और हार जीत के समान समझ ली जावे तो यह बहुता बढ़न नहीं पाती है। किन्तु ऐसा नहीं हो पाता है और चुनाव गहरे भाव करने चले जाते हैं। जिनसे सम्बंधित क्षेत्र कई दिना तक पीड़ित रहते हैं। राज्य सरकार में बड़े लोग उक्त हार जीत में पक्ष विपक्ष ग्रहण करके काम करने लगते हैं तो और भी बुराईया पदा हो जाते हैं और जब नीचे की इकाइयों को सुचारु रूप से संचालित होने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहितियों का दुरुपयोग होने लगता है तो समूचा आंदोलन झुग हो उठता है। राजस्थान में पचायती राज की स्थापना सन् १९५३ में हुई। उसके ठीक एक युग बाद सरकार को पचायती कानून में ऐसा संशोधन करने चुन लिये प्रतिनिधियों को निलम्बित करने के अधिकार प्रदान करने की जरूरत महसूस हुई। उक्त संशोधन के पक्ष विपक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं किन्तु हमने व्यवहार से पक्षपात की गंध आती हो ता इस पर अवश्य पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

संशोधन के पक्ष में जो दलील दी जाती है कि सरपंच और प्रधानों के खिलाफ ऐसी गिकायतें हैं कि जिनमें उन्होंने प्रदत्त शक्तियाँ का प्रतिक्रमण करके ऐसे काम कर डाले हैं कि जिनमें बाधरण हीनता भी शामिल हो तो जांच के दौरान उनको निलम्बित कर देना जनतंत्र की साथ के लिए जरूरी है। बात तो ठीक है। किन्तु इसका निष्पत्ति कौन हो कि वे शिकायतें सही या गलत? अगर गलत आरोप के आधार पर एक भी सरपंच या प्रधान निलम्बित कर दिया जावे तो धमका जिम्मेदार कौन और निर्दोष व्यक्ति को निलम्बित करने में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला "यक्ति प्रतिक्रमण का दोषी होने के कारण कौनसी सजा का हकदार है? क्या उस प्रतिक्रमण के लिए उसको भी निलम्बित करने की कोई धारा और प्रावधान है? किसी भी व्यक्ति को निलम्बित किये जाने के पहिले उस पर लगाये गये आरोपों की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है और उसके लिए उक्त जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जो प्रशासन के मातहत काम न करता हो, बल्कि "याय-व्यवस्था का भग्न हो।

राजस्थान के पचायत आंदोलन में जो वर्तमान संकट उपस्थित हो गया है उसके पीछे यही प्राधान्य और भय है। पक्ष सरपंच और प्रधानों के सिर पर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है— न जान कब किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोप भाजन हो जावे स निलम्बित हो जाना पड़े—साथ ही हमें जो इस कारण से निलम्बित किये गये व्यक्ति हैं उनके मामलों के फसलों की अवधि निर्धारित हानी चाहिए ताकि फसल में प्रभावित व्यक्ति याय के लिए कानूनी आगलनों में जा सके। किसी भी सरपंच या प्रधान को केवल निलम्बित करने छोड़ दिया जावे और वष दो वष पुरे हो जावे बल्कि चुनाव की पूरी अवधि खत्म हो जावे तो प्रशासन के ऊपर यह इल्जाम आगद होगा है कि उसके पास इस व्यक्ति का निलम्बित करने का कोई औचित्य तो था नहीं किन्तु चुन जान के बाद इसके प्रभाव को निरस्त करने की दृष्टि से इस बहाने को अपनाया गया है। कानून का संशोधन किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने के बहाने नहीं बनाना चाहिए। यह सावधानी राज्य सरकार को अवश्य बरतनी चाहिए।

इस संदर्भ में इतना और कहना जरूरी है कि राजस्थान में भी देश के साथ साथ जनतंत्र विकसित हो रहा है। उसके माग में सरकार या निहित स्वायत्त शासक टालन की चेष्टा करेंगे तो वे स्वयं ही परास्त हो जायेंगे। जन मत की रक्षा में जन आंदोलन होने के पहिले राजस्थान में लोकतंत्रीय परम्पराओं को बल मिलेगा।



सह-७

## पंचायती राज में निधोजित कार्यक्रम

१ गांव की योजना		१
२ ग्रामयोजना का आषाढ आर्थिक और सामाजिक सर्पेक्षण हो	श्री गोविन्दरसाद	२-१४
३ प बाघनें ग्राम योजनायें कैसे बनाए	श्री विष्णुन राय	१५-१६
४ ग्राम उद्योगीकरण कार्यक्रम निर्धारण	श्री जयदत्त नारायण	२०-२३
५ ग्राम औद्योगीकरण पर एक दृष्टि	श्री बाबूदिस	२४-२७
६ देशी और बेरोजगारी से निहृण		२८

— —





## गांव की योजना



गांव की योजना अब गांव वालों की ही बनानी पड़ेगी, उन्हें ही यह सोचना विचारना और मानना पड़ेगा कि उनके गांव की क्या आवश्यकताएं हैं ? क्या ऐसे काम हैं जो गांव के लिए किए जाने चाहिए ? क्या ऐसे काम हैं जो सघूर हैं और क्या गए सिरे से शुरू करने हैं ?

गांव की हड़दों और आवश्यकताओं को गांव वाले ही ज्यादा समझते हैं । परमांत उनकी अपनी सत्ता है वे पचायत से हैं, पचायत उनसे पूछे, ग्राम सभाएं की जाए । बहा सुनी चर्चाएं हों और फिर गांव की योजना बने वह योजना गांव की होगी और गांव ही मिलकर उसे पूरा करेगा ।

गांव की योजना बनाने के पहले गांव के हालात की जांच (सर्वेक्षण) करनी पड़ेगी । पढ़ाई के बारे में, सेतो के बारे में, खाद के बारे में, बजदारी के बारे में, उद्योग पंथों के बारे में, मानी हालात के बारे में गांव के घर घर की जांच करनी पड़ेगी सब सहो तसवीर सामने आयेगी । तब योजना बननी । वह योजना गांव की योजना होगा, उसने गांव का समस्याओं का हल निकलेगा । उसने गांव की सभी पूरी होगी । गांव वाल ही अपनी योजना बनायें । वे हा उस पूरा करें, और वे ही अपनी सुरुप्रम, मेहनत और कोशिशों से गांव को पूरी तरह सुखी और स्वावलम्बी बनायें ।

# योजना का आधार गांवों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हो

—श्री गोविन्दप्रसाद

भारत की सर्वोत्तम उन्नति भारत के गांवों के समुचित विकास में निहित है। भारत की जनता गांवों में निवास करती है। इसलिये ऐसी योजना बनाने का आवश्यकता है जिसका आधार ग्राम सुधार हो, कि तु योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामों की समस्याओं का अध्ययन निकटता से किया जाये। इन समस्याओं का अध्ययन निकटता से गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षणों से हमारा अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा ग्रामों की विभिन्न बारीकी से बारीक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के कारणों एवं प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सके तथा उन समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ निर्दिष्ट निष्कर्ष निकाले जा सकें।

इससे पूर्व कि ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला जाए हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में ग्रामों तथा उनके विकास का क्या महत्व है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व ही यह पहचान लिया था कि भारतवर्ष ग्रामों में बसता है न कि साम्राज्यवादियों द्वारा बनाये गये 'गहरो बक्खो' में उड़ाने भरे हुए हड्डि के समान। वे ग्रामीण विचारधारा स्पष्ट व्यक्त की है कि शहर तो पराधीनता की देन है। ग्रामों के महत्व को स्पष्ट करते हुये गांधीजी ने लिखा है कि—

If the villages perish India will perish too It will be no more India Her own mission in the world will get lost

भारत गावा का एक सघन है। यहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामीणों में निवास करती है, इसलिए यदि भारत का उन्नति के पथ पर प्रगतिमान होना है तो उसका विकास का कार्य गाँवों से ही प्रारम्भ करना चाहिये। ग्रामीणों का विकास ही भारत की उन्नति सन्निहित है। जैसा कि मोल्डस्मिथ ने कहा है कि गांव राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है इसलिए उनका विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बिना गांवों के विकास का भारत का विकास होना कठिन हो नहीं पायेगा अतः आवश्यक है। गाँवों की अनेक समस्याएँ हैं। पिछले दो-तीन दशकों में पश्चिम भारत के गाँवों की प्रगतिसमर्थता ग्राम सुप्त हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में इन समस्याओं को दूर करने के लिये देश के अनेक धनप्राप्तियों का प्रयास किया। इनके अभाव में ग्रामीणों की महत्वपूर्ण इस बात से भी प्रकट होती है कि भारतीय सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीणों के विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ग्रामीणों का सर्वोत्तम विकास करने के लिए हमारी सरकार ने सामुदायिक विकास योजना सन् १९५२ में प्रारम्भ की। इतना सब होने पर भी ग्रामीणों की अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ रह गई हैं जिनका कि समाधान नहीं हो सका है।

इस वर्तमान आर्थिक नियोजन के युग में ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। अतः विभिन्न क्षेत्रों की भौतिक एवं भौतिक विशेषताओं के विषय में जानकारी न होना के कारण सम्पूर्ण देश के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाना अति कठिन है। यदि यह योजना बना भी ली जाती है तो वह तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि प्रत्येक जिले, क्षेत्र एवं गाँव की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान अध्ययन न कर लिया जाए। आर्थिक नियोजन कमोन्तम न अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के ऊपर ही निर्धारित स्पष्ट रूप से निर्धारित व्यवस्था में क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्वपूर्णता का अभाव हो रहा है—

'That the needs and priorities of different regions as well as their potential for short term and long term development should be taken into account in drawing up and continually reviewing their developmental programmes'

इस गाँवों की समस्याओं में ग्रामीण क्षेत्रों में जांच के कार्य के लिए स्वतंत्र जांच संस्थाओं का पुराना जोर देना है। इसी प्रकार में बाउले राइटिंग कमेटी ने भी निर्देशन विधि के माध्यम से गाँवों के सर्वोत्तम द्वारा ग्रामीणों के विकास के लिए सहायता की है।

भारत की उनकी प्रारम्भिक प्रगति की कृषि उद्योगों का अभाव उत्पादकता का निम्नस्तर, निम्न आयें, (lower incomes) निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या और वह भी उच्च गति से बढ़ती हुई प्रचुरता जनसंख्या विशेषी ध्यानपूर्वक द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था (Foreign trade oriented economy) तथा बहुत बड़े मकानों में अतिशय के कारण घटती विकसित देशों या पिछड़े हुए देशों की समस्या में मिला जाता है। इन सब बातों के सिवाय हम अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण करना है। अतिशय बंधन की समाप्त करना है, उद्योगों का स्थापना करना है तथा उनकी विस्तार करना है। अर्थव्यवस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करना है, सिविल के वापनों का विकास करना है, कृषि के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा फिर सारे जनता के जीवनस्तर को उन्नत करना है। इसी की समस्त



समस्याओं का निवारण करना है तथा नवीन सड़कों एवं रेल्वे लाइनों का निर्माण करना है। यह कार्य भारत के प्रत्येक जिले, क्षेत्र तथा गाँव में करना है और यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक मयशील है तथा इसमें काफी मानवीय क्षिति एवं ताकत की आवश्यकता है। ये कार्य बिना सोच-विचार तथा गहन अध्ययन के करना असम्भव है और यदि कर भी दिया जाए तो उनके असफल होने का भय रहता है। असफल होने पर काफी ताना-बाना में मुग़ा एवं मानवीय क्षिति तथा प्रयत्नों की हानि होता है। सिखन के बजाय या बर्णन करने के बजाय जिसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इन सबके लिए उन दशाओं, स्थितियों का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है और यहाँ तक है कि प्रत्येक गाँव में भी भिन्न-२ पार्से जाते हैं। यहाँ दशायें भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक होती हैं। आर्थिक दशाओं एवं आर्थिक विकास की दर का लगातार अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों तथा कम विकसित क्षेत्रों में करना अति आवश्यक है। एवं अध्ययन के प्रोग्राम द्वारा समुचित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development) प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक आर्थिक सामोए सर्वेक्षण किसी गाँव की वास्तविक भौगोलिक स्थिति एवं उसका आर्थिक वातावरण का पूरा पता लगा सकता है। इसके द्वारा गरीबों की भाँव, रहन-सहन के तरीके तथा पूँजीपतियों द्वारा उनका शोषण का पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के सर्वेक्षण वहाँ की व्यवस्था सम्बन्धी एवं रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ प्रदान करते हैं। कृषि कुटीर उद्योग पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सफाई, शिक्षा, कला एवं संस्कृति रहन-सहन, जीवनस्तर आदि सामाजिक एवं आर्थिक सुझाव सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त जब हम पचायती राज में विन-डीकृत अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, जिसका कि मुख्य उद्देश्य गाँवों को प्रशासनिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की दृष्टि से स्वायत्तता बनाना है, तो इन क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए कहा जा सकता है कि गाँवों में कृषि का विकास करके उत्पादन वृद्धि की जाए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाए ग्रामाणों की भाँव में वृद्धि की जाए, उनके जीवनस्तर में वृद्धि की जाए। इन सबके लिए योजना बनाने में पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि वे कौन-कौन से कारण हैं जो इनके माग में बाधक हैं। उन कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद में यह भी मालूम किया जाना है कि ये कारण किस प्रकार बाधक हैं। इन सब बातों का उत्तर सही रूप में हमें गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षणों से मिलता है।

उपयुक्त तथ्यांश के अतिरिक्त हमारी वर्तमान प्रजातांत्रिक सरकार के लिए जिसकी महत्वपूर्ण अभिलाषा इस युग में समाज का समाजवादी ढंग (Socialist Pattern of Society) का ढाँचा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण सरकार की इस महत्वपूर्ण अभिलाषा को परिपूर्ण करने में अति सहायक होंगे। इन सर्वेक्षणों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र एवं गाँव की समस्त आर्थिक एवं सामाजिक तथा भौगोलिक आदि दशाओं के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

किसी क्षेत्र के विकास एवं पुनर्गठन के लिए आर्थिक नियोजन को लागू करने तथा उसकी

सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका आधार कुछ तथ्य एवं भावों के होने चाहिये। इसलिये यह स्वीकार किया जा सकता है कि किसी भी नियोजन के परिवर्तन के लिए ग्रामीण जीवन के सम्बन्धित प्राथिक एवं सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी क्षेत्र के लिए प्राथिक नियोजन वास्तविक रूप में उस क्षेत्र के विभिन्न लोगों व सभी अनुमान पर निर्भर रहता है। प्राकृतिक, मानवाय, कृषि व उद्योगीय एवं अन्य स्रोतों को ध्यान में रखते हुये कोई भी व्यक्ति किसी भी विकास की योजनाओं बना सकता है तथा उनका परिणाम देख सकता है। इसको हम दृष्टि से भी दखा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सरकार ग्रामीणों के जीवन-स्तर को उठाने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं से वास्तविक लाभ क्या हो रहा है तथा ग्रामों की प्राथिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों एवं लाभों को देखने के लिए गांवों का सर्वेक्षण आवश्यक है। इन सर्वेक्षणों के द्वारा उन कमियां को ढूँढ निकाला जा सकता है जो योजना बनाते समय रह गई थी। इन कमियों को पूरा करने के लिए ग्रामीण योजनाओं में विचार किया जा सकता है तथा उचित स्थान प्रदान किया जा सकता है।

ग्राम सुना जाता है कि सूत की योजनाओं को बड़े सोव विचार के साथ बनाया गया था तथा उनका निर्माण सकुशल व्यक्तियों द्वारा किया गया था फिर भी वे अपने लक्ष्य पूरा करने में असफल रहे। इसका क्या कारण है? शायद उनसे साथ क्या गड़बड़ थी जिसके कारण वे असफल हो गई। स्पष्ट है कि उन योजनाओं का निर्माण ऊपर की स्तरों के आधार पर किया गया था तथा नीचे के स्तरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। यह स्थिति एक उल्टे पिरामिड की तरह हो गई थी जिसका कि शीर्ष ऊपर को न होकर नीचे की ओर होता है। इन प्रकार के पिरामिड द्वारा भी धन के धरापायी हो सकता है। इनके विपरीत यदि योजनाओं का आधार ग्रामीण सर्वेक्षण बना लिया जाए तो हमारी योजनाओं के सफल होने का प्रश्न ही पड़ा नहीं होता क्योंकि नीचे की नींव जब मजबूत होगी तो ऊपर का हिस्सा भी स्वयं ही मजबूत होगा।

यह भी सम्भव हो सकता है कि जब ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में न रखते हुये योजनाओं का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें लागू किया जाता है तो ग्रामीण लोग यह सोच कर भी इनसे हमें क्या फायदा है, योजनाओं के सफल निष्पादन में सहायक नहीं होते हैं। मोर इस प्रकार से जन सहयोग के कारण योजना गठन नहीं होती है। धन स्वराज्य की नींव पक्की करने, लोकतन्त्र का मजबूत करने तथा विविधित धर्म व्यवस्था की सफलता के लिए ग्रामीण प्राथिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण प्राथमिक आवश्यकता होना चाहिए।

पंचायती राज में विविधित धर्मव्यवस्था की योजना करते समय अपने नागरिक स्वराज्य, नामक विषय में सर्वोच्च नेता श्री जयप्रकाशनारायण ने भी विविधित धर्मव्यवस्था की सफलता के लिए गांवों के सर्वेक्षणों के विषय में मुझसे कहा है। लेकिन उन्होंने यह बात मुझ से रूप में ही की थी। इसका स्पष्टीकरण के सर्वेक्षण का ढांचा, स्वरूप एवं आधार क्या होना तथा येना जा ग्राम सर्वेक्षण का स्वरूप, ऊँचा एवं विधि के सम्बन्ध में सोचा है, वह उनके सर्वेक्षण के द्वारा मैं मिनता कुतूहल हो है या भिन्न है तो निम्न प्रकार :

देग की योजनाओं का आधार ग्राम का प्राथमिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण होना चाहिये, जिसकी कल्पना मैंने अपने इस लेख में की है उसका स्वरूप 'डाचा तथा आधार एवं विधि निम्न लिखित प्रकार होगी—

१—प्राथमिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के लिए विशिष्ट पद्धति की सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिये। इस पद्धति व अनुसार सर्वेक्षित क्षेत्र का निदिष्ट कर दिया जाता है और सर्वेक्षणों व उद्देश्यों की पूरा करने के लिए इस पद्धति व अंतर्गत अनेक वनानिक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है जैसे—निर्देशन, सगठन अनुसूची, साक्षात्कार, एवं व्यक्तिगत अध्ययन आदि। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि सामाजिक पद्धति का प्रयोग मौखिक विज्ञान व अध्ययन में किया जाता है इसलिए इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में उपयुक्त नहीं है।

२—यू कि हमारे यहाँ ग्राम सभु होते हैं इसलिए निर्देशन विधि क बजाए सगणना विधि का ही प्रयोग लाभदायक रहता है। यहाँ सगणना विधि एवं निर्देशन विधि का स्पष्टीकरण आवश्यक है। सगणना विधि से तात्पर्य उक्त विधि से है जिस में प्रत्येक इकाई का अध्ययन अलग एवं विस्तृत रूप से किया जाता है। यह विधि अत्यंत साधक एवं सही है। यह विधि सरल भी है। लकिन कुछ लाग इस विधि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार धारति उठा सकते हैं—(१) इसमें समय अधिक लगता है तथा श्रम भी अधिक लगता है क्योंकि इस विधि व अनुसार सर्वेक्षणकर्ता की प्रति व्यक्ति व घर जाकर सूचना प्राप्त करनी पड़ता है। (२) यह विधि व्ययशील है क्योंकि सगणना का कार्य काफी धरस तक चलता है। (३) यह बड़े २ गाँवों के लिए अनुविभाजनक है।

ये आपत्तियाँ नाममान की हैं क्योंकि यह पद्धति अत्यंत सरल एवं शुद्ध है। तथा इसके द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाती है।

इसके विपरीत एक निर्देशन विधि में अभिप्राय उस विधि से है जिसके अंतर्गत प्रतिनिधि इकाईयाँ का अध्ययन करते हैं। इस विधि के अनुसार एक प्रतिनिधि इकाई प्रति दस या बीस इकाईयाँ के बराबर चुन ली जाती है। ताहरण के लिए मान लीजिए एक गाँव में १००० परिवार हैं उनका सर्वेक्षण करना है। यदि हम प्रति १० इकाईयों के बराबर १ इकाई का अध्ययन करते हैं तो हमें केवल १०० इकाईयों का अध्ययन ही करना पड़ेगा तथा परिणाम व अनुसंधान द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है जबकि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो क्योंकि इस विस्तृत क्षेत्र में प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी है। यह विधिपूर्ण विस्तृत है नहीं। इस प्रकार से दाना की तुलना करने पर सगणना प्रणाली खरी उतरती है।

३—अनुसूची विषय सम्बन्धी तथ्य करने के लिए बनाया जाना चाहिये। इसमें सगणना व सम्बन्ध में समस्त प्रश्नों का समावेश होना चाहिये।

४—साक्षात्कार के लिए प्रश्न सूची में किये गये प्रश्नों को परिवार के मुखिया से पूछ करके उत्तर लिखते जाना चाहिये तथा प्रश्न पूछने में जल्दी नहीं करनी चाहिये जिससे गलती रहने की सम्भावना न रहे।

५—प्रश्न सूची में समस्त तथ्य एकत्र करने के बाद उनका टेबुलेशन करना चाहिये जिससे

सम्बन्धित तथ्यों का सम्बन्धित समस्याओं के अनुसार वर्गीकरण किया जा सके।

६ तथ्यों के एकत्रित हो जाने पर समस्त देश की योजना बनाने के लिए विभिन्न गावों की सामुहिक समस्याओं का चयन एवं तरह करके एवं सामुहिक योजना का निर्माण करना चाहिए जो सामुहिक समस्याओं के लिए समस्त गावों का लाभप्रद हो सके। इसका पश्चात् भिन्न २ समस्याओं पर भिन्न २ प्रकार से लघु ग्राम योजनाएँ बनाई जानी चाहिये। इसमें प्रत्येक गाव की विशेष समस्या का समाधान संभव होगा।

समस्याओं सम्बन्धी तथ्य एकत्रित करने के लिए प्रश्न सूची का मैं निम्न स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ —

### — प्रश्न सूची —

#### १—सामान्य —

- (घ) परिवार के मुखिया का नाम
- (ब) लिंग
- (स) आयु
- (द) जाति
- (ई) धर्म
- (उ) मकान न०
- (ऊ) मौहल्ला
- (ए) धन्धा

१—मुख्य धन्धा

२—सहायक धन्धा

३—अन्य धन्धा

#### २—पारिवारिक स्थिति —

(अ) पारिवारिक सदस्य संख्या

- |                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| (ब) पुरुष संख्या | (१) बालिन | (२) नाबालिन |
| (स) स्त्री       | (१) बालिन | (२) नाबालिन |

(द) सदस्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएँ —

सदस्य का नाम	लिंग	आयु	विवाहित अविवाहित	शिक्षित अशिक्षित	कमाने वालों की संख्या	कमाने वाले एवं आश्रित	कुल आश्रित
१	२	३	४	५	६	७	८
१—							
२—							
३—							
४—							
५—							
योग							

३—निवास सम्बन्धी सूचनाएँ

क्रम	संख्या	मकान का प्रकार	संख्या	क्षेत्र	फल	दोवार	छत	कमरे	दरवाजा	रोशन	पान	प्रयोग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१—	प्रकाश											
२—	आधा पक्का											
३—	कच्चा											
४—	झोपड़ी											
५—	बाड़ा											
६—	अन्य											
	(१)											
	(२)											

४—जन्म मरणसम्बन्ध —

(क) परिवार में कुल बितने बच्चों का जन्म हुआ

(ख) परिवार में वर्तमान में कितने बच्चे हैं

(ग) परिवार में मृतक बच्चों की संख्या

(घ) मृत्यु के समय आयु

(ड) यदि मृत्यु का कारण बीमारी है तो इलाज सम्बन्धी बातें —

- (अ) किससे इलाज करवाया डाक्टर / सघाने ?
- (ब) किम जगह इलाज करवाया ?
- (स) क्या बीमारी बतलाई गई ?
- (द) अन्य बातें ?

५—पुनर्निवास —

- (१) गाव म कब आये ?
- (२) कहा से आये ?
- (३) क्या परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर रहना है ? यदि हा तो कहा और क्यों ?
- (४) क्या करता है ?
- (५) कितना कमाता है ?
- (६) विवाहित है या अविवाहित ?
- (७) घर के लिए क्या मेजता है ?

(६) पारिवारिक ऋण सम्बन्धी स्थिति

ऋण का सम्बन्ध	सूचक	समय	व्याज दर	गिरवी का प्रकार	जमानत	ऋण लेने का उद्देश्य
१	२	३	४	५	६	७
१—बैंक						
२—सहकारी समिति						
३—साहूकार						
४—व्यापारी						
एक महाजन						
५—मित्र एवं सम्बन्धी						
६—अन्य योग—						

## ८—परिवार की कुल वार्षिक आय

### (क) भूमि पर कृषि से आय

कसले वास्तविक जोती गई	उपज मनो	बाजार	उपज किस काम में	अप्य भातें
भूमि का क्षेत्रफल	मे	मूल्य	साई जाती है	
१	२	३	४	५

बाजारा

ज्वार

मोंठ

मू ग

म्वार

बीला/बीली

उडद

मू गफली

चना

जौ

गेहू

सरसो

भरहर

मक्का

प्याज

पटसन

तिल

कपास

बगीची से आय

अप्य

योग—

कृषि सम्बन्धी व्यय

(१) खाद

- (२) जुताई
  - (३) जुवाई
  - (४) नराई
  - (५) बीज
  - (६) सिंचाई
  - (७) कृषि क्रियाये
  - (८) कृषि औजार
  - (९) भूमि का लगान
  - (१०) अग्न्य
- योग

कुल कृषि आय  
 कुल कृषि व्यय  
 शुद्ध आय कृषि से  
 (ख) कृषि भ्रम से आय  
 (ग) कृषि के अनिश्चित भ्रम्य भ्रम से आय  
 (घ) सरकारो नौकरो से आय  
 (ङ) गैर सरकारा नौकरो से आय  
 (च) व्यवसाय या व्यापार से आय  
 (छ) व्याज की आय  
 (ज) विविध  
 योग  
 कुल योग

८—कुल भूमि

- (१) खेती योग्य भूमि
- (२) मजद भूमि
- (३) भूमि जिसमें पिछले वर्ष खेती की गई हो लेकिन इस वर्ष नहीं की गई है
- (४) भूमि जिस पर इस वर्ष खेती की गई है
- (५) भूमि जिस पर पिछले वर्ष खेती नहीं की गई वरन् इस वर्ष की गई



- (६) स्वयं की भूमि या कच्चे में है ?  
 (७) क्या वास्तुकार स्वयं वास्तु करता है ?  
 (८) भूमि पर फसलें—  
 (अ) रबी—  
 (ब) खरीफ—  
 (स) जायद—  
 (६) अन्य बातें

६—परिवार का वार्षिक उपभोग व्यय

(क) भोज्य पदार्थ

(अ) अनाज

मात्रा

मूल्य

१

२

३

१—

२—

३—

४—

(ब) दालें

(स) शाक तरकारी

(द) चीनी

(ई) गुड़

(उ) मांस

(ऊ) अण्डे

(ए) दूध

(ऐ) फल

(ओ) घी इत्यादि देशी-हालहा

(घो) मसाले

घ ) अन्य

कुल भोज्य पदार्थों पर व्यय

(ख) कपड़े

गज—गिरह

मूल्य— सूती/ऊनी/ब अन्य

पुरुष

स्त्री

बच्चे

देत का सामान

ग्रन्थ

योग

(ग) जूती एवं जूता                      संस्था जोड़ी                      किस्म                      मूल्य

पुरुष

स्त्री

बच्चे

योग

(घ) ई धन एवं मिट्टी का तेल

लकड़ी

उपले

मिट्टी का तेल

मात्रित

अथ

योग

(ङ) मकान किराया एवं अथ मकान सम्बन्धी व्यय

१ मकान किराया

२ नया मकान बनाने पर

३ मरम्मत करवाने पर

योग

(च) स्वास्थ्य एवं शिक्षा

(छ) नशीली वस्तुयें

१—दाराव देशी / विदेशी

२—भग

३—तम्बाकू

४—भय

(ज) त्योहार एवं संस्कार

(झ) सेवार्यें

(ञ) विविध—

मात्रा

मुकदमा

अथ

कुल योग—

१०) — यदि परिवार में बचत होती है तो उसका किम प्रकार प्रयोग किया जाता है—

- (अ) पैतृक ऋण का भुगतान करने में—
- (ब) स्वयं द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान करने में—
- (स) ऋण देने में—
- (द) नई सम्पत्ति का क्रय करने में—
- (इ) अथ न्याज आदि

१— यदि आय से व्यय अधिक रहना है तो परिवार का बजट पूरा कैसे किया जाता है—

- (क) ऋण लेकर
- (ख) पूँजी सम्पत्ति या स्थायी सम्पत्ति का विक्रय करके
- भूमि मकान पशु गहने अथ
- (ग) अथ साधन

१२— कुल पशु

- (अ) दूध देने वाले
- (१) गायें दूध देने वाली गाय जो दूध नहीं देती बड़ड़े/बछड़िया
- गायों से प्रतिदिन दूध की मात्रा एवं उसका उपयोग
- (अ) मात्रा (ब) उपयोग
- (२) भैंसें — दूध देने वाली भैंसें जो दूध नहीं देती भावारा पाड़े/पाड़िया
- भैंसें के प्रतिदिन की दूध की मात्रा उपयोग
- (१) बकरिया बकरिया दूध देने वाली
- बकरिया जो दूध नहीं देती बकरा/बकरी/बच्चे
- बकरियों से प्रतिदिन दूध की मात्रा उपयोग
- (ब) ऊँट प्रदान करने वाल मेढे मेमने
- (स) बीभा डोने वाले
- ऊँट ऊँटी गधे लकड़र
- (द) कृषि के प्रयोग में आने वाले
- बैल
- भैंसे
- ऊँट
- (ई) अथ

१३— आय उपयोगी बातें

# पचायतों ग्राम योजनाओं कैसे बनायें

—श्री निम्णुदत्त शर्मा

हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि कोई गांव विकास की स्थापक योजना के बिना स्वावलम्बी एवं स्वायत्ती नहीं बन सकता। इसलिए हमें गांवों के बारे में ऐसी योजना के संवध में पहिले जात कर लेनी चाहिए। हमारे गांवों की योजना का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिससे गांवों में उपलब्ध सभी साधनों का अधिकारिण उपयोग हो सके और इस योजना को पूरुत सफल बनाने के लिए जहाँ तक सम्भव हो बाहरी सहायता प्राप्त कर सकें। ग्राम विकास की योजना तैयार करते समय तीन मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा—

(१) सर्वेक्षण (२) गांव की आवश्यकता, और (३) कार्य करने की योजना।

(१) सर्वेक्षण—

ग्राम की योजना तैयार करते समय यह जरूरी है कि उस गांव के सब साधनों का (स्वयत्त व सामान) पूरी तरह समझीना कर लिया जाय। गांव की स्थिति का ज्ञान जब तक पूर्ण रूप से न हो योजना की आधार बसा में कमजोरी रहने की आशंका है।

(२) गांव की आवश्यकता—

बिस्वी भी गांव की योजना बनाने से पहले वहाँ के निवासियों की प्रमुख आवश्यकताओं को जानना जरूरी है। यह कार्य गांव वालों से बातचीत और दृष्टताय करने पर ही संपादित किया जा सकता है।

गाव वानों की मूनमून झलरता को जान लेने के बाद, उनको गावबिहारी के आधार पर भागे पोछे किया जाने चाहिए उनको एक एक करके काम में लिया जा सके।

## (३) योजना कार्य की रूपरेखा—

यह पतित आवश्यक है कि गाव की योजना गाव वाले स्वयं तैयार करें। क्योंकि गाव के विकास की योजना किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने पर यह भय है कि गाव वानों की समस्त स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल न हो। इसके अतिरिक्त गाव वानों को यह भी विश्वास नही होगा कि वह उनकी अपनी योजना है और इसलिए उसे करने में वे अपनी निष्कम्पी नही लेंगे। अतः यह परमावश्यक है कि गाव वाले अपने गाव की योजना अपनी ग्राम पंचायत के जरिये तैयार करें, प्रसबता ग्राम स्तर के कार्यकर्ता से इसमें मन्त्रा लो जा सकता है। यह हा सकता है कि पंचायत को योजना तैयार करने में कुछ दिक्कत हो लेकिन ग्राम सेवा उनमें गावा के लिए उचित योजना बनाने में उत्साह जगा सकता है। इस काम में सही ढंग में मदद करने के लिए ग्रामसेवा को वना के टेक्निकल स्टाफ द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।

गावों की योजना में नीचे बताई गई बातों का समावेश किया जाना चाहिए —

- (१) प्रोग्राम को कार्यान्वित करने और प्रतापन बनाने का याचना,
- (२) कृषि को उत्तम बनाने की योजना,
- (३) पशु-पालन के विकास की योजना,
- (४) स्वास्थ्य-सफाई और चिकित्सा की सुविधा की योजना,
- (५) शिक्षा की योजना
- (६) सहकारिता और देहातों में कर्ज देने की व्यवस्था के विकास की योजना
- (७) ग्रामीणों के विकास की योजना,
- (८) गाव के मकानों में सुधार की योजना,
- (९) मानवशक्ति के साधनों के विकास की योजना, तथा
- (१०) गावों की संस्कृति के विकास की योजना।

## (१) गाव का प्रशासन—

यह एक माना हुई बात है कि गाव के सब लोग विकास के सभी कार्यों में सीधे अपना पार्ट प्रदा नही कर सकते परन्तु उनकी किसी एक लोकतांत्रिक संस्था के माध्यम से विकास के कार्यों में लाया जा सकता है। गाँव में पंचायत से अधिक मन्त्रो और कोई लोकतांत्रिक संस्था नही हा सकती और ग्राम पंचायत कोई नई संस्था नही। ग्रामिया से इस देश में गाव वान अपनी पंचायत को प्रारंभ की दृष्टि से देखते आये हैं। ग्राम-पंचायत न जन-पंचायत के उल्लेख प्राप्त हैं ही। यदि हमें अपने देश में लोकतांत्रिक को

व्यापक और सुदृढ़ बनाना है और देश के दूर दूर के क्षेत्र के माध्याम्य ग्रामीण के लिए भी उसे मूर्तरूप देना है तो इस समस्या का हमें ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों की कार्यावधि करने का वेद बनना पड़ेगा।

गांव के विकास के सब कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी पचायत को सौंपा जानी चाहिए क्योंकि किसी बाहरी एजेंसी की प्रेरणा पचायत उन्हें प्रसन्न दिनचरसी में कार्योन्मुख करेगी। और पचायतों को भी चाहिये कि वे ग्रामीणों की अलाई व बखूनी के लिये सब विभाग का क्रम को स्वयं हाथ में लें।

## (२) कृषि—

गांवों के विकासियों का मुख्य पारा कृषि है और मनुष्य चापीण समाज का हृत् तक लेनी बाड़ी पर ही प्रभावित होता है परन्तु देश में अधिकांश गांवों में अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों का उत्पन्न नहीं होता और हमें उनकी कमी को दूर करने के लिये बाहर से सहायता मंगाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक गांव का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे अपनी जरूरत के अनुसार साधन तो पैदा करें ही, साथ ही कमी के लिए प्रतिस्पर्धन सहायता पैदा करने के प्रयत्न करें।

## (३) पशु पालन—

ग्रामीण समय व्यवस्था में पशुपालन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घात स्वस्थ और मजबूत मवेशियों को पैदा करने और पालने की आवश्यकता है साथ ही बकरियों और मुँगे मुनिया का भी उचित विकास दिया जाना चाहिये। हमारा लक्ष्य दूध का उत्पादन बढ़ाने की ओर रहना चाहिए ताकि गांव के प्रत्येक परिवार के हर व्यक्ति को प्रति दिन घाघ मेर दूध पीने के लिये मिल सके इससे सहायता उत्पन्न किस्म के बैलों की साहाय्य बढ़ाये जानी चाहिये और उन्हें अच्छी खुराक दी जानी चाहिये। पशु चिकित्सा की व्यवस्था द्वारा मवेशियों का धून की बीमारियाँ न बचाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। मवेशियों के लिए चरागाहों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

## (४) स्वास्थ्य एवं सफाई—

गांवों में स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए योजना तैयार करते वक इन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है—प्रायः गांवों के सभी वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए पीने का पानी के कुपा की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्वस्थ मादलों की व्यवस्था कर गांवों को साफ सुपरा रखने की योजना की जानी चाहिए।

गांवों में बीमारों की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए छोटे छोटे गांवों के सत्रों के लिए एक औपचारिक या डिपो-वरी भी कायम की जानी चाहिये। जनसमाजों की देखभाल के लिए गांवों की व्यवस्था भी आवश्यक है। जेबक और हैजे के टीने भी सभी की मजदूर जा सों, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए।

## (५) शिक्षा—

हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली देश की सब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। शिक्षा का महत्व इस बात से नहीं कि कितने विषय में शिक्षा प्राप्त की जाती है बल्कि इस बात से माफ़ा जाना चाहिए कि जिन विषयों में शिक्षा प्राप्त की गई है उनमें से दैनिक जीवन के कार्यों में उसका किस हद तक इस्तमाल किया जाता है।

## (६) सहकारी—

गांव में सहकारी संस्थाओं का बचपन कृषि एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने बल्कि गांव बातों का सामूहिक प्रयत्न को संगठित करने के लिए था अब संस्थाएं होती हैं। घट गांवों के विकास की योजना में सहकारी संस्थाओं का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। गांव में सहकारी समितियों की उचित ढंग से संगठित करने से, गांव के विकास के बहुत से कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक गांव में एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना की जाय और प्रत्येक परिवार को उसका सदस्य बनाया जाय। यह समिति गांवों की प्रतिरिक्त उपज की बिक्री और लोग की जरूरत की चीजों के बटवारे का काम में सक्षम हो। खाद, बीज उचित कृषि औजारों की सप्लाई एवं बटवारे का काम भी इन समितियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामोद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का स्टॉक भी यह समिति अपने पास रख सकती है। गांव में उपयोग के लिए सहकारी समिति अच्छी नस्ल का साढ़ भी रख सकती है।

## (७) ग्रामोद्योग—

हमारे देश में बेकारी और कम रोजगार की समस्या इसलिए भी बनी हुई है कि हमारे ग्रामोद्योगों की उपेक्षा होती रही है। हालांकि हमारा देश कृषि प्रधान है। फिर भी पहले से ही हम लोग ग्रामोद्योगों को उचित स्थान देते आये हैं। और यही कारण है कि ग्रामोद्योग द्वारा तयार की गयी कलात्मक वस्तुएं हम देखने को मिलती हैं।

## (८) मकान—

गांवों में मकानों का सुगम दो तरीकों से हो सकता है—एक तो मौजूदा मकानों में सुधार करके और दूसरे नये मकानों का निर्माण करके।

गांवों के जो लोग पुराने मकानों का सुधार करना चाहते हो या नये मकानों का निर्माण करना चाहते हों वे एक सहकारी समिति बना सकते हैं। नये मकानों के निर्माण के लिए सहकारी समिति द्वारा ऋण की व्यवस्था भी की जा सकती है।

## (९) यातायात—

जब तक गांव का बाहर के इलाकों से सड़क यातायात का संबंध नहीं होता तब गांव अपना

भरपूर विकास नहीं कर सकता। इसके लिये आवश्यक है कि गांव की सड़क या विकास सड़क के क्षेत्र में जाड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाय। ये सड़कें बाह्य महिनों उपयोग में लाई जा सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

### (१०) सांस्कृतिक विकास—

गांव के विकास कार्यक्रम में सांस्कृतिक पक्ष को अवसर नजरान्दाज कर दिया जाता है। लेकिन ग्राम विकास के जरिये जो सामानिर्भरता होगी वह प्रबन्धों और डिफाइज नहीं होती यदि उसने गांव का सांस्कृतिक आधार पूर्ण रूप से प्राप्त न हो।

यैने देखा जाय तो ग्रामीण जीवन ग्रामीण प्रमोद और खल-कूद के अभाव में सुखी नहीं हो सकता। एक बात और है—मनोरजन के जरिये नये विचारों को ग्रामवासियों तक ग्रामांभी से पहुँचाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि गांव में प्रचलित साधन-धुनों एवं संगीतों का प्रोत्साहित किया जाय।

उत्तरीय भाग का ध्यान में रख कर ग्रामीणों द्वारा बनाई जाने वाली ग्राम विकास की योजना को शायचित्त करने में गांव की सामानिर्भर बनने और करने क्षमता में भरा पूरा बनने में बहुत सफलता मिल सकती है।

\*\*\*\*\*





## ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम का निर्धारण

—श्री जयप्रकाश नारायण

हमारे देश का प्रत्येक राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण है—कुछ अधिक और कुछ कम। इसलिये भारतीय ग्राम व्यवस्था को सर्वविधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी जा बातें बहुत कम महत्व की हैं वे अधिक उत्सुकता पैदा करती हैं और मंत्रियों व अधिकारियों का अधिक समय लेती हैं। गावा में जो लोग रहते हैं उनकी समस्या सारे देश की जनसंख्या का ८२ प्रतिशत है उसके लिये खेती के पलायन ग्राम काम बूझने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह कार्य महत्वपूर्ण और आवश्यक है। १९५७ में नागमभा में भाषण देने हुये प० नेहरू ने कहा था कि भारत का विकास गावों के विकास पर निर्भर है। यह बात पहली बार नहीं कही गई थी और न आखिरी बार और न पंडित नेहरू ने पहले कहा था। हर एक नेता ने यही बात कही थी। बात भी सही है—इसके विपरीत हो भी कैसे सकता है। इसलिये यह बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम की प्राथमिकता नहीं दी।

में इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि राज्या की जो हाबत है उसमें यदि मुख्यमंत्री निजी

तोर पर दिनचर्या नहीं लेत हैं और इस कार्यक्रम को उचित महत्व नहीं दत हैं और अपनी सत्ता और मोह में नोकरशाही के आनन्द को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह कार्यक्रम भागे नहीं चल सकता है। यह ठीक है कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यस्तर की कमेटी का अध्यक्ष है लेकिन इसमें कमेटी को आवश्यक दर्जा नहीं मिलता और न वह सत्ता व शक्ति मिली जिससे ग्राम उद्योग योजना कमेटी गांव वाली का भना कर सकती। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि राज्या में कृषि विकास के बाद ग्राम उद्योगों का महत्व दिया जायगा। निम्न-देह कृषि विकास को प्रथम दर्जा मिलना चाहिये।

## प्रशासनिक समस्याएँ

प्रशासन के मुख्य उद्देश्य दो थे (१) उद्योगों के विकास में सम्बन्धित सभी एजेंसियाँ के माध्याम, प्रत्यक्ष और योजनाओं को एक सूत्र में बाधना (२) प्रशासनिक कार्यविधि का साधारण बना कर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।

जहाँ तक पहले उद्देश्य का सम्बन्ध राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियाँ के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर एकीकरण के उद्देश्य को कुछ मात्र तक प्राप्त किया गया है। लेकिन वह प्रारम्भ मात्र है। प्रोजेक्ट स्तर पर अविभाजित एजेंसियाँ के पास संगठनात्मक इकाई नहीं है। अब देखना यह है कि उस स्तर पर एकीकरण कैसे होता है।

इस क्षेत्र में मुख्य समस्या यह है कि अल्प उद्योगों के बीच संजीव व कल्पनापूर्णा मनुष्य कैसे लाया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक काम बढ़ता रहे। इस समस्या का अध्ययन ग्रामीण उद्योग व योजना कमेटी की स्थायी समिति द्वारा किया जाना है। इस प्रकार सार जटिल प्रश्न जिनमें उत्पादन कार्यक्रम, कच्चे माल का निर्धारण, कीमत निर्धारित करना, बेचना आदि हैं सभी हल किये जाते हैं।

जहाँ तक दूसरे उद्देश्य का सम्बन्ध है आपकी ध्यान होना कि ग्रामीण उद्योग योजना कमेटी की राय की कि कार्यक्रम का प्रशासनिक जाल से बचाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि पत्र-व्यवहार इस प्रकार हो—स्थायी कमेटी, राज्य स्तर कमेटी प्रोजेक्ट कार्यालय कमेटी। वास्तव में मैं अपने छोटे अनुभव के आधार पर यह बताना चाहूँगा कि राज्य स्तर कमेटी को सहायकारी कमेटी के रूप में बना दिया गया है और विभाग इतने हावी हो गये हैं कि छोटी कार्यालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो सके है। कोई काम पूरा किया जाय इस पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। इस यदि और अधिक स्पष्ट किया जाय जो प्रारम्भ में साधा गया था कि प्रोजेक्ट कार्यालय कमेटी वित्तीय मापनों के अनुकूल एक विशेष कार्यक्रम बनायगी। उस कार्यक्रम पर विधायीय जोर हारा। विभागों के मुद्दों का दृष्टि में योजना में फिर हाँकर किया जायगा। फिर वह राज्य स्तर कमेटी के पास जमाया। उसका जो निष्पत्ति होगा वह राज्य सरकार के निर्णय के समान होगा। फिर वह योजना प्रोजेक्ट स्तर पर जायगी जहाँ उसे कार्यान्वित किया जायगा। लेकिन हुआ क्या है। राज्य स्तर कमेटी का निर्णय पर विचार विचार करते हैं। इससे राज्य स्तर कमेटी का अस्तित्व बेकार हो जाता है और कार्यक्रम की गति रुक-रुक हो जाती है।

उपयुक्त प्रशासनिक प्रश्नों से अधिक मौलिक प्रश्न उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली एजेंसियां क्या हैं। प्रायः ध्यान है कि मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि एक ग्रामीण भौद्योगिकरण प्रायोग की स्थापना की जाय जिसमें वर्तमान में तमाम एजेंसियां शामिल की जायें जो ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंध रखती हैं। उस प्रस्ताव को प्रथमव्यवहारिक समझा गया। एक दूसरा प्रस्ताव योजना प्रायोग ने स्वीकार कर लिया लेकिन उसे भी प्रस्वीकार कर दिया गया और अंत में निम्न एजेंसियां बनाई गई (१) ग्राम उद्योग याजना कमेटी (२) राज्यस्तरीय कमेटी, (३) प्रोजेक्ट कमेटी। यह निम्न प्रयोग के रूप में किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

इस समय केन्द्र में ग्रामीण उद्योग योजना कमेटी व स्वाधीन समिति संतोषजनक एजेंसियों सम्मिलित जा रही हैं। फिर भी दो बातें स्पष्ट हैं (१) जैसे जिस कार्यक्रम और क्षेत्रों में फलता जाता है वे कमेटियां उस कार्य का सम्भाव नहीं पायेंगी। यही बात राज्य कमेटियां के बारे में होगी। (२) इन दोनों कमेटियां में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिये जो तकनीकी और व्यवसाय की शिक्षा जानते हों।

राज्य स्तर कमेटी के सम्बंध में मैंने ऊपर काफ़ी कहा है। अब नीचे प्रोजेक्ट कमेटी के बारे में मुझे संदेह है कि क्या वह संस्था अपने वर्तमान रूप में कार्य को आगे बढ़ा सकती है? बिहार की दो प्रोजेक्ट कमेटियां को छोड़ कर बाकी ४४ कमेटियां विभागीय की तरह काम करती हैं।

प्रशासन व उद्योग के बीच अंतर निम्नानुसार साधारण बात होगी। वह तो हर कोई बना रहा है। हानि ही मैंने मुद्रास्फीति ने कहा था, "मौखिक प्रशासन की सेवा जोला के नियंत्रण से मुक्त किया जाय।" उद्देश्य आगे कहा कि प्रौद्योगिक कार्यों का "प्रशासन राजनैतिक प्रशासन से विभक्त होना है। यदि मात्र उद्योग का विभाग की भांति चलना चाहें तो वह प्रसक्त हो जायगा।" अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनकी बात हो रही है लेकिन इनके बारे में इतना कम किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट क्षेत्र के बारे में सोचने हुए हमें आगे बढ़ाने वाली एजेंसी के सबसे प्रच्छेद रूप को बनाने पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। जब तक ऐसी एजेंसी नहीं होगी ग्रामीण उद्योग अपने आप विकास नहीं कर सकते हैं। बड़े और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में सरकारी सहायता से निजी उद्योग इन सेवाओं का प्रदान कर सकता है। ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में ये सेवाएँ सामाजिक प्रणाली से ही मिल सकती हैं। इस सम्बन्ध में श्री शूमाकर का सुझाव जो उन्होंने याजना प्रायोग को दिया है कि जिना विकास निगम की स्थापना की जाय विचारणीय है।

ग्रामीण उद्योगों का सारा भविष्य प्रशासनिक लगना है क्योंकि कम मिलने वाला और नियंत्रित कच्चा मान उल्लेख नहीं है। गहरा के उद्योगों का यह मान मिल सकता है लेकिन गांवों के उद्योगों की नहीं। इस कारण से ग्रामीण उद्योगों का क्षेत्र सीमित हो गया है। यह क्षेत्र खाने-पाने प्रायोगिक प्रमाणन के अंतर्गत आता है। फिर प्रायः कमेटियां व अथवा दो कमेटियों के बनाने की आवश्यकता कहाँ रह जायेगी है।

मैं तो कहूँ कि हम सब की महत्त्वा गांधी की बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी

चाहिए। मैं देखा कि खादी सामाजिक क्रांति के लिए जो उद्योग होते हैं उन पर शहरी लोग हसते हैं लेकिन जब यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि समाज की हालत में गांवों में इनके प्रस्ताव और कोई उद्योग नहीं बनाये जा सकते हैं तो क्या मजाब बन्द नहीं होगा और क्या इन उद्योगों का समर्थन नहीं होने लगेगा ? जापान में शिल्प उद्योग व कुटीर उद्योग लोगों के उपयोग के लिए बहुत सा सामान तैयार करते हैं और शहरी के कारखानों में तैयार किया हुआ माल निर्यात किया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा पैदा की जा सके। क्या हम सोचें कि समाज व समझदार लोग इसी दशभक्ति की भावना से प्रेरित होंगे ?

यदि ग्रामीण उद्योगों का विकास स्थानीय वस्त्रों के माध्यम पर ही करना है तो तीन बातें करनी चाहिये। (१) योजना आयोग को अध्ययन करना चाहिये कि कौनसे उद्योग गांवों में चल सकते हैं और उनकी रूपरेखा तैयार करने की देनी चाहिए। (२) ग्रामीण उद्योगों की टेक्नॉलॉजी को उन्नत बनाने के लिये साधन दिया जाना चाहिये। श्री शुभाकर ने कहा कि ऐसी टेक्नॉलॉजी बनानी चाहिये ताकि उद्योगों में अधिक उत्पादन व अधिक लाभ हो। (३) बिजली की कमी का ध्यान में रखते हुए, प्रायः शक्ति स्रोत खोजने की काशिश करना चाहिए। प्रयोग प्रयोग में बहुत सा समय भी बहता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया है।

### नीति व इच्छा का प्रभाव

मैं ऊपर कहा है कि अच्छे और कम अच्छे उद्योगों के बीच सहयोग होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करना है लेकिन जिन उद्योगों के बारे में सम्मति हो चुका है जैसे तेल निर्यातना, धान कुटना आदि उनके बारे में राज्य सरकारों की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और यदि कोई नीति है भी तो उसे अच्छी तरह नहीं जाना रहा है। यह प्रश्न इसलिये भी महत्वपूर्ण बन गया है कि ग्रामीण उद्योगों का क्षेत्र सीमित है। यह खेद की बात है कि उद्योग गांवों से हट कर शहरों की ओर जा रहा है। गांवों में उद्योगों के बारे में हाशियार लग रही है। उनका दृष्टिकोण भी बदलना चाहिये।



## ग्राम औद्योगीकरण पर

### एक दृष्टि

— प्रो. डी. आर. गाडगील

मैं समझता हूँ कि ग्रामिक विकास की योजना का मुख्य आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य गाँवों का औद्योगीकरण है। इसलिए इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि सारी विकास योजना विशेषकर औद्योगीकरण की योजना इस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए बनाई जाये। आज ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं या जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उनसे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। और भागे चलकर बड़े उद्योगों में सम्मिलित जो नीति व मुद्दा है वह निश्चितरूप से उद्योग को शहरी व पूँजी आधारित बना देगा और देश को गरीब व उच्चांग्र बिहून कर देगा मैं समझता हूँ कि ग्राम औद्योगीकरण का उद्देश्य काराबार मिलने कि शक्ति में प्रमुख है और विकास की आवश्यकताओं को पूरी करता है। योजना की कला के बारे में जो वर्तमान मान है वह इस समस्या का शीघ्र व सरल हल नहीं बताता है। इसलिए इस पर थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करना चाहिए।

बड़े उद्योगों के लिए सामान निरिवित करने के लिये जो निर्यात किये जाते हैं और जो सामानों दिये जाते हैं व देश के उद्योगों के लिए का भावी रूप बताते हैं। विकास पं. में जो काम किया जाता है वह आवश्यक तत्व है जो भावी व्यवस्था को निश्चित करेगा। इस सम्बन्ध में निर्यात बढ़ाने में जो प्रयत्न किया गया और विश्वोत्पादन सहयोग के बारे में नीति निर्धारित की गई वह भी महत्वपूर्ण बन गई है। इस समय ऐसा नहीं लगता है कि उपर्युक्त बातों का प्रभाव उद्योगों के लिए बड़े बड़े सहयोगों से बड़ा सम्बन्ध है। इन परिस्थितियों में उन बातों का परिणाम यह होता है कि ऐसे ऐसे उद्योग खुल जाते हैं जिनकी तुलना बड़े बड़े उद्योगों के देशों में की जा सकती है। इन उद्योगों के लिए बड़े बड़े सहयोगों का उपयोग सम्भव होता है। निश्चित है कि इन कारणों के विकास का भावी रूप भी उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार तकनीक, दर्जा व स्थान बनेगा।

इस समय जो व्यवस्थाएँ व रीतियाँ चल रही हैं उनके प्रभाव के अन्तर्गत भागे चलकर उनके महत्वपूर्ण परिणाम भी होंगे। सामानों के प्राप्त होने के बारे में भी कुछ कहना है। ग्रामों की उद्योगों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार वह बच्चा मान है जो भावी में प्राप्त है। यदि उस बच्चे को माँ का सहारा के माधुनिक व बड़े बड़े उद्योगों में प्रयोग कर लिया जायगा तो भावी का उद्योगों के सम्बन्ध है। आज यहाँ हा रहा है और जहाँ तक मुक्त पता है कि कदम उठाया जा रहा है उनके परिणामों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिये चीन का उद्योग से जो सीरा निकलती है उसे बड़े बड़े उद्योगों में काम में लाने की योजना है। मैं सुना है कि व्यापक पानी निकालने के लिये विदेशी सहायता से एक बड़ी कैन्ट्री लगाई जाने वाली है। जब तक नाति स्पष्ट रूप से नहीं बनवाई जायगी तब तक यही सो होगा। तकनीकी के बिना नहीं बताएँगे कि माधुनिकतम तकनीक की इकाई स्थापित की जाय जिसका क्षेत्र अधिक से अधिक हो। वे विज्ञानों पर तभी विचार करेंगे जबकि नीति निर्धारण उच्च विचार करने के लिए आवश्यक है।

एक ऐसा मामला है जिसमें नीति के निर्धारण के औद्योगिक विकास पर प्रभाव डालना है। वह है बच्चा उद्योग। उसमें निर्धारण के लिए प्रोत्साहन के नाम पर कमजोरियाँ देनी पड़ी हैं। बच्चा उद्योग में काम नकारात्मक है। इसका कारण यह है कि ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम जो पहली योजना में स्वीकार किया जा चुका है उसे पूरा तोर पर नहीं चलाया गया है। उत्पादन के कार्यक्रम की सीमित रक्का गयी है। यह उन तक ही सीमित है जहाँ साधन ही साधन पुराने व माधुनिक तकनीक सीमित हैं। अतः मैं नहीं नहीं बच्चा उद्योग का उत्पादन अधिक क्षेत्र में होगा इसलिए माधुनिक उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था करनी चाहिये। इन व्यवस्थाओं की उद्योगों की योजना में शामिल करना होगा।

ग्राम उद्योगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिये। सुविधाओं को पैलाना चाहिये। बड़े बड़े बच्चा व सहयोग का कार्यक्रम सब जगह पाई जाने वाली बात है। प्राथमिक विकास की हरेक योजना में इन बातों का ध्यान रखा होगा और यातायात, जल, बिजली आदि की सुविधाओं को पैलाना पड़ेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में योजनाओं को दुबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पचोढ़ी सम्मया खड़ी हो जाती है। स्पष्ट है कि हमारे माधुनिक साधन-सुविधाओं की सीमित ही रखने की बाध्य करेंगे। इसलिये ग्राम उद्योगों को पैलाना में व. के साथ साथ ही धारण किया जाना चाहिये। नितने बच्चा या छोटे, कि नितने निश्चित व फलित हुए वे केन्द्र हों—इस पर विचार करना है लेकिन अनिश्चित समय व

व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर। इसका अर्थ होगा कि कार्यक्रम छोड़े किन्तु बड़े कदमों में प्रारम्भ किया जाय और बाद में उसे बढ़ा दिया जाय।

ग्राम उद्योगों की योजना में एक सबसे बड़ी आवश्यकता शोध कार्य की है। जो देश औद्योगिक उन्नति कर चुक है वहाँ भी शोध कार्य जारी रहते हैं। बहुत क्षेत्रों में विकास में काराबार के बारे में कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं। यदि उनके तकनीकी ढाँचे को हम स्वाकार कर लें तो बड़ी मुशकिल खड़ी हो जायेगी। यह किसी विशेष उद्योग की समस्या नहीं है बल्कि इस पर सबका प्रभाव पड़ता है। आवश्यकताओं को शोध कार्य में प्राधुनिकता लाने से पूरा किया जा सकता है। उद्योगों के बारे में अपनी विचार नीति को भी अब एक नया रूप देना चाहिये।

शोध कार्य का एक पहलू है जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। ग्राम उद्योगों के आधार के लिए वन भूमि, वन भूमि व झरियाँ से ढकी भूमि को विस्तृत किया जाना चाहिये। वहाँ पर तरह-तरह का कच्चा माल पैदा किया जा सकता है। ग्राम उद्योगों का स्थानीय कच्चा माल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और आज जो क्षेत्र खेती के योग्य नहीं हैं वे ऐसे माल की प्रपूर्ति के लिये बढ़ते जा रहे हैं।

अपने देश की स्थिति को देखते हुये यह हमें केवल वाञ्छनीय है बल्कि बहुत आवश्यक है कि पूरे प्रयत्न किये जायें ताकि देश में छोटे पैमाने पर उद्योगों का फैलाव हो। यह लक्ष्य जिसे मैं ग्राम उद्योगीकरण मानता हूँ भाषाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिरोध का मार्ग छोड़ दिया जाय जो आज हमारे देश में अपनाया जा रहा है और पूरा पूरा प्रयत्न औद्योगिक व आर्थिक विकास के मार्गदर्शन के लिये करना चाहिये। यह मार्गदर्शन और कही नहीं मिलेगा। इसलिये अपने प्रयोग के लिये तैयार होना चाहिये। इस प्रयत्न से सफलता प्राप्त हो सकती है यदि हमारा प्रयोग ईमानदारी के साथ हो और विस्तृत हो। इसकी प्रथम आवश्यकता सारे उद्योगीकरण के बारे में अपनी विचारधारा को नया रूप देना है। ग्राम उद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुये विदेशी स्तर।। यातायात और अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों व शोध कार्यों पर फिर से विचार करना है।

ग्राम उद्योगीकरण की परिभाषा को कुछ विस्तृत बनाना है। और ग्राम उद्योगीकरण समिती के प्रथम कार्यक्रमों के अंतर्गत मौजूदा से अधिक कार्य होने चाहियें। कार्य की क्या योजना हो, क्षेत्र किस प्रकार विस्तृत हो—इसकी दिशा निम्न सुझावों से मिल सकती है —

(१) परम्परागत ग्राम व नगर के हस्तकला उद्योग। इनको पुनः चलाने व इनकी रक्षा करने की कोशिश तकनीकी व उच्च आर्थिक आधार पर करनी चाहिये। उसके साथ साथ भावी उन्नति के कार्यक्रम भी हो।

(२) कृषि की उपज को संभरना बनाना उसे बचाना वन भूमि व झरियों में पैदा होने वाली चीजों को उपयोग के अनुकूल बनाना आदि। प्रयत्न यह होना चाहिये कि एक योग्य सहकारी संगठन हो जिसमें ये तमाम कार्य किये जायें। शोध से इन कार्यों को नेत्र का बढ़ाया जाता रहे।

(३) गाँव में इमारती कार्य भी बढ़ाये जायें। ग्राम उद्योगों के लिए इसमें महत्वपूर्ण नेत्र

प्राप्त होगा जब काम कम म लोगों का अधिक काम मिलेगा तो तरह तरह के कल, पुर्जों व मय चीजों के लिए बाजार बनेंगे। इन बाजारों में ग्राम उद्योगों के छोटे पैमाने पर बनाए गए माल को बेचा जा सकता है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि गाँवों के नवरो में सुधार किया, जाय अच्छे पच्चे मकान बनवाये जायें और स्थानीय बाजार तैयार किए जायें।

१४) गाँवों के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिये नया माल भेजा जा रहा है और भी बहुत सी दिशाएँ हैं। खास उद्योगों की वस्तुओं में भी उन्नति की जा सकती है। राज राज्य व जिला के बीच होठ लगी हुई है कि बड़े उद्योगों के वेद कहा स्थापित किए जायें। ये बड़े बड़े उद्योग पड़ोस के लोगों की तभी लाभ पहुँचा सकते हैं जब कुछ मय उपायों में छोटे पैमाने पर उद्योगों का लगाना, तैयार की गई वस्तुओं का बचना आदि हैं। ये उपाय भी तभी किए जा सकते हैं जब ग्राम उद्योगों पर ध्यान दिया जाये।





# बेकारी और बेरोजगारी से जिहाद

कोई बेकार न रहे  
कोई बे रोजगार न रहे

गाव में कोई बेकार न रहे, कोई बेरोजगार न रहे गाव में सब महनत करें सब कमाए, सब खाए पीए और अपने ही घर में खुश रहें ।

ऐसा हो सकता है पंचायत सर्वेक्षण करे, सर्वेक्षण अर्थात् जाच पड़ताल करे पता लगाए कि अपने गाव में कितने बेकार हैं कितने धंधे बेकार हैं कितने खाली हैं जिसने लोगो को काम चाहिए कैसा काम चाहिए, पता लगाए कि कौन कैसा राजगार कर सकता है पता लगाये कि गाव में कसे उद्योग धंधे चल सकते हैं, और फिर लोगो की जरूरतो के अनुसार तथा लोगो की योग्यता और काम करने की शक्ति और क्षमता के अनुसार गाव में नए नए उद्योग धंधे शुरू कर दे कि जिससे फिर बस को काम मिल सके ।

गाव में काम धंधे बनाने के लिए धन भी मिलना है मशीनें भी मिलती है औजार भी मिलते हैं, पंचायत यह सब तयबीज कर सकती है ।

गाव में नए नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए पंचायत तो सर्वेक्षण भी करेगी और नए उद्योग शुरू भी करवाएगी, लेकिन गाव के लोगो को भी अपनी इच्छा से आगे आकर अपनी सहकारी समितियों बनानी चाहिए और गाव में सहकारिता के आधार पर नए नए राजगार शुरू करने चाहिये ।

जब गाव में धंधे होंगे तब सब को काम मिलेगा तब गाव छोड़कर कार्ड नहर नहीं जाएगा न कोई मिल में मजदूर बनेगा, न कुनो बनेगा और न रिक्शा चलाने जाएगा, तब गाव में कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा ।

खंड-८

## विविधा



१ उदयपुर सगोष्ठी घीर उसके बाप

२ पचायती राज के कुछ पहलुओं पर प्रसिद्ध भारतीय पचायत परिवर्तन के विचारों का एक समिन्त विवरण

१-१४

१५-२७



## उदयपुर गोष्ठी और उसके बाद

“पंचायती राज” सस्यामों को जिला विकास क्षेत्र और ग्राम स्तर पर स्वशासन की इकाई के रूप में काम करना है। हालांकि ये सस्यामों विनियमित राज्य के एक स्वरूप को निर्माण प्रवर्धन करेंगी पर राज्य की शाखा नहीं होगी। अपनी प्रावधानता और साधनों की सीमा में ही इसे स्वशासन की इकाई के रूप में दायित्वों को निभाना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि जहाँ पंचायत प्रदत्त होगी वहाँ समिति और जहाँ समिति प्रदत्त होगी वहाँ उससे ऊँचे स्तर की इकाई को वह दायित्व निभाना होगा। इस हेतु ही उसी प्रकार जैसे भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजित हैं इनके कार्यों को भी स्पष्ट निदेश देन वाला विधान हो। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि एक (अथवा) निश्चित समय के बाद इन्हीं सस्यामों की प्रशासन के पूर्ण दायित्व व आत्मन होगे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त इसी धारणा को बल प्रदान करते हैं। इन नीतिनिर्देशों को क्रियार्थित भी करना है पर पंचायती राज की धारणा को पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप देने का सबसे बड़ा जिम्मेदारों उनकी है, जो ‘पंचायतराज’ के हामी हैं।

यह वह विचारधारा है जो ‘पंचायतीराज’ की भूल-भूत-समस्याओं पर उदयपुर में जनवरी सन् १९६४ में आयोजित सेमिनार ने पंचायती राज्य पर व्यक्त की। इस विचार धारा की सर्व प्रथम प्रति प्रिया समारोह पत्रों में जाहिर की। पर इनमें से कुछ ही समाचार पत्र पंचायती राज की धारणा को पूरे सके रूप से तो सेमिनार में व्यक्त विचारों और निर्णयों की भावना तक पैठ भी नहीं पाए। तथापि कुछ प्रमुख समारोह पत्रों की टिप्पणियाँ का सार निम्नलिखित है—

दो टाइम्स आफ इण्डिया (दिसम्बर २७/१)—की दृष्टि में ग्राम समा के स्तर को उन्नत करने के लिए उदयपुर सेमिनार की विचारों से किसी सीमा तक पंचायत राज कार्यों के विस्तार में

मदद करने वाली है। उदयपुर सेमिनार ने सिफारिश की है कि ग्राम सभा का उत्पादन पचायत राज कायों में सुधार लाएगा। पर पूरा ध्यानाधीन रहते हुए भी इस पत्र का विचार है कि स्थानीय नस्ल के धर्माव में ग्राम सभा को नए अधिकार देने से ही ग्राम-जीवन में कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। फिर पचायत राज पर विधान में नया अनुच्छेद जोड़ने का जो जयप्रकाश नारायण का प्रस्ताव था वह चयनक है। पत्र की राय में नया अनुच्छेद जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक परिवर्तन की जरूरत को दृष्टि में रखते हुए पत्र का मत है कि सत्ताह्वय ग्रामस्तर पर व्यवस्थित संगठन कायम कर स्वस्थ नस्ल द्वारा काफी कुछ कर सकता है। इसके पूर्व (२३/१) पत्र में पत्र ने टिप्पणी की थी कि पचायत राज का सम्पूर्ण अस्तित्व सरपंचों की अनुभवहीनता की वजहों नींव पर खड़ा है।

डॉ. स्टेटसमैन (दिल्ली २०/१) का कथन है कि सरकार के उदार अनुदानों से पचायत राज अपने ध्येय से भटक गया है। वह आत्मनिर्भर होने की बजाय सरकार का भुजापेसी ही अधिक बन गया है। पत्र को शक है कि पचायत राज को और अधिकार देने से उसकी क्षामिया दूर हो जाएंगी। बल्कि इसमें भी शक है कि सत्ता और सरकार की भुजापेसी यह सत्ता जनता का आधार बन सकेगी।

डॉ. इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली २३/१) महसूस करता है कि पचायत राज के कार्यो ने प्रारम्भिक धारा हो स्वस्थ नहीं की वरन् शक्यों भी उत्पन्न कर दी हैं। पत्र का मत है कि पचायत राज की क्षामियों की नींद हो दूर नहीं किया गया तो यह बदनाम होकर रह जायगा। फिर विधान सभाओं द्वारा पचायत का निर्माण हो काफी नहीं है शेष भी अनिश्चित है।

डॉ. ट्रोब्यून (म्बाला २४/१) की राय है पचायत राज की सत्ताओं को अपनी समस्या पर विचार करने में उनका हाल खोजने के लिए सभी राजनैतिक दलों को उन्हें मुक्त छोड़ देना चाहिए। यह प्रारम्भिक असफलता वही पचायतों राज के प्रति विश्वास को नष्ट न कर दे। तदर्थ इसके कार्यो में बाधक तत्वों को खोज निकालना और उन्हें दूर करना है। यिन चुन लोगों द्वारा पचायत राज के अधिकारों का उपयोग इसलिए घातक है। पचायतों को उनके वास्तविक अधिकार दिये जान चाहिए।

डॉ. एक्सप्रेस जनरल (बम्बई २२/१) न सचेत किया है कि योजनाओं से भी अधिक घातक निर्णायक पचायतों राज को पूर्ण असफलता होगी। पचायत राज की समस्या का मूल निर्वाचक जनता के मत का महत्वहीन होकर रह जाता है। मतदाता का इस सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है। आवश्यकता तो यह है कि गांव की लोकसभा का निर्माण करने वाली ग्राम-सभा को विकेंद्रित ग्राम व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हो।

डॉ. डकन हेराल्ड (बंगलोर २१/१) न लिखा है कि पचायतों पर हुई पहली समितार से लेकर अब तक पचायतों को कोई स्पष्ट निदेश नहीं दिया गया। माना कि मुक्त विचार विमर्श हेतु अवसर दिये जाने की दृष्टि से समितार का अत्यधिक महत्व है। पर सेमिनार ने पचायत राज्य को दायित्व प्रदान करने में बाधाओं पर अवश्य प्रकाश डाला है पर उसके दूसरे (धर्परे) पक्ष को तो अनुभव तक नहीं किया है।

डॉ. इकोनोमिक टाइम्स (बम्बई २८/१) न था जयप्रकाश नारायण के इस विचार पर कि

पंचायत राज निक नारा बनकर रह गया है टिप्पणी करते हुए लिखा है कि कई क्षेत्रों में पंचायतों ने सफलता भी प्राप्त की है । स विधान में पंचायत राज पर अनुच्छेद जोड़ने पर बल देने की बजाय, अपनी आवश्यकताओं के प्रति गांवों को सजग करके ग्राम सभा की अधिक समय बनाया जाना पत्र की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है ।

दो हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता २५।१) ने अपने की बहार में पंचायत राज तक ही सीमित रखते हुए कहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के बिना पंचायत राज योजना अपूर्ण है । गांवों में बसी गांवों राजनीतिक का जिक्र करते हुए और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पत्र ने लिखा है कि पंचायत राज की सफलता के लिए अधिकारियों को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए ।

नव भारत टाइम्स (हिंदी, दिल्ली) का विचार है कि जातीयता और स्वायत्तता के दावा से पंचायतों को बचाना अनिवार्य है । ग्राम विकास कार्यों में सगे अधिकारियों की पंचायतों के साथ पूर्ण सहयोग से अपना काम करना चाहिए ।

दो सचल्लाइट (पटना २८।१) की शिषायत है कि बिहार में पंचायत राज गवाओं पर लडा है । सरकार द्वारा पंचायत चुनावों का स्थगन आदि इस बात के सबूत हैं और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंचायत राज की एनी ही सवाओं को अधिक बढ़ाया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान (हिंदी, दिल्ली) उदयपुर सेमिनार में श्री श्री का कथन था कि १० जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकार का सम्मालन के लिए पंचायतों का हजारों नेना समर्थ हा जाएंगे, पर इस पत्र का विचार है कि यह अभी सम्भव होगा जब सत्ता का पूर्ण विवेकावरण कर दिया जाय और पंचायतों को वास्तव में प्रशासनिक काम सौंप दिए जाए पर नीकरगाही के रहने ऐसा होना असम्भव है ।

उपर महकारी और साधुदायिक विकास के वैदेशीय मन्त्रालय द्वारा पंचायत राज पर 'गवेषणा परिषद्' की निष्पत्ति के रूप में सरकार की प्रतिनिधिया नामन आई । ६ जुलाई ६४ को दिल्ली में हुई अपनी मीटिंग में इस परिषद् ने उदयपुर सेमिनार की उन सिफारिशों पर विचार किया जिनमें पंचायत को स्वशासन की पूर्ण इवाई के रूप में उसके कार्यों, प्राथिक साधनों आदि की चर्चा है । पंचायत के कार्यों और अधिकारों, साथ ही यदि उसकी एकता और सामर्थ्य के लिए जरूरी हो तो संविधान में संशोधन, परिवर्धन के हेतु भी इस दिशा में पूर्ण ध्यान देकर के लिए परिषद् ने निम्नांकित मददों की एक समिति का गठन किया —

१ श्री बलवन्तराम जो० मेहता	अध्यक्ष
२ „ श्रीमन्नारायण	सदस्य
३ „ के० सन्धानम्	
४ „ हरिद्वार भार्गव	
५ „ भटल बिहारी कावपेयी	“
६ „ राजेश्वर पाटिल	“
७ „ एम० वाई० फोरपटे	“
८ डा० जे० एन० सोसवा	“

उदयपुर सेमिनार की सिफारिशों के मन्त्रों में इस समिति ने जो अन्तरिम रिपोर्ट दी, वह सार रूप में या थी —

- १ हम उदयपुर सेमिनार और गवेषणा परिषद की इस राय से सहमत हैं कि पंचायत राज की ग्राम विकास क्षेत्र और जिलास्तरी पर त्रिवृत्तात्मक संस्थाओं सरकार की शान्ति नहीं करना चाहिए वास्तविक रूप में स्वायत्तता की पूर्ण इकाई है। हम महसूस करते हैं कि संविधान के संशोधन में काम की बजाय इसी धारणा को क्रियावत् करना अच्छा है।
- २ संविधान की धारा ४० है —  
“राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु ऐसे कदम उठाये और उन्हें वे सब अधिकार और शक्तियाँ सौंपेगी जिनकी उन्हें स्वायत्तता की इकाई के रूप में कार्य करते वक्त आवश्यकता पड़ेगी।  
इसी धारा में पंचायत समिति और जिला परिषद को सम्मिलित करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष आया था।
- ३ हालांकि इस धारा में ग्राम पंचायतों की ही चर्चा है पर हमारा दृष्टि में इसमें त्रिवृत्तात्मक पंचायत राज की उच्च संस्थाओं भी सम्मिलित हैं। वास्तव में यही व्याख्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी रिपोर्टों और उद्देश्यों में तथा राज्यों की विधान सभाओं में भी व्यक्त की है।
- ४ तो भी क्योंकि कई राज्यों में इस त्रिवृत्ता की दो संस्थाएँ ही कार्यरत हैं और पूरे देश में उन्हें एक ही स्वरूप देना भी है इस दृष्टि से हम जिला परिषद और पंचायत समिति के साथ ग्राम पंचायत की परम्परागत व्याख्या करने की सिफारिश करते हैं।
- ५ हम आश्वस्त हैं कि इस परम्परा के बाद संविधान में संशोधन जो कि सदैव ही एक कठिन और विरोधजनक कार्य होता है करना की जरूरत नहीं रहेगी।
- ६ हम उदयपुर सेमिनार के इस मत से सहमत हैं कि सतोषप्रद एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य करने देने के लिए पंचायत राज के तीनों स्तरों की पूर्ण अधिकार और शक्ति दी जानी चाहिये। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रामस्तर पर पूर्ण सतोषप्रद और प्रभावशाली ढंग से जो कार्य वे पंचायतें कर सकती हैं वे सभी कार्य उन्हें सौंप दिए जाने चाहिये। जो कार्य पर्याप्त नहीं कर सकें वे पंचायत समिति को और जो समिति न कर सके वे जिला परिषद को सौंपे जाने चाहिये।
- ७ पंचायत राज की समस्याओं के कार्य सुनिश्चित सूचीबद्ध एवं स्पष्ट रूप से विभाजित होना आवश्यक एवं अपेक्षित है। तदर्थ पांच विस्तृत सूचियाँ संलग्न हैं —

१ पंचायत (ग्राम सूची)

२ पंचायत समिति (ग्राम सूची)

३ जिला परिषद (ग्रन्थ सूची)

४ पंचायत और पंचायत समिति (सम्मिलित सूची)

५ पंचायत समिति और जिला परिषद (सम्मिलित सूची)

किसी भी सम्मिलित दायित्व पर यदि निचली संस्था का भिन्न निष्पत्ति हो तो ऊच्च संस्था का निष्पत्ति लागू होगा। इसी संघे कार्यो की सूची का पूरा सत्यापन होना जरूरी है।

श्री नगर म जुलाई ६५ में राज्यो के सामुदायिक विकास और पंचायत राज के मंत्रियों के वार्षिक अधिवेशन में गवेषणा परिषद की सिफारिशों पर विचार किया गया और निम्न लिखित निर्णय लिए गए -

गवेषणा परिषद की इस सिफारिश पर कि सविधान की धारा ४० में वर्णित ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद को परस्परगत 'यास्था' द्वारा संयुक्त किया जाय, इसकी विधि सम्मिलित क्रियाविधि पर और और कर लिया जाय। यदि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो तो समन के लिए इस सिफारिश को राज्यो को प्रेषित कर दिया जाय।

११ और १२ अगस्त ६६ को सामुदायिक विकास और पंचायत राज के दिल्ली में हुए वार्षिक अधिवेशन में अजयन्त और मोहन में कहा गया है -

विधि मन्त्रालय से राय मांगी गई। मन्त्रालय की विधि-सम्मिलित राय में सविधान की धारा ४० में प्रयुक्त शब्द 'ग्राम पंचायत' में पंचायत समिति और जिला परिषद संयुक्त हैं। राज्यो को इस बारे में सुविधा कर दिया गया है।

प्रसिद्ध भारतीय पंचायत परिषद ने अपने वार्षिक अधिवेशन में इसी कारण विचार करने बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ—

‘प्रसिद्ध भारतीय पंचायत परिषद अपने वार्षिक अधिवेशन में सन् १९६१ में जयपुर में आयोजित अधिवेशन में स्वीकृत नहीं जाया को दोहरानी है जिनमें पंचायत राज संस्थाओं को अपने स्तर पर शासन की पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करने देने की दृष्टि से शक्ति, सम्पत्ति और अधिकार दिए जाने की जगह है। परिषद मान्य करती है कि आवश्यक परिवर्तन साम, हेतु सविधान में मशौयन के लिए शक्ति दी गई कार्यवाही की जाए। जिससे इन संस्थाओं को अपना स्थान ठीक उसी प्रकार प्राप्त हो जहाँ वे देश के राज्यो की हैं। फिर जब तो सरकार को ग्राम समिति जिला राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर पंचवर्गात्मक संस्था के रूप में कार्य करना है। इसी मर्दान में यह परिषद पूर्ण यास्था के साथ उदयपुर सेमिनार की सिफारिशों की पर मत से स्वागत करती है।’

‘यह परिषद बनवताराय मेहता समिति का स्वागत करती है। समिति ने सविधान की मत मान धारा में ऐसे संशोधन की सिफारिश की है जिससे कि गांव, समिति और जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं वास्तविक एवं प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकें।

‘पंचायत राज पर कार्य करने के लिए गवेषणा समिति का गुरुत मठन करने हेतु राष्ट्रीय



सामुदायिक विनाश मन्त्रालय को भी यह परिषद धन्यवाद देती है और आशा करता है कि उदयपुर सम्मिनार की सिफारिशों की क्रियाविति हेतु भी इसी त्वरित गति से कदम उठाएगी।

सन् १९६५ में, अखिल भारतीय पंचायत परिषद् ने दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर पर 'ग्राम्यजन कम्प' का आयोजन किया। कम्प में उदयपुर सम्मिनार के निष्कर्षों से श्री जयप्रकाशनारायण ने एक कदम और आगे सुझाया। उन्होंने पंचायती राज की सच्ची धारणा के लिए समुदाय और उसकी अविच्छेदनीय मूल भूत बहुता को नहीं मान्यता प्रदान की। उनके विचारों का सार यों है —

‘यदि पंचायत राज की धारणा को बल प्रदान करना है तो इसे उगार दृष्टि में देखना होगा। पंचायत राज को अस्तित्व प्रदान करने का अर्थ समुदाय के रूप में नई समाज व्यवस्था का सृजन करना है। विश्व में आज दो प्रकार के समाज हैं एक पश्चिम का बहुत समाज और दूसरा साम्यवादी समाज। बहुत समाज में कोई समुदाय और व्यक्तिगतता नहीं तो साम्यवादी समाज में बहुत व्यक्तिगतता है। पर सच्चे लोकतन्त्र में समुदाय में व्यक्तिगतता सहयोग की भावना एक दूसरे का हित की भावना और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होती है। समुदाय व सामुदायिक जीवन पद्धति से व्यक्तित्व दायित्व की भावना आती है। पंचायत राज का महान ध्येय समाज के अंग के रूप में समुदाय की स्थापना करना ही।

पंचायत राज की धारणा में निहित इस विस्तृत समाज सिद्धांत पर उदयपुर सम्मिनार में या केन्द्रीय सरकार ने विचार नहीं किया था। अब समय आ गया है कि हम आशिक आशों से मुक्त रह कर तक सोचें और नए प्रकार की समाज रचना के साथ इसे सम्मिल करें।

ग्राम समाज का वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचा समुदाय की इस भावना के विकास में बाधक है। उधर पंचायत राज सिर्फ राजनीतिक निर्णय सेता है। पर अब यह माना जान लगा है कि आर्थिक विवेकीकरण के बिना सत्ता का विवेकीकरण आगे नहीं चल सकेगा। गांधी की आर्थिक और आर्थिक विकास प्रदान करना होगा। आज अर्थ तंत्र कुछ ही लोगों के हाथों में है। इसमें औद्योगिकरण उनके द्वारा हुआ तो सत्ता का विवेकीकरण आगे होना बलोर भर रह जाएगा।

यदि समुदाय के विभिन्न हितों और अपेक्षाओं को निभायें तो पंचायत राज्य संस्थाएँ सामुदायिक समाज का निर्माण कर सकती हैं। इन संस्थाओं को किसानों भजदूरा और नारीगरा के हितों का संरक्षण करना चाहिए। इस दिशा में हमें अधिकारियों सहित स्वयं सेवी सगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए; साथ ही समुदाय के प्रति सच्ची लगन से कार्य भी करने रहना चाहिए।

## पंचायत राज संस्थाओं के कार्य

### १—पंचायतो के कार्य (अग्रुक्त)

#### (अ) सफाई और स्वास्थ्य

- (१) कई गाँवों के सम्मिलित दायित्वो वाली नौ छोड़कर पशुओं और घरेलू कार्यों के लिए जन-व्यवस्था हेतु सावजनिक कुँधों, पोखरो और तालाबो (तिचाई के तालाबो के प्रतिरित्त) का निर्माण व मरम्मत कराना और उनकी देखभाल रखना ।
- (२) सावजनिक सब्जो, नालियो, बघा, तालाबा, कुँधों (तिचाई के कुँधो और तालाबों के प्रतिरित्त) स्थानों और कार्यों की मफाई के साथ-साथ घातक कार्यों या चीजा की वमी रोकथाम और नालो घादि की व्यवस्था करना ।
- (३) सावजनिक दीवालियो का निर्माण व उनकी मरम्मत ।
- (४) साधारण मुढों, हड्डियो तथा पशुओं का विक्रय करना ।
- (५) निर्णमित इकट्ठा करन हुए बाँव के कुँधे करवट और साद को हटाना व विक्रय करना ।
- (६) दमगाना व काँवस्तानों की व्यवस्थित व उनकी सभाल रखना ।
- (७) मकाना व दूबाना की व्यवस्थित रखना ।
- (८) साथ व मनोरंजन कला म प्रश्रयों को व्यवस्थित रखना ।
- (९) भावारा कुतो व चूहो का नाग करना ।

#### (ब) सावजनिक कामं (सयुक्त दायित्व)

- (१) बाँव की सीमा मे पडने वाली, पर दूसरो किसी सत्वा को न सौरी यह बाँव की सदकों ओदने

वाली सड़को, नालियो, बाँधो और भूमिगत नालिया का निर्माण व मरम्मत करवाना तथा सम्भाल रखना ।

- (२) सावजनिक रास्ता स्थानीय व पंचायत के प्रहारा में पड़न वाली बाधाया छुज्जा और छावणो को हटाना ।
- (३) चरागाह पंचायत के नियन्त्रण म दिए गए या स्थाना-उचित सरकारी भवना की साज सम्भाल व व्यवस्था रखना ।
- (४) रास्ता की रोशनिया ।
- (५) जिला परिषद व पंचायत समिति द्वारा प्रदत्त तथा स्थानीय महत्व के पशु मेलो सहित ग्राम मेलों का प्रबन्ध करना ।
- (६) सावजनिक स्थाना के सूखे पेडा की बिक्री, पेडा की कटाई तथा वन सरक्षण का काय करना ।
- (७) नित्य के बाजारा की व्यवस्था व प्रबन्ध ।
- (८) सावजनिक बागों, विरापकर अपने कामचारियो के लिए भवना का निर्माण व उनकी साज सम्भाल ।

## (स) कृषि

- (१) क्षेत्र मे लागू भू सरक्षण बागों की क्रियाचिन्ति मे सहयोग ।
- (२) खाद के गड्डे खोदना ।
- (३) बाग बोदिका लगवाना ।
- (४) जो एक से अधिक गाँवो की भागीनारी म न हो ऐसे, ग्राम वन, ग्राम-चरागाह तथा ग्राम नसरी का काय ।
- (५) भृगी तथा सूखर पालन ।

## द अन्य कार्य

- (१) पंचायत साज क विकास की योजना बनाना ।
- (२) ग्राम पुस्तकालय व वाचनालय ।
- (३) प्राकृतिक प्रकोषों से गाँव को रक्षा ।
- (४) महाने छोने के घाट
- (५) ग्राम सेवक दल ।
- (६) गाँव और फसला की देखभाल ।
- (७) पशु पालन ।
- (८) मत्स्य वनत योजना तथा बीमा के एजन्ट के रूप में व्यापार करना ।
- (९) चाय का काफी गृहों के, भोजनालयो व दुकानो की साइडिड देना ।

## पंचायत समिति के कार्य (अयुक्त)

### १. सामुदायिक विकास कार्य

पंचायतो, सहकारी संघटनों तथा स्वेच्छानियमित अन्य निकाया तथा जनता के सहयोग से सामुदायिक विकास के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों का संपादन ।

### २. कृषि और पशुपालन

- (१) खडो में कृषि सुधार की योजना का पालन ।
- (२) कृषि के सुधरे हुए तरीकों और प्रणालियों का प्रचार तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना ।
- (३) बीमा की रक्षा के तरीकों का प्रचार और उनकी रक्षा में सहायता देना ।
- (४) कुआ के पुनर्स्थापन और उन्हें गहरा उतारना सालाबा की परम्परा और खुदाई तथा सरकारी तालु मिर्चाई माधना (२५० एकड़ तक जमीन की सिंचाई जिनसे की जा सके) तथा धातुरक कुल्यामा या नहरों को बनाय रखना ।
- (५) प्रदूषण के स्थानों की व्यवस्था और फार्म प्रबंध के अन्तर्गत तरीके विकसित करना ।
- (६) पशु चिकित्सा सम्बन्धी औषध वितरण केन्द्रों को चलाना ।

### स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वच्छता

- (१) विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ ।
- (२) टीका मत सेवा और निगु-व्याख्या ।
- (३) जिलास्तर की गहिया की छोटी गहिया की स्थापना और उनका नियंत्रण ।
- (४) पशु मेला समेत ऐसे मत्त त्योहारों का नियन्त्रण जो जिला परिषद् द्वारा दहे संपि जाय ।

### ३. संचार व्यवस्था

- (१) ग्रामा-सभा की जाने वाली सड़क का निर्माण और उन्हें बनाये रखना ।
- (२) सम्पर्ककारी सड़क के निर्माण और बनाये रखन में पंचायतों को सहायता देना ।
- (३) एम सावर्जनिक बाटा आदि का प्रबंध जो दूसरे वि-ही निवासी या वर्गों का न संपि गय हों ।

### ४. सामाजिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा

- (१) प्राथमिक शिक्षा
- (२) प्राथमिक शिक्षा
- (३) प्रौ- शिक्षण समेत सामाजिक शिक्षा ।

## फ लघु सिंचाई

छोट सिंचाई कार्यों का निर्माण पुनरुद्धार और उ हें बनाये रखना ,

## ज मत्स्य पालन

### ह ग्रामीण जल प्रदाय

एक पचायत से अधिक की आवश्यकता पूर्ति करने वाले सावजनिक कुओं तालाबों तथा जल प्रदाय कार्यों का निर्माण और मरम्मत ।

## जिला परिषदों के कार्य (अयुक्त)

### (क) विकास कार्य

गावा के लिए योजना बनाना और उनमें सम्मिलित स्थापित करना ।

### (ख) कृषि

यात्रिक और दूसरी सीमाओं में ही कृषि संस्थानों को आर्थिक मदद देना उनको देख भाल, साज सम्भाल और प्रबंध करना किन्तु निम्नांकित विषयों के अतिरिक्त -

- १ पाठ्यक्रम का निधारण करना ।
- २ पाठ्य पुस्तकों का चयन करना ।
- ३ वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करना ।

### (ग) पशु-पालन

- (१) पशु-अस्पतालों की स्थापना और व्यवस्था ।
- (२) माहमारियों पर नियन्त्रण करना ।

### (घ) भवन तथा आवागमन

- (१) जिल की सड़कें व पुलों आदि का निर्माण, मरम्मत और व्यवस्था करना ।
- (२) जिला-परिषद की आवश्यकतानुसार प्रांतीयकीय भवनों तथा अन्य भवनों का निर्माण ।

### (च) लघु सिंचाई

प्रतर्जित योजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई के ऐसे साधनों का निर्माण मरम्मत तथा प्रबंध करना जो २५० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करते हों ।

### (छ) कुटीर तथा अन्य उद्योग

- (१) कुटीर व ग्रामोद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों की व्यवस्था करना ।

(२) प्राय-उद्योग क्षेत्र कायम करना ।

(३) प्रशिक्षण-उत्पादन केंद्रों का संचालन करना ।

## (ज) शिक्षा

(१) निर्धारित वार्षिक व दूसरी प्रशासनिक सीमाओं में ही माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, व्यवस्था, प्रबंध और निरीक्षण करना । जिनसे निम्नांकित कार्य सम्मिलित न किए जाए ।

[क] पाठ्यक्रम का निर्धारण

[ख] पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण,

[ग] अनुदान की दर व शर्तों की व्यवस्था

[घ] माध्यमिक को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाये जान की स्वीकृति ।

[च] गुरु दर ।

[छ] मा गता व लिए साधारण शर्तों का निर्धारण ।

[ज] प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा संचालन ।

[झ] राज्य सरकार द्वारा 'ग्रांट इन एड कोड' के तहत भारक्षित अथवा शिक्षा संचालक को प्रदत्त अधिकार के कार्य ।

(२) माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व भत्ते (Stipends) की स्वीकृति ।

(३) सक्तीकी या त्रिगिष्ट विद्यालय

## (क) अन्य कार्य—

पट्ट मेला सहित जिल के मेला व त्योहारों का संचालन व व्यवस्था ।

पंचायत व पंचायत समिति के समुक्त दायित्व वाले कार्य

## (क) स्वास्थ्य और सफाई—

(१) घूम की बीमारियों की रोकथाम व प्लाज

(२) मास, मछली आदि शीघ्र गड़न वाले खाद्यों का प्रारक्षण व नियंत्रण

३) कबाई घरा का संचालन और व्यवस्था

(४) चमड़ की पकाई रंगाई आदि की व्यवस्था

(५) श्रवणानिक एवं घातक बागों का कमी के लिए रोकथाम व जान बचना

(६) विद्यार्थियों के लिए दुपट्टर के भाजन की व्यवस्था

## (ख) सार्वजनिक काम

(१) धर्मशाला विधायक तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों का निर्माण व प्रबंध ।

- (२) बिक्री केट्रो, डूकाना के लिये भवनो का निर्माण व सभास ।
- (३) सावजनिक उद्यान तथा बालोद्यानो की सरचना और सभास ।
- (४) गाव की जमीन का विस्तार व विकास ।

### (ग) कृषि और पशुपालन

- (१) कृषि कार्यों की ओर विशेष ध्यान देकर गाववासियो के आर्थिक स्तर का उत्पान और विकास
- (२) फल व सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहन ।
- (३) कम्पोस्ट और हरे खाद में आत्म निर्भरता की प्राप्ति ।
- (४) सिंचाई के लिए समय पर सथा समान रूप से पानी का वितरण ।
- (५) कृषि व सिंचाई साधनो के विकास के लिए ऋण तथा सुविधायें देना ।
- (६) पशु धन की सुरक्षा उनकी नस्ल में सुधार तथा वद्धि के कार्य ।
- (७) चरागाहो का विकास ।

### (घ) वन

वन रोपण तथा ग्राम वन के लिए विकास कार्य ।

### (च) शिक्षा

पंचायत समिति के नियंत्रण में विद्यालयों के लिए भवन साज सामान बेल का मंगान तथा वाग आदि के लिए धन जुटाना ।

### (छ) अन्य कार्य

- (१) ग्रामोद्योगो का विकास ।
- (२) सहकारिता ।
- (३) सावजनिक व व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा ग्राम-भूमि क्षेत्र के आकडा तथा सवे रेकार्ड की सुरक्षा ।
- (४) प्राय वाड संक्रामक रोग ग्रथवा ग्रथ दुर्भिक्षो द्वारा विनाश की संकटकालीन घटो के लिये सुरक्षित धन ।

पंचायत समिति और जिला परिषद के संयुक्त दायित्वपूर्ण कार्य

### (क) पशु-पालन व कृषि

- (१) सूचीबद्ध उन्नत बीज सठाकर सथा वितरण करके उत्पादन बढ़ाने ।

- (२) भूमिगत पानी का उपयोग,
- (३) उन्नत कृषि साधना का प्रयोग,
- (४) बीज तथा भादश कृषि-क्षेत्र
- (५) योदाय और रक्षा गृह
- (६) फसल की सुरक्षा
- (७) फल व सब्जियाँ का उत्पादन
- (८) साठ की नस्ल में सुधार,
- (९) पशु महामारियों का रोकथाम,
- (१०) भण्डारी नस्ल की गाया भुगियो, सूखरो व भडा का विनरल
- (११) दुग्धशाला

### (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई

- (१) प्रायुर्वेदिक व सुनानी दवाखानों प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व विविध बीमारी होने पर चिकित्सा कर्मों का संचालन
- (२) गाव की नई बस्ती की संरचना
- (३) सार्वजनिक तथा व्यक्ति सम्पत्ति और गाव की जमीन का सर्वे संचालन ।

### (ग) सार्वजनिक कार्य—

- (१) यात्रियों के लिए मकान व विद्यालय गृह
- (२) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा भ्रमण हाथ में लिए गए ऐतिहासिक स्थलों तथा आलेखों की सुरक्षा

### (घ) शिक्षा

माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन, सामान और व मदद तथा भाग आदि के लिए धन का प्रबंध ।

### (च) सहकारिता

सहकारी कृषि सहित अन्य कार्यों में सहकारिता ।

### (छ) कुटीर एवं लघु उद्योग

- (१) कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना-संचालन ।



(२) बिन्नी वेन्डा व एम्पोरियमों का संचालन।

## (ज) अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण कार्य

- (१) अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों के हित में सांस्कृतिक सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान-कार्यों का संचालन।
- (२) ऐसे वर्गों व जातियों का शोषण तथा भ्रष्टाचार को रोकथाम तथा उन्हें मदद।
- (३) वस्त्रोपर सबको के लिए होस्टल का संचालन और दूसरे कल्याण कार्य।
- (४) रिहायशी तथा आश्रम विद्यालयों का संचालन।
- (५) पिछड़े क्षेत्रों में भाग्यमन के लिए मार्गों आदि का विकास।

## (झ) समाज का कल्याण कार्य

- (१) बीमार व अपंगा की मदद।
- (२) परिवार नियोजन।
- (३) पुस्तकालय वाचनालय सूचना केन्द्र तथा अन्य सांस्कृतिक कार्य।
- (४) युवक समिति महिला समिति और कृषक समिति सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बच्चों के सिलाई के द्र। जैसे ही अन्य कार्यों का संचालन और प्रोत्साहन।
- (५) महिला उत्थान व बाल विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन उनके लिए कल्याण केन्द्रों का संचालन जैसे कि शिक्षण केन्द्र उद्योग केन्द्र सिलाई केन्द्र आदि।
- (६) गाँव के लिए ग्रह योजना।
- (७) वारीगटा को प्रशिक्षण के लिए विद्यालय या कम्पा का संचालन।



# पंचायती राज के कुछ पहलुओं पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के विचारों का संक्षिप्त विवरण

## ग्राम समुदाय

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् इस बात को समझती है कि पंचायती राज की योजना जो प्राजक्ल चलाई जा रही है केवल पहला कदम है। यदि इसके द्वारा लोकतन्त्र एवं विकास के कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाना है तो अभी बहुत कुछ करना बाँका है। वर्तमान पंचायती राज एक कमजोर ढाँचा है जिसके पास न सत्ता है और न साधन। इसलिए सबसे पहला कार्य गाँव के प्राथमिक समुदायों को पुनर्जीवित व सशक्त बनाना है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् अनुभव करती है कि आज गाँव में आपसी विरोध अधिक है। हम इस गाँव के हैं, हम सब की आपस में गाँव के लोगों को बाट बर उपभोग करना चाहिए, ऐसी भावनाएँ जो समुदाय की साधन बनाती हैं आज गाँवों से लुप्त होनी जा रही हैं।\*

- १ अखिल भारतीय पंचायत परिषद् एवं गैर सरकारी, निदेशीय पंचायती राज की सम्पादा का अखिल भारतीय स्वच्छता सेवी सत्पा है जो पंचायती राज के स्वरूप के प्रसार करने में और पंचायती राज की संस्थाओं के अधिकार कम एवं साधनों को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
- २ यह लक्ष्य पत्र अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का कोई धोषचारिक लेख पत्र नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत के मौखिक विचार समीक्षा हैं जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद् द्वारा आयोजित विभिन्न विचार गोष्ठियों में सम्मेलन में प्रगट व स्वीकार किए गए हैं।
- ३ आज का गाँव एवं छिन्न भिन्न परिवार जैसा है। उनमें जाति व वर्ग के मतभेद पाय जात हैं और भा दवर्गिया है। गाँव में सामूहिक इच्छा का प्रभाव पाया जाता है। दूसरे और भाग गाँव में सामान्य भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें एकता और सामूहिक प्रयत्न के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। उचित सामुदायिक विवरण के पूरे सामूहिक भावना पैदा करने चाहिये।

— श्री जयप्रकाश नारायण, सामाजिक दर्शन एवं दैवीय मो ५८८ २३२

“आप आज गांव को ही लीजिए जैसा कि वह थाज है और वहां पचायती राज लागू कर दीजिए तो मेरी समझ में वह सफल नहीं हो पायगा। गांव में फट के तत्व विद्यमान है। ग्राम पचायती को प्रभावपूर्ण कार्य करने के लिए उन तत्वों को हटाना पड़ेगा।”

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार आन फंडामेंटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ ३६

ग्रामिण भारतीय पचायत परिषद के इस सम्मेलन की सम्मति में वास्तविक पचायती राज के विकास के पूर्व हरेक गांव में सरकारी व एकोकृत समाज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक शर्त है। प्रस्ताव ७ जयपुर में होने वाले ग्रामिण भारतीय पचायत परिषद के द्वितीय अधिवेशन।

ग्रामिण भारतीय पचायत परिषद के अध्यक्ष श्री जयप्रकाशनारायण ने जोर स्वराज्य में लिखा है कि पचायती राज को प्रभावपूर्ण होने के लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं।\*

इसके अतिरिक्त ग्रामिण भारतीय पचायत परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री जयप्रकाशनारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे पचायती राज के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन को महात्मा गांधी के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के सहज मानते हैं जिसमें एक और तो समुदाय पर जोर दिया गया है और दूसरी ओर कम से कम शासन पर। पचायती राज परमपैन्टिव एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ २६।

ग्रामिण भारतीय पचायत परिषद का विश्वास है कि समुदाय का पुनरुज्जीवन प्रथम महत्व की बात है, यद्यपि गांव को विकास कार्यक्रम की इकाई मानना चाहिए।

पचायती राज नीचे से प्राथमिक समुदाय से आरम्भ होता है। प्राथमिक समुदाय माय-साथ रहने वाले परिवारों के समूह को कहते हैं जिनकी आपस में साझेदारी होती है जो साथ-साथ प्रयत्न करते हैं, मिलजुल कर अपने काम निबटाते हैं और जो काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनमें दूसरे समुदायों का सहयोग लेते हैं। इस प्रकार समुदायों के एक बड़े सघ एक पचायती राज की संस्थाओं की रचना करते हैं। श्री जयप्रकाशनारायण सेमिनार आन फंडामेंटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ ३७-३८।

४ संक्षिप्त में शर्तें इस प्रकार हैं —

पहल साक्षरता जैसी कि आमतौर पर समझी जाती है इस प्रयाग को सफलता के लिये आवश्यक शर्तें हैं। जो निष्पक्ष और निस्वार्थ संस्थाएँ ग्राम विकास का कार्य में लगी हुई हैं वे इस गिनती की भली भांति प्रमाण कर सकती हैं। यह भी विचार करना चाहिये कि क्या निर्दली और विमुक्त मतदाताओं की एक प्रशिक्षणीय संस्था नहीं बनाई जा सकती जिसका नाम ग्रामिण भारतीय मतदाता सघ हो सकता है ताकि मतदानाग्रा को शिक्षित बनाया जाय।

दूसरे इस बात पर जोर देना उचित होगा कि पचायती राज की सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि किस सीमा तक राजनीतिक दल उसमें हस्तक्षेप करने से दूर रहते हैं और उसे अपने हानि की कठपुतली नहीं बनाते हैं या सत्ता प्राप्त करने के लिये उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इन

## भारतीय राज्य व्यवस्था

अग्निल भारतीय पंचायत परिषद का मत है कि भारत को जनमभाओ के राजनीतिक स्वतंत्र को नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि वे बालू के ढेर के सामान होते हैं। उसके कणों में कोई आगिक सम्बंध नहीं होता है। भारत में सदस्य लोकतांत्रिक अनुभव जितने व्यक्ति कुछ वर्षों में एक बार विधान मण्डलों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं-अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। इस दशा को अथ क्षेत्रों की भाँति राजनीतिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भी अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। अग्निल भारतीय पंचायत परिषद सरकार की पाँच स्तरीय व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्न कर रही है। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषदें राज्य सरकारें व केन्द्रीय सरकार होगी। इन सबमें आगिक सम्बंध होगा।

इस समय रुविधान केवल दो प्रादेशिक सरकारें संगठना की स्वीकार करना है-केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें। ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों, और जिला परिषदों को भी रुविधान में उचित स्थान मिलना चाहिए। रुविधान में उनके अधिकारी और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण, पंचायत राज पर्स पैक्टव एण्ड प्रोग्राम पुठ-४०

सत्ताओं की शक्ति और क्रियाशीलता के लिए लोकतंत्र में जनता को भागीदार बनाना चाहिये। इसलिये इन सत्ताओं को जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में छोड़ देना चाहिये। दत्ता को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं।

तीसरे, सत्ता वास्तविक अर्थ में दी जानी चाहिए दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी का निर्वाना तब तक नहीं सोख सकता है, जब तक कि उसे जिम्मेदारी सौंपी न जाये। यदि पंचायती राज को सच्चे अर्थ में सत्ता सौंप दी जाय तो जिस मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी या फिर वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहता जिस प्रकार राज्यों में राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहता है।

चौथे, यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर स्थानीय अधिकारियों का 'पुनर्गठन' साधन देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि भूमिदर जा बहुत अधिक नहीं होता है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को दे दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार का यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि भूमिदर में से कुछ अनुमान इन मस्याओं को प्रदान करे। अथ साधन स्थान भी सोझाए इन सत्ताओं का नियंत्रण जान चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि विकास बाधों के लिये पंचायती राज को राज्य या केन्द्रीय सरकार से और धन नहीं मिलना चाहिए।

पाँचवें, जहाँ तक सम्भव हो सीमानिर्णीत पंचायती राज को प्रमत्त अधिकारी वर्ग पर वास्तविक सत्ता का प्रयोग करने के साथ बनाना चाहिये। अधिकारी वर्ग उन मस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। नियुक्ति का सम्बंध में भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता देनी चाहिये।

जाये या पचायत समिति को केवल जिला परिषद का एक कार्यपालिका अंग बनाकर रखा जाये।

। श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार ऑन फंडामेंटल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज—पृष्ठ-४२

## ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पचायत परिषद् ग्राम सभा की शक्ति को बड़ा महत्व देती है। यह प्राथमिक समुदाय और मौलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायणजी कहते हैं—

मुझे शक है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान को पूरी तौर पर नहीं समझा गया है या शायद हमारे मन में जनता की पहल करने की शक्ति के बारे में काफी अटकबाध है। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को शक्तिशाली नहीं बनाया जाता है तो पचायती राज अवास्तविक हो रहेगा और विकास कार्यक्रमों में भी जनता का उत्साह व भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम मन के अटकबाध को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा।

अखिल भारतीय पचायत परिषद् के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री महताजी ने कहा—

ग्राम सभा के योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह कम है। लोचतायिक विक्रेतों का पूर्ण महत्व अभी अनुभव किया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तौर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जाती है।

पचायती राज परंपरित्व एण्ड ग्रामागम—पृष्ठ-२१

इस बीच ग्राम सभा को बजट पर बहुत करने का और पचायत की समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और वह जो सिफारिशें करें उस पर पचायत पूरी तौर पर विचार करे।

जब कि ग्राम सभा का अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपना वार्षिक बजट बनाये और स्वीकार करे। पचायतें अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाओं के सामने पेश करना चाहिए, जहाँ उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अंतिम स्वीकृति का प्रश्न उन पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

सेमिनार ऑन फंडामेंटल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज,—पृष्ठ-५४

पचायती को ग्राम सभा में पूर्ण विश्वास रखना चाहिये और वर, विकास व निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों को उसके सामने उल्लेख विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में कार्य समितिवा होनी चाहिए। पच उनके मयोजक हो, और ग्रामसभा के चुन हुये सन्त्य उनके सदस्य हो। गाँव का चौकीदार ग्रामसभा व अधीन हो।

। सेमिनार ऑन फंडामेंटल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज पृष्ठ-५४

## भारतीय राज्य व्यवस्था

अखिल भारतीय पंचायत परिषद का मत है कि भारत को जनभाषा के राजनीतिक स्वल्प को नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि वे बालू के ढेर के सामान होते हैं। उसके बणों में कोई आंगिक सम्बन्ध नहीं होता है। भारत में सदीय लोकतन्त्र का अनुभव जिसमें व्यक्ति कुछ वर्षों में एक बार विधान मण्डलों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं-अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। इस देश को ग्राम क्षेत्रों की भाँति राजनीतिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में भी अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। अखिल भारतीय पंचायत परिषद सरकार की पाँच स्तरीय व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्न कर रही है। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषदें राज्य सरकारें व केन्द्रीय सरकार होगी। इन सबमें आंगिक सम्बन्ध होगा।

इस समय संविधान केवल दो प्रादेशिक सरकारों की स्वीकार करना है-केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों को भी संविधान में उचित स्थान मिलना चाहिए। संविधान में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण, पंचायत राज पर्स पैक्टिव एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ-४०

संस्थाओं की शक्ति और क्रियाशीलता के लिए लोकतन्त्र में जनता को भागीदार बनाना चाहिये। इसलिये इन संस्थाओं को जनता के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में छोड़ देना चाहिए। दलों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं।

तीसरे, सत्ता वास्तविक रूप में दी जानी चाहिये, दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी का निभाना तब तक नहीं सीख सकता है जब तक कि उस जिम्मेदारी सौंपी न जाय। यदि पंचायती राज को सच्चा अर्थ में सत्ता सौंप दी जाय तो जिला मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी या फिर वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेगा, जिस प्रकार नगरों में राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहता है।

चौथे, यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर स्थानीय अधिकारियों की न्यूनतम स्थापना देना चाहिए। मेरा मुझाव है कि भूमिदार जो बहुत अधिक नहीं होता है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का दे दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार का यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि भूमिदार में से कुछ प्रमुख इन संस्थाओं को प्रदान करे। ग्राम स्थापन स्त्रोत भी खोजकर इन संस्थाओं का लिये जाना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि विकास कार्यों के लिये पंचायती राज को राज्य या केन्द्रीय सरकार से और धन नहीं मिलना चाहिये।

पाँचवें, जहाँ तक सम्भव हो सीधे-निर्गोप पंचायती राज की धर्मनिरपेक्ष अधिकारी वर्ग पर वास्तविक सत्ता का प्रयोग करने के योग्य बनाना चाहिये। अधिकारों के इन संस्थाओं के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों। नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता लेनी चाहिये।

अन्तिम विश्लेषण में इस दृष्टि का यह अर्थ होता है कि प्रत्येक स्तर अप्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए । \* इस बात को विस्तार पूर्वक बताते हुये श्री जयप्रकाश नारायण ने विभिन्न स्तरों पर चुनावों की एक प्रणाली के बारे में मुभाव दिया है । इस दृष्टिकोण का सम्मर्थन गांधीजी के कुछ लेखों द्वारा होता है ।

भारत में साथ साथ गांव है । उनमें प्रत्येक का संगठन नागरिकों की दृष्टानुसार होगा । वे सभी मत देगे । फिर साथ साथ मत बन जायेगे । दूसरे शब्दों में प्रत्येक गांव का एक मत होगा । ग्रामीण जिले के प्रशासन को चुनेगे । जिले के प्रशासनों द्वारा प्रांतों के प्रशासन चुने जायेगे । बाद में वे ही राष्ट्रपति को चुनेगे जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा ।

—महात्मा गांधी

छठे पंचायती राज के मस्तक ठाके में नीचे का स्तर ग्राम पंचायत निश्चित रूप से नीचे है । इसलिये मारे डाक की शक्ति और सजीवता के लिये ग्राम पंचायत की शक्ति सजीवता और उसका लोकतांत्रिक रूप आवश्यक है । ग्राम पंचायत की शक्ति और प्रभावपूर्णता इस बात पर निर्भर है कि उसके कार्यों में ग्रामीण समुदाय सहयोग करें और बुद्धि एवं उत्साह के साथ उनमें रुचि ले । पंचायत से नीचे जनता तक जाना आवश्यक है और गांव के सभी व्यक्ति 'गोपा' की ग्राम सभा बनानी चाहिये । पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी के रूप में काम करे । ग्राम सभा को बैठक सभी कभी यानी तीन माह में होगी और उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें और बजट पैसा दिया जायेगा जिस पर न केवल वह विचार करेगी बल्कि उसे स्वाभिकार करगी । ग्राम पंचायत के चुनाव सब सम्मति से होने चाहिये । वहां चुनाव सफ़ा शुरू करने से बड़ी धीना भपटी होगी ।

सातवें पंचायती राज के दैनिक कार्यों को राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर रखना चाहिये । जब आवश्यक कानून पारित कर दिये जायें तो उनके वायन्वियन को एक ऐसी स्वतंत्र संस्था के नियंत्रण में कर देना चाहिये जसी लोक सेवा आयोग या विषयविशालय अनुदान आयोग होती है । यह वाछनीय होगा कि उनकी सहायता पर्यप्रदर्शन और देखभाल का कार्य एक पर सरकारी स्वतंत्र संस्था को सौंप देना चाहिये जिसका अध्ययन असैनिक अधिकारी वर्ष में से न हो ।

—श्री जयप्रकाश नारायण, लोकतन्त्र सर्वोच्च डेमोक्रेसी का सार पृष्ठ २४६ ५७

५. मन यह बताने की कोशिश की है कि सत्ता न तो समर्पित की जा सकती है और न प्रशासन को विकेंद्रित किया जा सकता है यदि वर्तमान राज्य स्तर के नीचे स्वायत्त शासन केन्द्र व सत्यायें न हों और विभिन्न स्तर का सरकारें एक साथ आधिकारिक रूप से न जोड़ दी जायें ताकि उच्च स्तर की संस्थाओं निम्न स्तर से समर्थन और सत्ता प्राप्त करें और सम्पूर्ण देश के व्यक्तियों का ग्राम सभाओं पर आधारित हो ।

हर प्रणाली में बुराईया व दोष होने । पंचायती राज अथवा भागीदारी के लोकतंत्र में बुराईया होंगी, लेकिन वह प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक होगी और उसके दोषों को ठीक करने में काफी गुंजाइश होगी, क्योंकि वह अधिक लोकतांत्रिक होगी । बहुत सी बुराईयों को धारम्भ में ही दूर किया जा सकता है यदि चुनाव निर्विरोध हो जायें ।

## पंचायती राज

अखिल भारतीय पंचायत परिषद समझती है कि वर्तमान पंचायती राज एक कार्यक्रम है जिस पांच स्तरीय सरकार के निर्माण की दिशा में प्रथम कदम बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद इस बात पर जोर देती है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप जो सस्याये बनाई जायेगी उन्हें स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में समझना चाहिये और उनके कर्तव्यों व अधिकारों का उन्हीं के अनुसार निश्चय होना चाहिए।

ग्राम ब्लॉक व जिला स्तर पर पंचायती राज की सस्याओं को स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में काम करना चाहिए इन सस्याओं को राज्य सरकार का अंग नहीं बनाया जा सकता है यद्यपि वे विकेन्द्रीत राज के भाग होते हैं।

फाइनल प्रोब्लमस आरु पंचायती राज—पृष्ठ—८२

## पंचायती राज और राज्य सरकार

अखिल भारतीय पंचायत परिषद इस विचार के विरुद्ध है कि पंचायत राज की सस्याओं को राज्य सरकार की ऐजेंसियों के रूप में काम करना चाहिए। परिषद का मत है कि चूंकि इन सस्याओं की स्थापना लोकतांत्रिक ढंग से हुई है, उनके भी उसी प्रकार निश्चित कार्य और क्षेत्र

अब जिन प्रश्न पर विचार है वह है कि पंचायती राज को किस प्रकार उच्च स्तर पर बढ़ाया जाय।

यह उचित होगा कि नीचे की स्तर की सस्यायें ऊँचे स्तर की सस्याओं की चुनें। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्राम सभा पंचायत समिति, पंचायत समिति जिला परिषदों, जिला परिषदों [ राज्य विधान सभा को और राज्य विधान सभायें लोक सभा को चुने, लेकिन बाद में सावधानी पर यह प्रक्रिया अवांछनीय होगी। इसके विरुद्ध मुख्य आपत्तियाँ ये होंगी—(१) इसमें सकीर्णता की प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक और नीचे की सस्यायें अनुभव करेगा कि राज्य व केन्द्र के स्तर पर सस्याओं के बनाने में इसका कोई हाथ नहीं है। (२) चूंकि निर्वाचन की संख्या थोड़ी होगी, धनी लोगों को उहें अछूत करना आसान होगा।

वर्तमान प्रणाली के बारे में भी ऐसी ही आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रस्तावित प्रणाली के दोषों को दूर करने के उपाय का न हूँदा जाये। इसका हम यह नहीं कि वर्तमान प्रणाली से चिपका रहा जाये जिसमें और भी भारी दोष है।

विधान सभा व लोक सभा के चुनावों के लिये यह एक शुभाव प्रयोग के रूप में रखा रहा है।

प्रत्येक गाँव सभा को ग्राम सभा में दो प्रतिनिधियों को चुनना चाहिये। जिन्होंने निर्वाचक परिषद कहा जा सकता है। उनका चुनाव हम प्रकार किया जाये। ग्राम सभा में नागरिक पत्र का



होना चाहिए जैसे कि समग्र व राज्य स्वारो के कार्य सविधान मे दिये गये हैं । जवनक इम लक्ष्य को पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया जाता है ताकि पचायती राज व राज्य सरकार के बीच के सम्बन्ध के बारे मे दुविधा कम की जास्के तब तक प्रत्येक राज्य मे एक स्वतंत्र पचायती राज आयोग होना चाहिए जो पचायती राज के मामलो की देख भाल करेगा, और उहे स्वायत्त शासन की शर्कियो के रूप मे बनायेगी ।

राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र राज्य पचायत बोड होना चाहिए और एक जिला पचायत बोर्ड जो नीचे की सस्याओ को सलाह दे और उसका मार्ग दर्शन करे । प्रस्ताव अखिल भारतीय पचायत परिषद के द्वितीय अधिवेशन मे पारित ।

श्री जयप्रकाश नारायण ने इस सुझाव को अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया है । उन्होंने बताया है कि यह बोड राजनीतिक दलो के हस्तक्षेप से दूर होना चाहिए और इसका अध्यक्ष एक अधिकारी हो जो अनैतिक सेवा का सदस्य न हो ।

मांगा जाये और जिन नामो के प्रस्तावक व समर्थक हा उहे एक बोड पर लिख दिया जाये । यदि केवल दो नाम आने हैं तो वे अपने आप प्रतिनिधि चुन सम्म बन चाहिये । इसके बाद बार बार मतदान हो ताकि केवल दो नाम ही रह जायें । प्रत्येक बार कम से कम प्राप्त करने वाले का नाम हटा देना चाहिये । यह साधारण व कम खर्च की प्रणाली होगी और चूकि ग्राम सभायें बठको का संचालन करती हैं बजट पास करती हैं, श्रम नियम बनती हैं इसलिये यह प्रक्रिया उनके लिये एक आसान काम हो जायेगी ।

पचायत के अध्यक्ष व नेतृत्व में पूवाभ्यास करने में उन कठिनाइयो को दूर किया जा सकेगा जो पहले उनके सामने आ सकती हैं ।

इसके बाद निर्वाचन परिषद की वरक चुनानी चाहिये और प्रत्येक प्रस्तावित व समर्थक के नाम पर मत लिये जायें । जो नाम निश्चित मतदान ज्यादातरण के लिये ३० प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करें उहे उस क्षण से विधान या लोक सभा के लिये उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिये ।

म लोकतंत्र की पूछ बनान के लिये यह आवश्यक समझता हू कि इसकी प्रक्रिया जहां तक सम्भव हा सके मज-जोम पदा करन वाली हो । इसलिये मैं औरदार शब्दो में घुमुरोध करता हू हर वधानिक व सक्षणिक उपाय द्वारा प्रयत्न किया जाये कि निर्वाचन परिषद प्रत्येक स्थान के लिये एक हा उम्मीदवार सजा करे । आखिरकार सख्या कुछ भी हो अन्त में उस निर्वाचन क्षण से एक व्यक्ति ही चुना जायेगा । लोकतान्त्रिक सिद्धांत तक के विरुद्ध कुछ ऐसा कहता है कि जब एक प्रतिनिधि बन जाना है और उस अपने विरोधियों की भी सेवा करनी चाहिये । यदि निर्वाचन परिषद को समझाया जा सके कि वह एक उम्मादवार ही सजा करे तो अनावश्यक आवेध और घन व शक्ति की खर्चो की रोना जा सता है । यदि वह व्यवहारिक न हो तो कुछ मामलो में इस प्रकार चुने गये नामो की निम्न ढग में रखना चाहिये ।

## पंचायती राज के विभिन्न स्तर

पंचायती राज के विभिन्न स्तरों के बीच के सम्बन्ध वैसे ही होने चाहिये जैसा कि सरकार की दो इकाईयों के होते हैं। बड़े और छोटे का कोई प्रश्न नहीं होता चाहिये। इन समस्याओं के बीच निम्न-उच्च आंगिक सम्बन्ध होगा। ऊँचे स्तर की समस्याएँ नीचे स्तर की समस्याओं द्वारा ही बनाई जायेंगी। ऊँचे स्तर की योजनाएँ मुख्य रूप से निम्न स्तर की योजनाओं का ठोस रूप होंगी। निम्न स्तर की योजनाएँ भी उच्च स्तर की सीमाओं में क्षेत्र का ध्यान रख कर बनाई जायेंगी।

मरी समझ से इस प्रश्न पर अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि तीनों में से हरेक मस्या अपने स्तर पर एक सरकार हो, तो वह एक जैसी महत्वपूर्ण होगी और अपने अपने साधनों से वह सब कुछ कर सकेंगी जो उसका उतरदायित्व होगा। ग्राम पंचायत व अन्य दो मस्याओं की प्रशासन के मार अधिकार होने चाहिये जिनके कार्यविमन में वे योग्य हों। ऐसा कोई कारण नहीं कि जिला परिषद की केवल सम्पर्क या परामर्शदात्री मस्या बना कर रक्खा

---

निर्वाचक परिषद द्वारा चुन हुए नामों को सम्बन्धित क्षेत्र की ग्राम मस्याओं की भेंट दिया जाये। प्रत्येक ग्राम सभा अपने अपने बटवें बुलावे जहाँ प्रत्येक उम्मीदवार का मन लिया जाना चाहिये। उसके बाद नीचे लिखे दो तरीकों में कोई एक अपनाया चाहिये।

जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करे उसे ऐसा व्यक्ति घोषित किया जाये जिस विशेष ग्राम सभा उन्वत्तर सभा में प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहती है। ऐसे सभी व्यक्तियों में उक्त व्यक्ति को ग्राम सभा का सदस्य घोषित कर देना चाहिये।

दूसरा विवरण यह है कि ग्राम सभा की ग्राम बैठक में प्रत्येक उम्मीदवार को जो मत मिले उन्हें लिख लेना चाहिये। इसी प्रकार उसे अन्य ग्राम सभाओं में भी जो वोट मिले हों उन्हें लिख लेना चाहिये। इस प्रकार जिसे सबसे अधिक वोट मिलें उसे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि घोषित कर देना चाहिये।

स्पष्ट है कि इस चुनाव प्रणाली में कई बाधित परिणाम निश्चित हैं। पहला हमसे लोकतन्त्र की इमारत का ऊपरी भाग नीचे के भाग से झुट जाता है। ग्राम सभा की प्रतिष्ठा, शक्ति और महत्व प्राप्त हो जाता है। वह स्थानीय सर्वोत्तमता का दलदल से ऊपर उठ जाती है। दूसरे प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को एक सीधा अवसर प्राप्त होता है कि वह सावजन के सबसे ऊँचे संगठन के चुनाव में भागीदार बन। ग्राम सभाओं का निर्वाचक मण्डल द्वारा ऐसा सम्भव हो जाता है ताकि वह अपने प्रतिनिधियों पर प्रभाव डाल सके। इस प्रकार बात के बराबर पृथक् सधु और असहाय बण नहीं रहते हैं बल्कि पत्थर की ठोस ईंटें बन जाते हैं। इस प्रकार जो मजान पत्थर की ईंटों पर बनता है वह बाजू के ऊपर बने मजान से मिल्न होता है।

—*श्री जयप्रकाश नारायण, गोपालगंज, बेगान सा पृष्ठ २६५ ७०*

जाये या पचायत समिति को केवल जिला परिषद का एक कार्यपालिका भग बनाकर रक्खा जाये।

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार ओन फ डामेन्टल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज—पृष्ठ-४२

## ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पचायत परिषद् ग्राम सभा की शक्ति को बड़ा महत्व देती है। यह प्राथमिक समुदाय और मौलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायणजी कहते हैं —

मुझे शक है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान को पूरी तौर पर नहीं समझा गया है या शायद हमारे मन में जनता की पहल करने की शक्ति के बारे में काफी अटकान हैं। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को शक्तिशाली नहीं बनाया जाता है तो पचायती राज अवास्तविक हो रहेगा और विकास कार्यक्रमों में भी जनता का उत्साह व भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मन के अटकान को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा।

अखिल भारतीय पचायत परिषद् के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री महताजी ने कहा —

ग्राम सभा ने योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह कम है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रों का पूर्ण महत्व तभी अनुभव किया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तौर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जाती है।

पचायती राज परंपरित्व एण्ड प्रोग्राम—पृष्ठ-३१

इस बीच ग्राम सभा को बजट पर बहस करने का और पचायत की जनता की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और वह जो गिफ्टारिशे करे उस पर पचायत पूर्ण तौर पर विचार करे।

जब कि ग्राम सभा का अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपना वार्षिक बजट बनाये और स्वीकार करे। पचायत अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाओं के सामने पेश करना चाहिए, जहाँ उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अंतिम स्वीकृति का प्रश्न उन पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

सेमिनार ओन फ डामेन्टल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज—पृष्ठ-८४

पचायती को ग्राम सभा में पूर्ण प्रिन्सिपल रचना चाहिये और कर, विकास व निर्माण सम्बंधी कार्यक्रमों को उसके सामने उसके विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में कार्य समितियाँ होनी चाहिए। पंच उनके एग्जीक्यूटिव, और ग्रामसभा के चुन हुये सदस्य उनके मदस्य हैं। गांव का चौकीदार ग्रामसभा का अधीन हो।

सेमिनार ओन फ डामेन्टल प्रोब्लम्स ऑफ पचायती राज पृष्ठ-८४

पंचायतो को ग्रामसभा की कार्यकारिणी के रूप में काम करना चाहिए। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में बिना सघर्ष के होना चाहिए।

यह सम्मेलन पंचायता, ग्रामीण जनता व सभी रचनात्मक संस्थाओं से अनुरोध करता है कि उह पंचायती राज की संस्थाओं के चुनावों में एकमत प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता है कि वे ऐसे उचित कदम उठाये ताकि पंचायती राज की संस्थाओं में एकमत से निर्वाचन हो सके। राजनीतिक दलों को पंचायता के चुनावों से दूर रहना चाहिए। पंचायता को दलबन्दी व राजनीति व से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने दल के आधार पर पंचायतों के कोई चुनाव न लडे। यह सम्मेलन प्रत्येक राजनीतिक दल से अपील करता है कि वह इस प्रकार का निर्णय करे और उसे कार्यान्वित करे। प्रस्ताव न०—१ अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का तीसरा अधिवेशन।

पंचायतों की आर्थिक प्रशसन के रूप में ढूँढ बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उहे सारा प्रशासन एवं भूमिकर सौंप दिया जाय। इस प्रस्ताव द्वारा अन्य राज्य सरकारों से सिफारिश की जाती है कि वे भी गुजरात की भांति पंचायतों को भूमिकर सौंप दे। प्रस्ताव न० ५, अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का तीसरा अधिवेशन।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् पंचायतों के लिये और अधिक अधिकार देने का अनुरोध करता है, और अन्तिम लक्ष्य यह होगा कि वे पटवारी और अन्य ग्राम अधिकारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण करें।

पटवारी या ग्राम का हिसाब बिताने वाले को सभी दानविल-स्वार्जिज की एक प्रति पंचायत प्रधान के सामने पेश करना चाहिये। पंचायत को उक्त दानविल-स्वार्जिज के बारे में ग्राम सभा को रिपोर्ट देनी चाहिये, और उचित अधिकारी को उक्त परिवर्तनों के बारे में सूचित करना चाहिये।

सेमिनार प्राम्बलास और कं डामेंटल आफ पंचायती राज पृष्ठ-८४

यह आवश्यक है कि ऐसे सभी अधिकार व कर्त्तव्य-ग्राम पंचायतों को सौंपे जाये जिनसे व गाँव के वास्तविक और एकमात्र केन्द्र बन जाये।

प्रथम-अखिल भारतीय पंचायत परिषद् सम्मेलन पृष्ठ-३

इस सम्मेलन की राय में एक पंचायत सेवा संगठन बनाया जाये जिसमें अनुभवों और प्रशिक्षित व्यक्ति हों—प्रथम अखिल भारतीय पंचायत परिषद् सम्मेलन-३

गाव में स्वायत्त शासन का क्या रूप हो, इसके बारे में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के विचारों का और उन्हें स्पष्ट शब्दों में प्रगट करने का जहाँ तक सम्भव है परिषद् को अभी अपने विचारों को सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में भारत-०० पाटिल ने विचार-करने के लिये इसी

जाये या पंचायत समिति को केवल जिला परिषद का एक कार्यपालिका अंग बनाकर रखा जाये।

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार और फंडामेंटल प्रोग्राम्स आफ पंचायती राज—पृष्ठ-४२

## ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् ग्राम सभा की शक्ति को बड़ा महत्व देती है। यह प्राथमिक समुदाय और मौलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायणजी कहते हैं—

मुझे शका है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान को पूरी तौर पर नहीं समझा गया है या शायद हमारे मन में जनता की पहल करने की शक्ति के बारे में काफी अटकबाध है। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को शक्तिसाली नहीं बनाया जाता है तो पंचायती राज अवास्तविक ही रहेगा और विकास कार्यक्रमों में भी जनता का उत्साह व भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मन के अटकबाध को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री मेहनजी ने कहा—

ग्राम सभा के योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह कम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रों का पूर्ण महत्व सभी अनुभव दिया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तौर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जाती है।

पंचायती राज परियोजना एण्ड प्रोग्राम—पृष्ठ-३१

इस बीच ग्राम सभा को बजट पर बहुत करने का और पंचायत की उन्नति की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाता चाहिए और वह जो सिफारिशें करें उस पर पंचायत पूरी तौर पर विचार करे।

जब कि ग्राम सभा का अंतिम लक्ष्य यह जाना चाहिए कि वह अपना वार्षिक बजट बनाये और स्वीकार करे। पंचायतें अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाओं के सामने पेश करना चाहिए, जहाँ उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अंतिम स्वीकृति का प्रश्न उन पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

सेमिनार और फंडामेंटल प्रोग्राम्स आफ पंचायती राज—पृष्ठ-८४

पंचायती को ग्राम सभा में पूर्ण विचार रखना चाहिये और कर, विकास व निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों को उसके सामने उसके विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में कार्य समिति का होना चाहिए। पंच उनके सयोजक हों, और ग्राम सभा के चुन हुये सदस्य उनके सदस्य हों। गांव का चौकीदार ग्राम सभा का अधीन हो।

सेमिनार और फंडामेंटल प्रोग्राम्स आफ पंचायती राज पृष्ठ-८४

पंचायतो को ग्रामसभा की वायव्यारिणी के रूप में काम करना चाहिए। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से बिना सघर्ष के होना चाहिए।

यह सम्मेलन पंचायतो, ग्रामीण जनता व सभी रचनात्मक संस्थाओं में अनुरोध करता है कि उन्हें पंचायती राज की संस्थाओं के चुनावों में एकमत प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता है कि वे ऐसे उचित कदम उठाये ताकि पंचायती राज की संस्थाओं में एकमत से निर्वाचन हो सके। राजनीतिक दलों को पंचायतो के चुनावों से दूर रहना चाहिए। पंचायतो को दलबन्दी व राजनीति व से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने दल के आधार पर पंचायतो के कोई चुनाव न लड़े। यह सम्मेलन प्रत्येक राजनीतिक दल से अपील करता है कि वह इस प्रकार का निर्णय करे और उसे कार्यान्वित करे। प्रस्ताव न०—१ अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, का तीसरा अधिवेशन।

पंचायतो को आर्थिक प्रशासन के रूप में दृढ़ बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सारा प्रशासन एवं भूमिकर सौंप दिया जाय। इस प्रस्ताव द्वारा ग्राम राज्य सरकारों से सिफारिश की जाती है कि वे भी गुजरान की भांति पंचायता को भूमिकर सौंप दे। प्रस्ताव न० ५, अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का तीसरा अधिवेशन।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् पंचायतो के लिये और अधिक अधिकार देने का अनुरोध करता है, और अन्तिम लक्ष्य यह होगा कि वे पटवारों और ग्राम प्राप्त अधिकारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण करें।

पटवारी या ग्राम का हिस्सा किताब रखने वाले को सभी दायित्व-कारिज की एक प्रति पंचायत प्रधान के सामने पेश करना चाहिये। पंचायत को उन दायित्व-कारिज के बारे में ग्राम सभा को रिपोर्ट देनी चाहिये, और उचित अधिकारी को उन परिवर्तनों के बारे में सूचित करना चाहिये।

'सेमिनार प्रान्तास और फाउन्डेशन ऑफ पंचायती राज पृष्ठ-८४

मह। आवश्यक है कि ऐसे सभी अधिकार व कर्तव्य-ग्राम पंचायतो को सौंपे जायें जिनसे व गांव के वास्तविक और एवमात्र केन्द्र बन जायें।

प्रथम अखिल भारतीय पंचायत परिषद् सम्मेलन पृष्ठ-३

इस सम्मेलन की राय में एवं पंचायत सेवा संगठन बनाया जायें जिसमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति हों—प्रथम अखिल भारतीय पंचायत परिषद् सम्मेलन-३

गांव में स्वायत्त शासन का क्या रूप हो, इसके बारे में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के विचारों का और उन्हें स्पष्ट रूप में प्रगट करने का जहां तक सम्भव है परिषद् को अपनी अपने विचारों को सूत्रबद्ध करना है। हाल ही में ग्राम० के० पाटिल ने विचार-चक्र-केन्द्र के तंत्र में इसी

विषय पर एक लेख लिखा है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् जन्दी ही उस पर विस्तारपूर्वक विचार करने वाली है।

## आर्थिक विकेन्द्रीकरण

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ अखिल भारतीय पंचायत परिषद् आर्थिक विकेन्द्रीकरण का भी समर्थन करती है। इसका मन है कि पंचायतों को भी अपने कृषि सम्बन्धी उद्योगों को आरम्भ करना चाहिये। इनसे गांव की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और पंचायतों के भी आर्थिक साधन दृढ़ बनेंगे। आगे का दृष्टिकोण यह है कि सहकारी समितियां और ग्राम मस्याये पंचायत के नियंत्रण में लाई जायें ताकि गांव का समाज आत्म निर्भर बने। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् द्वारा की गई आर्थिक विकेन्द्रीकरण की मांग से यह सुझाव अवश्य भावी बन जाता है। अतिरिक्त काल के लिये राय यह है कि सहकारी समितियां व अन्य ग्रामीण संस्थायें ग्राम पंचायतों को उचित महत्व दे और सबको मिल जुलकर काम करना चाहिये। भूमि जैसे उत्पादन के साधनों को ग्राम समाज के स्वामित्व में लाना चाहिये।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की राय है कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ चलना चाहिए। आज की परिस्थितियां विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था की कुछ आवश्यक बातें व शर्तों के बारे में श्री जयप्रकाशनारायण ने बताया हैं। उनके विचार से केवल खादी और ग्राम उद्योग पर ही अधिक बल देने से हम बहुत आगे नहीं जा सकते। हमें इस विषय पर स्पष्ट चिंतन का विकास करना चाहिये। ६

६—प्रथम, यह स्पष्ट है कि ऐसी आर्थिक व्यवस्थाएँ छोटी मशीनों व अम प्रधानता के आधार पर होनी चाहियें। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि छोटी मशीनों को उन्नत बनाने के लिये लगातार व सुनियोजित प्रयास होने रहने चाहिये ताकि उसकी कीमत को अधिक बढ़ाये बिना उसकी निपुणता और उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती रहे। इसके लिये आवश्यक शोध की योजना बनाई जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय। जहां कहीं आवश्यक हो और प्राप्त हो सके वहां विजली का प्रयोग करना चाहिये। लेकिन आर्थिक व्यवस्था की तत्सर्वो हमेशा सामने रहनी चाहिये ताकि जहां तक सम्भव हो क्षीयता व उत्पादन रोजगार और पदार्थों के उपयोग के बीच असंतुलन पैदा न हो जाय।

द्वितीय, एक विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिये कि स्थानीय व प्रादेशिक आवश्यकताओं के धनुर्वृक्ष स्थानीय व प्रादेशिक साधनों का मानव या पदार्थ के रूप में ही पूरा-पूरा प्रयोग किया जाय। इस वास्ते प्रादेशिक सर्वेक्षण और नियोजन आवश्यक होगा। इसके आगे यह भी मानना पड़ेगा कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक इकाइयों के रूप में बनाना होगा ताकि बनावट व क्षेत्रीय उद्योग हा दूसर जितना राज्य व राष्ट्रीय उद्योग हा। साथ के कुछ और सच के समी उद्योग बड़े पैमाने पर होंगे। इसका यह भय नहीं कि एक क्षेत्र की बचन दूसरे क्षेत्र की बचन में परिवर्तित नहीं की जायेगी। लेकिन इसका यह भय अवश्य है कि ग्रामतौर पर हर प्रकार के उद्योगों व नित्य सम्भावित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र होंगे जिनके अन्तर्गत यह

मे अनुभव करता हूँ कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण के बिना राजनीतिक विकेन्द्रीकरण संभव नहीं है। मेरे विचार से यह स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह बनाना चाहिये कि राजनीतिक रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह बनाना चाहिये कि राजनीतिक रूप से स्वायत्त शासित इकाईयाँ किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वायत्त सरकार का रूप धारण कर लेंगी। यह पूर्ण रूप से करना सम्भव है। यदि नहीं तो किस सीमा तक और कैसे यह किया जा सकता है? यदि इन प्रश्नों के हल में विलम्ब किया जायेगा तो इसका अर्थ पचायती राज को प्रभावहीन करना होगा।

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार फ्रामेन्टन आफ पचायती राज—६

उद्योग होगा। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त आर्थिक तरीके विकसित पड़ेंगे ताकि लघु स्तर से औद्योगीकरण के लिये सुविधा हो और जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आर्थिक व्यवस्था के इस भाग की बढ पमाने के केंद्रित उद्योगों में रक्षा करनी होगी ताकि यह आर्थिक व्यवस्था अच्छी तरह विकास कर सके और अपने पक्ष पर खड़ा होन वाला बन।

तोसर जन शक्ति और भूमि के अनुपात की दृष्टि से और जन मस्या की वृद्धि का ध्यान में रखते स गांव की आवादी को कृषि व विकास के वाक्जुद घेरे घेरे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा यदि वह पूरी तौर पर भूमि पर ही निर्भर रहती है। इसलिये उद्योगीकरण जिसका अणुन ऊपर किया गया है कृषि के साथ मिला जुला होना चाहिये ताकि प्रत्येक गांव या ग्राम समूह को कृषि औद्योगिक समाज के रूप में विकसित किया जा सके। यहा पर भूमि उद्योग का अर्थ केवल उन उद्योगों से नहीं है जिनमें कृषि से पैदावार की गई वस्तुओं को सवारा जाता है। इसका अर्थ है कि कृषि और उद्योगों में आगिन मेल-जोल बनाया जाय। उदाहरण के लिये कृषि उद्योगिक समाज न केवल पत्र सजिन्ना, गन्ना रूई हो पदा करेगा बल्कि रेडियो, साइकिल के पुर्जे, छोटी छोटी मशीनें बिजली का सामान जो पदा करेगा ऐसे विकास से नगर और गांव के बीच का अंतर भी कम हो सकेगा और नगरीकरण की बुगार्यों को दूर किया जा सकेगा।

चोथे यह स्पष्ट है कि विवेकित उद्योगों में व्यवसाय का संगठनात्मक रूप भी केन्द्रीय सख्ठ से भिन्न होना चाहिये। वह निजी उद्योगों में हो या सरकारी उद्योगों में, विवेकित रूप धारित रूप से सहकारी जसा होगा इसमें केन्द्रीय सख्ठ या आर्थिक समानता होंगे—बाह निजी हो या सरकारी।

पाचवा, पचायती राज की राजनीतिक मस्याओं की इस आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करना पड़ेगा। सम्म्या यह है कि यह सबकुछ होगा।

मे कुछ अर्थ विचारों को पत्र करने समाप्त करना चाहूंगा। मे पहले यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उत्पन्न प्राचीन तरीकों की रक्षा करना मेरा मतलब नहीं है। मेर उद्देश्य से आधुनिक और प्राचीन व बीच बहुत अन्तरांगिक है। वास्तव में मे जो मुझाव रख रहा हूँ, वह सबसे अधिक



## पंचायती राज का भविष्य

पंचायतीराज के विकास में अखिल भारतीय पंचायत परिषद को पूर्ण विश्वास है। भारत की राज-व्यवस्था का आधार निश्चित रूप से पंचायती राज ही होगा। लेकिन परिषद यह भी जानती है कि हमारे मार्ग में कौन सी कठिनाइयाँ हैं। पंचायती राज के स्वरूप के बारे में जनता को अच्युती तरह प्रशिक्षित बनाना है। उसे यह भी सिखाना है कि पंचायती राज की संस्थाओं को उचित रूप से किस प्रकार चलाया जाता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भूमि सुधारों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाय और ग्राम की आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाये। इसके अतिरिक्त देश के राजनैतिक नेताओं एवं प्रमुख लोगों का पंचायती राज के प्रति जो उदासीनता का दृष्टिकोण है उसे बदलने का भी प्रश्न है। दूसरी बड़ी कठिनाई इन संस्थाओं के प्रति सरकारों के दृष्टिकोण की है।

प्राथमिक ग्राम व्यवस्था है। वही ग्राम व्यवस्था न कहीं रही और न कहीं है। जिसकी रचना में विज्ञान व समाज विज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में एक मजबूत नवीन तकनीकी और साधन-साधन में एक नवीन सामाजिक आर्थिक तकनीकी पदा करनी होगी। यह वह विवर्तन नहीं है जो पश्चिम या जापान की सबसे अधिक विकसित ग्राम व्यवस्था में पाया जाता है। मेरे विचार से ग्राम व्यवस्था का प्रभावपूर्ण रूप एक ऐसा विवर्तन है जिसमें कौशल उतना विवर्तन हो जिसे मलग नहीं किया जा सकता है। दाना व बीज में कुछ सतुल्य आवश्यक है, लेकिन निस्संदेह विकेंद्रित खण्ड केंद्रित खण्ड का पूरक मात्र नहीं होगा।

दूसरे, यह याद रखना आवश्यक है कि विवेचित आर्थिक व्यवस्था जिसका प्रतिपादन मैं कर रहा हूँ केवल इसलिए वांछनीय नहीं है कि यह लोकतांत्रिक होगी बल्कि इसलिए कि इसने द्वारा जनता को तुरन्त लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक बड़े पमान पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो सामान पदा होगा वह बड़े पमान पर बाँटा जा सकेगा और साधारण उपभोक्ता को तुरन्त ही उसकी आवश्यकता की सामग्री मिलेगी। केंद्रित खण्ड में याद रखना चाहिये उद्योगीकरण का लाभ धीरे धीरे ऊपर से नीचे की दिशा में जायगा। पश्चिम में सगमग से बरस से जाग साधारण यत्ति तक पहुँचा स्पष्ट है कि भारत जस गरीब देश में जहाँ कम से कम आवश्यकता की वस्तुओं का मिलना कठिन है और जहाँ बेरोजगारी या कम रोजगारी इतनी यापक मात्रा में पायी हुई है। एक विकेंद्रित ग्राम व्यवस्था केंद्रित ग्राम व्यवस्था नहीं एक सबसे बड़ी आवश्यकता है बल्कि आर्थिक विकास का उद्देश्य लोक-कल्याण हो।

तीसरे, ऊपर बताई गई आर्थिक व्यवस्था पदा करने के लिये ग्रामवासियों की शिक्षा में प्रामुल पूल परिवर्तन करना होगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ग्रामवासियों की शिक्षा अभिवाश रूप से पुस्तक से प्रपन्न होनी चाहिये। यह व्यवहारिक व तकनीकी हो जिसमें कृषि तकनीकियों की शिक्षा भर विशेष जोर दिया गया हो।

शिक्षा प्रणाली में इस सुधार को जोड़ और नियोजन का एक अंग होना चाहिये। इससे

यह छिपी हुई वान नहीं है कि देश में एक प्रभावशाली जनमत है जिससे सिद्धान्त की दृष्टि से दलितों या मध्य वर्ग में नहीं बांटा जा सकता है। वह विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता है। मुख्य कारण दो बताये जाने हैं (१) जनता स्वायत्त शासन के लिये योग्य नहीं है (२) सत्ता और सरकार के विकेंद्रीकरण में राष्ट्र छिन भिन हा जायेगा।

श्री जयप्रकाशनारायण, पंचायती राज एक दर्शन पृष्ठ-२८

भूतिरिक्त ग्रामीणों की शिक्षा के अंतर्गत बट पमाने पर व्यक्तों को 'याग्यारिक शिक्षा' दी जाय। इस प्रकार की शिक्षा एक दूसरे कठिन प्रश्न का उत्तर देगी कि विवैदित ग्रंथ 'यवस्था' के विकास के लिये 'यकित' कहा स साथे जायें ?

अन्त में आज देश की साधारण परिस्थिति में जब बड़ी बड़ी योजनायें फगन बन गई हैं जो विदेशों की भारी सहायता पर निर्भर होती हैं यह स्वाभाविक है कि वे 'उन' तमाम साथियों पर एक मात्र अधिकार रख लिये 'राज्य' में बांटा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में केन्द्र बहुत शक्तिशाली हो जायेगा और सब नीचे की सत्तायें भिलारी के स्तर पर आ जायेंगी। लोकतन्त्र के विकास के लिये यह भयंकर बात होगी लेकिन यहाँ विदेशी सहायता के हथार प्राधिक विकास पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन पर पड़न बाल प्रभाव पर बहुत नहीं करना है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि विवैदित प्राधिक विकास को विदेशी सहायता पर केन्द्रित खण्ड को घपेक्षा कम निर्भर रहना होगा। इसके तीन मुख्य कारण हैं। (१) स्वेच्छिक ग्रंथ का तत्व अधिक होगा। (२) छोटी छोटी बचत की रकमों का अधिक स अधिक प्रयोग किया जायेगा। (३) यातायात ऊगरी खर्च और ग्रंथ सामाजिक खर्च भी बहुत कम हो लें। इसलिये इस ग्रंथ में विवैदित ग्रंथ व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक होगी।

(श्री जयप्रकाश नारायण सोचलियम सर्वोन्म एण्ड डमोन् लो।)

